राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 228

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 25 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

श्रेयस बोले, मैच को छक्के के साथ खत्म करना अच्छा लगता है

>> 14

हमें भी अभिव्यक्ति का अधिकार

इशारों की ही सही, लेकिन यही हमारी भाषा है, यही अभिव्यक्ति। इसे संवैधानिक मान्यता मिलने से हमारी यह भाषा संरक्षित और समृद्ध होते हुए हमारे समाज के लिए मददगार सिद्ध होगी...। यह कहना है नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ का। पेज-11

जागरण विशेष

कोशिश यही रहती है कि हर बार कुछ अलग करूं...

कोलकाता : राजपथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड समारोह की बीते एक दशक से कमेंट्री करते आ रहे रिटायर्ड कर्नल जीवन कुमार सिंह का कहना है कि वे हर वर्ष कुछ बेहतर और नया करने का प्रयास करते हैं। इस बार क्या है उनकी तैयारी, विशेष बातचीत। (पेज-6)

राजनीति का अपराधीकरण खत्म हो : सुप्रीम कोर्ट

निर्देश ▶ चुनाव आयोग और याचिकाकर्ता एक सप्ताह में रूपरेखा तैयार करके लाएं

अपराधियों को टिकट नहीं देने के लिए राजनीतिक दलों को निर्देश देने की उठी मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राजनीति में अपराधीकरण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के लिए जल्दी ही कुछ करने की जरूरत पर बल दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक हफ्ते में रूपरेखा तैयार करके पेश करने को कहा है। कोर्ट ने ये निर्देश शुक्रवार को उस वक्त दिए जब आयोग ने कहा, उम्मीदवारों का आपराधिक ब्योरा प्रकाशित कराने के कोर्ट के आदेश पर अमल के बावजूद अपराधीकरण रुक नहीं रहा है। कोर्ट सियासी दलों को निर्देश दे कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट ही न दें।

न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन व एस रविन्द्र भट्ट की पीठ ने शुक्रवार को भाजपा नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने कहा,चुनाव आयोग और याचिकाकर्ता एक साथ बैठकर एक हफ्ते के भीतर राष्ट्रहित देखते हुए राजनीति का अपराधीकरण रोकने की रूपरेखा तैयार करके लाएं। इस मामले में अगले शुक्रवार को फिर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 25 सितंबर, 2018 में आदेश दिया था कि हर उम्मीदवार नामांकन दाखिले के बाद तीन बार अपना आपराधिक ब्योरा अखबार में प्रकाशित कराए। टीवी चैनल पर भी विज्ञापन दे, ताकि जनता को उम्मीदवारों की पूरी जानकारी हो और वह उचित निर्णय ले सकें।

याचिकाकर्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास नहीं किया। न ही समाचार पत्रों की और न ही टीवी चैनल की लिस्ट और प्रचार का समय तय किया है जिसमें उम्मीदवार को ब्योरा प्रकाशित कराना हो। ऐसे में उम्मीदवार छोटे-छोटे स्थानीय अखबार में ब्योरा प्रकाशित करा देते हैं और टीवी चैनल पर भी देर रात प्रचार किया जाता है। सरकार के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने इस मुद्दे पर कानून बनाने को कहा था, लेकिन इस पर कानून नहीं बनाया गया। सरकार का कहना है कि कोर्ट ने उसे कानून बनाने का कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया था। इसलिए अवमानना की याचिका खारिज की जाए।

इस मामले में अगले शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट — फाइल फोटो

दागी सांसदों की संख्या 34 फीसद से 46 फीसद हुई

अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि यह ठीक है कि कोर्ट संसद को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता लेकिन राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है। 2014 में दागी सांसदों की संख्या 34 फीसद थी जो 2019 में 46 फीसद हो गई है। कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वह सियासी दलों पर दबाव डालें कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं को टिकट न दें। ऐसा होने पर आयोग राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करे।

कोर्ट ने कहा,राष्ट्रहित में जल्द कुछ करने की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है। राष्ट्रहित में जल्दी ही इस पर कुछ किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि आयोग और याचिकाकर्ता एक साथ बैठकर राजनीति का अपराधीकरण रोकने के प्रभावी उपाय और रूपरेखा तैयार करें। राष्ट्रहित में ये जल्दी ही होना चाहिए। इसे विपरीत कानूनी कार्रवाई नहीं माना जाना चाहिए।

आयोग ने नामांकन फार्म में जरूरी बदलाव किए

चुनाव आयोग के वकील विकास सिंह ने कहा कि आयोग ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नामांकन संबंधी फार्म में जरूरी बदलाव किए हैं लेकिनउम्मीदवारों के आपराधिक रिकार्ड का ब्योरा प्रकाशित करने के आदेश से राजनीति का अपराधीकरण रोकने में मदद नहीं मिल रही है। कोर्ट राजनीतिक दलों को आदेश दे कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट न दें।

'रासुका का इस्तेमाल नहीं करने का व्यापक आदेश नहीं दे सकते'

नई दिल्ली : दिल्ली व अन्य राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के प्रावधान लाग किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा,रासुका का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके इस्तेमाल पर रोक का व्यापक आदेश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियां जलाई जा रही हैं ये संगठित भी हो सकता है। (पेज-3)

लखनऊ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल होगा अनुच्छेद 370 और सीएए

जागरण संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय (लविवि) में राजनीति शास्त्र के छात्र अब अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के बारे में भी पढ़ेंगे। विवि प्रशासन पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी में है। बोर्ड बैठक व कार्यपरिषद की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। विवि प्रशासन ने सभी संकायाध्यक्षों व विभागाध्यक्षों को जल्द नए सेलेबस को डिजाइन करने का लक्ष्य दिया है। विवि प्रशासन के मुताबिक राजनीति शास्त्र विभाग ने अनुच्छेद 370 और सीएए को भी कोर्स में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। उनका तर्क है कि प्रतियोगी परीक्षा में नए पाठ्यक्रम का लाभ ही परीक्षार्थी को मिलता है। विवि के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय का कहना है कि चूंकि अनुच्छेद 370 और सीएए अब कानून का रूप ले चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि विद्यार्थी इससे भलीभांति परिचित हों।

वहीं, इस मुद्दे पर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया कि सीएए पर बहस आदि तो ठीक है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई जारी रहने के बावजूद विवि द्वारा इस विभाजनकारी कानून को पाठ्यक्रम में शामिल करना अनुचित है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि हर मोर्चे पर फेल हो चुकी भाजपा शिक्षण संस्थाओं को भी विद्वेष की राजनीति का अड्डा बना देना चाहती है।

आधार को वोटर आइडी से जोड़ने के लिए कानून बना रही सरकार

- मतदाताओं को कई जगह नाम दर्ज कराने से रोकना है सरकार का मकसद
- चुनाव आयोग ने की है जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की सिफारिश

नई दिल्ली, आइएएनएस: कानून मंत्रालय चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद आधार संख्या को वोटर आइडी से जोड़ने की खातिर कानून तैयार करने के लिए कैबिनेट नोट पर काम कर रहा है। इसका मकसद लोगों को कई जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से रोकना है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन पर काम कर रहा है। प्रस्तावित संशोधनों को विचार के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है, ताकि वह इसे संसद में रख सके।

जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के बाद नागरिकों को गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र को 12-अंकों के आधार नंबर से जोड़ने की आवश्यकता होगी। एक अधिकारी ने बताया कि अभी यह फैसला नहीं लिया गया है कि कैबिनेट नोट को कब मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन, इसे 31 जनवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले या इसके दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।

चुनाव आयोग ने अगस्त 2019 में कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन की सिफारिश की थी, ताकि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वालों और मौजूदा मतदाताओं से आधार नंबर मांगा जा सके। मतदाता सूची में कई प्रविष्टियों की जांच करने और उन्हें त्रुटि मुक्त बनाने के लिए आयोग ने 2015 में मतदाताओं के डाटा के साथ आधार संख्या को जोड़ने की खातिर राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धीकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम परियोजना शुरू की थी। आयोग ने 23 जनवरी, 2015 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा था। इसके मुताबिक, मतदाता सूची के आवेदकों से आधार संख्या एकत्र करने के लिए 3 मार्च, 2015 को अभियान शुरू किया गया। लेकिन, 11 अगस्त, 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस पर रोक लगा दी कि मतदाताओं का आधार नंबर जुटाने के लिए कानून बनाने की जरूरत होगी। उस समय तक आयोग 38 करोड़ मतदाताओं का आधार नंबर जुटा चुका था, जबकि भारत में 75 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं। ज्ञात हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जन वितरण प्रणाली, खासकर अनाज व केरोसिन लेने के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

'भारत में ज्यादा दिन नहीं रहेगी आर्थिक सुस्ती'

- आइएमएफ प्रमुख ने अर्थव्यवस्था में गिरावट को अस्थायी बताया
- कहा, आने वाले दिनों में तेजी की राह पर चलेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

दावोस, प्रेट्र : भारत जैसी बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्था में कुछ गिरावट दिख रही है। हमारा मानना है कि यह गिरावट ज्यादा दिन नहीं रहेगी। यहां की आर्थिक सुस्ती अस्थायी है। आने वाले दिनों में इसमें तेजी का अनुमान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के वार्षिक सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित करते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जिवा ने शुक्रवार को यह बात कही।

आइएमएफ प्रमुख ने दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बढ़त की उम्मीद जताई। इसमें इंडोनेशिया और वियतनाम से काफी बेहतर आंकड़े दिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ सुस्ती है, लेकिन यह अस्थायी लगती है। आगे चलकर यहां की अर्थव्यवस्था फिर गति पकड़ेगी। कई अफ्रीकी देश अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जॉर्जिवा ने मेक्सिको समेत कुछ देशों की अर्थव्यवस्था पर चिंता भी जताई।

ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर आइएमएफ प्रमुख का भरोसा मजबूत दिखा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर, 2019 में आइएमएफ की ओर से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करते समय की तुलना में आज ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति बेहतर दिख रही है। अमेरिका और चीन के बीच पहले चरण का कारोबारी समझौता होने से तनाव में आई कमी ने माहौल को सकारात्मक बनाया है। हालांकि अब भी ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार 3.3 फीसद है, जिसे बहुत शानदार नहीं कहा जा सकता है।

आइएमएफ प्रमुख ने कहा, 'ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर अब भी धीमी है। हमें नीतिगत मोर्चे पर ज्यादा तेजी से कदम उठाने, ढांचागत सुधार करने और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है।' उन्होंने उत्पादकता में सुस्ती और महंगाई को ग्लोबल इकोनॉमी के समक्ष अहम चुनौती बताया। जॉर्जिवा ने कहा, 'हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहां जोखिम की आशंका ज्यादा है। अभी जनवरी है और अभी से ग्लोबल इकोनॉमी को संकट में डालने वाले कुछ संकेत दिखने लगे हैं।'

डब्ल्यूईएफ के बोर्ड का हिस्सा बनीं आइएमएफ प्रमुख : वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने आइएमएफ प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जिवा और अफ्रीकन रेनबो मिनरल्स के चेयरमैन पैट्रिस मोसेपे को अपने ट्रस्टी बोर्ड में शामिल करने का एलान किया है। डब्ल्यूईएफ ने कहा कि वैचारिक नेतृत्व के मामले में दोनों का बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है। साथ ही अपने-अपने क्षेत्र में दोनों लंबे समय से सफलतापूर्वक भूमिकाएं निभा रहे हैं। डब्ल्यूईएफ ने बोर्ड में जॉर्जिवा और मोसेपे के शामिल होने से फोरम का पब्लिक-प्राइवेट को-ऑपरेशन स्वरूप और मजबूत होने का भरोसा जताया।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलीना जार्जिवा की फाइल फोटो। एएफपी

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

फड़नवीस ने विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराए थे : देशमुख

मुंबई : महाराष्ट्र में पूर्व की भाजपा नीत सरकार में विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराए जाने के आरोपों पर सियासत गरमा गई है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि फड़नवीस सरकार ने लोस व विस चुनावों के दौरान कांग्रेस और राकांपा नेताओं के फोन टैप कराए थे। साइबर सेल से मामले की जांच कराई जाएगी। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

सड़क निर्माण में देरी करने वाले अफसरों का परफॉरमेंस ऑडिट

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से कहा है कि वे लंबित सड़क परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे जल्द सुलझाएं। उन्होंने परियोजनाओं में विलंब के जिम्मेदार अधिकारियों के परफॉरमेंस ऑडिट के निर्देश भी दिए हैं। मानेसर में दो दिनों तक चली बैठक में गडकरी ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ गहन विमर्श किया।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

चीन ने चार करोड़ से ज्यादा आबादी पर लगाईं बंदिशें

बीजिंग : चीन में रहस्यमय कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने से वुहान समेत 13 शहरों में सार्वजनिक परिवहन रोक दिया गया है। इससे चार करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इन शहरों में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। चीन में इस वायरस से अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है और 830 से ज्यादा लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं।

निर्भया के दो दोषी फिर कोर्ट पहुंचे

- तिहाड़ जेल प्रशासन पर दस्तावेज नहीं देने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों ने पटियाला हाउस अदालत में अर्जी दायर कर तिहाड़ जेल प्रशासन पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। इनकी याचिका पर शनिवार को सुनवाई हो सकती है।

दोषियों अक्षय कुमार सिंह और पवन की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका दायर करनी है। इसके लिए तिहाड़ जेल प्रशासन से कुछ दस्तावेजों की जरूरत है, आग्रह किए जाने के बावजूद दोनों को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। अधिवक्ता एपी सिंह के मुताबिक, जेल में अक्षय और पवन के आचरण व अन्य दस्तावेजों की जरूरत है, ताकि जल्द से जल्द याचिका दायर की जा सके। याचिका में दोषियों के परिजनों का हवाला देते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की जाएगी।

पटियाला हाउस अदालत में इस मामले से जुड़ी याचिकाओं को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा सुन रहे थे, जिनका अब सुप्रीम कोर्ट में तबादला हो चुका है। निर्भया की मां की याचिका पर कोर्ट ने दोषियों अक्षय, पवन, विनय और मुकेश का एक फरवरी के डेथ वारंट जारी किया था।

दया याचिका के साथ डायरी दाखिल करना चाहता है विनय

अर्जी में विनय की डायरी भी उपलब्ध कराने की गुहार लगाई गई है। वह अपनी याचिका के साथ 70 पन्नों की इस डायरी को भी दाखिल करना चाहता है।

अधिक टैक्स लगाना अन्याय : सीजेआइ

- कहा, टैक्स उसी तरह वसूला जाए, जैसे मधुमक्खी फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना रस निकालती है
- प्रधान न्यायाधीश ने पुराने समय में प्रचलित टैक्स कानूनों का भी दिया उदाहरण

नई दिल्ली, एजेंसियां : देश में हफ्ते भर बाद आम बजट पेश किया जाना है ऐसे में प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने टैक्स को लेकर अहम बयान दिया है। शुक्रवार को जस्टिस बोबडे ने कहा कि नागरिकों पर अधिक टैक्स लगाना सामाजिक अन्याय है।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के 79वें स्थापना दिवस समारोह में जस्टिस बोबडे ने कर चोरी को अपराध करार देते हुए उसे अन्य लोगों के साथ सामाजिक अन्याय बताया। इसके साथ ही यह भी कहा कि सरकार द्वारा लोगों पर मनमाना या अधिक कर लगाना भी एक तरह का सामाजिक अन्याय है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) ने कहा कि नागरिकों से उसी तरह से टैक्स वसूला जाए, जिस तरह से मधुमक्खी फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना उससे रस निकालती है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को साल 2020-21 का आम बजट पेश करने जा रही हैं। इस बार उनसे टैक्स में राहत की उम्मीद की जा रही है।

नई दिल्ली में शुक्रवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के 79 वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे। एएनआइ

कर विवाद का त्वरित समाधान प्रोत्साहन के समान

प्रधान न्यायाधीश ने कर से संबधित विवादों के त्वरित निकारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विवादों का त्वरित समाधान आयकर दाताओं के लिए इंसेंटिव के समान है और इससे मुकदमों मे फंसा पैसा भी निकल जाता है। जस्टिस बोबडे ने जोर देकर कहा कि कर न्यायपालिका देश के लिए संसाधन जुटाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। न्याय में देरी पर चिंता जताते हुए सीजेआइ ने कहा कि इसी के चलते न्यायाधिकरणों का गठन हुआ।

सीजेआइ ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल पर दिया जोर पेज>>3

बच्चे अधिकारों के बजाय दायित्वों को अधिक अहमियत दें : पीएम

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले बच्चों से भेंट की और उनके कार्यो की सराहना की। साथ ही कहा, युवा साथियों के साहसिक काम के बारे में सुनने से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि वह अपने अधिकारों के बजाय अपने दायित्वों को अधिक अहमियत दें। (पेज-3)

जम्मू-कश्मीर में आज से हर मोबाइल पर चलेगा इंटरनेट

जम्मू : गणतंत्र दिवस से ठीक पहले राज्य प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में शनिवार से पोस्टपेड और प्रीपेड पर 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। ब्राडबैंड सेवा भी हर शहर और कस्बे में उपलब्ध होगी, लेकिन सशर्त और पाबंदियों के साथ। कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को नहीं चला सकेगा। (पेज-6)

घुसपैठियों में खौफ

बंगाल के सीमावर्ती इलाके में एक माह में पकड़े गए 268 बांग्लादेशी, ज्यादातर उत्तर 24 परगना जिले के पारंपरिक रूट से भाग रहे थे, बीएसएफ का दावा-देश में घुसपैठियों की संख्या में आई कमी

सीएए का दिख रहा असर, घुसपैठियों के भागने का सिलसिला जारी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने का असर दिखने लगा है। घुसपैठिये देश छोड़कर भाग रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले एक महीने में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में काफी कमी आई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शुक्रवार को दावा किया कि ज्यादातर घुसपैठिये बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पारंपरिक रूट से भाग रहे हैं। जनवरी माह में बीएसएफ ने 268 बांग्लादेशियों को सीमा पर पकड़ा है, जो अपने देश भाग रहे थे।

बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के आइजी वाईबी खुरानिया ने कहा, सीएए लागू होने व प्रस्तावित एनआरसी को लेकर घुसपैठियों में डर बढ़ा है। पिछले एक माह में बंगाल के सीमांत क्षेत्रों से होकर वापस बांग्लादेश भागने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। जवानों ने इस साल जनवरी माह में अब तक 268 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। इनमें से अधिकतर बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादातर घुसपैठिये उत्तर 24 परगना जिले की सीमा से होकर भाग रहे हैं, जो घुसपैठियों के आने-जाने के लिए पारंपरिक रूट रहा है।

मवेशियों की तस्करी में 90 फीसद तक की कमी : इस मौके पर बीएसएफ के डीआइजी एसएस गुलेरिया ने दावा किया कि उनके क्षेत्र में मवेशियों की तस्करी में काफी कमी आई है। मवेशी तस्करों के खिलाफ उठाए गए कड़े कदमों व सीमा पर कड़ी निगरानी के फलस्वरूप यह सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि 90 से 95 फीसद तक पशु तस्करी कम हो गई है। अब चोरी-छिपे इक्का-दुक्का ही पशुओं की तस्करी हो रही है, जिसके लिए बॉर्डर के जटिल हालात जिम्मेदार हैं।

दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के आईजी वाईबी खुरानिया ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में बंग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जानकारी दी। जागरण

बंगाल में जमीन अधिग्रहण में समस्या के चलते नहीं हो पा रही फेंसिंग

आइजी ने बताया कि दक्षिण बंगाल फ्रंटियर का बहुत बड़ा इलाका खुला है। वहां फेंसिंग की व्यवस्था नहीं है। रिवरलाइन बॉर्डर है। ऐसे एरिया में गश्ती व निगरानी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे इलाकों में हमारे जवानों को अतिरिक्त सतर्क रहना पड़ता है। विभिन्न बाधाओं के बावजूद सीमा पर तैनात हमारे जवान अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और इसमें हमें सफलता भी मिली है। बंगाल में फेंसिंग नहीं होने की सबसे बड़ी दिक्कत जमीन अधिग्रहण की है। बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जो जमीन की जरूरत है, वह यहां नहीं मिल रही है।

मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ी

डीआइजी ने बताया कि पशु व अन्य चीजों की तस्करी पर नकेल कसने में बड़ी सफलता मिली है। लेकिन, पिछले साल मादक पदार्थों, खासकर याबा टैब्लेट की तस्करी में काफी इजाफा हुआ है। यह हमारे लिए चिंताजनक है और इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

नागरिकता संसोधन कानून के समर्थन में राष्ट्रपति से मिले 154 बुद्धिजीवी पेज>>5

विदेश में भारत होटल्स ग्रुप की हजार करोड़ की बेनामी संपत्तियां

- आइटी विभाग ने एनसीआर में 13 ठिकानों पर मारे छापे, 23 करोड़ के गहने भी मिले
- 35 करोड़ की कर चोरी भी पकड़ी गई, 'द ललित' के नाम से होटल चलाता है समूह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बड़े कारोबारी घरानों में छिपे काले धन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आयकर विभाग ने गत दिनों देश के प्रमुख होटल समूह भारत होटल्स और उसके प्रमोटर के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में 35 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी और विदेश में ग्रुप के एक हजार करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियों का पता चला है। यह ग्रुप देश-विदेश में 'द ललित' ब्रांड नाम से लग्जरी होटल चलाता है।

भारत होटल्स ग्रुप ने हाल ही में देश में भारी निवेश करने की घोषणा की थी। ग्रुप की प्रबंध निदेशक (एमडी) ज्योत्सना सूरी का भारत के उद्योग जगत में अलग रसूख है और वह प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वह सरकार की तरफ से गठित कई समितियों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

वित्त मंत्रालय ने छापेमारी की जानकारी तो दी है, लेकिन होटल समूह का नाम नहीं बताया है। अधिकारियों के मुताबिक, 19 जनवरी को आयकर विभाग ने भारत होटल्स ग्रुप, ज्योत्सना सूरी व अन्य के दिल्ली-एनसीआर स्थित 13 ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान 71.3 लाख की नकदी, 23 करोड़ के गहने और 1.2 करोड़ रुपये की घड़ियां बरामद हुई हैं। छापेमारी में मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि ग्रुप ने विदेश के कई बैंकों में अरबों रुपये का काला धन भी छिपा रखा है।

20वीं सदी के आखिरी दशक में विदेश में छिपानी शुरू की थी काली कमाई पेज>>3

27 मामले दर्ज हुए हैं शुक्रवार को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में। अब तक दर्ज 302 मामलों में से 292 में एफआइआर और 10 में डीडी एंट्री की गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 25 जनवरी 2020

केजरीवाल के दावों पर शाह का हमला

घेराबंदी ▸ बस, वाई-फाई, बिजली, प्रदूषण और स्वास्थ्य सेवाओं पर को लेकर उठाए सवाल

करावल नगर, मुस्तफाबाद और गोकलपुर विधानसभा क्षेत्रों में की जनसभा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यमुनापार में तीन जनसभाएं कीं। करावल नगर, मुस्तफाबाद और गोकलपुर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित जनसभाओं में अमित शाह ने आप और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हर दावे को एक-एक कर खारिज कर दिया। उन्होंने बस, वाई-फाई, बिजली, पानी, प्रदूषण और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आप सरकार पर दिल्ली के वातावरण को जहरीला बनाने का भी आरोप लगा दिया।

अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था, इसमें वह पूरी तरह से विफल रहे। पांच हजार डीटीसी की बसें खरीदने का दावा ढकोसला निकला।

सोनिया विहार में आयोजित जनसभा में भारत माता की जय के नारे लगाते (दाएं से बाएं) गृहमंत्री अमित शाह, सांसद मनोज तिवारी और करावल के भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट। हरीश कुमार

फ्री वाई-फाई का वादा किया था, लेकिन ढूंढ़ते-ढूंढ़ते मोबाइल की बैट्री खत्म हो रही है। यह पूछने पर केजरीवाल कहते हैं कि बिजली फ्री है, बैट्री चार्ज कर लीजिए। इस पर लोग अपना बिजली का बिल लेकर सामने आ रहे हैं। इसमें पता चलता है कि दो सौ यूनिट से कम खपत करने वाले लोगों का भी बिजली का बिल छह-छह हजार आ रहा है। अमित शाह ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा गंदा पानी दिल्ली के लोग पी रहे हैं। यह आप पार्टी की देन है। क्या गरीब लोग क्लीनिक में ही इलाज कराएंगे। उन्हें निजी अस्पतालों में इलाज कराने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन इसे केजरीवाल ने रोका है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो यहां के गरीब लोग भी आयुष्मान योजना के तहत बड़े निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। केजरीवाल अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने के पक्ष में नहीं थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर जहां झुग्गी, वहीं मकान देंगे। उन्होंने कहा कि सिख विरोधी दंगे के दोषियों को आज जेल की सलाखों को पीछे भेजा जा चुका है। दंगे से प्रभावित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा भाजपा की सरकार ने दिया है। उन्होंने कहा कि आपने 15 साल तक कांग्रेस का मौका दिया। पांच साल आप को दिया। अब एक बार भाजपा को मौका दीजिए। दिल्ली को विश्व में सबसे अच्छा शहर बना देंगे। भाजपा की परंपरा है, हम जो कहते हैं, वह करते हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हटाया। इन जनसभाओं में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने कुछ माह पहले अनधिकृत कॉलोनियों की जनता से राय ली थी और सातों सांसदों ने मिलकर जनमत शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया। इसका केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया और लाखों परिवारों का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मालिकाना हक दिया।

कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई, संदीप ने तोड़ी चुप्पी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में नाम शामिल नहीं करने पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने इशारों-इशारों में दिल्ली प्रभारी पीसी चाको पर हमला बोला है। उन्होंने बताया कि उनका नाम नहीं शामिल होने के पीछे कुछ पार्टी नेताओं से उनके मतभेद हैं।

कांग्रेस के दिग्गज नेता संदीप दीक्षित ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम नहीं आने के लिए पार्टी के क्षेत्रीय नेतृत्व को भी जिम्मेदार ठहराया है। पूर्वी दिल्ली से दो बार सांसद रहे दीक्षित ने कहा कि पार्टी नेताओं के साथ मतभेद के चलते ही उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि दीक्षित ने यह भी कहा कि वह अपने पुराने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। मालूम हो कि कांग्रेस ने बुधवार को स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इनमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी शुमार था, लेकिन संदीप दीक्षित को जगह नहीं मिली। दीक्षित ने यह भी कहा कि शीला दीक्षित के योगदान को भूलाना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली में बड़ा बदलाव आया। नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित को उतारने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया।

जनसभा नहीं, अब केवल रोड शो ही करेंगे मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जनसभा को लेकर बढ़ती मांग को देखते हुए अब आप ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। मुख्यमंत्री की जनसभाओं की जगह अब रोड शो किए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री एक दिन में कम से कम दो रोड शो करेंगे। एक रोड शो में कम से कम तीन विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।

केजरीवाल ही पार्टी के सबसे बड़े स्टार हैं। यह चुनाव भी उनके नाम पर ही लड़ा जा रहा है। ऐसे में प्रत्याशी चाहते हैं कि उनके मुखिया हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचे। जनसभा के माध्यम से यह संभव नहीं है। ऐसे में पार्टी ने रोड शो का रास्ता निकाला है। यही वजह है कि पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए तैयार की गई रणनीति में बदलाव किया है। चुनाव प्रचार के लिए अब इस तरह के अभियानों पर जोर दिया जाएगा, जिनमें सीधे लोगों से संपर्क किया जा सके। आप के दिल्ली संयोजक गोपाल राय का दावा है कि पार्टी के सर्वे में यह पता चला है कि मुफ्त पानी, बिजली व महिलाओं को मुफ्त यात्रा सहित उन सभी कामों पर जनता चर्चा कर रही है, जो दिल्ली सरकार ने पिछले पांच साल में जनहित के लिए किए हैं। यह चुनाव काम के मुद्दे पर होने जा रहा है। ऐसे में उनका प्रयास है कि मुख्यमंत्री अधिक से अधिक क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर अपनी बात रखें।

पार्टियों की रणनीति

आप की मदद को पहुंच रहे दूसरे राज्यों के बांकुरे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव में प्रचार को धार देने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) की मदद के लिए दूसरे राज्यों के बांकुरे (कार्यकर्ता) भी पहुंचने लगे हैं। इस समय ऐसे करीब पांच हजार कार्यकर्ता दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। इनमें करीब दो हजार ने आप में पंजीकरण कराया है, जबकि तीन हजार लोग सीधे प्रत्याशियों के पास पहुंचे हैं। अभी दिल्ली में 10 हजार और ऐसे लोग पहुंचने जा रहे हैं। इनमें युवाओं के साथ ही महिलाएं भी शामिल हैं। आप के समर्थन के लिए नामांकन से पहले ही आप के कार्यकर्ताओं ने राजधानी पहुंचना शुरू कर दिया था। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीधे प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं।

चुनावी हलचल

बच्चों व अपने भविष्य को ध्यान में रखकर वोट देना : मान

नई दिल्ली : पंजाब से आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद भगवंत मान ने गढ़ी गांव में आयोजित चुनावी जनसभा में कहा कि लोग बच्चों और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर वोट दें। इस दौरान भाजपा व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मान ने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है। भाजपा व कांग्रेस में टिकट देने के लिए जहां रिश्तेदारों की लाइन ही खत्म नहीं होती है, वहीं आप आम लोगों को टिकट देकर विधानसभा व संसद पहुंचने का मौका देती है। दिल्ली सरकार की योजनाओं की तारीफ हो रही है। दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक को विदेश से लोग देखने आ रहे हैं और अपने देश में मोहल्ला क्लीनिक की मिसाल दे रहे हैं। मान ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में अच्छे दिन भले ही न आए हों, लेकिन दिल्ली की आप सरकार के नेतृत्व में सच्चे दिन जरूर आए। भाजपा की ओर से दिल्ली में मुख्यमंत्री घोषित न किए जाने के मामले में भी उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा वालों को दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा है। इस दौरान कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी मदन लाल भी मौजूद रहे। (जासं)

भाजपा को समर्थन का फैसला नहीं कर सके अकाली

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने को लेकर शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) में एक राय नहीं बन सकी है। इसे लेकर पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में भी कोई फैसला नहीं हो सका। अब पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल इस बारे में फैसला करेंगे। भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन देने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका की अध्यक्षता में शुक्रवार को पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। कई नेताओं का कहना था कि भाजपा के साथ पुराना संबंध है। केंद्र में पार्टी की नेता हरसिमरत कौर बादल मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिखों से संबंधित कई फैसले लिए हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी जेल पहुंचने लगे हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन करना चाहिए। वहीं, कई नेताओं का कहना था कि पार्टी ने चुनाव से अलग रहने का फैसला किया है। इस स्थिति में किसी भी पार्टी को समर्थन करने का कोई औचित्य नहीं है। आम सहमति नहीं बनने के बाद इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार सुखबीर बादल को सौंप दिया गया। दिल्ली के प्रमुख नेता बादल से मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। (जासं)

'जाति-धर्म नहीं, जनता काम पर देगी वोट'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पांच साल तक उन्होंने राज्य में बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए काम किया है। इसलिए राज्य की जनता इस बार इन्हीं कामों पर वोट करने जा रही है, जाति-धर्म पर नहीं। इस बीच उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जाति-धर्म के नाम पर विकास की अनदेखी करने और जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को रोहिणी विधानसभा से आप प्रत्याशी राजेश नामा बंसीवाला के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने बीते पांच वर्षों में दिल्ली की जनता की खुशहाली के लिए काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया है। 70 साल से जो काम अटके हुए थे, उन्हें पांच साल में पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की व्यवस्था में सुधार हुआ है। यदि सत्ता किसी और के हाथ में चली गई तो सारा सही किया काम खराब हो जाएगा। दिल्ली वालों से अब जाति-धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि आप सरकार ने काम करने में भेदभाव नही किया है। स्कूल में सभी पार्टियों के समर्थकों के बच्चे पढ़ते हैं। डीटीसी की बसों में सभी महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर रही हैं। दिल्ली में जिसने काम किया है, उसे ही दिल्ली की जनता वोट देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस जाति-धर्म के नाम वोट लेती आ रही हैं, लेकिन दिल्ली में अब ऐसा नहीं चलने वाला है। लोग विकास के नाम पर ही सरकार चुनेंगे।

रोहिणी में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जागरण

- केजरीवाल का दावा, बीते पांच वर्षों में जनता की खुशहाली के लिए काम किया
- भाजपा और कांग्रेस पर जाति-धर्म के नाम वोट मांगने का लगाया आरोप

दिल्ली को चमकाने के लिए करेंगे काम : मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में दिल्ली में हर क्षेत्र में विकास को नई धार देंगे। डीटीसी बसों में छात्रों को निःशुल्क यात्रा, 11 हजार नई बसें, दो करोड़ पेड़ तथा यमुना को साफ करने को लेकर काम किया जाएगा। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने पर भी जोर रहेगा। हर वर्ष दिल्ली प्रदूषण के जाल में फंस जाती है। प्रदूषण कम करने की उन्होंने पूरी कोशिश की और 25 प्रतिशत तक प्रदूषण को कम करने में सफलता भी मिली है। अगले पांच साल में प्रदूषण को खत्म करने के लिए काम किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन के दौरान कांग्रेस के कई क्षेत्रीय नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए।

विधानसभा के चुनावी मैदान में बचे 668 उम्मीदवार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आयोग की तैयारी

नामांकन वापसी का समय खत्म होने के साथ ही दिल्ली का चुनावी मंच तैयार हो चुका है। इस चुनाव में कुल 668 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आप, कांग्रेस व भाजपा तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। आप से आठ, भाजपा से छह व कांग्रेस ने 10 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। आठ फरवरी को मतदान होगा। उस दिन एक करोड़ 47 लाख 86 हजार 389 मतदाता वोट देकर उनके भविष्य का फैसला करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (सीईओ) के अनुसार, 1009 उम्मीदवारों ने कुल 1528 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें 821 पुरुष व 188 महिला उम्मीदवार शामिल थीं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 311 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हो गए। इनमें ज्यादातर तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के कवरिंग उम्मीदवार, निर्दलीय व कुछ छोटे दलों के प्रत्याशी शामिल थे। वहीं, 70 विधानसभा सीट के लिए 698 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए गए थे। इनमें 615 पुरुष व 83 महिला उम्मीदवार शामिल थीं। 24 जनवरी को नामांकन वापसी के आखिरी दिन 30 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद 668 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं।

सबसे अधिक नई दिल्ली सीट से 88 नामांकन पत्र भरे गए थे। इनमें 54 नामांकन पत्र खारिज और 34 स्वीकृत हुए थे। इस सीट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाजपा प्रत्याशी सुनील यादव व कांग्रेस प्रत्याशी रोमेश सब्बरवाल चुनावी मैदान में हैं। नामांकन के आखिरी दिन तीनों प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी पर्चा भरा था। करीब 42 निर्दलीय उम्मीदवारों का पर्चा गलतियों के कारण रद हो गया। इसके बाद इस सीट से सबसे अधिक 28 उम्मीदवार व पटेल नगर से सबसे कम चार उम्मीदवार हैं। आप 70, भाजपा 67 व कांग्रेस 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने तीन सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं। इनमें से दो सीटों (बुराड़ी व संगम विहार) से जेडीयू व सीमापुरी से लोक जन शक्ति पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन की तरफ से चार सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।

पटपड़गंज में रोड शो करें शाह, मैं स्कूल दिखा दूंगा : सिसोदिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करें। उन्हें दूरबीन लेकर स्कूल ढूंढ़ने की जरूरत नहीं है, वह उन्हें नया बना स्कूल दिखा देंगे। दरअसल सिसोदिया उनके उस आरोप का जवाब दे रहे थे, जिसमें शाह ने नए स्कूलों का निर्माण नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर सिसोदिया ने कहा कि गृहमंत्री पटपड़गंज में कोई भी जनसभा या रोड शो रख लें, वह उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा स्कूल दिखाएंगे, जो भाजपा शासित किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में न तो देखा होगा और न ही बनवाया होगा। यही नहीं सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के अन्य किसी क्षेत्र में शाह चाहें तो वहां भी वह स्कूल दिखा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार में न केवल नए स्कूलों का निर्माण हुआ है, बल्कि दिल्ली के पुराने स्कूलों की भी कायापलट हुई है।

सियासी दलों के बीच जुबानी जंग के साथ ही सोशल मीडिया पर भी जंग तीखी होती जा रही है। भाजपा के मॉडल टाउन से उम्मीदवार कपिल मिश्रा के हिंदुस्तान-पाकिस्तान मैच और मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर सिसोदिया ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा ट्वीट किया कि कुछ भी कर लें आठ फरवरी को जीतेगा तो हिंदुस्तान ही।

'लोग तय करें, जिन्ना वाली आजादी चाहिए या भारत माता की जय'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आरोप-प्रत्यारोप

- प्रकाश जावडेकर ने आप और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर शाहीन बाग में हो रहे धरना-प्रदर्शन पर भाजपा का कांग्रेस व आम आदमी पार्टी (आप) पर हमला जारी है। उसका आरोप है कि चुनावी लाभ के लिए सीएए को लेकर दोनों पार्टियां लोगों विशेषकर मुस्लिमों को गुमराह कर रही हैं। जिन्ना वाली आजादी लेने के नारे लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और दिल्ली चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने कहा कि दिल्ली के मतदाताओं को तय करना होगा कि उन्हें जिन्ना वाली आजादी चाहिए या भारत माता की जय वाली। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए लोगों को भड़काने वाले अमानतुल्लाह खान को आप ने टिकट दिया है। कांग्रेस नेता भी शाहीन बाग जाकर लोगों को भड़का रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े होने का एलान कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि इस धरने से परेशान लोगों के साथ उनकी सहानुभूति क्यों नहीं है? प्रदर्शन में बच्चों को गलत जानकारी देकर उनके मन में जहर भरा जा रहा है। प्रधानमंत्री व गृहमंत्री को मारने की धमकी दे रहे बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल कह रहे हैं कि सीएए लागू होने से करोड़ों लोगों की नागरिकता चली जाएगी। राहुल गांधी ने भी इसी तरह का बयान दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल, राहुल व इमरान के बयान की भाषा एक तरह की क्यों होती है? उन्होंने कहा कि सीएम टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आने वालों, जिनमें ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, के साथ कोई सहानुभूति नहीं है।

कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआइआर दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मॉडल टाउन से भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज कराया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने शाहीन बाग को लेकर विवादित ट्वीट किए थे।

कपिल मिश्रा ने 23 जनवरी को किए ट्वीट में शाहीन बाग की तुलना मिनी पाकिस्तान से की थी। साथ ही लिखा था कि आठ फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान व पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। इस पर चुनाव आयोग ने 23 जनवरी को कपिल मिश्रा को नोटिस दिया था। शुक्रवार को मिश्रा ने आयोग के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन आयोग उनके पक्ष से संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद रिटर्निंग अफसर (आरओ) की शिकायत के आधार पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने उन के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जाति या धर्म से संबंधित बयान देने पर तीन साल तक कैद या जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान है। वहीं, चुनाव आयोग को दिए गए अपने जबाव में कपिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने जनप्रतिधिनित्व अधिनियम 1951 का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

नेशनल कैपिटल

रोशनी में नहाया नॉर्थ और साउथ ब्लॉक

नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दोनों ओर स्थित नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रंगबिरंगी रोशनी से नहा उठा है। पानी के चारो ओर लगी छोटी-छोटी लाइटें और बीच में जगमगता फव्वारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। दूसरी ओर गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर निकलने वाली परेड लाल किले तक जाएगी। परेड के दौरान कई मार्गों पर यातायात पर प्रतिबंध रहेगा। कई मार्ग 25 जनवरी की रात से ही बंद कर दिए जाएंगे। ये मार्ग 26 जनवरी को परेड खत्म होने के बाद खुलेंगे। वहीं रविवार को कई मेट्रो स्टेशन भी सुबह से लेकर दोपहर तक बंद रहेंगे। इन मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा तो होगी, लेकिन यहां से यात्रियों के बाहर निकलने और प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। ध्रुव कुमार

सियासी वार

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने पांडव नगर और आनंद विहार में तीन जगहों पर नुक्कड़ सभाओं के जरिये मांगे वोट

किसके अच्छे बीते पांच साल, लोगों के तो नहीं : नड्डा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पांडव नगर और आनंद विहार में तीन जगहों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इस दौरान लक्ष्मीनगर के भाजपा प्रत्याशी अभय वर्मा और विश्वास नगर के प्रत्याशी ओमप्रकाश शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा और कहा कि भाजपा हमेशा लोगों की सेवा करने वाली पार्टी रही है। भ्रम और झूठ फैलाने वाली नहीं।

उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि जगह-जगह अच्छे बीते पांच साल के बोर्ड लगे हैं, जबकि केजरीवाल साढ़े चार सालों तक यही कहते रहे कि मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही है। जब काम नहीं करने दे रही है तो फिर किसके अच्छे बीते पांच साल। उन्होंने लोगों से ही पूछा कि क्या 500 नए स्कूल बन गए, 20 नए कॉलेज खुल गए, पांच हजार नई बसें आ गईं, दिल्ली वाई-फाई युक्त हो गया, डेढ़ लाख सीसीटीवी कैमरे लग गए। दर्शकों की तरफ से आवाज आई कि कुछ नहीं हुआ है जी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लोगों से सिर्फ झूठ बोला है और फरेब किया है। लेकिन केंद्र सरकार ने लगातार दिल्ली की बेहतरी के कार्य किया। इसके तहत मेरठ एक्सप्रेस वे लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल वे सहित 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं दीं। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। 40 लाख लोग वर्षों से बिना मालिकाना हक के थे उन्हें एक दिन में घर का मालिक बना दिया।

पांडव नगर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जागरण

उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में ऐसे-ऐसे कार्य हुए हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। 500 साल पुराना राम मंदिर विवाद खत्म हुआ । एक साथ तीन तलाक कानून को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को वास्तविक आजादी दी। जम्मू-कश्मीर में 70 सालों से जो अव्यवस्था व अराजकता थी उसे एक झटके में खत्म कर दिया। उन्होंने शाहीन बाग को लेकर कटाक्ष किया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बाग-बाग की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी से लेकर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक ने यह वकालत की थी कि पाकिस्तान में जिन नागरिकों के साथ अमानवीय अत्याचार हो रहा है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। लेकिन अब यही लोग नागरिकता संशोधन काननू सीएए का विरोध कर रहे हैं।

फिलहाल पुराने नियमों पर ही पंजीकरण कराएं छात्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- जेएनयू छात्र संघ की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा, नहीं लगेगा जुर्माना
- कोर्ट ने विवि प्रशासन व मानव संसाधन मंत्रालय से मांगा जवाब

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में फीस वृद्धि के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने विवि प्रशासन और मानव संसाधन मंत्रालय से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही, छात्रों से कहा है कि नए सत्र के लिए एक सप्ताह के अंदर पुरानी नियमावली के तहत ही आवेदन करें, उनसे जुर्माना नहीं लिया जाएगा।

फीस वृद्धि को लेकर इंटर हॉस्टल मैनेजमेंट (आइएचए) के फैसले के खिलाफ जेएनयू छात्र संघ ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। छात्र संघ अध्यक्ष आईशी घोष समेत अन्य छात्रों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि छात्र संघ से फीड बैक लिए बगैर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले साल अक्टूबर में नए हॉस्टल मैनुअल और बढ़ी हुई फीस को छात्रों पर लागू कर दिया था, जो मनमाना, अवैध और असंवैधानिक है। याचिका के अनुसार इससे पहले दो बेड वाले कमरे और एकल कमरे के लिए क्रमशः 10 रुपये (प्रति बेड) और 20 रुपये लिए जाते थे। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप और अन्य समकक्ष छात्रवृत्ति या फेलोशिप की श्रेणी में शामिल सभी छात्रों के लिए अब एकल और डबल सीटर कमरों का किराया बढ़ाकर 600 रुपये और 300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। बीपीएल छात्रों के लिए डबल और सिंगल सीटर रूम का किराया बढ़ाकर 150 रुपये और 300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। याचिका के अनुसार पहले उपयोगिता और सेवा शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अब विश्वविद्यालय बीपीएल छात्रों को 500 रुपये और अन्य छात्रों को एक हजार रुपये का शुल्क लेगा।

कई केंद्रों में हुई परीक्षा

जेएनयू में शुक्रवार को कई केंद्रों की परीक्षाओं का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ अन्य स्कूल व केंद्रों की कक्षाएं आने वाले दिनों में आयोजित होंगी।

छात्र संघ की तरफ से निकाला जाएगा मार्च

जेएनयू छात्र संघ की तरफ से शनिवार की रात 9 बजे विभिन्न मुद्दों को लेकर गंगा ढाबा से साबरमती ढ़ाबा तक मार्च निकाला जाएगा। छात्र संघ ने कहा कि हम अपने गणतंत्र को वापस करने के लिए मार्च निकालने जा रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि हम नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी व एनपीआर को अस्वीकार करते हैं।

69 फीसद प्रबंधकों का काम 2024 तक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) के जरिये होने लगेगा। यह दावा अनुसंधान और सलाहकार फर्म गार्टनर इंक ने एक शोध के बाद की है।

बोल्सोनारो आए, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो शुक्रवार को चार दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए। उनकी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता होगी। वार्ता के बाद दोनों देशों के सहयोग के 15 समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। राष्ट्रपति बोल्सोनारो राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्रपति बोल्सोनारो के भारत आगमन का स्वागत किया है। उम्मीद जताई है कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयां छुएंगे।

बोल्सोनारो के साथ उनकी बेटी लौरा बोल्सोनारो, पुत्रवधू लेतीसिया फर्मो, आठ मंत्री, ब्राजीली संसद के चार सदस्य और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है। उच्च स्तरीय वार्ता के बाद तेल व गैस, खनन, स्वास्थ्य और साइबर सिक्युरिटी समेत 15 समझौतों पर दस्तखत होंगे। मोदी और बोल्सोनारो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत बनाने पर विचार करेंगे। मंदी के दौर से गुजर रहे दोनों देश आपस में व्यापार और सहयोग बढ़ाकर आर्थिक सक्रियता बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। नई दिल्ली आने के कुछ घंटों बाद बोल्सोनारो अपने कुछ अधिकारियों के साथ अक्षरधाम मंदिर देखने गए।

ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो चार दिन की भारत यात्रा पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। एपी

ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार ब्राजील की आबादी 21 करोड़ है और उसकी अर्थव्यवस्था 1.8 ट्रिलियन डॉलर (126 लाख करोड़ रुपये) है। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने कहा है कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो की भारत यात्रा बहुत महत्व वाली है। यह दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में फिर से जान फूंकने वाली होगी। बोल्सोनारो की यह पहली भारत यात्रा है। ब्राजीली सेना के पूर्व कैप्टन बोल्सोनारो ने अपने देश में अक्टूबर 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद जनवरी 2019 में उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला।

बच्चे अपने अधिकारों के बजाय दायित्वों को अधिक अहमियत दें : पीएम

मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों से कहा, मुझे आपसे प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है

नई दिल्ली, एजेंसियां : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बच्चों के कार्यों की सराहना की और कहा कि युवा साथियों के ऐसे साहसिक काम के बारे में सुनने से उन्हें प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। उन्होंने पुरस्कृत बच्चों से आग्रह किया कि वह अपने अधिकारों के बजाय अपने दायित्वों को अधिक अहमियत दें।

मोदी ने शुक्रवार को अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के 49 बाल विजेताओं से बातचीत में कहा, 'हमें अपने कर्तव्यों को वरीयता देनी चाहिए। हम कब तक अपने अधिकारों पर ही ध्यान देंगे? मुझे इस बात पर गर्व है कि आप समाज और देश के प्रति अपने दायित्वों के प्रति सजग हैं।' उन्होंने कहा, 'थोड़ी देर पहले आप सभी का परिचय जब हो रहा था, तब मैं सच में हैरान था। इतनी कम आयु में जिस प्रकार आप सभी ने अलग-अलग क्षेत्रों में जो प्रयास किए, जो काम किया है, वो अद्भुत है।' उन्होंने कहा कि आप अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अपने कर्तव्य पालन के लिए जिस प्रकार से जागरूक हैं, यह देखकर गर्व होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं आप सभी युवा साथियों के ऐसे साहसिक काम के बारे में जब भी सुनता हूं, आपसे बातचीत करता हूं, तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को अपने आवास पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बच्चों ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। एएनआइ

पुलिस का आदर करना चाहिए : उन्होंने होनहार बच्चों को बताया कि आजादी के बाद से लोगों की सुरक्षा के लिए 33 हजार पुलिस कर्मी अपने प्राणों का बलिदान कर चुके हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए। कई बार लोग पुलिस वालों को पसंद नहीं करते क्योंकि वह उन्हें साइकिल या अन्य वाहन सही से चलाने को कहते हैं। उन्होंने बच्चों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जाने के लिए प्रेरित किया।

पीएम के चेहरे की चमक का राज! : मोदी ने बच्चों को बताया कि बहुत साल पहले किसी ने उनसे पूछा था कि उनके चमकते चेहरे का राज क्या है? उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा, 'मैं बहुत मेहनत करता हूं और मुझे बहुत पसीना होता है। मैं वह पसीना पोंछता हूं तो चेहरा चमक जाता है।' उन्होंने बच्चों से कहा कि वह औरों को भी बोलें कि कोई बच्चा ऐसा रहने ना पाए जिसे दिन में चार बार खूब पसीना ना हो।

साफ पानी व जूस पीने की सलाह : : मोदी ने बच्चों को स्वच्छ पेयजल तथा जूस पीने की सलाह दी और शारीरिक दृष्टि से सक्रिय रहने का भी सुझाव दिया ताकि उन्हें (बच्चों को) दवा नहीं खाना पड़े। इस बातचीत के दौरान एक विजेता बच्चे हृदयनारायण सिंह भाटी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित हुआ हैं और उसने उनसे देश के लिए काम करना सीखा है। भाटी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सर मैंने आपसे सीखा है कि अगर देश आपको कुछ देता है तो आपको भी किसी न किसी रूप में देश को कुछ देना होगा।

कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल के भी बच्चे : ये 49 पुरस्कृत बच्चे देश के विभिन्न राज्यों के हैं, जिनमें एक-एक पुरस्कृत बच्चा जम्मू कश्मीर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का भी है। इन बच्चों ने कला एवं संस्कृति, नवाचार, प्रतिभा,समाज सेवा, खेल और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में पुरस्कार हासिल किया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं में 12 वर्षीय दर्श मलानी भी शामिल हैं जिन्होंने दुनिया भर में 50 मैजिक शो किए हैं और इसमें 11 वर्षीय मनोज कुमार लोहार भी शामिल है जिन्होंने तबला वादन में महारत हासिल की है।

न्यूज गैलरी

देश के नाम राष्ट्रपति का संबोधन आज शाम सात बजे

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 'राष्ट्रपति के संबोधन का शाम सात बजे हिंदी में ऑल इंडिया रेडियो (एआइआर) के पूरे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद उनके संबोधन के अंग्रेजी संस्करण का प्रसारण किया जाएगा।' हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। एआइआर पर संबोधन को क्षेत्रीय भाषा में रात 9 .30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। (प्रेट्र)

भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी सिंघल को मिली जमानत

नई दिल्ली : भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी (मुख्य प्रबंध निदेशक) संजय सिंघल की जमानत अर्जी को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने मंजूर कर लिया है। 10 लाख के मुचलके और दो गारंटी पर उनको जमानत मिली है। उन्हें पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। इसी सप्ताह ईडी ने हजारों करोड़ के बैंक लोन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें सिंघल को मास्टरमाइंड बताया गया है। ईडी ने 22 नवंबर 2019 को सिंघल को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि 2007 से 2014 के बीच 33 बैंक और वित्तीय संस्थानों से लोन लिए गए। 30 जनवरी 2018 तक 47 हजार 204 करोड़ की रकम बकाया थी। बैंकों से पैसा लेकर उसे धोखे से अलग-अलग खातों में डायवर्ट किया गया था। (जासं)

डीजीसीए ने तनेजा एयरोस्पेस के पायलट को निलंबित किया

नई दिल्ली : डीजीसीए ने शुक्रवार को कहा कि उसने तनेजा एयरोस्पेस के सेसना विमान के पायलटों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया है। पिछले वर्ष पायलटों ने नांदेड़ हवाई अड्डे पर रनवे का उल्लंघन किया था। तनेजा एयरोस्पेस कारपोरेट सेक्टर के लिए चार्टर सेवा मुहैया कराता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की जांच में पाया गया कि एयर ट्राफिक कंट्रोल ने पिछले वर्ष 11 सितंबर को पायलटों को रनवे संख्या 28 पर अपना विमान उतारने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने इसकी जगह रनवे संख्या 10 पर विमान को उतारा। इस रनवे पर रोशनी प्रणाली काम नहीं कर रही थी। इससे विमान को नुकसान पहुंचा। (प्रेट्र)

रासुका का इस्तेमाल नहीं करने का व्यापक आदेश नहीं दे सकते : कोर्ट

स्पष्ट रुख ▶ शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट दी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली व अन्य राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के प्रावधान लागू किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, रासुका का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके इस्तेमाल पर रोक का व्यापक आदेश जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक संपत्तियां जलाई जा रही हैं ये संगठित भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक का व्यापक आदेश नहीं दे सकता इससे अफरातफरी मच सकती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप विशिष्ट घटना बताइए जिसमें इसका दुरुपयोग हुआ हो। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इन्कार करते हुए याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट देते हुए याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा

- रासुका का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर रोक का व्यापक आदेश नहीं दिया जा सकता इससे अफरातफरी मच सकती है
- क्या याचिकाकर्ता को नहीं पता कि कोलकाता, त्रिपुरा और असम में क्या हो रहा है। संपत्तियां जलाई जा रही हैं, ये संगठित हो सकता है। हमें लोगों की पृष्ठभूमि नहीं मालूम

वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर रासुका के इस्तेमाल की आशंका जताई थी और दिल्ली सहित कुछ प्रदेशों में रासुका लागू करने की अधिसूचना को चुनौती दी थी।

जस्टिस अरुण मिश्रा और इंद्रा बनर्जी की पीठ के समक्ष याचिका पर बहस करते हुए शर्मा ने कहा, सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में और अन्य राज्यों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। राज्यों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस कड़े कानून का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इन दलीलों पर पीठ ने कहा, आप इसके दुरुपयोग की कोई विशिष्ट घटना बताइए। इस बारे में कोई व्यापक आदेश नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि उनका मानना है कि यह कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस बारे में व्यापक आदेश जारी नहीं कर सकता। जब मनोहर लाल शर्मा कोर्ट से लगातार अनुरोध करते रहे कि प्रदर्शनकारियों पर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए, इस पर अदालत ने कहा, अगर कोई व्यक्ति हिंसा करता है या फिर गंभीर अपराध में शामिल होता है तो उस स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए। क्या सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने शर्मा से कहा कि वह यह याचिका वापस ले लें और एक संशोधित याचिका दाखिल करें जिसमें सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ रासुका का प्रयोग किए जाने की विशिष्ट घटनाएं बताएं। कोर्ट ने कहा कि वह सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप अर्जी भी दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद शर्मा ने याचिका वापस ले ली।

मालूम हो कि 10 जनवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली में 19 जनवरी से तीन महीने के लिए रासुका के प्रावधान लागू किए थे। इसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को 12 माह तक हिरासत में रखने का अधिकार है।

संसद में विपक्षी एकजुटता की कोशिश में जुटी कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ सीएए-एनआरसी पर सामने आए बिखराव को संयुक्त सदन प्रबंधन रणनीति से साधने का प्रयास

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी-एनपीआर पर विपक्षी दलों के आपसी मतभेदों के मद्देनजर कांग्रेस अब संसद सत्र के लिए इस दूरी को पाटने की पूरी कोशिश में जुट गई है। बजट सत्र में इस मुद्दे पर संसद में सरकार की मजबूत घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस विपक्षी दलों की संयुक्त सदन प्रबंधन रणनीति को सबसे अहम मान रही है, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सीएए-एनआरसी पर बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने वाले तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और शिवसेना से लेकर सपा जैसे दलों से भी संपर्क साधा जा रहा है।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा के साथ वरिष्ठ पार्टी रणनीतिकार अहमद पटेल संसद में विपक्षी दलों की संयुक्त रणनीति के लिए इन दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने कहा कि इन दलों के नेताओं से अब तक हुई अनौपचारिक बातचीत में संसद के दोनों सदनों में बड़े मसलों पर सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए संयुक्त रणनीति पर किसी तरह का विरोधाभास सामने नहीं आया है। इस पर अंतिम सहमति 30 जनवरी को विपक्षी पार्टियों की प्रस्तावित बैठक में ही बनेगी।

सीएए-एनआरसी-एनपीआर पर संसद में विपक्षी दलों की एकजुटता को कांग्रेस इसलिए भी जरूरी मान रही कि बजट सत्र का पहला चरण बेहद छोटा है। ऐसे में इन मुद्दों पर सदन में सरकार की घेरेबंदी के लिए विपक्षी पार्टियों का एकजुट रहना जरूरी है ताकि सत्तापक्ष के संख्या बल को विरोध के सुर से चुनौती दी जा सके। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और पहला चरण 11 फरवरी को ही समाप्त हो जाएगा।

मालूम हो कि सोनिया गांधी ने 13 जनवरी को सीएए-एनआरसी-एनपीआर को लेकर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, लेकिन तृणमूल, सपा, बसपा ही नहीं यूपीए की घटक द्रमुक और नई साथी शिवसेना तक इसमें शामिल नहीं हुई थी। विपक्षी दलों का यह बिखराव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था और इसके मद्देनजर ही पार्टी सियासी दूरियां पाटने में लग गई है। सीएए-एनआरसी के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शन के साथ इसके विरोध में आंदोलन करने वालों के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्रवाई के मुद्दे को बजट पेश होने के बाद सबसे पहले उठाने की विपक्षी दलों की तैयारी है।

फ्रांस को साथ लेकर एफएटीएफ में पाकिस्तान को घेरेगा भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पाक को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डालना फिलहाल संभव नहीं होगा
- अपने कुछ मित्र देशों की मदद से उस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा भारत

पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के सामने दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध बढ़ाने की बात कही थी। उससे यह साफ हो गया था कि इस्लामाबाद पर आतंकी फंडिंग के मामले में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) का अंकुश नहीं लग सकेगा। चीन का समर्थन उसे पहले से हासिल है। अमेरिका का साथ भी मिलने से उम्मीद है कि अगले माह पेरिस में जब एफएटीएफ की बैठक होगी तो पाक को काली सूची में नहीं डाला जाएगा। भारत इस नए हालात को समझ रहा है। इसके बावजूद अपने कुछ दूसरे मित्र देशों की मदद से पाकिस्तान पर जहां तक हो सके दबाव बनाने की कोशिश करेगा।

भारत की कोशिश यही होगी कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ठोस व निर्णायक कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर हाल के दिनों में भारत की सबसे ज्यादा मदद करने वाले फ्रांस ने एफएटीएफ में भी पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है।

पेरिस में आगामी बैठक होने की वजह से फ्रांस के विचार का अलग महत्व है। नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास के सूत्रों ने बताया कि उनके देश के लिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बहुत ही अहम है। जहां तक चीन में होने वाली एफएटीएफ की बैठक का सवाल है, तो वहां जिन देशों को निगरानी सूची में रखा गया है, उसे लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सनद रहे कि चीन की राजधानी बीजिंग में होने वाली बैठक में पाक पूर्व में दिए गए मानकों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देगा।

वैसे भारतीय पक्ष भी यह मान रहा है कि पाक को एफएटीएफ की तरफ से ब्लैक लिस्ट में डालना फिलहाल संभव नहीं होगा, लेकिन वह निगरानी सूची में बना रहेगा। इसका मतलब होगा कि पड़ोसी देश आतंकवाद को बढ़ावा देने की गतिविधियों से दूर रहेगा। एफएटीएफ के डर से पाकिस्तान सरकार ने पिछले एक वर्ष में आतंकी संगठनों के बैंकिंग सिस्टम पर न सिर्फ रोक लगाई है बल्कि कई बड़े आतंकियों को जेल में भी डाला है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मानते हैं कि अंतिम उद्देश्य यह है कि पाकिस्तान में आतंकियों व उनके संगठनों को जो भी मदद मिल रही हो वह पूरी तरह से खत्म हो। दूसरी तरफ आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान की कोशिश यह है कि वह ग्रे लिस्ट यानी निगरानी सूची से बाहर निकले। जब तक पाक ग्रे लिस्ट में रहेगा तब तक वहां बड़ी कंपनियां निवेश करने से हिचकती रहेंगी। एफएटीएफ कई देशों की सरकारों की तरफ से गठित संगठन है जो काला धन, आतंकी फंडिंग को रोकने की दिशा में काम कर रहा है।

विश्व के नक्शे पर चमकेंगी देश की 10 और झीलें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्र सरकार ने रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया
- अभी तक देश की सिर्फ 27 झीलों को ही मिला है यह दर्जा

देश की 10 और अति महत्वपूर्ण व बड़ी झीलों (वेटलैंड) को केंद्र सरकार ने रामसर साइट घोषित किया है। इनमें उत्तर प्रदेश की छह, पंजाब की तीन व महाराष्ट्र की एक झील शामिल है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही देश में अब रामसर कैटेगरी की कुल 37 झीलें हो गई हैं। सरकार ने यह घोषणा विश्व वेटलैंड दिवस से कुछ दिन पहले की है। बता दें कि दुनिया भर में दो फरवरी का दिन वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में इन झीलों को रामसर कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव किया था जिसे शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके तहत जिन 10 नई झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया है, उनमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की नवाबगंज झील, इटावा जिले की सरसई नवार, गोंडा जिले की पार्वती आंगन, मैनपुरी जिले की समन, हरदोई जिले की सांडी और रायबरेली की समसपुर झील शामिल है। पंजाब की केशवपुर मनी, नांगल और ब्यास तथा महाराष्ट्र की नंदूर झील को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। दुनिया भर में मौजूदा समय में रामसर कैटेगरी की करीब 2000 झीलें हैं।

क्या है रामसर कैटेगरी : रामसर ईरान के एक शहर का नाम है जहां 1971 में वेटलैंड को बचाने को लेकर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। कई देशों ने सम्मेलन में झीलों (वेटलैंड) को बचाने का संकल्प लिया था। तब से जिन झीलों को इस संरक्षित कैटेगरी में रखा जाता है, उन्हें रामसर कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी झील के शामिल होने को काफी अहम माना जाता हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में आने के बाद उस झील के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया मदद देती है। साथ ही सैलानियों की संख्या भी बढ़ जाती है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल पर दिया जोर

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधान न्यायाधीश ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ)के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे न्यायाधिकरण के फैसलों की सूची के प्रबंधन और निर्णय लेने में बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एआइ को मानवीय विवेक का विकल्प नहीं बनने दिया जा सकता, जो निर्णय लेने के लिए बहुत जरूरी है। सीजेआइ ने कहा कि अदालतों में हम जिस एआइ प्रणाली को लागू करने की सोच रहे हैं, वह प्रति सेकेंड 10 लाख अक्षरों को पढ़ सकता है। इससे मुकदमों को निपटाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

अदालतों में लंबित मामले कम हुए : सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) में लंबित मामले 61 फीसद कम हुए हैं। आधिकारिक डाटा के मुताबिक, 30 जून 2017 तक 2 लाख 73 हजार 591 केस लंबित थे। 31 मार्च 2019 तक इनकी संख्या 1 लाख 5 हजार 756 रह गई।

तैयारी

सेना के 100 दिग्गजों ने इसे लेकर मोर्चा संभाला है। इस यात्रा को 'मुंडमन गंगा परिक्रमा' नाम दिया है। दावा यह है कि पहली बार इस तरह की गंगा परिक्रमा होगी

गंगा को निर्मल बनाने के अभियान में अब उतरेगी सेना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- जनजागरूकता को लेकर करेगी गंगा की पैदल परिक्रमा
- गोमुख से गंगा सागर तक नदी के ताजा हालात पर देगी ब्योरा

गंगा को निर्मल और अविरल बनाने की मुहिम में अब सेना भी हाथ बंटाएगी। जनजागरूकता के तहत वह गंगा की पैदल परिक्रमा करेगी जिसकी शुरुआत फिलहाल अगस्त 2020 से होगी। सेना के 100 दिग्गजों ने इसे लेकर मोर्चा संभाला है। इस यात्रा को 'मुंडमन गंगा परिक्रमा' नाम दिया है। दावा यह है कि पहली बार इस तरह की गंगा परिक्रमा होगी जो गंगा के उद्गम स्थल गोमुख से शुरू होकर गंगासागर तक और फिर गंगासागर से गोमुख तक की होगी।

मुंडमन गंगा परिक्रमा की जानकारी देते हुए अतुल्य गंगा के संस्थापक गोपाल शर्मा ने बताया कि वर्षों से हम गंगा को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग अभी भी इसे लेकर जागरूक नहीं हैं। ऐसे में गंगा के मैदानी क्षेत्र और आसपास बसे लोगों को इस नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को लेकर शिक्षित करने की जरूरत है। उन्हें यह बताने की जरूरत है कि अभी भी इसका हमारी अर्थव्यवस्था, जीवन शैली और आजीविका पर प्रभाव है। यही वजह है कि इस पूरी पैदल यात्रा के दौरान गंगा किनारे बसे गांव के लोगों और आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस पूरे अभियान में जोड़ा जाएगा। उन्हें गंगा को निर्मल बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस टीम का नेतृत्व सेना पदक विजेता लेफ्टीनेंट कर्नल हेम लोहुमी करेंगे। इस दौरान गंगा के संरक्षण को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी पूरी दुनिया को बतलाने के लिए सेना के कर्नल मनोज केश्वर एक बाइक यात्रा पर भी निकलेंगे जो इसकी मशाल लेकर इंडिया गेट से लंदन तक जाएंगे।

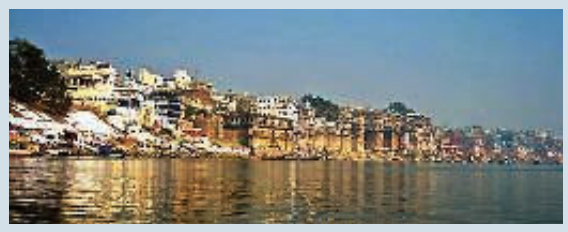

मुंडमन गंगा परिक्रमा से गंगा के साफ होने की उम्मीद जगी है। फाइल

4,700 किमी से ज्यादा लंबी होगी यह परिक्रमा : फिलहाल इस परिक्रमा का जो नक्शा तैयार किया है, उसके तहत यह यात्रा 47 सौ किमी से ज्यादा लंबी होगी जो करीब सात महीने चलेगी। इसके साथ ही यात्रा के कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जिसमें नदी तट से अधिकतम एक योजन यानी 13 किमी की दूरी से होकर ही यह गुजरेगी। साथ ही 24 घंटे में एक बार गंगा का दर्शन करना आवश्यक होगा। वहीं, परिक्रमा करने वाले यात्री को नदी के अंतिम छोर पर ही नदी को पार करने की अनुमति होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी की जान को खतरा न हो।

20वीं सदी के आखिरी दशक में विदेश में छिपानी शुरू की थी काली कमाई

प्रथम पृष्ठ से आगे

इस ग्रुप ने 20वीं सदी के आखिरी दशक से ही टैक्स हैवेन समझे जाने वाले देशों में ट्रस्ट बना कर अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया था। ये ट्रस्ट इस तरह से विदेशों में पैसा जमा कराते हैं कि इसके असली मालिक या प्रमोटर का पता दशकों तक नहीं लगता है। कई देशों में निवेश होने और असली प्रमोटर को छिपाने के कई रास्ते आजमाए गए हैं। ग्रुप के प्रमुख प्रमोटर ने अपने एक करीबी रिश्तेदार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस ट्रस्ट मुखिया बना रखा है। वित्त मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक अब इस समूह के काले कारनामों पर से पर्दा हट गया है। कंपनी का ब्रिटेन में एक होटल है और कई अन्य परिसंपत्तियों में भी ग्रुप ने निवेश किया है। यूएई में भी इसी तरह का निवेश किया गया है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

62 उड़ानों का संचालन हो रहा है जयपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में। गत 88 दिनों में जब से विंटर शेड्यूल लागू हुआ है तब से 73 फ्लाइट रद हो चुकी हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 25 जनवरी 2020

न्यूज गैलरी

एनआरआइ कारोबारी थांपी चार दिन के रिमांड पर

नई दिल्ली : रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार एनआरआइ कारोबारी सीसी थांपी को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने ईडी की मांग पर चार दिन के रिमांड पर भेज दिया। तीन दिन का रिमांड खत्म होने के बाद थांपी को विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी का कहना था कि रिमांड में पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है। अभी काफी दस्तावेजों और लोगों से आरोपित का सामना करवाना है। लंदन में एक फ्लैट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि यह फ्लैट मनोज अरोड़ा के बजाय वाड्रा का है और यह हथियार डीलर संजय भंडारी से 2010 में खरीदा गया था। इस मामले में सीसी थांपी की भूमिका सामने आने पर गिरफ्तार किया था। (जासं)

तमिलनाडु के शैक्षणिक समूह के पास 532 करोड़ का काला धन

नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु के एक शैक्षणिक समूह ने राज्यभर में अपने कई परिसरों पर आयकर छापे पड़ने के बाद 532 करोड़ रुपये की अघोषित आय होने की बात स्वीकार की है। आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाली संस्था ने हालांकि अपने बयान में शैक्षणिक समूह का नाम नहीं लिया है, लेकिन सूत्रों ने उसका नाम वेलम्मल समूह बताया है। सीबीडीटी ने कहा है कि इस समूह के चेन्नई और मदुरै इलाके में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज हैं। इसके अलावा यह चैरिटेबल ट्रस्टों के जरिये पूरे तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज और स्कूल संचालित करता है। इसके परिसरों पर छापेमारी के दौरान दो करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी भी मिली। सीबीडीटी के मुताबिक, छापेमारी को तात्कालिक रूप से रोक दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। इसने इस सप्ताह के शुरू में राज्य में 64 ठिकानों पर जांच और सर्वेक्षण अभियान चलाया था। (प्रेट्र)

ढींडसा ने कहा, शिअद में घुट रहा था दम

लुधियाना : शिअद से निलंबित राज्य सभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींडसा ने शुक्रवार को अपना दर्द बयां किया। कहा, शिअद में दम घुट रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आगामी विस चुनाव में टकसाली अकाली मिलकर कोई पार्टी बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो उस पर भी विचार करेंगे। शुक्रवार को माडल टाउन में नेताओं और जनता के साथ बैठक में पहुंचे ढींडसा ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (एसजीपीसी) की गोलक पर कुछ भ्रष्ट सदस्य ने कब्जा किया हुआ है। (जासं)

फड़नवीस सरकार ने कांग्रेस-राकांपा नेताओं के फोन टैप कराए : देशमुख

बड़ा मामला ▶ महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने साइबर सेल को सौंपी मामले की जांच

पूर्व सीएम फड़नवीस ने आरोपों को नकारा, जांच का स्वागत किया

अनिल देशमुख फाइल

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र में पूर्व की भाजपा नीत सरकार में विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराए जाने के आरोपों पर सियासत गरमा गई है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को कहा कि फड़नवीस सरकार ने पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस व राकांपा नेताओं के फोन टैप कराए। उन्होंने साइबर सेल से इस मामले की जांच करने को कहा है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

विदर्भ क्षेत्र के भंडारा जिले में मीडिया से बातचीत में देशमुख ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने कुछ अधिकारियों को इजरायल भेजकर फोन टैप कराने के लिए सॉफ्टवेयर मंगाए थे। उन्होंने सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि किन नेताओं के फोन टैप किए गए।

इजरायल गए अधिकारियों की पहचान कराने की कोशिश : भाजपा पर निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए देशमुख ने कहा कि उन अधिकारियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, जो इजरायल गए थे। इससे पहले, राज्य के मंत्री और राकांपा नेता जितेंद्र अवहाद ने कहा कि फोन टैपिंग मामले से भाजपा की बीमार मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने भी कहा कि पिछली सरकार में पुलिस के कुछ अधिकारी इजरायल गए थे और उन्हें फोन टैपिंग से इस मामले को जोड़ने की कोशिश की। बता दें कि पिछले साल इजरायल की एक कंपनी पर भारत समेत दुनिया के कई नेताओं, कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों के फोन टैप करने के आरोप लगे थे।

सरकार इस मामले की जांच कराने के लिए स्वतंत्र : पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता फड़नवीस ने देशमुख के आरोपों को पुरजोर तरीके से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसी का फोन टैप नहीं कराया। महाराष्ट्र की राजनीति की संस्कृति ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच कराने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने मामले की जांच कराकर रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की अपील की।

तब फड़नवीस सरकार के साथ थी शिवसेना : फोन टैपिंग का आरोप लगाने वाले अनिल देशमुख मौजूदा उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जिस फड़नवीस सरकार पर फोन टैप कराने के आरोप लगाए हैं, उस सरकार में शिवसेना भी शामिल थी। इस बार भी शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ी थी, लेकिन किसी दल को बहुमत नहीं मिलने पर उसने मुख्यमंत्री पद मांगा और बात नहीं बनने पर कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर सरकार बना ली।

फोन टैप कराने के बावजूद सरकार बनाई : राउत : फोन टैपिंग के लिए शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने सीधे-सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। राउत ने कहा कि शिवसेना नेताओं के भी फोन टैप कराए गए, जिनमें वह भी शामिल थे। इसके बावजूद शिवसेना सरकार बनाने में सफल रही। राउत ने यह भी दावा किया कि भाजपा के ही एक नेता ने उनसे कहा था कि उनका फोन टैप कराया जा रहा है।

राकांपा का आरोप, दिल्ली में पवार के घर से सुरक्षा हटाई गई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के दिल्ली स्थित घर से सुरक्षा हटा ली है। पार्टी ने कहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के बाद भाजपा बदले की राजनीति कर रही है। महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि इस तरह के हथकंडों से पार्टी के नेता डरेंगे नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। मलिक ने कहा कि राज्यसभा सदस्य पवार को दिल्ली में वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। उनके छह जनपथ वाले आवास पर 20 जनवरी से ही सुरक्षाकर्मी नहीं आ रहे हैं।

अमरावती में 796 गरीबों ने खरीदी 200 करोड़ की जमीन!

- सीआइडी जांच में उजागर हुआ तेदेपा काल का जमीन घोटाला
- जमीन खरीदने वाले सभी लोगों के पास बीपीएल राशन कार्ड
- इन लोगों का इस्तेमाल बेनामी सौदों के लिए किए जाने का संदेह

अमरावती, आइएएनएस : कथित जमीन घोटाले की जांच में आंध्र प्रदेश पुलिस को पता चला है कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रह रहे 796 लोगों ने 2014-15 के दौरान राज्य की राजधानी अमरावती और उसके आसपास करीब 200 करोड़ रुपये कीमत की 761.34 एकड़ जमीन खरीदी थी। इन जमीन सौदों के समय राज्य में तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) की सरकार थी।

अधिकारियों के मुताबिक, सभी 796 लोगों के पास श्वेत राशन कार्ड हैं। ये राशन कार्ड पांच हजार रुपये से कम मासिक आय वाले बीपीएल परिवारों को जारी किए जाते हैं। संदेह है कि इन लोगों का इस्तेमाल बेनामी सौदों के लिए किया गया है, लिहाजा इन सौदों में शामिल वास्तविक लोगों की पहचान के लिए सीआइडी अधिकारियों ने चार टीमों का गठन किया है। सीआइडी ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से भी मामलों की जांच का आग्रह किया है क्योंकि इन खरीददारों में से अधिकतर के पास पैन कार्ड तक नहीं हैं और जमीन सौदों का लेनदेन नकदी में किया गया था।

अमरावती में इनसाइडर ट्रेडिंग में संलिप्तता के आरोप में सीआइडी ने जिन 700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं उनमें दो पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में जमीन सौदों की जांच कराने की घोषणा के तीन दिन बाद सीआइडी ने एफआइआर दर्ज की थी। वित्त मंत्री बी. राजेंद्रनाथ रेड्डी ने विधानसभा में कहा था कि सरकार के पास इस बात के सुबूत हैं कि तेदेपा सरकार द्वारा अमरावती को राज्य की राजधानी घोषित करने से पहले जून-दिसंबर, 2014 के दौरान तेदेपा नेताओं व उनके समर्थकों ने 4,700 एकड़ जमीन खरीदी थी। एफआइआर में आरोपित बनाए गए दो मंत्रियों में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री पी. नारायण और तत्कालीन कृषि मंत्री पी. पुल्ला राव शामिल हैं। उन पर ग्रामीणों की जमीनें जबरन खरीदने का आरोप है। सीआइडी ने छद्म तरीके से अमरावती में जमीनें खरीदने के लिए टीडीपी नेता बी. नरसिम्हा राव और अन्य के खिलाफ भी मामले दर्ज किए हैं।

तेदेपा नेताओं ने कार्रवाई को जगनमोहन रेड्डी सरकार की बदले की राजनीति करार दिया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने राज्य की राजधानी विकेंद्रीकृत करने का यह भी एक कारण बताया है। सरकार के फैसले के मुताबिक, अब विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल को न्यायिक राजधानी और अमरावती को विधायी राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा।

गुजरात के एक और भाजपा विधायक ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी

- अपने क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं 30 फीट ऊंची लोहे की हनुमान प्रतिमा
- वडोदरा विधायक मधु श्रीवास्तव ने कहा, अनुमति नहीं मिली तो राजस्व अधिकारी को मार दूंगा थप्पड़

अहमदाबाद, प्रेट्र : गुजरात के एक और भाजपा विधायक ने पद और पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। वडोदरा जिले के विधायक मधु श्रीवास्तव ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रतिमा लगाने की इजाजत देने से इन्कार करने वाले राजस्व अधिकारी को थप्पड़ मार देंगे। वह अपने विधानसभा क्षेत्र की एक झील में लोहे की 30 फीट ऊंची हनुमानजी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं।

मधु श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्व मंत्री कौशिक पटेल के विभाग से उन्हें प्रतिमा लगाने की इजाजत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द इजाजत नहीं मिली तो वे विधानसभा और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। छह बार के विधायक व गुजरात एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन के चेयरमैन श्रीवास्तव ने इस मामले की कवरेज कर रहे पत्रकारों से भी दुर्व्यवहार किया।

उन्होंने कहा, 'मैंने इस परियोजना पर पहले ही तीन करोड़ रुपये खर्च कर दिया है। प्रतिमा की स्थापना के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुझे नहीं पता कि पटेल के अधीन काम करने वाले अधिकारियों को इससे क्या परेशानी है। मैं कह देता हूं... अगर मुझे अनुमति नहीं मिली तो निश्चित तौर पर अधिकारी को थप्पड़ मार दूंगा।'

गुजरात भाजपा के प्रवक्ता भरत पांड्या ने कहा कि विधायक के व्यवहार के मामले में पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि सभी मांगें पूरी की जाएं। उन्होंने कहा, 'झील, तालाब व नदियों के संरक्षण के नियम हैं। यह जरूरी है कि झील की बनावट को नुकसान न पहुंचे। राजस्व विभाग मधुभाई के प्रस्ताव पर काम कर रहा है।' उल्लेखनीय है कि वडोदरा के सावली से भाजपा विधायक केतन इनामदार ने गत दिनों अपनी मांगों को लेकर इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतूभाई वघाणी से वडोदरा में मुलाकात के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था।

मुनादी के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं हुए आजम

जागरण संवाददाता, रामपुर

- वेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र से संबंधित है मामला
- अदालत में अब 11 फरवरी को होगी सुनवाई
- आजम की पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा भी हैं आरोपित

आजम खां फाइल

धोखाधड़ी के मुकदमे में मुनादी कराने के बावजूद सांसद आजम खां कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस मामले में अदालत (एमएलए/एमपी स्पेशल कोर्ट) अब 11 फरवरी को सुनवाई करेगी। धोखाधड़ी का यह मुकदमा सांसद के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र से संबंधित है। आरोप है कि सांसद और उनकी पत्नी ने बेटे के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए सांसद और उनकी पत्नी ने शपथ-पत्र देकर गलत तथ्य पेश किए। पुलिस ने इस मुकदमे में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच-पड़ताल करने के बाद पुलिस ने अप्रैल, 2019 में तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद से ही अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। इस मुकदमे में तीनों न तो कोर्ट में हाजिर हुए और न ही जमानत कराई। इस पर अदालत ने तीनों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करते हुए धारा 82 के नोटिस जारी किए थे।

9 जनवरी को पुलिस ने सांसद के घर के आसपास मुनादी भी कराई थी। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि तीनों आरोपितों में कोई भी कोर्ट नहीं पहुंचा। अदालत ने पिछली सुनवाई पर कुर्की से पहले धारा 82 के नोटिस जारी किए थे। यह नोटिस पुलिस ने 9 जनवरी को तामील करा दिए थे। इस नोटिस के बाद आरोपितों के पास एक माह का समय होता है। यदि उस दौरान वह कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने आरोपितों को हाजिर होने के लिए 11 फरवरी तक का समय दिया है।

जौहर विवि में जमीनों की कराई मेड़बंदी, किसानों ने मनाया जश्न

जौहर यूनिवर्सिटी में राजस्व टीम ने तीसरे दिन शुक्रवार को भी कार्रवाई की। किसानों के खेतों की मेड़बंदी कराई। दूसरी ओर जमीनों पर कब्जा मिलने से आलिया गंज में जश्न का माहौल है। आलियागंज के 26 किसानों ने सांसद आजम खां के खिलाफ पिछले साल जुलाई में मुकदमे दर्ज कराए थे। आरोप था कि सपा शासनकाल में उनकी जमीनों पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी में मिला लिया गया है। प्रशासन ने 26 किसानों को कब्जा दिलाने के लिए गुरुवार को कार्रवाई की थी।

धोखाधड़ी में सपा विधायक नाहिद हसन को जेल भेजा

जागरण संवाददाता, शामली : जमीन खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी के आरोप में कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने एक माह में न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया था। 17 जनवरी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विधायक के स्थायी जमानत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। विधायक का मेडिकल परीक्षण भी कोर्ट परिसर में ही किया गया। शुक्रवार शाम लगभग 4 बजे विधायक को कड़ी सुरक्षा में मुजफ्फरनगर की जिला जेल भेज दिया गया।

हेमंत सरकार से झाविमो का समर्थन वापस, नहीं पड़ेगा असर

राज्य ब्यूरो, रांची

- विधायक दल के नेता पद से हटाए गए प्रदीप यादव

प्रदीप यादव फाइल

झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) ने हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। झाविमो ने पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शुक्रवार को झाविमो महासचिव सरोज सिंह ने यह जानकारी दी। हालांकि, झाविमो की समर्थन वापसी से हेमंत सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

गौरतलब है कि झाविमो के तीन विधायकों ने बिना शर्त सरकार को समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी थी। झाविमो ने आरोप लगाया कि पार्टी हेमंत सरकार को अपना समर्थन दे रही थी, लेकिन इसी बीच यूपीए महागठबंधन की घटक दल कांग्रेस झाविमो के विधायकों को तोड़ रही है और उन्हें दल में शामिल करा रही है। यह उचित नहीं है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि हेमंत सरकार से समर्थन वापस लेंगे। इसके अलावा प्रदीप यादव विधायक दल के नेता पद से मुक्त कर दिए गए हैं। इसकी आधिकारिक सूचना विधानसभा सचिवालय को भी दे दी गई है।

भाजपा में विलय का रास्ता साफ : दो विधायकों को बाहर निकालने के बाद अब झाविमो का भाजपा में विलय का रास्ता साफ हो गया है। विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव संगठन का भाजपा में विलय का विरोध कर रहे थे। दोनों संगठन से बाहर किए जा चुके हैं और ऐसे में झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी को भाजपा में पार्टी के विलय में दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने मन मुताबिक नई कमेटी भी गठित कर ली है। जानकारी के अनुसार, जल्द ही वे झारखंड विकास मोर्चा की नवगठित कमेटी की बैठक बुलाकर संगठन के भाजपा में विलय की घोषणा करेंगे।

मप्र में भाजपा का प्रदर्शन, ताई सहित सैकड़ों नेता गिरफ्तार

नईदुनिया, इंदौर

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन शुक्रवार को मध्यप्रदेश प्रदेश के इंदौर में मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुईं। नईदुनिया

भाजपा ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन (ताई) सहित भाजपा के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया था। इस दौरान ब्यावरा की घटना को लेकर भी भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

इंदौर में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, महापौर मालिनी गौड़, सांसद शंकर लालवानी सहित 353 नेता-कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। नेताओं ने राजगढ़ कलेक्टर को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव के खिलाफ हुई एफआइआर को लेकर भी नाराजगी जताई। 10 से ज्यादा बसों में कार्यकर्ताओं को जिला जेल ले जाया गया, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए 'माफिया' अभियान चला रही है। उसकी आड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके निर्माण तोड़े जा रहे हैं। विदिशा में पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने कहा कि राजगढ़ की घटना प्रजातंत्र के मुंह पर तमाचा है। लोकतंत्र में कलेक्टर जनसेवक होते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार में वे खुद को खुदा समझने लगे हैं। गुना, होशंगाबाद, रायसेन, ग्वालियर सहित प्रदेशभर में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन ने इस प्रदर्शन को लेकर कहा कि माफिया और गुंडों को बचाने के लिए भाजपा नेता सरकार की कार्रवाई का विरोध और आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की कार्रवाई बिना भेदभाव के की जा रही है। सभी फरार माफिया जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।

मप्र में कलेक्टर पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री गिरफ्तार, रिहा

राजगढ़, नईदुनिया : मध्य प्रदेश के राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार दोपहर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता बद्रीलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 20-20 हजार रुपये के मुचलके पर दो मामलों में उन्हें जमानत दे दी। गौरतलब है कि राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सीएए के समर्थन में निकाली गई रैली में कलेक्टर निवेदिता ने भाजपा कार्यकर्ता को थप्पड़ मारे थे। इस घटना के विरोध में आयोजित भाजपा की सभा में मंच से पूर्व मंत्री ने कलेक्टर के बारे में अशोभनीय शब्द कहे थे। ब्यावरा सिटी थाने में एसडीएम संदीप अस्थाना की शिकायत पर पूर्व मंत्री के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी डीपी लोहिया ने बताया कि घर से गिरफ्तारी के बाद पूर्व मंत्री को कोर्ट ले जाया गया था। न्यायालय से 20 हजार के मुचलके पर जमानत दी।

राजद के ट्रबल इंजन के जवाब में जदयू की करप्शन मेल

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में कव्वाली की तर्ज पर इन दिनों पोस्टरबाजी का दौर चल रहा है। यह सत्तारूढ़ जदयू और मुख्य विपक्षी राजद के बीच है। एक दल दूसरे की आलोचना के लिए शाम को पोस्टर लगाता है। अगली सुबह जवाब आ जाता है। जल्दबाजी में तुक मिलाने की जहमत नहीं उठाई जाती। मसलन, गुरुवार को राजद ने एक पोस्टर जारी किया। यह रेलगाड़ी की थीम पर था। शुक्रवार को जदयू ने भी रेल चला दी।

स्टेशन पर एक रेलगाड़ी खड़ी है-पटना-होटवार। यानी रांची जेल। नाम है-करप्शन मेल। बोगी का नाम है स्वार्थी। राजद सुप्रीमो दोनों हाथ से एक किताब पकड़े हैं। किताब का नाम अपराध गाथा है। उसपर राजद का चुनाव निशान लालटेन भी है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव प्लेटफार्म पर खाट बिछाकर बैठे हुए हैं। यह पोस्टर पटना के आयकर गोलंबर पर लगाया गया है। इसका कोई आधिकारिक प्रकाशक नहीं है। विषय वस्तु के आधार पर इसे जदयू की ओर से जारी माना जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार कहते हैं-पोस्टर जिस किसी ने लगाया हो, विषय बहुत उचित है।

सलाह

नई दिल्ली में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष से महापौर और सभापतियों के साथ मिला भूपेश मंत्रिमंडल

टीम छत्तीसगढ़ से सोनिया बोलीं- टूटने न पाए जनता का भरोसा

नईदुनिया, रायपुर

नई दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों, दस नगर निगमों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों व सभापति के साथ भेंट की। एएनआइ

नई दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी पूरी टीम के साथ मुलाकात की। उनके साथ हालिया निकाय चुनाव में जीते सभी दस नगर निगमों के मेयर और सभापति भी थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के एक साल के कामकाज की रिपोर्ट सौंपी। वहीं, सोनिया ने सत्ता और संगठन के नेताओं से कहा कि जो भरोसा जनता ने जताया है, उसको आप टूटने न दें।

सोनिया ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ शहरों का विकास करेंगे। जन हित को प्राथमिकता में रखकर काम करेंगे। मुलाकात के दौरान सोनिया और राहुल ने टीम भूपेश की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, नवनिर्वाचित महापौर को नगरीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड जीत के लिए बधाई दी। दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि हमारी मुलाकात काफी अच्छी रही। आज सिर्फ नवनिर्वाचित महापौर, निगम सभापतियों से मुलाकात थी, तो इसमें अन्य विषयों पर बात नहीं हुई। राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें जीत की बधाई दी, हमें आशीर्वाद दिया। कामयाबी पर खुशी जाहिर की यह बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमने भी भरोसा दिलाया है कि नगरीय क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव में पार्टी रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास को बनाकर रखना है। जो कामयाबी पार्टी को मिली है, उसे बरकरार रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद संघर्ष और जनता के भरोसे को भूल जाएं। आपको हमेशा इसी तरह से मिलजुल कर काम करते रहना होगा।

आठ मार्च को छत्तीसगढ़ आ सकती हैं सोनिया

मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया गया है। मंत्री अनिला ने सोनिया गांधी को बस्तर दौरे पर आने के लिए आमंत्रित किया। अनिला ने कहा कि आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें। इस पर सोनिया ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ आने का पूरा प्रयास करेंगी।

पूर्व राज्यपाल कुरैशी मप्र उर्दू अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त

नईदुनिया, भोपाल

अजीज कुरैशी फाइल

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के राज्यपाल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. अजीज कुरैशी (80) को मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यभार संभालते ही कुरैशी ने घोषणा की कि उर्दू पत्रकारिता के स्तंभ राजा राममोहन राय अंतरराष्ट्रीय उर्दू सम्मान पुनः प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही अकादमी द्वारा तीन अन्य प्रादेशिक सम्मान भी शुरू किए जाएंगे।

डॉ. कुरैशी ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन 'नईदुनिया' को बताया कि ये सम्मान रचनात्मक साहित्य, शोध साहित्य और हास्य व्यंग्य लेखन के लिए दिए जाएंगे। रचनात्मक साहित्य और उर्दू अफसाना लेखन के लिए प्रो. आफाक अहमद सम्मान, शोध साहित्य के लिए प्रो. अब्दुल कवी दसनवी सम्मान और उर्दू हास्य-व्यंग्य लेखन के लिए प्रो. शफीका फरहत सम्मान अगले वर्ष से दिए जाएंगे। डॉ. कुरैशी ने बताया कि 2003 के पहले राजा राममोहन राय अंतरराष्ट्रीय सम्मान उन्होंने ही शुरू कराया था। यह एक साल ही दिया गया। उस समय इस सम्मान के तहत प्रशस्ति पत्र और सवा लाख रुपए नकद देते थे, तब यह सबसे बड़ी राशि थी। अब सम्मान राशि में बढ़ोतरी करेंगे।

8 वर्षों से प्रदर्शनों की संख्या का रिकॉर्ड रखा जा रहा है दिल्ली में। 2019 में 12,652 विरोध-प्रदर्शन और धरने दिल्ली में हुए, जो 2018 से 46 फीसद ज्यादा हैं।

कोई भी देश अपना झंडा जलाने की अनुमति नहीं दे सकता : वरुण गांधी

साक्षात्कार

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर विपक्ष का विरोध और आंदोलन अब भी जारी है। कांग्रेस के नेतृत्व में आगामी बजट सत्र में इसे और तेज करने की रणनीति भी बन रही है। वहीं, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नए कानून के तहत बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए काम भी शुरू हो गया है। पीलीभीत से ही भाजपा सांसद **वरुण गांधी** ने कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा कि यह राजनीति एक दिन उसके हाथ जला देगी। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख **आशुतोष झा** से बातचीत के अंश :

वरुण गांधी (फाइल फोटो)। आर्काइव

● नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में कई स्थानों पर अभी भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं, आपके संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में हजारों लोगों को नागरिकता देने पर कदम उठाया गया है। जबकि अभी नियम कायदे भी तय नहीं हुए हैं?

मेरे क्षेत्र में बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत में आए लगभग डेढ़ लाख शरणार्थी हैं। आप जाकर देखिए उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मुझे तो उन्हें देखकर बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन कानूनन वह भारतीय नागरिक नहीं थे। वह तो इस डर में जी रहे थे कि कभी भी उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि जल्दबाजी क्यों हो रही है। अरे भाई 70 साल तो बीत गए अब क्या इस समस्या को 700 साल खींचना है।

● आपने कहा कि डेढ़ लाख शरणार्थी हैं, जबकि पहचान तो 37 हजार की ही की गई है। बाकियों का क्या होगा?

-जो भी हैं सभी पर फैसला होगा। मेरी जानकारी के अनुसार कुछ लोगों को तो सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नागरिकता मिल चुकी है। बाकियों को भी मिलेगी।

● कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सीएए को समाज में विभाजन का हथियार बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे?

-मैं सीधे शब्दों में कहूं तो कांग्रेस दोहरी राजनीति और मानसिकता में जी रही है। इससे बाज आना ही होगा, वरना अपने ही हाथ जलाएगी। 2003 में अटल जी के काल में नागरिकता कानून में संशोधन के लिए एक समिति बनी थी और अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। उस समिति ने कहा था कि धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आने वाले केवल अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जाए, बहुसंख्यकों को नहीं। 2003 में डॉ. मनमोहन सिंह जी ने भी राज्यसभा में ऐसी ही मांग की थी। महात्मा गांधी का मानना था कि बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों अपने-अपने देशों में अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता भी हुआ था। हमने तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की लेकिन पाकिस्तान में किस तरह जुल्म हुआ ये सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी, नेहरू, प्रणब मुखर्जी की बातों के लिए सम्मान नहीं है। मुझे अचरज है कि कांग्रेस खुद के अंदर झांककर सही फैसले लेना कब सीखेगी।

● लेकिन पिछले कुछ दिनों में सड़क पर लोग उतरे हैं। और पुलिस कार्रवाई में कइयों की जानें भी गईं?

-हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हम लोगों को देश के नागरिक होने के नाते आत्मा से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि वह कौन सी लक्ष्मण रेखा है जो पार होती है तो देश को विखंडित करने का अस्त्र बन जाता है। कोई भी देश -अमेरिका, रूस, चीन, अफ्रीका कोई भी देश अपने झंडे जलाने की अनुमति नहीं देता है, जो यहां कई जगहों पर हुआ। कोई भी देश यह अनुमति नहीं देता है कि आप कहें कि हमें देश के संवैधानिक ढांचे से आजादी चाहिए। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन देश को खंडित करने की आजादी नहीं है। जहां तक उप्र की बात है तो कुछ बयान ऐसे आए जिसकी आलोचना होनी चाहिए। संभल में, मुजफ्फनगर के कुछ हिस्सों में, बदायूं में, लखनऊ में जिस तरह दंगा भड़काया गया वह क्या था। ऐसे में पुलिस क्या करेगी। क्या दंगाइयों को छूट दे दी जाए? किसी की जान जाए यह किसी को पसंद नहीं आएगा लेकिन अगर दंगाई समूह के ऐसे व्यक्ति की जान गई है जो देश विरोधी कार्यक्रम में जुटा था तो यह न्याय है। उसे कानून व्यवस्था की रक्षा कहते हैं।

क्षतिपूर्ति वसूली नोटिस रद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस निरस्त करने की मांग की गई है। जिला प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के एवज में वसूली के लिए प्रदर्शनकारियों को नोटिस थमाया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से नोटिस जारी किया गया है। जिसके नाम से नोटिस भेजा गया है उसकी छह साल पहले 94 वर्ष की अवस्था में मौत हो चुकी है। दो अन्य भी 90 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं। शुक्रवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ के सामने सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध की गई थी। पीठ के नहीं बैठने से याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में याची वकील परवेज आरिफ टीटू ने नोटिसों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि ये उन लोगों को भेजे गए हैं जिनके खिलाफ किसी भी दंड प्रावधान के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है और उनके खिलाफ न तो एफआइआर दर्ज की गई है और न ही आपराधिक मामला बनाया गया है। यह याचिका वकील निलोफर खान के माध्यम से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं। यह शीर्ष कोर्ट के 2009 के फैसले में जारी दिशानिर्देश का उल्लंघन करता है। बाद में 2018 में इसकी पुष्टि की गई थी।

इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरह के प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2009 और 2018 में तय किए गए दिशानिर्देश की प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सीएए-एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच गठित करने की मांग की गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वतंत्र न्यायिक आयोग का गठन किया है।

न्यूज गैलरी

फीका रहा महाराष्ट्र बंद का असर

मुंबई : प्रकाश आंबेडकर के संगठन वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के महाराष्ट्र बंद का असर फीका रहा। संगठन ने सीएए एवं एनआरसी के विरोध में महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी हुईं। शुक्रवार को दिनभर चले बंद के बाद शाम करीब चार बजे स्वयं बंद वापस लेने की घोषणा करते हुए प्रकाश आंबेडकर ने कहा पूरे राज्य में बंद शांतिपूर्ण रहा। कुछ स्थानों पर हुई तोड़फोड़ की घटनाओं में उनके संगठन का हाथ नहीं था। दूसरे संगठनों ने इस काम को अंजाम दिया है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि वह सीएए, एनआरसी एवं एनपीआर के विरुद्ध संदेश देने में कामयाब रहे। यह न सिर्फ मुस्लिमों, बल्कि हिंदुओं के लिए भी घातक है। आंबेडकर के अनुसार, बंद के दौरान पूरे राज्य में वंचित बहुजन अघाड़ी के करीब 3000 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन वह किसी तरह की हिंसा में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। सोलापुर एवं मुंबई के चेंबूर इलाके में दो सरकारी बसों पर पथराव की घटनाएं हुईं। सोलापुर में बस की विंडस्क्रीन टूट गई और मुंबई में एक बस चालक घायल हो गया। चालक को अस्पताल ले जाना पड़ा। (राब्यू)

छत्तीसगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों का हमला

बिलासपुर : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री सन्नी केसरी एवं कार्यकर्ताओं ने गुरुवार शाम को गुर घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों पर हमला कर किया। इस घटना के बाद देशभर में छात्र राजनीति फिर गरमा गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) दिल्ली और मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्र भी बिलासपुर सीयू के छात्रों के सपोर्ट में आ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जेएनयू के छात्र घटना की कड़ी निंदा कर भड़ास निकाल रहे हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को छात्रों में कहासुनी छात्र परिषद के फार्म बिक्री के दौरान हुई थी। आरोप है कि शाम को तीन-चार वाहनों में भरकर कुछ युवक हाथों में डंडा लेकर विवि परिसर में घुसे और छात्रों को मारना शुरू कर दिया। (नईदुनिया)

सीएए के समर्थन में राष्ट्रपति से मिले 154 बुद्धिजीवी

रखी बात ▶ कहा, लोगों को गुमराह कर इसके खिलाफ उकसाया जा रहा है, हिंसा के आरोपितों पर हो कड़ी कार्रवाई

साधु-संत भी गांव-गांव जाकर दूर करेंगे कानून के बारे में भ्रांतियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध प्रदर्शनों में हिंसा के खिलाफ देश के बुद्धिजीवियों से लेकर साधु-संत तक एकजुट होने लगे हैं। इस सिलसिले में 154 बुद्धिजीवियों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वहीं, विश्व हिंदू परिषद साधु-संतों को गांव-गांव में भेजकर आम जनता को सीएए के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रम के निवारण की तैयारी में जुटी है। इसके साथ ही विहिप ने सीएए के समर्थन में प्रदर्शनों पर हिंसक हमले के खिलाफ गहरी नाराजगी जताते हुए आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

कैट के पूर्व अध्यक्ष और सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रमोद कोहली के नेतृत्व में बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से कहा कि सीएए के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों को हवा देने में राजनीतिक शक्तियां सक्रिय हैं। लेकिन उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि कुछ समूह द्वारा माहौल को जहरीला बनाने और देश को बांटने की साजिश चिंता का कारण है। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि वे किसी भी मुद्दे पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इससे आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बुद्धिजीवियों के अनुसार सीएए का किसी भारतीय की नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है। फिर भी लोगों को गुमराह कर इसके खिलाफ उकसाया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में हाई कोर्ट के 11 पूर्व न्यायाधीश, आइएएस, आइपीएस, आइएफएस समेत 72 पूर्व नौकरशाह के साथ-साथ 56 पूर्व रक्षा अधिकारी और शिक्षाविद शामिल थे।

सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हिंदुओं पर हमले के बाद विहिप भी मैदान में उतर आया है। विहिप के महासचिव मिलिंद परांडे ने आरोप लगाया कि इसके पीछे देश विरोधी शक्तियां सक्रिय हैं। कश्मीर के मुद्दे का, जिसका सीएए से कोई लेना-देना नहीं है, विरोध प्रदर्शनों के दौरान सामने आना इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों विहिप मार्गदर्शक मंडल में आम जनता को सीएए की हकीकत से अवगत कराने का फैसला किया गया। इसके तहत देश के साधु-संत गांव-गांव में प्रवास करेंगे। विहिप ने लोहरदगा में सीएए के समर्थन में निकली रैली पर हिंसक हमले की निंदा करते हुए आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विहिप ने साफ किया कि सब्र की सीमा होती है। यदि राज्य सरकारें हिंसा करने वाले आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो इससे हिंसा को उनके परोक्ष समर्थन का संदेश जाएगा।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन और इसको लेकर हुई हिंसा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को पूर्व जजों, नौकरशाहों और बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें मांगपत्र सौंपा। संजय

...तो भाजपा में बने रहने पर विचार करूंगा : चंद्र बोस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने कहा कि वह नेताजी के राजनीतिक मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं और अगर धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो वह पार्टी में बने रहने पर पुनर्विचार कर सकते हैं। बोस ने सीएए की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि कुछ बदलाव करने होंगे, ताकि सभी पीड़ितों को नागरिकता दी जा सके। चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उन्होंने कहा, 'मैं भाजपा के मंच का इस्तेमाल करके धर्मनिरपेक्षता और समावेश के सिद्धांतों को फैलाना चाहता हूं। जब मैंने जनवरी, 2016 में भाजपा की सदस्यता ली थी तो मैंने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से कही थी। वे भी इस पर सहमत हुए थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं नेताजी के सिद्धांतों का पालन नहीं कर पा रहा। अगर यह चलता रहा तो मुझे पार्टी में बने रहने पर सोचना होगा। हालांकि, मैं नरेंद्र मोदी से बात किए बिना कोई फैसला नहीं लूंगा।' उधर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्वजन एवं पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद कृष्णा बोस ने शुक्रवार को कहा कि सीएए और एनआरसी को लागू करने का भाजपानीत केंद्र सरकार के निर्णय से देश 'गृहयुद्ध'की तरफ बढ़ रहा है।

जामिया हिंसा में कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत तीन से पूछताछ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ बीती 15 जनवरी को जामिया नगर में हिंसक उपद्रव के मामले में क्राइम ब्रांच के विशेष जांच दल (एसआइटी) ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान, स्थानीय नेता आशु खान व जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र चंदन कुमार से सात घंटे तक पूछताछ की। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार देर रात जामिया नगर इलाके से मोहम्मद फुरकान को गिरफ्तार किया गया। छह घंटे तक पूछताछ के बाद एसआइटी ने शुक्रवार को उसे साकेत कोर्ट में पेश किया, जहां से तीन दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

15 जनवरी को जामिया व न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बसों में आग लगा दी गई थी। पथराव में 30 पुलिसकर्मी व 39 प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। जामिया नगर थाना पुलिस ने दो और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस ने एक एफआइआर दर्ज की थी। तीनों मामले को अगले ही दिन क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब तक 17 आरोपितों को गिरफ्तार कर तिहाड़ भेजा जा चुका है।

सात घंटे हुई पूछताछ : एसआइटी ने मोहम्मद आसिफ खान, आशु खान व चंदन कुमार को गुरुवार शाम नोटिस भेज शुक्रवार सुबह 11.30 बजे चाणक्यपुरी आकर जांच में शामिल होने को कहा था। तीनों समय पर पहुंच गए। इनसे पहले अलग-अलग फिर एक साथ बैठाकर पूछताछ की गई। तीनों से 18-18 सवाल पूछे गए। उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। पूछताछ के दौरान तीनों ने कहा कि वे शंतिपूर्वक प्रदर्शन का हिस्सा थे। जहां पर हिंसा व तोड़फोड़ हुई वे वहां मौजूद नहीं थे।

आसिफ ने फैलाई गिरफ्तारी की अफवाह : ओखला से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान से जिस वक्त क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ की जा रही थी, उसी दौरान आसिफ ने अपने मोबाइल से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया कि क्राइम ब्रांच ने उन्हें जामिया हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। लोग उनके साथ खड़े रहें। वह तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।

अमानतुल्लाह ने किया हंगामा

गुरुवार रात पुलिस मो. फुरकान को गिरफ्तार कर थाने लाई। कुछ देर में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और वहां हंगामा किया। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद पुलिस ने जब फुरकान को नहीं छोड़ा तब हारकर वह समर्थकों के साथ वापस चले गए।

70 वर्षीय वृद्ध ने पर्चे उछाल खुद को आग लगाई, हालत गंभीर

नईदुनिया, इंदौर : इंदौर में शुक्रवार शाम 70 वर्षीय वृद्ध ने आत्मदाह की कोशिश की। उसे गंभीर अवस्था में एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वृद्ध ने कुछ पर्चे उछाले थे, जिस पर सीएए, एनआरसीए के संबंध में कुछ लिखा हुआ था। इसके साथ खुद को आग लगा ली।

तुकोगंज थाना प्रभारी निर्मल श्रीवास के मुताबिक, इंदौर के फूटी कोठी निवासी रमेश पुत्र केशरीमल प्रजापति हाथ में केरोसिन से भरी कैन लेकर आए और गीता भवन चौराहे पर खुद पर उंडेलकर आग लगा ली। वहां से गुजर रहे डीएसपी (पीटीसी) सुनील तालान ने एंबुलेंस बुलवाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डीएसपी के मुताबिक, लोगों ने बताया कि आत्मदाह के पूर्व रमेश ने हवा में कुछ पर्चे उछाले थे। मौके पर पहुंचे सिपाहियों ने पर्चे और एक बैग बरामद किया है। सूचना मिलते ही मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि रमेश पार्टी के सदस्य हैं। रमेश 90 प्रतिशत से ज्यादा जल गए हैं। आत्मदाह का प्रयास क्यों किया, इसका कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। सीपीआइएम राज्य मंडल के सदस्य कैलाश लिंबोदिया के अनुसार वे दो दिन तीन से हमारे साथ थे, लेकिन कभी जिक्र नहीं किया। स्वजनों को भी घटना का कारण नहीं पता है।

कर्नाटक की भाजपा सांसद के बयान पर केरल में मुकदमा

▶ **शोभा करंदलाजे ने केरल में सीएए समर्थक हिंदुओं की जलापूर्ति रोके जाने का लगाया था आरोप**

मलाप्पुरम, बेंगलुरु : कर्नाटक की भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे व अन्य पर केरल पुलिस ने दो समुदायों के बीच दुश्मनी भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। केरल पुलिस ने करंदलाजे के उस ट्वीट पर कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मलाप्पुरम जिले की एक पंचायत में रहने वाले हिंदुओं की जलापूर्ति इसलिए रोक दी गई, क्योंकि उन्होंने सीएए का समर्थन किया था। इस मुद्दे पर भाजपा केरल सरकार पर हमलावर हो गई है।

लोकसभा सदस्य करंदलाजे कर्नाटक भाजपा की महासचिव भी हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट वकील केआर सुभाष चंद्रन की तरफ से गुरुवार को दी गई तहरीर के आधार पर दर्ज की गई है। उडुपी के चिकमंगलूर की सांसद ने कार्रवाई को लेकर ट्वीट किया, 'केरल सरकार की जय हो! कुट्टीपुरम पंचायत के चेरुकुन्नू निवासी अनुसूचित जाति के लोगों से भेदभाव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मुझ पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया। यह अकर्मण्य और पूर्वाग्रहग्रस्त राज्य सरकार के खिलाफ एकजुट होने का उपयुक्त समय है।' उन्होंने कहा, 'जो लोग सीएए का समर्थन कर रहे हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है। उन्हें मौलिक सुविधाओं से भी महरूम किया जा रहा है। इन घटनाओं पर केरल सरकार ने आंखें मूंद ली है।'

भाजपा के आइटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और पार्टी के अन्य नेताओं ने भी करंदलाजे के समर्थन में ट्वीट किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत मुस्लिम बहुल है और वे अनुसूचित जाति के लोगों को पानी देने से इन्कार कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सांसद व अन्य के खिलाफ आइपीसी की धारा 153-ए (धार्मिक आधार पर दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करना) व धारा 34 (समान उद्देश्य के लिए कई लोगों द्वारा एक ही काम करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चेरुकुन्नू में पिछले कुछ महीने से मोटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। बिजली विभाग ने आपत्ति जताई थी कि मोटर का इस्तेमाल सिर्फ सिंचाई कार्य के लिए किया जाना चाहिए।

भाजपा सांसद करंदलाजे ने 22 जनवरी को ट्वीट किया था, 'केरल कश्मीर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मलाप्पुरम की कुट्टीपुरम पंचायत के चेरुकुन्नू निवासी हिंदुओं को पानी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उन्होंने सीएए का समर्थन किया। क्या मीडिया इन शांतिदूतों की असहिष्णुता का प्रसारण करेगा।' करंदलाजे के ट्वीट को 6,000 बार रिट्वीट किया गया और करीब 8,000 लाइक मिले।

शाहीन बाग-कालिंदी कुंज रोड खुलवाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

▶ **विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती**

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के कारण बंद शाहीन बाग-कालिंदी कुंज रोड खुलवाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। शुक्रवार को याचिकाकर्ता अमित साहनी ने कोर्ट से याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस बारे में मेंशनिंग ऑफिसर के पास जाने को कहा।

पेशे से वकील अमित साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर रोड खोलने का आदेश नहीं दिया था बल्कि कहा था कि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था की स्थिति देखते हुए कार्रवाई करने को स्वतंत्र है।

दाखिल याचिका में लोगों की आने जाने की दिक्कतों का जिक्र करते हुए शाहीन बाग-कालिंदी कुंज रोड खुलवाने की मांग की गई है। कहा गया है कि यह सड़क फरीदाबाद, दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और रोजाना करीब पांच लाख लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। इसके बंद होने से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है।

इस सड़क के बंद होने से ट्रैफिक को दो जगह आश्रम और डीएनडी पर डाइवर्ट किया गया है, लेकिन इसके कारण दोनों ही जगह जाम लगा रहता है जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है। इसके अलावा प्रदूषण भी बढ़ता है। याचिका में कहा गया है कि सड़क बंद होने से उससे आने जाने वालों के अधिकारों का हनन हो रहा है।

याचिका में कहा गया है कि प्रशासन के सड़क खुलवाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश करें ताकि शांतिपूर्ण ढंग से सड़क खुलवाई जा सके और हिंसा न हो। यह सड़क पिछले 15 दिसंबर से बंद है। याचिका में ओखला अंडरपास भी खुलवाने की मांग की गई है।

जनमत

मुद्दा

क्या हालिया हालात से उपजे इस सवाल से आप सहमत हैं कि केंद्र सरकार संविधान के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ कर रही है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं।

दो टूक

योग गुरु ने कहा-सीएए और एनआरसी को लेकर फैलाई जा रही है गलतफहमी, बोले-कानून बनाकर दो बच्चे से ज्यादा के पिता को दंडित करें, मताधिकार भी छीनें

जिन्ना वाली आजादी की बात करना देश के साथ गद्दारी : रामदेव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

योग गुरु बाबा रामदेव ने देश में सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के पीछे कुछ विपक्षी दलों, मजहबी लोगों और विदेशी ताकतों का हाथ बताया। इन प्रदर्शनों में लग रहे 'आजादी के नारों' को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा है कि जिन्ना वाली आजादी की बात करना देश के साथ खुली गद्दारी है। ऐसे लोगों पर तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्होंने जेएनयू में भी छात्रों के एक गुट की ओर से लगाए जा रहे इस तरह से नारों को गलत बताया और उन्हें राजनीतिक मामलों से दूर रहकर पढ़ाई और भविष्य निर्माण पर ध्यान देने का सलाह दी। राजनीतिक आंदोलन के लिए विपक्ष है, जो इस काम को कर रहा है।

बाबा रामदेव ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार साफ-साफ कहा है कि सीएए से किसी की नागरिकता खत्म नहीं हो रही है। यह तो नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी भारतीय मुस्लिम की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। यह देश जितना मेरा है, उतना ही उन देशभक्त मुसलमानों का भी है। उन्हें इस देश से कोई नहीं निकाल सकता। हालांकि उन्होंने देश को तबाह करने और टुकड़े-टुकड़े करने की बात कर रहे लोगों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि मैं इसे मुस्लिम समाज की विचारधारा नहीं मानता हूं। मेरी मुस्लिम समाज के बड़े बुद्धिजीवियों से अपील है कि वह आगे आए और जो लोग एक समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे है, उनका पुरजोर विरोध करें। उन्होंने लोगों के बीच गलतफहमी फैला रहे विपक्ष को सलाह दी कि भाजपा और मोदी को देश के लोगों ने 2024 तक के लिए जनादेश दिया है। ऐसे में उन्हें धैर्य के साथ राजनीतिक विरोध करना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में हाथ बंटाना चाहिए। दुनिया में देश की बदनामी करना ठीक नहीं है। वैसे भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके बोलने से पाकिस्तान में ज्यादा चर्चा होती है।

जनसंख्या नियंत्रण पर भी उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी और कहा कि सरकार को इसके नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए। सिर्फ दो बच्चे पैदा करने की अनुमति होनी चाहिए। इससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले पिता को दंडित किया जाना चाहिए। इनके वोटिंग के अधिकार को भी छीन लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में बताया कि वह दिल्ली-एनसीआर में दुनिया का सबसे बड़ा एक विश्वविद्यालय भी खोलने जा रहे हैं, जो एक लाख से ज्यादा छात्रों की क्षमता का होगा। साथ ही उनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित सभी क्षेत्रों से जुड़ी पढ़ाई होगी। एक अन्य सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि ने वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भी 13 हजार करोड़ टर्न ओवर वाली रुचि सोया कंपनी का अधिग्रहण किया है। पतंजलि का लक्ष्य 2025 तक देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को पूरा करना है।

नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेस में सवालों का जवाब देते योग गुरु बाबा रामदेव। प्रेट्र

▶ **कहा- विरोध कर दुनिया की देश में बदनामी कराना ठीक नहीं, राष्ट्र निर्माण में बंटाएं हाथ**

▶ **दिल्ली-एनसीआर में एक लाख छात्र क्षमता वाला विश्वविद्यालय खोलेंगे रामदेव**

आंदोलनकारियों से आज मिल सकते हैं योग गुरु

बाबा रामदेव ने इस बीच दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी को आंदोलन कर रहे लोगों से मुलाकात की भी इच्छा जताई है। संभवत: उनकी यह मुलाकात 25 जनवरी को हो सकती है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि वह न तो इसका समर्थन करने जा रहे है, न ही विरोध। न ही वह बिचौलिये बनकर जा रहे है। वह उनके बीच सीएए-एनआरसी को फैलाई गई गलतफहमियों पर अपनी बात रखने जा रहे है। जो सही है। बाबा रामदेव ने इस दौरान सड़क को रोककर किए जा रहे आंदोलन पर भी सवाल उठाया और कहा कि वह ऐसे किसी आंदोलन के पक्षधर नहीं हैं, जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो।

14 लोगों को नामजद किया गया है पश्चिम सिंहभूम के बुरुगुलीकेरा गांव में पंचायत के दौरान सात ग्रामीणों की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में। इसके अलावा 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज की गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 25 जनवरी 2020

जम्मू-कश्मीर में आज से हर मोबाइल पर चलेगा इंटरनेट

राज्य ब्यूरो, जम्मू

गणतंत्र दिवस से ठीक पहले राज्य प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में शनिवार से पोस्टपेड और प्रीपेड पर 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। ब्राडबैंड सेवा भी हर शहर और कस्बे में उपलब्ध होगी, लेकिन सशर्त और पाबंदियों के साथ। कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को नहीं चला सकेगा। फिलहाल, यह सुविधा 25 से 31 जनवरी 2020 तक रहेगी।

हालात में सुधार और हाल ही में प्रीपेड व पोस्टपेड सेवा की बहाली के बाद की स्थिति का आकलन करने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सभी पोस्टपेड और प्रीपेड मोबाइल सिम के अलावा सभी फिक्स्ड लाइन पर इंटरनेट सुविधा बहाल करने का फैसला लिया है। यह सेवा 25 जनवरी शनिवार से बहाल होगी। जम्मू-कश्मीर गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने देर रात इस संदर्भ में आदेश जारी किया।

आदेश के अनुसार, कोई भी इंटरनेट सेवा का दुरुपयोग न कर सके, इसलिए उन्हीं पोस्टपेड और प्रीपेड मोबाइल सिम धारकों के नंबरों पर डाटा इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी, जिनके बारे में निर्धारित नियमों के तहत जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। ब्रांडबैंड पर भी सिर्फ श्वेत सूची में शामिल वेबसाइट को ही सर्च किया जा सकेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाले ही इसके किसी भी दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे।

पिछले वर्ष पांच अगस्त को लगाई गई थी पाबंदियां : पिछले वर्ष पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की घोषणा से पहले प्रशासन ने पूरे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया था। जम्मू प्रांत में अगले दो दिन में ही सभी टेलीफोन सेवाएं पूरी तरह सामान्य हो गई थी, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया था। वहीं, जम्मू प्रांत में ब्राडबैंड सेवा भी शुरू से बहाल रखी गई है। कश्मीर घाटी में अगस्त माह के दूसरे पखवाड़े में लैंडलाइन फोन सेवा को चरणबद्ध तरीके से बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो सितंबर माह में पूरी हुई। इसके बाद अक्टूबर में कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवा शुरू की थी। ब्राडबैंड सेवा को सिर्फ कुछ गिने चुने संस्थानों में ही सरकारी नियंत्रण में बहाल किया। 14 जनवरी को प्रशासन ने जम्मू प्रांत में सभी पोस्टपेड मोबाइल पर 2जी इंटरनेट सुविधा बहाल कर दी थी। इसके बाद 18 जनवरी को कश्मीर घाटी में भी सभी प्रीपेड फोन बहाल किए गए, लेकिन 2जी इंटरनेट सेवा सिर्फ पोस्टपेड फोन पर और वह भी दो जिलों कुपवाड़ा व बांडीपोरा में बहाल की गई थी।

कोशिश यही रहती है कि गणतंत्र दिवस पर हर बार कुछ अलग करूं...

जागरण विशेष

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

राजपथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड समारोह की बीते एक दशक से कमेंट्री करते आ रहे रिटा. कर्नल जीवन कुमार सिंह का कहना है कि वे हर वर्ष कुछ बेहतर और नया करने का प्रयास करते हैं। इस बार क्या है उनकी तैयारी? दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, हर बार कोशिश यही रहती है कि कुछ नया करूं, पहले से बेहतर और ऐसी प्रस्तुति दे सकूं कि श्रोता गणतंत्र के उत्सव का भरपूर आनंद उठा सकें। इस बार भी आपको नयापन अवश्य मिलेगा। 26 की सुबह की प्रतीक्षा करें...।

इसमें कोई संशय नहीं कि वे जब बोलते हैं तो पूरा देश उन्हें ध्यान से सुनता है। उनकी बातें और इन्हें कहने का उनका अंदाज श्रोता के मन में उठने वाले राष्ट्रभक्ति के सभी भावों को संतुष्ट करता है। उनकी आवाज कभी सुनने वालों के रोंगटे खड़े करती है तो कभी भावनाओं में बहाकर ले जाती है। रिटायर्ड कर्नल जीवन कुमार सिंह को उन्हें जानने वाले जेके कहकर पुकारते हैं। 55 साल के जेके गणतंत्र दिवस परेड में कमेंटेटर की भूमिका निभान को अपने लिए सौभाग्य मानते हैं।

उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड की कमेंट्री का ढर्रा बदलकर उसे नया आयाम दिया है। कभी महज तथ्यों पर आधारित कमेंट्री में अपनी रचनाशीलता, ओजपूर्ण लेखनी और जादुई आवाज से शौर्य, ऊर्जा, बलिदान और समर्पण की भावनाएं भरी हैं। वर्ष 2010 से गणतंत्र दिवस परेड की कमेंट्री करने के अलावा जेके 2007 से सेना के कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम में होने वाले विजय दिवस समारोह के भी उद्घोषक हैं। ये उनकी जबर्दस्त लेखनी और वाणी का ही कमाल है कि सेना के राष्ट्रीय स्तर के सभी बड़े कार्यक्रमों में कमेंट्री करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है। जेके को शानदार कमेंट्री के लिए सेना की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। वे वर्तमान में झारखंड पुलिस में एसपी (स्पेशल टास्क फोर्स) के पद पर कार्यरत हैं।

धनबाद, झारखंड निवासी जेके अपने उद्घोषक बनने का श्रेय पत्नी नितिका को देते हैं। कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक कार्यक्रम के लिए मैंने दूसरे अधिकारी को अभिभाषण लिखकर दिया था। जब उन्होंने इसे पढ़ा तो सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में मौजूद मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप अपने लिखे अभिभाषण को इससे भी बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे क्योंकि इसमें आपकी रचनात्मकता और भावनाएं हैं। इसके बाद मैंने 2003 में शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी के स्मरण में आयोजित सेना के एक कार्यक्रम में पहली बार उद्घोषणा की, जिसे काफी पसंद किया गया। फिर तो यह सिलसिला शुरू हो गया। 2005 से 2007 तक मैंने दिल्ली में आयोजित हुए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लगे रक्षा मंत्रालय के पवेलियन में बतौर उद्घोषक अपनी सेवाएं प्रदान कीं। रिटायर्ड कर्नल ने बताया, 2009 में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई। 15 जनवरी, 2010 को मैंने आर्मी डे परेड के लिए कमेंट्री की। उसी साल पहली बार राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए बोलने का मौका मिला। मैं इसके लिए काफी तैयारी करता हूं। आयोजकों की ओर से परेड में होने वाली मूल चीजें बता दी जाती हैं। मैं उसके अनुसार अपनी स्क्रिप्ट तैयार करता हूं। परेड की कमेंट्री डेढ़ से दो घंटे की होती है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिटायर्ड कर्नल जीवन कुमार सिंह (फाइल)। सौजन्य : रिटायर्ड कर्नल

पीएम मोदी भी हैं मुरीद...

रिटा. कर्नल जीवन कुमार सिंह की आवाज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुरीद हैं। वह बताते हैं, पिछले साल फरवरी में दिल्ली में पूर्व सैनिकों के एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए पीएम मोदी ने मंच पर जाने से पहले मुझसे हाथ मिलाकर मेरी तारीफ की थी, हौसला बढ़ाया था। पिछले दिनों सेना के एक कार्यक्रम में उन्होंने मुझसे गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों के बारे में भी पूछा था। मैंने उन्हें इससे अवगत कराया।

जब हिजबुल के आतंकी कमांडर को मार गिराया...

जेके सिर्फ आवाज ही नहीं, वीरता के भी धनी हैं। 1993 में उन्होंने कश्मीर के बड़गांव जिले में हिजबुल के आतंकी कमांडर को मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके लिए उन्हें सेना में बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने सैनिक स्कूल, तिलैया से एनडीए की परीक्षा में टॉप किया था और पूरे भारत में तीसरे स्थान पर रहे थे। उनके पिता प्रह्लाद प्रसाद सिंह झारखंड पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी हैं। मां स्व. देवकी देवी आम गृहिणी थीं। परिवार में पत्नी व दो बेटियां सृष्टि जीवंतिका सिंह और संस्कृति जीवंतिका हैं।

न्यूज गैलरी

सीबीआइ ने किया इंद्राणी की जमानत याचिका का विरोध

मुंबई : सीबीआइ ने शीना बोरा हत्याकांड की प्रमुख अभियुक्त इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी का विरोध किया है और कहा है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पाने की कोशिश में चार बार नाकाम रहने के बाद इंद्राणी ने दिसंबर 2019 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश जेसी जगदाले की अदालत में केस की मेरिट के आधार पर जमानत देने की अर्जी लगाई। उसको शीना बोरा हत्याकांड में 2015 में गिरफ्तार किया गया था। जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआइ ने कहा कि इंद्राणी ने अपनी ही बेटी की हत्या की है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। (प्रेट्र)

दो संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

आइजल : एनआइए ने आइजल की एक कोर्ट में दो संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया। भारत में गैरकानूनी रूप से प्रवेश कर गए आतंकियों ने जाली आधार कार्ड से अपनी पहचान छिपाई थी। जांच एजेंसी ने मुहम्मद हसन उर्फ शरीफुल इस्लाम और मुहम्मद साद हुसैन उर्फ मुहम्मद सैयद हुसैन के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं, विदेशी अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत शुक्रवार को आरोपपत्र दायर किया। (प्रेट्र)

आइआरसीटीसी के पूर्व प्रोग्रामर से जुड़े ई-टिकटिंग में सेंधमारी के तार

खुल रहे हैं राज ▶ सीबीआइ ने 2017 में गिरफ्तार किया था प्रोग्रामर अजय गर्ग को

क्रिस और आइआरसीटीसी के लोग करते रहे हैं वेबसाइट में खामी से इन्कार

संजय सिंह, नई दिल्ली

रेलवे में जब ई-टिकटिंग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, तो उसमें बार-बार 'गुरुजी' का नाम आया था। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह गुरुजी कोई और नहीं बल्कि सरगना हामिद अशरफ को फंडा सिखाने वाला आइआरसीटीसी व सीबीआइ का पूर्व प्रोग्रामर अजय गर्ग था।

अजय गर्ग 2007 से 2011 के बीच आइआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान व पर्यटन निगम) में काम करता था। इसके बाद उसने सीबीआइ में असिस्टेंट प्रोग्रामर की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसके बारे में जानकारी खुद अशरफ ने सीबीआइ को दी थी। इसके बाद सीबीआइ ने 2017 में उसे उसके सहयोगी अनिल गुप्ता के साथ गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआइ ने क्रिस (रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र) के मुख्यालय ले जाकर इन तीनों की पेशी अधिकारियों के समक्ष कराई थी। वहां तीनों ने सबके सामने आइआरसीटीसी की वेबसाइट में अनधिकृत घुसपैठ कर कैप्चा और ओटीपी को बाइपास कर फटाफट टिकट बुकिंग करने वाले एएनएमएस सॉफ्टवेयर का हुनर दिखाया था। इसी के बाद से क्रिस पर बंदी की तलवार लटक रही है।

अशरफ और अजय गर्ग के रहस्योद्घाटन के बाद आरपीएफ ने देशभर में कई जगहों पर छापेमारी कर ई-टिकटिंग रैकेट से जुड़े कई अन्य एजेंटों को पकड़ा था। इसके बावजूद क्रिस और आइआरसीटीसी के लोग लगातार इस बात से इन्कार करते रहे कि उनकी वेबसाइट में कोई खामी है। उनका कहना था मनुष्य के मुकाबले मशीनों के जरिये टिकटों की तेज गति से बुकिंग तो संभव है, परंतु वेबसाइट को हैक करना कतई संभव नहीं है। मशीन की घुसपैठ की संभावना को सीमित करने के लिए उन्होंने हर चरण में कैप्चा डालने तथा भुगतान के लिए ओटीपी की व्यवस्था की। लेकिन अशरफ के एजेंटों ने इससे जनता को परेशानी की सैकड़ों शिकायतें कर क्रिस को कुछ जगहों पर कैप्चा बंद करने को विवश कर दिया। लेकिन, इससे गैरकानूनी बुकिंग के मामले फिर बढ़ने लगे। इस पर कुछ मामलों को छोड़ कैप्चा को फिर से बहाल कर दिया गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेल मंत्रालय ने क्रिस और आइआरसीटीसी को यह साबित करने को कहा कि उनका सिस्टम फूलप्रूफ है। इसके लिए रेल भवन में बाकायदा साइबर एक्सपर्ट और एथिकल हैकर्स बुलाए गए और उन्हें वेबसाइट को हैक करने की चुनौती दी गई। इस सम्मेलन में क्रिस व आइआरसीटीसी वाले सिस्टम को हैकप्रूफ साबित करने में कामयाब रहे। लेकिन, एएनएमएस या लाल मिर्ची जैसे सॉफ्टवेयर से सेंधमारी व फटाफट बुकिंग को रोकने के लिए जटिल कैप्चा के उपयोग के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं था।

क्रिस को बंद करने की चल रहीं चर्चाएं

बताते हैं कि इसी सम्मेलन के बाद रेल मंत्रालय ने 'क्रिस' को अपना सिस्टम फूलप्रूफ बनाने अन्यथा बंदी के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी। तबसे क्रिस को बंद किए जाने की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। सूत्रों की मानें तो नवीनतम घटनाओं के बाद क्रिस को बंद किए जाने पर कभी भी मुहर लग सकती है। सेंधमारी रोकने के लिए पिछले दिनों उसने वेबसाइट पर गूगल रीकैप्चा वी3 का प्रावधान किया था, परंतु माफिया उसकी काट निकालने में भी कामयाब रहे।

मिलीभगत का संदेह

पिछले डेढ़ वर्षों में टिकट दलालों के विरुद्ध छेड़े गए अभियानों से यह संदेह पुख्ता हुआ है कि क्रिस और आइआरसीटीसी के भीतर के ही कुछ लोग टिकटिंग माफिया को सिस्टम से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं मुहैया कराते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि सिस्टम कभी पूरी तरह फूलप्रूफ हो। इसके बार-बार प्रमाण मिले हैं। सूत्रों के अनुसार सिस्टम को फूलप्रूफ बनाने के लिए आरपीएफ द्वारा जब कभी सूचनाएं मांगी जाती हैं, क्रिस के अधिकारी उसमें रोड़े अटकाने का प्रयास करते हैं। यहां तक कि अभी 11-20 जनवरी के दौरान डाले गए छापों में जब गुलाम मुस्तफा को पकड़ा गया और बेंगलुरु में उसके गढ़ का पता चला तो आरपीएफ ने आइआरसीटीसी और क्रिस के अधिकारियों को वहां जाकर जांच में मदद करने को कहा। परंतु, दोनों संगठनों के किसी अधिकारी ने ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई है।

फिर टला बेहमई कांड पर फैसला, सुनवाई 30 को

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात

- मूल केस डायरी के लिए अब डीएम-एसपी को भेजा जाएगा पत्र
- कोर्ट ने दिया आदेश, आगे बढ़ ही नहीं पाई मामले की कार्रवाई

39 साल पूर्व कानपुर देहात के बेहमई गांव में हुए सामूहिक नरसंहार मामले में शुक्रवार (24 जनवरी) को भी फैसला नहीं आ सका। मूल केस डायरी न मिल पाने से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। न्यायालय ने मूल केस डायरी उपलब्ध कराने के लिए डीएम और एसपी को पत्र भेजने के आदेश दिए गए हैं। अगली तारीख 30 जनवरी तय की गई है।

14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में फूलन देवी, मुस्तकीम, राम अवतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 डकैतों ने धावा बोला था। उन्होंने घरों में लूटपाट के साथ ही 26 पुरुषों को गांव के बाहर ले जाकर अधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी। छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में वादी राजाराम सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। 24 अगस्त-2012 को पांच अभियुक्तों भीखा, पोसे उर्फ पोसा, विश्वनाथ उर्फ पुतानी उर्फ कृष्ण स्वरूप, श्याम बाबू व राम सिंह के खिलाफ आरोप तय होने पर कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। पांचों आरोपितों में से भीखा, विश्वनाथ उर्फ पुतानी उर्फ कृष्ण स्वरूप व श्याम बाबू जमानत पर हैं, जबकि पोसा जेल में बंद है। 13 फरवरी 2019 को जेल में राम सिंह की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में चल रही है। न्यायालय ने केस की सुनवाई पूरी होने के बाद 6 जनवरी की तिथि निश्चित की थी, लेकिन बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पेश करने के लिए समय मांगा था। इस पर न्यायालय ने 18 जनवरी की तारीख तय की थी, लेकिन पत्रावली में मूल केस डायरी न मिलने पर सत्र लिपिक को नोटिस जारी कर 24 तारीख को सुनवाई की तिथि तय की गई थी।

फिर मिली तारीख

शुक्रवार को मामले की सुनवाई होते ही मूल केस डायरी पर चर्चा शुरू हुई तो सत्र लिपिक ने मूल केस डायरी न मिलने की बात कही। इस पर कोर्ट ने डीएम और एसपी को पत्र लिखने के आदेश दिए। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि मूल केस डायरी उपलब्ध न होने से फैसला नहीं आ सका है। अब 30 जनवरी को सुनवाई होगी।

गुदड़ी कांड की जांच करने जा रहे भाजपा नेताओं को रोका

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर

- बुरुगुलीकेरा गांव तक नहीं पहुंच पाई छह सदस्यीय टीम
- सड़क पर धरने पर बैठ गए जांच दल के सदस्य, हुआ हंगामा

पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड के बुरुगुलीकेरा में सात लोगों की हत्या मामले की जांच करने जा रही भाजपा की छह सदस्यीय राष्ट्रीय टीम शुक्रवार को गांव नहीं पहुंच सकी। टीम के पहुंचने के पहले ही प्रशासन ने चक्रधरपुर, सोनुआ और गुदड़ी प्रखंड क्षेत्रों में 26 जनवरी तक के लिए निषेधाज्ञा लगा दी और भाजपा के जांच दल को पहले कराईकेला और फिर सोनुवा में रोक दिया। इससे नाराज भाजपा नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। काफी हंगामे के बाद प्रशासन ने उनको सोनुवा तक जाने की इजाजत दी। वहां भी प्रेस वार्ता कर उन्हें धरना समाप्त करना पड़ा।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से गठित इस छह सदस्यीय कमेटी सांसद जसवंत सिंह भाभोर, राज्यसभा सदस्य समीर उरांव, सांसद भारती पवार, गोमती साय, जॉन बार्ला और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल हैं। टीम के साथ भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा, वरिष्ठ नेता डॉ. अरुण उरांव, पूर्व विधायक पुतकर हेंब्रम, चुमनु उरांव, गुरुचरण नायक भी शामिल थे।

जमकर होती रही नारेबाजी : कराईकेला थाने के सामने एसडीओ व अन्य अधिकारियों ने भाजपा नेताओं को समझाने-बुझाने की काफी कोशिश की। टीम को रोके जाने की बाबत सफाई देते रहे और इस दौरान जमकर नारेबाजी होती रही। भाजपा की टीम का धरना करीब एक घंटे तक चला। टीम को प्रशासन ने सोनुवा तक जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद टीम के सदस्यों ने पैदल मार्च कर सरकार विरोधी नारे लगाए और गाड़ियों से सोनुवा की ओर रवाना हो गए।

भारती पवार ने कहा, संसद में उठेगा मामला : महाराष्ट्र से सांसद भारती पवार ने कहा कि टीम को रोका जाना दर्शाता है कि मामले में सरकार की मंशा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों के परिजन दहशत में हैं और वे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। सरकार मामले की लीपापोती में जुटी है। यह मामला संसद में उठेगा।

गिलुवा बोले-फिर आएगी टीम : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि मामले की जांच एवं पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए भाजपा का दल दोबारा आएगा।

एक घंटे जाम रहा एनएच 75: सांसदों को रोके जाने के बाद धरने के कारण करीब एक घंटे तक कराईकेला में चक्रधरपुर-रांची मार्ग एनएच 75 जाम रहा।

कराईकेला में धरना के दौरान भाजपा सांसदों को हाथ जोड़कर समझाते एसडीओ प्रदीप प्रसाद। जागरण

भाजपा हुई आक्रामक

राज्य ब्यूरो, रांची : बुरुगुलीकेरा गांव में हुए नरसंहार तथा सीएए के समर्थन में निकले जुलूस पर पथराव के बाद लोहरदगा में हुए बवाल पर भाजपा आक्रामक हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दोनों घटनाओं को लेकर कांग्रेस और झामुमो को निशाने पर लिया। कांग्रेस पर जहां दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया, वहीं हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकलापों पर भी सवाल उठाया।

पुलवामा में मारा गया आतंकी था पाकिस्तानी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : पुलवामा के खियू में बुधवार को मारा गया जैश-ए-मोहम्मद का दुर्दांत आतंकी सैफुल्ला है। सात साल से कश्मीर में सक्रिय सैफुल्ला पर सुरक्षा एजेंसियों ने सात लाख रुपये का इनाम रखा था। वह अबु कासिम के कोड नाम से भी वारदात को अंजाम दे रहा था।

सुरक्षाबलों ने खियू में मंगलवार को आतंकियों को मार गिराने का अभियान चलाया था, लेकिन आतंकी घेराबंदी तोड़कर भाग गए थे। इस मुठभेड़ में दो सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। अगले दिन बुधवार को सुरक्षाबलों ने खियू से करीब दो किमी आगे नगीनदर इलाके में आतंकियों को घेर लिया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में आतंकी सैफुल्ला मारा गया था, जबकि उसके अन्य साथी फिर भागने में कामयाब रहे थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2013 की शुरुआत में कश्मीर में घुसपैठ कर आया पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्ला शुरू में उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में सक्रिय रहा था।

श्रीनगर में ग्रेनेड हमला, दो सुरक्षा कर्मचारियों समेत तीन घायल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- गणतंत्र दिवस से दो दिन पहले आतंकियों की नापाक हरकत
- हमला स्थल से महज पांच किमी. दूर हुई थी फुल डेस रिहर्सल

नए जम्मू-कश्मीर में अमन के बीच चल रही गणतंत्र दिवस की तैयारियां पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। पाक समर्थित आतंकियों ने शुक्रवार को कश्मीर की फिजा में डर व जहर घोलने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के डाउन-टाउन में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एक सीआरपीएफ कर्मी, एक पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस जगह यह हमला हुआ उससे करीब पांच किलोमीटर दूर शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर को गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी। इस बीच, सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरते हुए आतंकियों की धरपकड़ के लिए सघन तलाशी अभियान चला रखा है।

खुफिया एजेंसियों ने चंद दिन पहले ही पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों को गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आतंकियों द्वारा रची जा रही हमलों की साजिश का अलर्ट जारी किया था। इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया है।

जानकारी के अनुसार, आइजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दोपहर को गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान लोगों को सुरक्षा का पूरा यकीन दिलाते हुए कहा कि आतंकियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसके करीब छह घंटे बाद ही शाम करीब सवा सात बजे आतंकियों ने डाउन-टाउन में नूरबाग, वनियार स्थित पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला किया। उस समय सीआरपीएफ और पुलिस का एक संयुक्त गश्तीदल चौकी के बाहरी गेट के पास पहुंचा था। ग्रेनेड जवानों के पास गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस हमले में सीआरपीएफ की 161वीं वाहिनी से संबंधित जवान महेंद्र सिंह, पुलिसकर्मी सरताज अहमद और नागरिक शब्बीर अहमद घायल हो गए।

हमले के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षाबलों ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया। उन्होंने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करते हुए आतंकियों की धरपकड़ के लिए एक तलाशी अभियान चलाया जो देर रात तक जारी रहा।

मनोबल

कश्मीर में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 76 फीसद रहा 12वीं का वार्षिक परिणाम, अधूरा सिलेबस पूरा करने के लिए मुहल्लों में पढ़ाया गया बच्चों को

बच्चों की कलम ने दिखाया आतंकियों को आईना

नवीन नवाज, श्रीनगर

कश्मीर के बच्चों ने अपनी काबिलियत से दिखा दिया कि वे गुमराह होने वालों में नहीं हैं। हाल ही में घोषित 12वीं कक्षा के वार्षिक परिणामों में बच्चों ने इल्म की रोशनी को अंधेरे में बदलने की साजिश करने वालों के मुंह पर तमाचा जड़ा है। गत वर्ष नवंबर में 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं हुई थीं। चार दिन पहले घोषित परिणाम में 76 फीसद बच्चे सफल रहे हैं। इससे यहां के लोगों में खुशी का माहौल है।

कश्मीर में वर्ष 2019 में अधिकांश समय स्कूलों में अलगाववादियों के हिंसक प्रदर्शनों, जिहादियों के फरमान के चलते अकादमिक गतिविधियां लगभग ठप रही हैं। पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किए जाने के बाद पहले प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शिक्षण संस्थानों को बंद रखा। हालात सुधरने पर शिक्षण संस्थानों को क्रमानुसार खोला। यह प्रक्रिया अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक जारी रही। इस बीच, जिहादी संगठनों ने कश्मीर में सभी लोगों को शिक्षण संस्थानों से दूर रहने का फरमान सुनाया। हालत यह थी कि स्कूलों में किसी जगह एक तो किसी जगह तीन छात्र नजर आते थे। इस बीच प्रशासन के बोर्ड परीक्षाओं के एलान से हर कोई हैरान था।

शिक्षाविद जीएन वार ने कहा कि अगर यहां हालात खराब नहीं होते तो परिणाम शत-प्रतिशत होता। सभी छात्र, अध्यापक और अभिभावक बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मुश्किलों की घोर आंधी में भी इल्म के चिराग को जलाए रखा। यहां बाहर से कई बुद्धिजीवी बीते साल आए तो वह कहते थे कि इन बच्चों का क्या होगा। हमने उन्हें कहा था कि बच्चों का भविष्य बचाने के लिए कश्मीरी समाज एकजुट हैं। यहां विभिन्न मुहल्लों में पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों ने ही नहीं, विभिन्न स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों और डॉक्टर-इंजीनियर कम्युनिटी स्कूलिंग का हिस्सा बने। इन लोगों ने बच्चों की न सिर्फ पढ़ाई में मदद की, बल्कि परीक्षाओं की तैयारियां भी कराईं।

कम्युनिटी स्कूलिंग का कमाल : श्रीनगर से सटे छत्तरगाम में घर में कम्युनिटी स्कूलिंग के लिए जगह देने वाले ताहिर ने कहा कि 50 बच्चे सुबह शाम आते थे। ये बच्चे आठवीं से 12वीं के छात्र थे। हम कैसे अपने बच्चों को जहालत में रहने दे सकते हैं। 12वीं का परिणाम सुखद रहा है। मेरे घर आने वाले सभी बच्चे बेहतर अंकों में पास हुए हैं।

स्कूल से पेन ड्राइव में ले आते थे लेक्चर : कॉमर्स में टॉप करने वाली इलसा गुलजार के पिता गुलजार अहमद ने कहा कि बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी। खैर, खुदा ने मदद की। कभी कम्युनिटी स्कूलिंग का सहारा लिया तो कभी स्कूल से पेनड्राइव में बेटी के लिए लेक्चर लेकर आना पड़ता था। इसी का परिणाम है कि मेरी बेटी अव्वल आई है। इलसा ने कहा कि आसपास रहने वाली सहेलियां आपस में उन विषयों पर चर्चा करतीं जो मुश्किल थे। उन पर निकट में रहने वाले अध्यापकों और कम्युनिटी स्कूल से मदद लेती थीं। आपसी मेलजोल से हुई पढ़ाई की मदद से ही वह यह मुकाम हासिल कर सकी है।

अध्यापकों ने मनोबल बढ़ाया

हुमहामा की हुमैरा रशीद ने विज्ञान में टॉप किया है। उसने कहा मैं खुदा की शुक्रगुजार हूं उसने मुझे हिम्मत दी। मेरे अध्यापकों ने मेरा मनोबल बढ़ाया और मैं किसी तरह परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार हुई। श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र बेमिना में एक स्कूल में अध्यापक आदिल अहमद ने कहा कि वह जमाना लद चुका है जब यहां जिहादियों और अलगाववादियों के डर से कोई घर से नहीं निकलता था। यह जो रिजल्ट आया है, यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ स्थानों पर तथा हिमाचल प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा तथा बर्फबारी हो सकती है। मैदानी भागों में ठंडी तेज हवाओं का असर कम होगा। छिटपुट बादलों और खिली धूप के साथ दिन का मौसम सुहावना बना रहेगा। कोहरे का असर नहीं रहेगा।

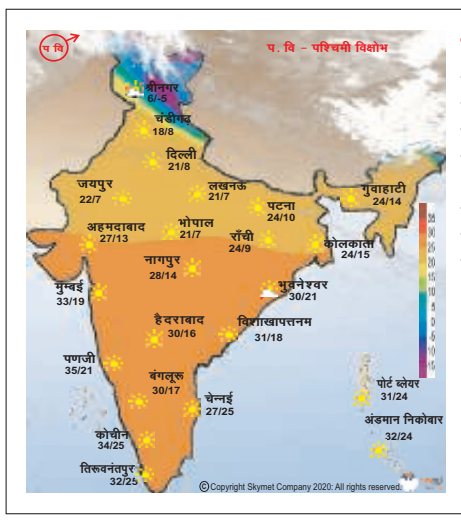

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/20/सा	अहमदाबाद	25/10/सा
कोलकाता	25/15/व	बड़ौदा	26/12/आंबा
चेन्नई	33/22/आंबा	नागपुर	29/15/आंबा
हैदराबाद	30/17/सा	इन्दौर	23/09/व
बंगलूरू	30/18/सा	रांची	31/17/सा
त्रिवेन्द्रम	33/25/सा	पटना	28/12/व
गुवाहाटी	25/14/सा	जमशेदपुर	32/18/आंबा
गंगटोक	05/-9/सा	पुणे	29/18/आंबा

15 विंचटल मछलियां मर गईं आसनसोल के एक तालाब में असामाजिक तत्वों के जहर डालने से। उन्होंने एक अन्य तालाब के किनारे लगे बंगाल के मंत्री मलय घटक के नाम के शिलापट्ट को उखाड़ दिया।

रियलिटी शो के तीन महीने बाद कलाकार कहां जाता है, पता भी नहीं चलता : शुभा

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल

राज्य ब्यूरो, जयपुर

▸ शास्त्रीय गायिका ने कहा- हम संगीत को सिर्फ फिल्म संगीत के नजरिए से देखते हैं

शुभा मुद्गल। (फाइल)

प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शुभा मुद्गल ने टीवी पर आने वाले रियलिटी शो के बारे में कहा है कि इनका फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि शो खत्म होने के तीन महीने बाद विजेता कलाकार कहां जाता है, पता भी नहीं चलता। उसे अनुबंध में बांध दिया जाता है और वह अपने संगीत को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि हम संगीत को सिर्फ फिल्म संगीत के नजरिए से देखते हैं, जबकि संगीत हमारे देश के कोने-कोने में है।

शुभा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन शुक्रवार को अपनी किताब 'लुकिंग फॉर मिस सरगम' पर आधारित सत्र में सुधा सदानंद से बात कर रही थीं। शुभा ने कॉपीराइट के विषय में कहा कि यह बहुत जटिल विषय है और हमें इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। यदि हम कहीं से कोई गीत लेकर उसे अपने तरीके से भी गा रहे हैं तो हमें कम से कम यह बताना चाहिए कि यह मूल रूप से कहां से आया है। कॉपीराइट को हमारी संगीत की तालीम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यह आज के समय में बहुत जरूरी है।

मीडिया का इतना लोकतंत्रीकरण पहले कभी नहीं हुआ: खन्ना

फेस्टिवल में अपनी किताब 'वर्ड, साउंड, इमेज' पर चर्चा करते हुए फिल्मकार अमित खन्ना ने कहा कि मीडिया का जितना लोकतंत्रीकरण इस समय हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। उनसे लेखिका शोभा डे और पत्रकार कावेरी बामजई ने बातचीत की। अमित ने कहा कि आज मीडिया और खासकर सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपनी बात कहते हैं। आपस में संवाद करते हैं। हालांकि, सोशल मीडिया कभी सामाजिक संवाद के लिए था, लेकिन इस अब इस पर बौद्धिक संवाद भी हो रहा है, जो यह बताता है कि देश क्या सोच रहा है। लेखिका शोभा डे ने कहा कि अच्छी या बुरी जो भी फिल्म बनती है, वह हमारे समाज का चेहरा दिखाती है। कबीर सिंह जैसी फिल्म यदि हिट हो रही है तो यह हमारी वजह से ही हो रही है। यह बताती है कि हम क्या देखना चाहते हैं।

फेस्टिवल की पृष्ठभूमि रचा गया जयपुर जर्नल्स : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) के 13वें संस्करण के साथ ही अब इसकी पृष्ठभूमि पर एक उपन्यास भी रच दिया गया है। फेस्टिवल की को-डायरेक्टर नमिता गोखले ने 'जयपुर जर्नल्स' नाम से यह उपन्यास लिखा है। शुक्रवार को आयोजन स्थल डिग्गी पैलेस के फ्रंट लॉन में लेखक व राजनेता शशि थरूर ने इस उपन्यास का लोकार्पण किया।

'आंखों के पानी को नदियों में भरना होगा'

ईश्वर शर्मा, जयपुर

जयराम रमेश। फाइल

पर्यावरण को लेकर हम रोते बहुत हैं। हर कोई कहता मिल जाएगा कि ग्लोबल वॉर्मिंग हो रही है। हमारी नदियां सूख रही हैं। समंदर प्रदूषित हो रहे हैं। प्रकृति परेशान हो रही है, लेकिन वह पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करता दिखाई नहीं देगा। किसी से कहो कि फेसबुक, ट्विटर पर सिर्फ बात करने के बजाय आओ पौधे लगाते हैं, तो वह बिदक जाएगा। यह रवैया ठीक नहीं है। दरअसल, हमें पर्यावरण को लेकर आंखों से पानी बहाने के बजाय आंखों के उस पानी को नदियों में भरना होगा। तभी नदियां बचेंगी, समंदर बचेंगे और बच सकेंगे हम सब। यह चिंता पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पर्यावरण को लेकर दुनियाभर में अपनी बात रखने वाले जयराम रमेश ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया से विशेष बातचीत में कही। वे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां अपनी बात रखने आए थे।

उन्होंने कहा कि भारत में पहले मानसून 120 दिन का होता था, जो जून से सितंबर तक चलता था। अब यह सिमटकर 20-30 दिन का हो गया है। मानसून के दिनों में भी बारिश कहां होती है। या तो एक साथ बहुत-सा पानी बरसकर बह जाता है या फिर बरसता ही नहीं और यह सब हम इंसानों की गलतियों के कारण है। यदि हम अब भी नहीं समझे तो प्रकृति हमें फिर समझने योग्य छोड़ेगी नहीं।

अमेरिका हमें न सिखाए कि क्या करना है : अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन, जनसंख्या विस्फोट, ग्लोबल वॉर्मिंग आदि को लेकर कई बार भारत को दोषी ठहराने के प्रश्न पर उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस हमें न सिखाएं कि प्रकृति के साथ कैसे रहा जाता है। हमारे तो हजारों वर्ष पहले लिखे गए उपनिषदों में 'प्रकृति रक्षति रक्षितः' का विचार दिया गया है, जिसका मतलब ही है कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को भारत को समझना हो तो हमारे गांवों में जाकर देखें कि आज भी लोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए जीते हैं। हमारे देवी-देवता, संस्कृति, संस्कार, पूजा-पद्धति आदि सबमें नदी, आकाश, वायु, सूर्य को देवता माना गया है। हम तो इन्हें पूजते हैं। इसलिए हमें सिखाने की कोशिश न ही की जाए तो अच्छा है।

देश जमीन का टुकड़ा नहीं, यह तो लोगों से बनता है : थरूर

जासं, जयपुर : देश क्या होता है? क्या सिर्फ जमीन के एक टुकड़े को, जिसकी भौगोलिक व राजनीतिक सीमाएं हैं, उसे देश मान लिया जाएगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता। यह तो आप-हम जैसे लाखों लोगों से मिलकर बनता है, इसलिए किसी को निकालने या किसी को ले आने की बात कहना कैसे पूरी तरह सही हो सकती है। यह बात जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कही। उन्होंने इशारों-इशारों में सीएए और एनआरसी पर अपनी बात कही। थरूर ने कहा कि राजनीतिज्ञ मुझे लेखक या बुद्धिजीवी मान लेते हैं, लेकिन जब मैं बुद्धिजीवियों में जाता हूं तो वे मुझे राजनेता मानकर बात करते हैं। सच यह है कि मैं दोनों भूमिकाओं में हूं और दोनों में नहीं भी हूं। सच पूछा जाए तो मैं राजनेता के बजाय लेखक के रूप में पहचाना जाना चाहता हूं, क्योंकि राजनेता तो भूतपूर्व हो जाते हैं, लेखक कभी भूतपूर्व नहीं होता।

न्यूज गैलरी

नित्यानंद व प्रदेश सरकार को कर्नाटक हाई कोर्ट का नोटिस

बेंगलुरु (कर्नाटक) : कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी नित्यानंद और राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। हाई कोर्ट शुक्रवार को के. लेनिन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें नित्यानंद को प्रदान की गई जमानत रद करने की मांग की गई है। नित्यानंद के अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं होने और देश छोड़कर भागने को याचिका में आधार बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि नित्यानंद निचली अदालत में खुद को इस तरह प्रस्तुत कर रहा है जैसे वह अभी भी भारत में है जबकि वह वैधता अवधि समाप्त हो चुके पासपोर्ट पर देश छोड़कर भाग चुका है। उसका पता लगाने के लिए गुजरात पुलिस के अनुरोध पर इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। (एएनआइ)

मध्य प्रदेश में चिंकारा का शिकार, दो गिरफ्तार

छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन में स्थित कुंभपानी रेंज में गुरुवार रात चार शिकारियों ने चिंकारा (हिरण की एक प्रजाति) का शिकार किया। वन अमले ने मौके से दो शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुंभपानी रेंजर मानसिंह परते के मुताबिक, देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि लोहार बथरी गांव के एक खेत में कुछ शिकारी बैठे हैं। अमले ने घेराबंदी कर आरोपित दौलत सिंह मेंहदोले और रमेश लोंदरे निवासी ग्राम हिवरा जयसिंह को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथी भागचंद विश्वकर्मा और जगदीश सरेयाम फरार हो गए। इन आरोपितों ने करीब छह साल के नर चिंकारा का शिकार कर लिया था। उनसे चिंकारा का शव, दो बाइक, एक बंदूक, कारतूस, एक चाकू और जाल जब्त किया है। चारों आरोपितों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। रेंजर ने बताया कि आरोपित आदतन अपराधी हैं और मांसाहार के लिए वन्यप्राणियों का शिकार करते हैं। (नईदुनिया)

41वें दिन भी जारी रहा साध्वी पद्मावती का अनशन

हरिद्वार : गंगा रक्षा समेत छह सूत्री मांगों को लेकर अनशन (तपस्या) कर रहीं साध्वी पद्मावती के स्वास्थ्य में गिरावट आई है। शुक्रवार को किए गए स्वास्थ्य परीक्षण में साध्वी के वजन में एक किलोग्राम की कमी दर्ज की गई है। अब उनका वजन घटकर 47 किलोग्राम हो गया है। अनशन की अवधि में साध्वी का सात किलो वजन कम हो चुका है। उधर, जगजीतपुर स्थित मातृसदन आश्रम में साध्वी पद्मावती का अनशन 41वें दिन भी जारी रहा। (जासं)

अब दांतों के डॉक्टर करेंगे सर्दी-बुखार का इलाज

पहल ▸ एलोपैथी डॉक्टरों की कमी को देखते हुए केंद्र उठा रहा कदम

तीन साल के ब्रिज कोर्स के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में होगी नियुक्ति

नईदुनिया, भोपाल

देशभर में एलोपैथी चिकित्सकों की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दांत के डॉक्टरों (डेंटिस्ट) को तीन साल का ब्रिज कोर्स कराकर प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ करने की तैयारी है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआइ) ने यह प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा है। इस पर निर्णय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) को लेना है। एमसीआइ की जगह नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बनने के कारण इसमें समय लग रहा है। एनएमसी की हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यह कोर्स शुरू करेगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यह कोर्स शुरू करेगा। प्रतीकात्मक

कोर्स शुरू करने के पहले एक कमेटी बनाकर कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इस कमेटी में एमसीआइ, डीसीआइ के अफसर रहेंगे। पाठ्यक्रम में साधारण बीमारियों में उपयोग होने वाली दवाओं, इन बीमारियों की जांच, गैर संचारी रोग जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक आदि की स्क्रीनिंग, केंद्र व राज्य सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा।

डेंटिस्टों को तीन साल का ब्रिज कोर्स कराने का प्रस्ताव है। एमसीआइ की जगह नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बन गया है। कमीशन ठीक से काम संभाल लेगा, इसके बाद इस प्रस्ताव पर निर्णय होगा।
-दिव्येंदु मजूमदार, प्रेसीडेंट, डीसीआइ

प्रदेश में हर साल एक हजार डेंटिस्ट पंजीकृत

मध्य प्रदेश में निजी और सरकारी डेंटल कॉलेजों की संख्या 15 है। यहां से निकलने वाले डॉक्टरों में हर साल करीब एक हजार मध्य प्रदेश डेंटल काउंसिल में पंजीयन कराते हैं। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में दंत रोग विशेषज्ञों के पद कम होने से उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। निजी अस्पतालों में भी उनके लिए अवसर कम हैं।

तमिलनाडु में पेरियार की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, नेताओं ने निंदा की

चेन्नई, प्रेट्र : कांचीपुरम जिले में ईवी रामासमय पेरियार की प्रतिमा क्षतिग्रस्त पाई गई। तमिलनाडू के राजनीतिक नेताओं ने इसकी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने कहा कि सुबह सलावक्कम में प्रतिमा क्षतिग्रस्त मिलने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। द्रमुक नेता एमके स्टालिन ने कहा कि पेरियार की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करना शर्मनाक है। राज्य सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। राज्य के पुलिस महानिदेशक एलके त्रिपाठी ने पेरियार या अन्य किसी नेता की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने में संलिप्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पीएमके नेता एस. रामदास ने कहा कि इससे शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। भाकपा के प्रदेश सचिव आर मुतारसन और एएमएमके नेता टीटीवी दिनाकरण ने भी तोड़फोड़ की निंदा की है।

यह घटना तमिलनाडु में छिड़ी एक नई बहस के बीच हुई है। अभिनेता रजनीकांत ने पिछले सप्ताह द्रविड़ नेता की 1971 की रैली के बारे टिप्पणी कर विवाद को जन्म दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रजनीकांत के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका द्रविड़ विधुतलै कषगम ने दायर की थी। कोर्ट ने हैरत जताई कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के 15 दिनों के भीतर याची कोर्ट क्यों पहुंचा है। तमिल पत्रिका तुगलक की ओर से 14 जनवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में रजनीकांत ने कहा था कि सलेम में 1971 में पेरियार ने रैली निकाली थी जिसमें उन्होंने भगवान श्रीराम और सीता की नग्न प्रतिमा रखी थी। उनकी प्रतिमा को चंदन की माला पहनाई गई थी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक पार्टी उतारने में जुटे अभिनेता ने माफी मांगने से मना कर दिया है।

पेरियार की क्षतिग्रस्त प्रतिमा। एएनआइ

अब खुद ही पटरियां बनाएगा रेलवे

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद : रेल प्रशासन पटरी का निर्माण स्टील फैक्ट्री से कराने के बजाय अब खुद करने जा रहा है। इससे तेज गति से ट्रेन संचालन के लिए पुरानी लाइन बदलने के काम में तेजी आएगी। मुरादाबाद रेल मंडल के रोजा में वर्कशॉप तैयार हो गई है। पटरी का निर्माण जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में स्टील फैक्ट्री में कच्चा लोहा पिघलाकर पटरी के लिए सिल्ली तैयार की जाती है। उसके बाद फैक्ट्री की दूसरी यूनिट में लाकर 50 मीटर की पटरी का निर्माण किया जाता है। अन्य काम करने के कारण स्टील फैक्ट्री में पटरी के निर्माण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा रेल प्रशासन को पटरी बदलने जोड़ने में अधिक समय लगता है। इसके चलते पटरी बदलने का काम धीमी गति से चल रहा है। रेलवे को हर साल देशभर में दो लाख किलोमीटर रेललाइन की आवश्यकता होती है, जबकि स्टील फैक्ट्री से 75 हजार किलोमीटर से भी कम की पटरी ही मिल पाती है।

रोजा में वर्कशॉप तैयार : रेल प्रशासन स्टील फैक्ट्री से तैयार लोहे की सिल्ली खरीदेगा और रोजा वर्कशॉप में उससे पटरी का निर्माण किया जाएगा। यहां 130 से 150 मीटर तक रेललाइन का निर्माण हो सकेगा। पटरी बदलने के बाद 50-50 मीटर की पटरी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।

आधार, शादी, हड़ताल भी अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हर साल की तरह इस साल भी कुछ हिंदी शब्दों को अंग्रेजी के अपने विश्वविख्यात शब्दकोष में जगह दी है। अपने नए संस्करण में हिंदी के कुछ ऐसे प्रचलित शब्दों को शामिल किया गया है जिसका इस्तेमाल देश में अंग्रेजी और हिंदी भाषी दोनों ही लोग आमतौर पर करते हैं। जैसे-आधार, चॉल, डब्बा, हड़ताल और शादी। डिक्शनरी के दसवें संस्करण को शुक्रवार को लांच किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 10वें संस्करण में 384 भारतीय अंग्रेजी शब्द हैं और 1000 से अधिक नए शब्दों को शामिल किया गया है। जैसे-चैटबॉट, फेक न्यूज और माइक्रोप्लास्टिक। इसके अलावा नए संस्करण में नए शब्दों जैसे आंटी, बस स्टैंड, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एफआइआर, नॉन वेज रिड्रेसल, ट्यूब लाइट, वेज और वीडियोग्राफ शामिल हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एडिशन में चार शब्द जैसे करंट, लूटर, लूटिंग और उपजिला शामिल हैं।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (ओयूपी) के मुताबिक, डिक्शनरी में हमेशा भाषाओं के बदलाव पर ध्यान दिया जाता है और कोशिश रहती है कि नए संस्करण में उन शब्दों को शामिल किया जाए जो प्रांसगिक हों और साथ ही समय के साथ अपडेट हों।

मस्जिद के लिए भूमि दिए जाने पर आपत्ति नहीं, लेकिन राम मंदिर से समुचित दूरी पर

रघुवरशरण, अयोध्या

▸ मस्जिद के लिए प्रस्तावित भूमि के हिसाब-किताब में उलझे संत

▸ अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से बाहर ही जमीन देने पर सहमति

रामजन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ मस्जिद निर्माण को लेकर उत्सुकता बयां हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मस्जिद के लिए पांच एकड़ भूमि दिए जाने में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कहां हो इस पर विमर्श छिड़ा है। विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा के अनुसार हम सभी कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन मस्जिद के लिए जमीन मुकर्रर करने में रामनगरी की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। कोशिश यह होनी चाहिए कि मस्जिद के लिए भूमि अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से बाहर हो।

आचार्य पीठ दशरथमहल बड़ास्थान के महंत बिंदुगाद्याचार्य देवेंद्र प्रसादाचार्य का मानना है कि सनातनियों की नगरी अयोध्या की आस्था के केंद्र में भगवान राम हैं। ऐसे में आस्था का कोई अन्य केंद्र विकसित करने के लिए यह ध्यान रखना होगा कि उसकी राम मंदिर से समुचित दूरी हो। जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य के अनुसार अयोध्या में पहले से ही अनेक मस्जिदें हैं। एक और मस्जिद बन जाने से रामनगरी के तौर पर अयोध्या की मर्यादा आहत होने की आशंका निराधार है। फिर भी मस्जिद के लिए भूमि का चयन करने में यह जरूर ध्यान रखना होगा कि उसके निर्माण से कोई व्यावहारिक दिक्कत न खड़ी होने पाए। शीर्ष पीठ रामवल्लभाकुंज के अधिकारी राजकुमारदास कहते हैं, अच्छा हो कि मस्जिद का निर्माण 14 कोसी परिक्रमा की परिधि से बाहर किया जाए। इसके पीछे दुराव की भावना न होकर व्यवस्था का सवाल है। इस व्यवस्था में सभी को सहयोग करना होगा। पौराणिक महत्व की पीठ नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास कहते हैं कि मंदिर हो या मस्जिद, दोनों भगवान का घर हैं। जब व्यवस्था नए सिरे से बनने को है, तब इस बात का ध्यान जरूरी है कि भविष्य में कोई दिक्कत न खड़ी हो। समाजसेवी एवं आचार्य पीठ तिवारी मंदिर के महंत गिरीशपति त्रिपाठी कहते हैं, मस्जिद होना कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन भूमि चयन में सावधानियां बरती जाएं।

मस्जिद के पक्षकार रहे मुहम्मद इकबाल चाहते हैं कि जिस कोटिया मुहल्ले में उनका आवास है, वहां स्थित बिजली शहीद मस्जिद को विस्तार दिया जाए। इस मस्जिद के इर्दगिर्द खाली पड़ी पांच एकड़ भूमि का हवाला देते हैं। इस आशंका को निर्मूल ठहराते हैं कि मस्जिद से रामनगरी की मर्यादा पर आंच आएगी।

गुजरात की वीणा बनीं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने गुजरात की किन्नर वीणा कुंवर को महामंडलेश्वर घोषित किया है। बताया कि उनका पट्टाभिषेक हरिद्वार कुंभ-2021 में होगा। शुक्रवार को माघ मेला क्षेत्र में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि वीणा गुजरात में किन्नर समाज की स्तंभ हैं। उनके जुड़ने से संगठन में मजबूती आएगी। किन्नरों की समस्याएं भी कम होंगी। अलोपीबाग स्थित भगवान शंकराचार्य आश्रम में पहुंचकर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और नवनियुक्त महामंडलेश्वर वीणा कुंवर ने स्वामी वासुदेवानंद का आशीर्वाद लिया। स्वामी वासुदेवानंद ने कहा कि किन्नर अखाड़े को मजबूत होना आवश्यक है।

'वकीलों को मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार नहीं'

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वकीलों को मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) प्रयागराज में केंद्र सरकार के मुकदमों के इंचार्ज द्वारा केंद्र सरकार के अन्य अधिवक्ताओं को केसों के आवंटन में अनियमितता के आरोप को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने कहा कि याचीगण केंद्र सरकार के अधिवक्ता हैं, उन्हें अपने मुवक्किल भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं है। यह कदाचार है। दूसरे अधिवक्ताओं के बीच केस आवंटन का विवेकाधिकार केंद्र सरकार या उसके अधिकृत स्थायी अधिवक्ता को है। कोर्ट ने कहा कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उससे याचीगण पीड़ित पक्ष नहीं है। इस आदेश से न्यायाधिकरण ने मुकदमों के दाखिले से पूर्व वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता को नोटिस देने का निर्देश दिया है। इससे याचियों के किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले केंद्र सरकार के वकीलों के खिलाफ कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिका दिग्भ्रमित होने के कारण दाखिल होने पर पोषणीय नहीं है। साथ ही अपने मुवक्किल के खिलाफ याचिका दाखिल करने के कदाचार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 की नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना।
ओए नं. 477/2019/डीआरटी-III के मध्य में
बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम अमित भटनागर एवं अन्य
आवेदक प्रतिवादी
To,
D-1 अमित भटनागर पुत्र श्री रविशंकर भटनागर
D-2 श्रीमती पुष्पा भटनागर पत्नी अमित भटनागर, दोनों निवासी: [illegible]
D-3 पै. इन्नति फानून होल्डिंग लि., [illegible]
यहां भी: [illegible]
यहां भी: [illegible]
उपरोक्त आवेदन अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है और उपरोक्त अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत आपको यह सूचित किया जाता है कि आपको इसे प्रतिवाद करना संभव नहीं है। इसलिए, विज्ञापन के जरिए आपको यह निर्देश देते हुए सूचित किया जाता है कि 30.03.2020 को प्रातः 10.30 बजे इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे।
ध्यान दें कि इस अधिसूचना में उल्लेखित तिथि को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में, मामले की सुनवाई के बाद आपकी अनुपस्थिति में फैसला हो जाएगा।
मेरे हाथ एवं इस अधिकरण की मुहर आज दिनांक 18 दिसंबर, 2019.
अधिकरण के आदेशानुसार
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 की नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की धारा ऋण की वसूली की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना।
ओए नं. 476/2019/डीआरटी-III
बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम मनीष कुमार शर्मा एवं अन्य
आवेदक प्रतिवादी
To,
D-1 मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री ज्ञान चन्द्र शर्मा
D-2 श्रीमती सोनिया शर्मा पत्नी मनीष शर्मा, दोनों का निवास: [illegible]
D-3 पै. इन्नति फानून होल्डिंग लि., [illegible]
उपरोक्त आवेदन अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है और उपरोक्त अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत आपको यह सूचित किया जाता है कि आपको इसे प्रतिवाद करना संभव नहीं है। इसलिए, विज्ञापन के जरिए आपको यह निर्देश देते हुए सूचित किया जाता है कि 30.03.2020 को प्रातः 10.30 बजे इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे।
ध्यान दें कि इस अधिसूचना में उल्लेखित तिथि को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में, मामले की सुनवाई के बाद आपकी अनुपस्थिति में फैसला हो जाएगा।
मेरे हाथ एवं इस अधिकरण की मुहर आज दिनांक 18 दिसंबर, 2019.
अधिकरण के आदेशानुसार
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

श्रद्धा

भोर के शंखनाद के साथ शुरू हुआ स्नान, स्नानार्थियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई

मौनी के महास्नान को संगम में आस्था का महासागर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

मौनी अमावस्या पर शुक्रवार को त्रिवेणी तट पर आस्था और आनंद का भी संगम हुआ। पतितपावनी गंगा, श्यामल यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पुण्य की डुबकी लगाने जनसैलाब उमड़ पड़ा था। मेला प्रशासन ने दावा किया कि शुक्रवार शाम तक एक करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। स्नानार्थियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई जा रही थी। अलौकिक आनंद के बीच शुक्रवार भोर से ही संत-महात्माओं के साथ श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगाने लगे थे। ज्यादातर श्रद्धालुओं ने शुभ मुहूर्त में मौन की डुबकी लगाई। सुबह होते-होते स्नान घाट श्रद्धालुओं से पैक हो गए। स्नान के दौरान खिली धूप श्रद्धालुओं के लिए सोने पे सुहागा साबित हुई। शाम तक स्नान, ध्यान और दान का सिलसिला चलता रहा।

लगभग 25 सौ बीघा में फैले मेला क्षेत्र में हर ओर श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। सभी 20 स्नान घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध दिखे।

माघ मेला के मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर शुक्रवार को संगम तट पर आस्था का महासागर उमड़ा नजर आया। संगम नोज पर आस्था की हिलोर ऐसी उठी कि हर मन भाव विभोर हो गया। शरद मालवीय

श्रद्धालु गुरुवार से संगम की रेती पर पहुंचने लगे थे। अन्नक्षेत्र में दिन भर भंडारा चला। शहर में भी चाय, नाश्ता के साथ ही भंडारे का आयोजन रहा था।

मंदाकिनी तट पर उमड़ी आस्था : चित्रकूट तीर्थक्षेत्र में तड़के से लाखों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी के राम घाट पर स्नान, दान व पूजा-अर्चना की। आस्था के सैलाब के बीच हर-हर गंगे की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया। गुरुवार सुबह से शुरू मेले में शुक्रवार को पूरे दिन भीड़ रही। मंदाकिनी स्नान व कामदगिरि परिक्रमा का विशेष महत्व होने के कारण श्रद्धालु शुक्रवार तड़के से जयघोष के साथ आगे बढ़ते रहे। साथ ही हनुमानधारा, स्फटिक शिला, सती अनुसुइया आश्रम, गुप्त गोदावरी के समेत मठ-मंदिरों में दर्शन किए।

काशी में मौन का डंका

वाराणसी : अमावस्या पर शुक्रवार भोर से गंगा तट पर मौन का डंका और श्रद्धा की हिलोरें थीं। मौन साधे, परंपराओं की पोटली हृदय में दाबे हजारों-हजार लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। दर्शन-पूजन किया और यथा शक्ति दान कर पुण्य बटोरा। गंगा की हिलोरें स्नार्थियों और घाट पर खड़े लोगों को तक को विभोर कर रहीं थीं। ठंड में कांपते हाथ पर अजुरी भर-भर अर्घ्य दान कर व्यथा पीड़ा प्रभु चरणों में धर दी। प्रदक्षिणा की पोटली से तिल, चावल, गरम वस्त्र, कंबल आदि का दानकर पुरोहितों को दक्षिणा दी। महात्म्य के अनुसार दशाश्वमेध घाट पर सर्वाधिक भीड़ तो शीतला घाट, सिंधिया घाट, भैंसासुर घाट समेत विभिन्न घाटों पर भी तिल रखने की जगह नहीं। लोगों रामेश्वर पंचक्रोश धाम में वरुणा में भी स्नान किया। श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, काल भैरव, मृत्युंजय महादेव, बड़ा गणेश समेत विभिन्न देवालयों में दर्शन पूजन भी किया।

दैनिक जागरण

चेतना अंतर्मुखी होते ही दैवी शक्ति आ जाती है

राजनीति का अपराधीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को ऐसे तौर-तरीके तैयार करने के निर्देश देकर राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में एक बड़ी पहल की है जिससे आपराधिक अतीत वालों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। यह पहल अंजाम तक पहुंचनी ही चाहिए, क्योंकि तमाम उपायों के बावजूद राजनीति में आपराधिक इतिहास वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके चलते भारतीय लोकतंत्र को गंभीर क्षति पहुंच रही है। जब आपराधिक प्रवृत्ति वाले विधानमंडलों में पहुंचते हैं तो वे केवल इन सदनों की गरिमा ही नहीं गिराते, बल्कि कानून एवं व्यवस्था के साथ लोकतंत्र का उपहास भी उड़ाते हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि जिन पर कानून एवं व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के संगीन आरोप हों वही कानून बनाने का काम करें। आखिर यह स्थिति लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महसूस किया कि नामांकन दाखिल करते समय अपने आपराधिक मामलों का विवरण देने की बाध्यता से बात बन नहीं रही है। कटु सच्चाई यही है कि ऐसे लोग चुनाव जीतने में समर्थ हैं जो आपराधिक मामलों का सामना कर रहे होते हैं। ऐसे लोग एक तो यह प्रचारित करने में सक्षम रहते हैं कि उन पर चल रहे मामले बदले की राजनीति का नतीजा हैं और दूसरे छल-छद्म से जाति-संप्रदाय का सहारा लेने में कामयाब हो जाते हैं।

निर्वाचन आयोग न जाने कब से यह कह रहा है कि कम से कम उन्हें तो चुनाव लड़ने से रोका ही जाए जिनके खिलाफ ऐसे मामलों में आरोप पत्र दायर हो चुका हो जिनमें पांच साल से अधिक की सजा हो सकती है। दुर्भाग्य से यह आड़ लेकर इस सुझाव की अनदेखी हो रही है कि दोष सिद्ध न होने तक व्यक्ति को निर्दोष ही माना जाना चाहिए। यह आड़ तब ली जा रही है जब हर कोई इस सच से अवगत है कि रसूख वाले लोग अपने मामलों की अदालती प्रक्रिया को किस तरह लंबा खींचने में कामयाब रहते हैं? राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के जो अनेक उपाय निर्वाचन आयोग समय-समय पर रेखांकित करता रहा है उन्हें दैनिक जागरण अपने जन जागरण अभियान के तहत जनता तक पहुंचाता रहा है। आम लोग वही चाहते हैं जो निर्वाचन आयोग चाहता है। चूंकि देश का जनमत राजनीति के अपराधीकरण से आजिज आ चुका है इसलिए यह अपेक्षित ही नहीं आवश्यक भी है कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हो। आपराधिक तत्वों को चुनाव प्रक्रिया से इसलिए हर हाल में दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही लोकतंत्र के प्रति आम आदमी की आस्था को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकता है।

मौत पर सियासत

दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत! बहिबल कलां गोलीकांड के मुख्य गवाह एवं पूर्व सरपंच सुरजीत सिंह की मौत के मामले में पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल की स्थिति कुछ ऐसी ही है। दोनों इस संवेदनशील मामले पर राजनीति भी कर रहे हैं और खुद को पीड़ित परिवार का हमदर्द बताने की होड़ में एक-दूसरे पर राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। वैसे तो धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी और उसके बाद हुए इस गोलीकांड का यह मामला पंजाब में पिछले पांच साल से सियासत के मुख्य मुद्दों में रहा है, लेकिन इस तरह किसी की मौत पर भी अगर सियासी रोटियां सेंकने की कवायद हो तो दलों एवं नेताओं की नैतिकता पर अंगुली उठनी स्वाभाविक है। ऐसा लगता है कि सियासी दल इस तरह के मुद्दों पर अपना हित साधने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उन्हें इसका अहसास ही नहीं होता कि वे जो कह रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं उन्हें जनता किस नजरिये से देखेगी। यह अत्यंत दुखद है कि सुरजीत सिंह की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, लेकिन इसे एक सामान्य घटना के तौर पर भी नहीं लिया जा सकता। उसकी पत्नी जसबीर कौर के उन आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिनमें उसने कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ और फरीदकोट के विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। यह जांच का विषय है कि क्या वाकई उस पर गवाही को लेकर दबाव डाला जा रहा था? अगर ऐसा था तो यह गंभीर व चिंताजनक पहलू होगा। सत्ता पक्ष के विधायक व सरकार के मंत्री पर आरोप लगेगा तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही। जाहिर है कि अकाली दल ने भी इसी का सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है। कितना अजीब लगता है कि दोनों दलों के नेता सुरजीत सिंह की मौत पर शोक व्यक्त करने आते हैं, लेकिन वहां निशाना एक-दूसरे पर साधते हैं। सुखबीर जहां मंत्री व विधायक पर केस दर्ज किए जाने की मांग कर रहे हैं, वहीं कांगड़ सुखबीर पर हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए। जो भी हो, इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। मौत पर कोरी सियासत ठीक नहीं।

किसी की मौत पर भी अगर सियासी रोटियां सेंकने की कवायद हो तो दलों व नेताओं की नैतिकता पर अंगुली उठनी स्वाभाविक है। सियासी दल इस तरह के मुद्दों पर अपना हित साधने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं

नए तेवर वाली विदेश नीति

हर्ष वी पंत

विदेश नीति के लिए मोदी ने जो खाका खींचा है उसमें भले ही कुछ खतरे हों, लेकिन सरकार उनका सामना करने को तैयार दिखती है

अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से दावोस में कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जैसी दो टूक प्रतिक्रिया व्यक्त की उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय विदेश नीति में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल जैसी ऊर्जा न केवल कायम रहने वाली है, बल्कि वह अपने नए तेवर दिखाने को भी तैयार है। अपनी सरकार की दोबारा कमान संभालते ही मोदी ने विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपना महत्वाकांक्षी खाका खींचने में देरी नहीं की। उन्होंने विदेश मंत्री जैसे प्रमुख राजनीतिक पद पर पूर्व राजनयिक एस जयशंकर की नियुक्ति करके तमाम लोगों को हैरान किया, मगर इसने विदेश नीति को लेकर उनकी गंभीरता को भी व्यक्त किया। यह नियुक्ति करते समय शायद उन्हें वैश्विक मोर्चे पर उथल-पुथल का बखूबी भान था जिसमें भारतीय विदेश नीति को अपनी प्राथमिकताएं तय करना बेहद जरूरी था। इसके लिए किसी मंझे हुए कूटनीतिज्ञ की दरकार थी। जयशंकर की नियुक्ति के साथ ही मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि विदेश नीति उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में होगी। यह जरूरत तब और ज्यादा महसूस हुई जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया। चूंकि यह मसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित हो गया इसलिए भारतीय पक्ष को बेहतर तरीके से रखना जरूरी था। वैश्विक बिरादरी को यह समझाना बेहद आवश्यक था कि भारत ने यह फैसला किन परिस्थितियों में उठाया। इसमें जयशंकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही।

विदेश नीति के व्यापक मोर्चे को देखें तो भारत बड़ी शक्तियों को साधने और दुनिया के तमाम अन्य कोनों में अपनी पैठ बनाने में जुटा हुआ है। पिछले साल आभास हुआ कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मुश्किल दौर में हैं। अमेरिका ने भारत को मिला जीएसपी का दर्जा छीन लिया था। इसके पीछे यही वजह बताई गई कि भारत इसके बदले अपने बाजार में अमेरिका को उचित अवसर प्रदान नहीं कर रहा। अमेरिका ने भारत से होने वाले शुल्क मुक्त निर्यात की राह मुश्किल बनाने के साथ ही इस्पात एवं एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। भारत ने भी अमेरिकी बादाम एवं सेब जैसे 28 उत्पादों के लिए आयात शुल्क बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई की।

इसके बाद सितंबर में मोदी के अमेरिकी दौरे में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहयोगी के साथ कारोबारी रिश्तों पर जमा बर्फ कुछ पिघली। वहां मोदी ने वाशिंगटन को यही संदेश दिया कि परस्पर लाभ के किसी भी समझौते के आधार पर नई दिल्ली व्यापक सक्रियता के लिए तैयार है। ट्रंप को आश्वस्त कर उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों में गिरावट को थामा। साथ ही कश्मीर के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आशंकाओं को भी दूर किया। यह मोदी का दौरा ही था कि भले ही दोनों पक्ष किसी अहम व्यापार समझौते को लेकर सहमत नहीं हो पाए हों, लेकिन भारत को लेकर ट्रंप के सुर अवश्य सकारात्मक रूप से बदल गए और अब इसके आसार दिखने लगे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ सकते हैं।

अवधेश राजपूत

चीन के साथ सक्रियता बढ़ाने की दिशा में भी मोदी के प्रयास जारी रहे। इसी सिलसिले में मामल्लपुरम में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ दूसरी अनौपचारिक बैठक हुई। इससे पहले 2018 में डोकलाम गतिरोध के बाद इस कड़ी में चीन के वुहान में हुई पहली बैठक में दोनों के बीच तल्खी कुछ कम हुई थी। नई दिल्ली में अब यह स्वीकृति आम होती जा रही है कि चीन भारतीय हितों पर आघात करने की कूटनीतिक एवं राजनीतिक कीमत चुकाने से परहेज नहीं कर रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसा मंच इसका गवाह बना जहां चीन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहा। भारत और चीन के बीच तमाम मतभेदों के बावजूद भारत के लिए चीन के साथ लगातार सक्रियता बढ़ाना बेहद जरूरी है।

पिछले साल सितंबर में ही रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। उस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय रिश्तों को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई गति देना था। इसी तरह पूर्वी आर्थिक मंच पर मोदी की मौजूदगी भी कई पहलुओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसे वक्त में जब वैश्विक आर्थिक धुरी एशिया की ओर केंद्रित होती दिख रही है उसे देखते हुए पुतिन एशियाई शक्तियों की सहायता से अपने पूर्वी इलाकों को विकसित बनाने पर जोर दे रहे हैं। रूस के इस इलाके में फिलहाल चीन का बढ़ता दबदबा मास्को को असहज कर रहा है। इसीलिए पुतिन चीन पर निर्भरता घटाने के प्रयास में भी जुटे हैं। भारतीय निवेशकों को भी वहां बढ़िया अवसर मिलेंगे।

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने में जुटी है ताकि वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय हितों की अधिकाधिक पूर्ति हो सके। इस रणनीति की छाप दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देशों से लेकर हिंद महासागरीय देशों, हिंद-प्रशांत देशों और पश्चिम एशियाई देशों तक दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं अपने हितों पर प्रहार करने वाले देशों को भारत अपनी आर्थिक मजबूती का अहसास कराने से भी गुरेज नहीं कर रहा। जैसे अनुच्छेद 370 पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने भारत का विरोध किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल अपना पहला तुर्की दौरा तत्काल रद किया, बल्कि भारत में प्रतिरक्षा संबंधी कारोबार में जुटी एक तुर्की कंपनी पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। मलेशिया को भी इसकी तपिश झेलनी पड़ रही है। भारतीय विदेश नीति निरंतर उभार ले रही है। वैश्विक शक्ति संतुलन में उभर रहे किसी देश के लिए यह बहुत स्वाभाविक भी है। इस दृष्टिकोण की पुष्टि जयशंकर के हाल के उस भाषण से भी होती है जिसमें उन्होंने कहा था कि 'भारत बदलाव के इस दौर में और अधिक आत्मविश्वास के साथ खड़ा है और महाशक्ति बनने की हसरत रखने वाला कोई देश सीमाओं के अस्पष्ट रेखांकन, छिन्न-भिन्न क्षेत्र और अवसरों को भुनाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इससे भी बढ़कर वह देश बदलते वैश्विक ढांचे को लेकर अड़ियल नहीं बना रह सकता।'

साफ है कि मोदी सरकार विदेश नीति के लिए खींचे अपने खाके पर आगे ही बढ़ेगी। इसमें कई परंपरागत नीतियों से पलटना भी पड़ सकता है जिसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि महाशक्ति बनने के लिए नई दिल्ली वह कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है।

(लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

अनुशासन मांगता है गणतंत्र

गिरीश्वर मिश्र

समानता, बंधुत्व, समरसता के लक्ष्य को पाने के लिए सबको एकजुट होकर काम करना होगा

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की फलश्रुति के रूप में देश ने संविधान को अंगीकार कर अपने भाग्य को उसके साथ 26 जनवरी, 1950 को जोड़ दिया। इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 'राम राज्य' का नक्शा होना था जिससे एक स्वाबलंबी समाज में हर सक्षम हाथ को काम, देश के निर्माण में सहयोग की अनुभूति, स्वस्थ जीवनशैली, प्रकृति का आदर, स्वार्थ की जगह लोक-हित की स्थापना, आवश्यकतानुरूप धन-संचय, बुद्धि, हृदय और शरीर तीनों के लिए शिक्षा, विकेंद्रीकृत शासन और अधिकाधिक जन-भागीदारी के अवसर की कल्पना की गई थी, पर जो सरकार बनी वह इन सबको अव्यावहारिक करार देते हुए इनसे दूर हटती गई। देश को आगे ले जाने का जो सपना देश के रहनुमाओं ने देखा उसके तहत ऐसा हो न सका। सात दशक बाद यह विचारणीय हो जाता है कि हम अपनी अब तक की यात्रा को टटोलें और देखें कि क्या भूल चूक हुई और अब हमारे पास क्या विकल्प हैं? महात्मा गांधी निःसंदेह संपूर्ण भारतीय समाज के सच्चे प्रतिनिधि थे। इस बार का गणतंत्र दिवस बापू की स्मृति की सघन छाया तले मनाया जा रहा है, लेकिन समस्या यह है कि हम सब महात्मा गांधी का प्रतीक तो चाहते हैं, परंतु उनके विचारों और व्यावहारिक सुझावों से दूरी भी बनाए रखना चाहते हैं। इस दुविधा का दुष्परिणाम यह है कि महात्मा गांधी कुछ अनुष्ठानों के विषय भर रह गए हैं।

वैश्विकता के दौर में आज हमारे सोच-विचार के पैमाने बदल गए हैं। हम एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं, जिसका कोई ओर-छोर नहीं दिख रहा है। आज हम मनुष्य और प्रकृति, दोनों के साथ बर्बर हुए जा रहे हैं। हिंसा का उन्माद चारों ओर फैल रहा है। गांधी जी ने हिंसा को प्रेम के रूप में परिभाषित किया था। वह अहिंसा में स्नेह और सख्य भाव को देखते थे। पारस्परिक निकटता और सौहार्द उसका स्वाभाविक परिणाम था तथा संवाद उसका माध्यम। आज समाज और देश के सरोकार पृष्ठभूमि में जा रहे हैं। हम अपने उन उत्तरदायित्वों से कटते गए हैं जो स्वतः हमसे जुड़े थे। हमसे अपेक्षा थी कि हम उनको व्यवहार में लाएंगे, लेकिन बड़े प्रयास से हमने जो संविधान बनाया था उससे छूट लेते गए। पिछले सत्तर वर्षों में हमने इसमें एक सौ तीन संशोधनों को स्वीकार किया है। इनमें कई निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्वीकार किए गए।

'हिंद स्वराज' में वर्णित बापू के सपनों का भारत

मनुष्य की बुनियादी संरचना एवं सभ्यता, उसकी आवश्यकताओं और सामाजिक सक्रियता और उत्पादकता से जुड़ा था। आज मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी दिनचर्या से जुड़ी बीमारियों का व्यापक प्रसार सबका ध्यान खींच रहा है। श्रम स्वास्थ्य और उत्पादकता दोनों ही दृष्टियों से आवश्यक है। उसका विनियोग अर्थव्यवस्था के लिए हितकर है। इसीलिए बापू ने शिक्षा में शुरू से ही श्रम और हस्त कौशल को स्थान दिया। हाथ, हृदय और मस्तिष्क के संतुलन वाली नई तालीम का यही उद्देश्य था। शिक्षा जीवनोपयोगी होनी चाहिए। आज शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को देखकर सभी दुखी और त्रस्त हैं। गांधी जी परिवर्तनों के साथ जीवनशैली को बदलना चाहते थे। वे जानते थे कि कहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो चाहते हैं उसे करना ही सही तरीका है। जो परिवर्तन हम चाहते हैं उसे हमें जीना भी चाहिए। हमने संविधान में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाईं जिससे सबकी भलाई हो, परंतु उन्हें लागू कर पाने में काफी हद तक नाकामयाब रहे। क्षुद्र स्वार्थों में फंसकर गलत ढंग से लाभ उठाना जायज होता गया। नैतिकता के प्रश्न से परे लगने लगा। आर्थिक भ्रष्टाचार के अनेक रूप पनपने लगे। आर्थिक उदारीकरण में जो भागीदार हुए उसमें कइयों ने नियमों-कानूनों की आंखों में धूल झोंककर अपना ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित किया। बड़े-बड़े आर्थिक घोटालों की झड़ी लग गई। सरकार सब्सिडी देकर जनता को लुभाती रही। आज एक और प्रवृत्ति विकसित हो रही है कि सरकारें लोगों को सस्ते कर्ज देकर पर निर्भरता का पाठ पढ़ाकर उनके आचरण को दूषित कर रही हैं। इसके चक्र में फंस कर किसानों की आत्महत्या के अनेक मामले भी सामने आए हैं। अब तक विकास और प्रगति का लाभ सीमित वर्ग तक था। वर्तमान सरकार ने आम जन से सीधा संपर्क साधा है और गरीबों तक उनके हित को सीधे पहुंचाया है।

आज की स्थिति एक जटिल विसंगति की है। एक ओर संसाधन घटते जा रहे हैं दूसरी ओर लोभ, संचय, परिग्रह और लिप्सा की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यथोचित उपभोग की भावना समाप्त होती जा रही है। हम भविष्य की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारी नजरें तकनीक पर हैं। हम सोचते हैं कि इसके सहारे हम सभी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। हम जीवन के अधिकाधिक काम इसके हवाले करते जा रहे हैं। गांधी जी उचित तकनीक और छोटी मशीनों के पक्षधर थे, परंतु अज हम सब तकनीक के दास हुए जा रहे हैं और हाथ, पांव तथा दिमाग से भी पंगु होते जा रहे हैं। गणतंत्र अनुशासन मांगता है, परंतु हम सब अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्था चलाना चाहते हैं। आज राजनीति का स्वभाव सीमित और संकुचित होता जा रहा है। समाज के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि वे व्यापक सामाजिक हित को साधने की कोशिश करें और सत्ता का समीकरण साधने में भ्रामक व्याख्याओं तथा अतिवादी आग्रहों के उपयोग से बचें। युवतर हो रहे भारत के सामने ढेरों जन आकांक्षाएं हैं। समानता, बंधुत्व, समरसता का लक्ष्य सामने है और इसके लिए सबको एकजुट होकर काम करना होगा। इस गणतंत्र दिवस पर हम सबको ऐसा संकल्प लेना चाहिए।

(लेखक पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आस्तिकता

भारत की सनातन परंपरा में आस्तिकता के तीन प्रमुख आधार माने गए हैं। पहला, वेद में विश्वास करना, दूसरा, आत्मा की अमरता में विश्वास करना और तीसरा, ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा व्यक्त करना। वेद अपौरुषेय हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित नहीं है, न भगवान के द्वारा ही रचे गए हैं। दरअसल ऋषि वेदमंत्रों के द्रष्टा यानी साक्षात्कारकर्ता हैं। इस लिहाज से जो लोग वेद के मंत्रों में श्रद्धा व्यक्त करते हैं वे आस्तिक कहे जाते हैं। इसके अलावा आत्मा की अमरता में विश्वास करने वालों को भी आस्तिक कहा जाता है। आत्मा चेतन, शाश्वत और अविनाशी है। यह दिक और काल से अतीत है। प्रत्येक जीव में अलग-अलग आत्मा है। इसे जीवात्मा भी कहा जाता है। वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा को परमात्मा कहा जाता है।

परमात्मा को ही ईश्वर कहा गया है। आस्तिकता का सर्वाधिक लोकप्रिय आधार ईश्वर में आस्था है। जगत का सृजन, पालन और संहार ईश्वर की लीला है। ईश्वर अपनी कुशलता से जगत का निर्माण करते हैं। वे जगत को अपने अंदर से उत्पन्न करते हैं। सनातन धर्म में ईश्वर को पूर्ण माना गया है। वे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और पूर्णस्वतंत्र हैं। ईश्वर अनंत गुणों से युक्त हैं, परंतु छह गुण उनमें प्रधान है। ये इस प्रकार हैं-आधिपत्य, सर्वशक्तिमत्ता, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ईश्वर मनुष्य को उसके नैतिक-अनैतिक कर्मों का परिणाम देते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख-दुख इन्हीं के कारण आते हैं।

जगत में जो भी छोटे से लेकर बड़े कार्य हो रहे हैं वे सब ईश्वर के कारण हैं। कहा भी जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जाहिर है ईश्वर ही इस जगत के नियंता हैं। वे इस जगत के कण-कण में व्याप्त हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाले को भौतिक जीवन में सफलता मिलने पर अहंकार नहीं होता और असफलता मिलने पर निराशा नहीं होती। इसलिए हमें ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए।

डॉ. बिपिन पांडेय

समझनी होगी मतदान की अहमियत

देवेंद्रराज सुथार

अब समय आ गया है कि हमारे देश में भी ऑनलाइन वोटिंग को लेकर चर्चा हो और इस प्रणाली को अपनाने के लिए एक राय बने

किसी भी लोकतांत्रिक देश में मतदान जनता का सबसे अहम अधिकार होता है। जनता का मत ही तय करता है कि सत्ता की डोर किसके हाथ में रहेगी, लेकिन विडंबना है कि हमारे देश में वोट देने के दिन लोगों को जरूरी काम याद आने लग जाते हैं। कई लोग तो वोट देने के दिन अवकाश का फायदा उठाकर परिवार के साथ घूमने चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर पर होने के बावजूद भी वोट देने के लिए बूथ तक जाने में आलस करते हैं। इसलिए हमारे किसी भी चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता। साथ ही एक तबका ऐसा भी है जो प्रत्याशी के गुणों को नहीं, बल्कि धर्म, मजहब एवं जाति देखकर अपने वोट का प्रयोग करता है। वहीं वोट की खरीद-फरोख्त से भी हमारा मतदाता वर्ग अछूता नहीं है। अतः हम तब तक अच्छी व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाएंगे, जब तक हम मतदाता होने के फर्ज को पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ निभा नहीं देते।

अब सवाल उठता है कि आखिर लोग वोट क्यों नहीं करते हैं? प्रायः इसका कारण या तो लोगों को कोई प्रतिनिधि पसंद नहीं आया या फिर उनका लोकतंत्र से विश्वास ही उठ गया समझा जाता है, लेकिन ऐसा होने के पीछे अन्य कारण भी होते हैं। जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। दरअसल बदलते समय के साथ हमारी युवा पीढ़ी को वोट के दिन मतदान केंद्रों पर जाना, अपना नंबर आने के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े रहना, इंतजार करना अब बोरियत भरा लगने लगा है। वहीं कई लोग अपने रोजगार और नौकरी के सिलसिले में अपने निवास स्थान से बाहर रहते हैं और वोट वाले दिन उनका अवकाश लेकर आना संभव नहीं होता है। इस तरह एक बड़ी संख्या इच्छुक होने के बाद भी इस महापर्व से बाहर रह जाती है। निःसंदेह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इतनी बड़ी संख्या का मतदान प्रक्रिया से दूर रहना उचित नहीं है। यह बात चुनाव आयोग एवं सरकार की चिंताओं में प्रमुखता से शामिल होनी चाहिए। वोट के दिन प्रवासी लोग भी अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें इसके लिए विकल्प तलाशने चाहिए। अब समय आ गया है कि हमारे देश में भी ऑनलाइन वोटिंग को लेकर चर्चा हो और इस प्रणाली को अपनाने के लिए एक राय बने। इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता ने ई-डेमोक्रेसी की अवधारणा को जन्म दिया है। वर्तमान समय में दुनिया के 14 देशों में यह सुविधा किसी न किसी रूप में मौजूद है। एस्टोनिया पूरी तरह ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला देश बन चुका है।

यदि ऐसा होता है तो हमारा वोट प्रतिशत भी काफी हद तक बढ़ सकता है। साथ ही यह चुनावी खर्च और भारी ताम-झाम को कम कर सकता है। यह सही है कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए यह सब इतना आसान नहीं होगा, पर कोशिश की जानी चाहिए। इसके लिए हमें इंटरनेट के विस्तार के साथ ही भरोसेमंद सेवा उपलब्ध करवानी होगी एवं डिजिटल डिवाइड की समस्या को हल करना होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

भ्रम जाल से बाहर निकलने की जरूरत

बुरे नतीजों वाला बेजा विरोध शीर्षक से युक्त अपने लेख में एडवोकेट डॉ. सैयद रिजवान अहमद ने जो संदेश दिया है उसे समझने की जरूरत है। सीएए को मुस्लिम विरोधी बताकर इसका बेजा विरोध करना उन विपक्षी दलों की साजिश है जो मोदी सरकार के राष्ट्र हितैषी निर्णयों और 2019 में इस सरकार की दमदार वापसी से खीजा हुआ है। इस दृष्टि से विपक्षी नेताओं के इस दुष्प्रचार से कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है, देश को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। क्या कोई बताएगा कि मोदी सरकार के किसी निर्णय या नीति से इस देश के शांतिप्रिय मुस्लिम वर्ग के हितों पर कोई कुठाराघात हुआ है या उनके संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुए हैं? बावजूद इसके यदि कुछ लोग निहित स्वार्थवश शाहीन बाग जैसे प्रायोजित धरना स्थलों पर विपक्षी नेताओं की मोदी विरोधी तकरीर सुनने के बाद अपनी नारेबाजी से आमजन की शांति भंग करने में ही स्वयं को आनंदित महसूस कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का ये आनंद भविष्य में कष्टदायी भी साबित हो सकता है। क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं देश की समूची आबादी के लिए होती हैं। मोदी सरकार की जन-धन, आयुष्मान, उज्ज्वला जैसी सैकड़ों लोकहितैषी योजनाएं भी बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र भारतीय नागरिकों के लिए लागू की गई हैं। ऐसे में मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताकर दुष्प्रचारित करना एक शरारतपूर्ण हिमाकत है। देश के मुस्लिम वर्ग को विपक्षी नेताओं के इस भ्रम जाल से बाहर निकलने की जरूरत है।

pandeyvp1960@gmail.com

सक्षम नेतृत्व की दरकार

दैनिक जागरण के 24 जनवरी के अंक में प्रकाशित रशीद किदवई ने अपने लेख, दूर होती नहीं दिखती कांग्रेस की दुविधा, में सही आकलन किया है कि देश का जो युवा भाजपा से नाराज है वह कांग्रेस को विकल्प के रूप में नहीं देख पा रहा। असल में अपनी इस स्थिति के लिए कांग्रेस स्वयं ही जिम्मेदार है। कांग्रेस पचपन साल तक सत्ता में रही है, लेकिन वह आज भी सत्ता के खोल से बाहर नहीं निकल सकी है। नरसिम्हा राव के बाद कांग्रेस नेहरू-गांधी परिवार के दायरे में ही सिमट कर रह गई है। पिछले बीस साल से कांग्रेस अध्यक्ष पद परिवार के पास है। पहले 17 साल तक सोनिया गांधी निरंतर इस पद पर रहीं, फिर राहुल गांधी पदासीन हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद वे पद से हट गए। कांग्रेस पार्टी के पास परिवार से इतर कोई ऊर्जावान नेतृत्व खोजने का अवसर था, लेकिन कांग्रेस परिवार की छत्रछाया से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, इसलिए राहुल से ताज लेकर फिर सोनिया गांधी के सिर पर सजा दिया गया। अब सुना है कि फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस की दशा उस व्यक्ति की तरह हो गई है जो पेड़ के नीचे लेट कर अपेक्षा करता है कि पेड़ से फल अपने आप टूट कर उसके मुंह में आ पड़ेगा, जबकि फल खाने के लिए पेड़ पर चढ़ कर फल तोड़ने पड़ते हैं। कांग्रेस सिर्फ भाजपा की आलोचना कर सत्ता की चौखट तक नहीं पहुंच सकती। इसके लिए उसे खुद को भाजपा के विकल्प के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा। यदि कांग्रेस को अपनी बदतर स्थिति से बाहर निकलना है तो एक सक्षम नेतृत्व की तलाश करनी होगी।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

फिल्मों में धर्म एवं आस्था

दैनिक जागरण के 20 जनवरी के अंक में प्रकाशित धीरज शर्मा का लेख, सिनेमा में धर्म की महत्ता, में उन्होंने बॉलीवुड द्वारा सिनेमा में अतीत की तुलना में आस्था और धर्म को अब उतना महत्व न देने की बात कही है। उन्होंने 1960 से लेकर फिल्म तान्हाजी जी तक के विश्लेषण के आधार पर कहा कि बॉलीवुड धर्म एवं आस्था आधारित फिल्मों को तरजीह नहीं दे रहा, बल्कि धर्म एवं आस्था को मजाक बना कर रख दिया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नैतिक सोच हमारे धर्म और आस्था के प्रति पहले के बजाय विकृत हुई हो और हमने ही जाने अनजाने में उपहास उड़ाना शुरू कर दिया हो?

पवन कुमार मुरली, गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्याय

8.2 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था भारत और ब्राजील के बीच वर्ष 2018-19 में, जो इससे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग सात प्रतिशत अधिक रहा।

आजकल

खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें और बजट

प्रो. लल्लन प्रसाद
पूर्व विभागाध्यक्ष, बिजनेस इकोनॉमिक्स विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

खाद्य पदार्थों की कीमतों में चढ़ाव से वर्ष 2020-21 का बजट प्रभावित होने की संभावना है। वित्तीय घाटा 3.5 से 3.8 तक जा सकता है। खाद्य सब्सिडी 6.6 प्रतिशत है जिसके भी बढ़ने की संभावना है। सब्जियों, दूध आदि की कीमतों में कई बार अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है, उपभोक्ताओं को इससे बचाने के लिए यदि सरकार को इसका आयात करना पड़ा तो उसका भी बजट पर असर पड़ेगा। औद्योगिक उत्पादन व मांग में गिरावट बेरोजगारी और बढ़ा सकती है। वित्त मंत्री के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनमें खाद्य पदार्थों की उछलती कीमतों को रोकना भी एक है

प्रतीकात्मक फोटो।

देश की अर्थव्यवस्था आज विरोधाभास की स्थिति से गुजर रही है। जहां एक ओर खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का घरेलू बजट असंतुलित हो रहा है। औद्योगिक पदार्थों की मांग में गिरावट की स्थिति बनी हुई है, उनकी कीमतें गिर रही हैं, उत्पादन में कमी आई है, किंतु कंपनियों के शेयरों की कीमतों में उछाल है, शेयर बाजार रिकार्ड स्तर पर है। देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान गिरता जा रहा है और सेवा क्षेत्र का बढ़ रहा है। लघु और मध्यम उद्योग जो बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं, चीन से आयातित सस्ते पदार्थों के कारण बड़ी संख्या में बंद हो चुके हैं। इसका असर निर्यात पर भी पड़ा है। वर्ष 2022 तक सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा कर रही है, किंतु जमीनी स्तर पर प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए हैं।

उपभोक्ता कीमतों के सूचकांक में बढ़ोतरी बड़ी चुनौती : खुदरा कीमतों का सूचकांक वर्ष 2019 के प्रारंभ से ही चढ़ाव पर है। जनवरी में यह 139.6 प्वाइंट था जो दिसंबर के आखिर में 150.4 प्वाइंट पर पहुंच गया। मुद्रास्फीति दर इस बीच 1.97 से बढ़कर 7.4 तक आ गया। सर्वाधिक वृद्धि खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई, विशेष रूप से सब्जियों, दूध मांस आदि में। उपभोक्ता कीमतों के सूचकांक में खाद्य और पेय पदार्थों का अधिमान सबसे अधिक है लगभग 45 प्रतिशत, बाकी में यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउसिंग, ऊर्जा और बिजली आते हैं। खाद्य पदार्थों में गेहूं, चावल और अन्य अनाज, दालें, तेल, घी, सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध पदार्थ, मिठाइयां, मांस, मछली आदि सम्मिलित हैं। उपभोक्ता कीमतों का सूचकांक मुद्रास्फीति दर निर्धारण में सहायक होता है। इस सूचकांक में खाद्य और पेय पदार्थों का अधिमान अधिक होने से, इन वस्तुओं की कीमतों में उछाल सूचकांक को तेजी से बढ़ाती है।

प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों का समाधान : पिछले कुछ महीनों में सब्जियों, विशेषकर प्याज और टमाटर की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, तिलहन, दालों, दूध और मांस आदि भी महंगे हुए जिस कारण खुदरा कीमतों का सूचकांक तेजी से ऊपर आया। बीते माह केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने संसद में कहा कि प्याज की कीमतों में 400 प्रतिशत वृद्धि होने के बाद सरकार ने बड़े पैमाने पर प्याज आयात की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि अनाज की कीमतों में वृद्धि का असर मध्यम वर्ग को अधिक झेलना पड़ता है, गरीब परिवारों को कम, क्योंकि गेहूं और चावल उनको एक से तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से सार्वजनकि वितरण प्रणाली के तहत सरकारी दुकानों से मिल जाता है, किंतु सब्जियों, दूध, मांस आदि की कीमतों में वृद्धि का असर उन पर भारी पड़ता है। हालांकि जीवन शैली में परिवर्तन के फलस्वरूप अनाज की खपत पहले की अपेक्षा अब कम होती है, जबकि सब्जियों, फलों, दूध, घी, मांस, मछली, अंडे आदि पर अपेक्षाकृत अधिक होती है। नतीजन इन वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही है।

प्याज और टमाटर अब पूरे वर्ष खाया जाता है जबकि इनका उत्पादन मौसम और मिट्टी पर निर्भर है और देश के सभी हिस्सों में पूरे साल इनका उत्पादन नहीं होता। मांग और पूर्ति के असंतुलन से कीमतों में गिरावट या उछाल आता है। जिन महीनों में प्याज की पैदावार होती है मौसम अनुकूल नहीं होता या अन्य कठिनाइयां आ जाती हैं, फसल खराब हो जाती है तो बाजार में आपूर्ति कम हो जाती है जो कीमतों में उछाल का कारण बनती है। पैदावार बहुत अच्छी होती है तो कीमतें नीचे आ जाती हैं, किसान त्रस्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि टमाटर और प्याज की लागत ना मिलने से किसान आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। सरकार गेहूं और चावल एवं दालें न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर किसानों से खरीदती है, किंतु प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों की खरीद और वितरण बाजार व्यवस्था पर निर्भर है। समय आ गया है जब सरकार को अनाज और दालों के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों, जिनकी मांग बहुत है, किंतु पूर्ति की अनिश्चितता रहती है, उन्हें भी अपनी वितरण व्यवस्था में लेने की योजना बनाए। बजट में इसके लिए प्रावधान की आवश्यकता है।

बढ़ाना होगा कृषि निर्यात : कृषि पदार्थों का निर्यात अभी सीमित मात्रा में है, कुल निर्यात का 12 प्रतिशत के लगभग। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा कृषि पदार्थों का उत्पादक देश है। निर्यात की संभावनाएं बहुत हैं जिसके लिए योजनाबद्ध रूप से काम करने की आवश्यकता है। बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने, भंडारण की अच्छी व्यवस्था, कृषि निर्यात जोन की स्थापना, निर्यातकों के लिए कर्ज की अच्छी सुविधा और प्रक्रिया का सरलीकरण, विदेशों में भारतीय कृषि पदार्थों की अच्छी मार्केटिंग, निर्यात योग्य नए पदार्थों को बढ़ावा देना और निर्यात की जाने वाली चीजों की गुणवत्ता में वृद्धि जैसे कदम कृषि पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक है। अभी बासमती चावल, कपास, मसाले, चाय, काफी, मांस और रबड़ जैसे पदार्थों का निर्यात होता है, निर्यात की टोकरी बढ़ाने की जरूरत है।

किसानों को मिले विविध सुविधाएं : आर्गेनिक पदार्थों की मांग बढ़ रही है। प्रोसेस्ड फूड और जूस का विश्व में बड़ा बाजार है। सब्जियों और फलों की मांग भी बढ़ रही है। कृषि पदार्थों के निर्यात में वृद्धि के लिए नए बजट में प्राविधान की आवश्यकता है। इससे किसानों को लाभ होगा और जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी। कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसानों को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि लाभप्रद हो। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है। इसके लिए सरकार ने जो समिति बनाई थी उसने सितंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति के प्रमुख सुझाव थे फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाए, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाई जाए, सघन खेती पर जोर दिया जाए, अधिक कीमत की विविध फसलें उगाई जाए, किसानों को जो वास्तविक कीमत मिलती है, उसमें वृद्धि की जाए, गांवों में कृषि के अलावा अन्य धंधों को भी विकसित किया जाए जिसमें लोग रोजगार पा सकें। किसानों को मिलने वाली वास्तविक कीमत में बढ़ोतरी के लिए समिति ने विपणन व्यवस्था में व्यापक सुधार और बदलाव के सुझाव दिए।

अनाज की खरीद के लिए अपनाया जाए नया तरीका : कृषि पदार्थों की बिक्री के लिए आइटी और ई-कामर्स को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार ने कृषि पदार्थों की बिक्री के लिए एक ई-प्लेटफॉर्म बनाया है और राज्य सरकारों को इसके उपयोग की सलाह दी गई है। पूरे देश की अनाज की मंडियां इससे जुड़ जाएं तो जहां अधिक पूर्ति है, वहां से अनाज उन मंडियों तक आसानी से बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकेगा जहां पूर्ति कम है। इससे किसानों को लाभ होगा। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि जरूरत पड़ने पर सरकार कृषि पदार्थों की कीमत निर्धारण में हस्तक्षेप करे। यह दो तरीकों से हो सकता है- सीधे किसानों से अनाज खरीदकर या किसानों को सही कीमत ना मिलने पर, अनाज बेचने में किसान को न्यूनतम निर्धारित मूल्य से जितना कम मूल्य मिलता है, उसकी भरपाई करके।

वैश्विक बाजार का आकलन : खाद्य पदार्थों की कीमतों में जो उछाल पिछले कुछ महीनों में हुआ है वह भारत तक ही सीमित नहीं है, विश्व बाजार में भी यही स्थिति रही। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) जो प्रतिमाह कीमतों का विश्व स्तर पर आकलन करती है उसके अनुसार चीन, भारत, नाइजीरिया सहित अधिकांश विकासशील देशों में 2018 की तुलना में 2019 में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। जिन पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं उनमें सब्जियां, दूध, चीनी, चिकन एवं मांस शामिल हैं। भारत के सभी पड़ोसी देशों में खाद्य पदार्थों की कीमतें पिछले कुछ महीनों से उछाल पर रहीं। श्रीलंका में सितंबर 2018 की तुलना में सितंबर 2019 में कीमतें पांच प्रतिशत अधिक थीं। नारियल, सब्जियां, दूध, मछली, चिकन के दाम तेजी से बढ़े। बांग्लादेश में खाद्य पदार्थों की कीमतें भारत से अधिक हैं। पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों की कीमतों में पिछले एक वर्ष में भारी वृद्धि हुई है। उपभोक्ता कीमतों की वृद्धि दर सितंबर 2018 के 1.4 प्रतिशत से सितंबर 2019 में 14.3 प्रतिशत पर आ गई।

पारदर्शी बने सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार किसानों से अनाज निर्धारित समर्थन मूल्य, जो कृषि पदार्थों की कीमतों के निर्धारण के आयोग की सिफारिशों पर होता है, उस पर खरीदती है और सरकारी वितरण केंद्रों से गरीबों को उपलब्ध कराती है, जो विश्व की सबसे बड़ी वितरण व्यवस्थाओं में एक है। इसका उद्देश्य है किसानों को उचित मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अनाज की खरीद, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण और वितरण सरकारी संस्थान फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। पांच हजार से अधिक केंद्रों से अनाज लाकर उसका भंडारण और 4,60,000 उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरण की जिम्मेदारी जिस कॉरपोरेशन पर है उसकी कार्य प्रणाली भी उतनी ही पारदर्शी और प्रभावशाली होनी चाहिए जो नहीं है। लाखों टन अनाज हर वर्ष गोदामों में सड़ता है, चूहे खाते हैं, रेलवे वैगन और ट्रकों से लूटा जाता है। ऐसे में निगम की कार्यकुशलता और क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता है। इसकी पूंजी में वृद्धि के लिए सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 65,000 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था। निगम समय-समय पर सरकारी गारंटी के ब्रांड द्वारा भी बाजार से उधार लेती रही है। इसकी क्षमता में वृद्धि करके और प्रबंधन में सुधार करके बड़ी बचत हो सकती है जिसका लाभ उपभोक्ताओं को होगा। किसानों से निर्धारित मूल्य पर अनाज खरीदने और इससे काफी कम दाम पर वितरण के फलस्वरूप खाद्य पदार्थों पर सरकार को भारी रकम की सब्सिडी बजट में देनी पड़ती है जो पिछले वर्ष जीडीपी का 6.6 प्रतिशत था। सब्सिडी का प्रावधान जिन और चीजों के लिए किया जाता है उनमें मुख्य है कच्चा तेल जिसका बड़े पैमाने पर आयात होता है और जिसकी कीमतें बढ़ने पर महंगाई बढ़ने लगती है। कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होती है जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। हाल ही में अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने लगा है। नए वर्ष के बजट में सब्सिडी के लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रकम का प्राविधान सरकार को करना पड़ सकता है।

खरी-खरी

नए जमाने में महानता का पैमाना

कमलेश पांडेय

अगर आपको बात-बात पर किसी महान शख्सियत की मिसाल देने या उसकी कोई सूक्ति का वर्णन करने का शौक है तो ध्यान रखें कि अब देश बदल चुका है और इसके साथ-साथ बदल चुका है दौर भी। इस बदले दौर में महानता के पुराने मानदंडों यानी पैमानों का भी नवीनीकरण हो चुका है। अब आप किसी को इसलिए महान नहीं कह सकते कि वह पहले भी महान रहा है। आज सभी किस्म के महानों के लिए ढेरों शर्तें लागू हैं। इतना ही नहीं, महान की दी गई मिसालों और सूक्तियों का भी बाकायदा पोस्टमार्टम होता है।

अब किसी को महान बताकर उसकी मिसाल देने से पहले चेक कर लें कि वह प्राणी महानता की नई आचार-संहिता पर खरा तो उतरता है। वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। आप यह सुनिश्चित करें कि आपके महान के पास दुनिया का हर ज्ञान हो। ताकि कोई ये न कह सके कि इतिहास में तो खूब बोले, लिखे या ज्ञान दे गए, पर भूगोल में पूरी तरह गोल थे। या संगीत में तो बड़े प्रवीण थे, पर पाक-कला के बारे में उनका लिखा ग्रंथ तो क्या, कोई बयान तक नहीं मिलता।

हमारे कहने का मतलब यह कि मिसाल देनी ही हो तो महान ऐसा चुनिए, जो इस कदर दूरद्रष्टा हो कि बोलने से पहले ही जिसने तौल लिया हो कि दो-तीन सदियों बाद जब भावी पीढ़ियों के हाथों उनके विचारों का मलीदा बन चुका हो, तब भी हर उक्ति इस दौर पर फिट बैठे। बल्कि महान से नई अपेक्षा तो ये है कि हजार साल बाद के दौर की आबादी के हर तबके की भावनाओं को आहत होने से बचाते हुए बोल सके। बोले तो ऐसा कि कोई बात संदर्भ से काटी न जा सके।

हां, एक और बात! महान के जीवन में कहीं भी बाल बराबर झोल न हो। बस अपने जैसे महान लोगों के बीच ही उठा-बैठा हो। ऐसी कोई हरकत न की हो, जो हम-आप जैसे साधारण इंसान करते रहते हैं। हरकतें की भी हों, तो महानता का हिसाब रखने वालों के संज्ञान में न आई हों।

ऐसी फुल-प्रूफ, सुरक्षित व गारंटेड महानता मिले, तभी उसकी मिसाल देने का शौक फरमाएं। हालांकि सोशल मीडिया के इस चरम-बौद्धिक युग में इस बात की गारंटी नहीं कि आपका महान और उसकी मिसाल, आमजन के लिटमस टेस्ट पास कर जाएं।

ट्वीट-ट्वीट

आपने विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा और केएल राहुल के उत्कर्ष को देखा होगा। अब आप श्रेयस अय्यर के अभ्युदय को देखिए। न्यूजीलैंड में पहली बार खेलने के बावजूद उनका सहज और आत्मसंयम से भरपूर खेल बहुत ही मनमोहक था।
मोहम्मद कैफ@MohammadKaif

टुकड़े-टुकड़े गैंग। असली टुकड़े-टुकड़े गैंग कौन है? वह जो हमें भड़काता है। वह जो हमें बांटता है। वह जो हमें सांप्रदायिक बनाता है।
कपिल सिब्बल@KapilSibal

जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक संकट नहीं है, बल्कि आगामी दशक में यह नवाचार और उद्यमशीलता के लिए सबसे बड़ा अवसर भी है। सूचनाओं और सर्वश्रेष्ठ परंपराओं का आदान-प्रदान इसमें सफलता की कुंजी है।
आनंद महिंद्रा@anandmahindra

निर्भया मामले में वकील फांसी की प्रक्रिया अमल में लाने को देर करने की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से वे हमारी न्याय प्रणाली का मजाक बना रहे हैं। हमें तेज न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करना होगा, जिससे न्याय को सक्षम बनाने और इसमें मौजूद सभी प्रकार की खामियों को दूर करने के लिए कानूनों में बदलाव किया जाए।
मनीष सिसोदिया@msisodia

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या मुंबई की तर्ज पर अन्य बड़े शहरों में भी 24 घंटे मॉल-दुकानें आदि खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए?

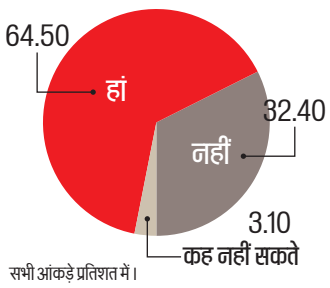

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर पर निशाना साध कर अपनी फजीहत कराई?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बरतन-भांडे बज रहे गूंज रही आवाज,
पवन-प्रशांत किशोर अब बने कोढ़ में खाज।
बने कोढ़ में खाज रहे जो कभी चहेते,
हैं बिन पूछे आज बेवजह पंगा लेते।
रिश्तों में जब स्वार्थ लगे करने परिवर्तन,
कैसे चचा नितीश संभालें अपने बरतन।
- ओमप्रकाश तिवारी

धार्मिक आधार पर भेद नहीं करता नागरिकता कानून

अभिषेक गुप्ता
स्वतंत्र टिप्पणीकार

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कई तबकों और दलों द्वारा निरंतर जारी है। हालांकि इस बारे में अब तक बहुत कुछ कहा और बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी हमें यह समझना होगा कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? विभाजन के दौर में धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान में से पाकिस्तान दो टुकड़ों के रूप में अलग किया गया। साथ ही तय किया गया कि जो जहां रहना चाहता है, वह वहां रहे और सरकारें उसे परेशान नहीं करेंगी। बड़ी संख्या में पलायन का दौर चला। हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहे थे और मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। बीच-बीच में पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म की महिलाओं के साथ दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें भी बड़ी संख्या में आ रही थीं। दोनों देश गंभीर रूप से शरणार्थी संकट का सामना कर रहे थे। दूसरी ओर 1948 तक कश्मीर मसले को लेकर दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो चुके थे। ऐसे में में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1950 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसके अनुसार धार्मिक आधार पर हिंदू, मुस्लिम, पारसी अथवा सिख समुदाय जैसे अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत ने तो अपने यहां अल्पसंख्यकों के विकास व सुरक्षा हेतु कई कानून बनाए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा न कर सका।

इस विधेयक में तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति को जान लेना चाहिए। पाकिस्तान में आज भी कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पद पर काबिज नहीं हो सकता। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तानी संसद नेशनल एसेंबली में एक ईसाई सांसद ने एक विधेयक पेश किया था जिसमें गैर मुस्लिमों को राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री बनाने संबंधी कानून का प्रस्ताव था, लेकिन यह विधेयक खारिज कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में अक्टूबर में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, पाकिस्तान में कुछ हफ्तों पहले हिंदू बच्चों के एक स्कूल पर कुछ मुस्लिमों ने हमला किया। फिर ईशनिंदा का आरोप लगाकर एक डॉक्टर का क्लीनिक जला दिया गया। सिंध प्रांत के गोटकी जिले में रहने वाले एक हिंदू दुकानदार ने कहा कि हमारे पूर्वज विभाजन के दौरान पाकिस्तान छोड़कर नहीं गए। लेकिन अब वे इस फैसले पर पछता रहे हैं। अमेरिका में सक्रिय मानवाधिकार संगठन हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक, इस्लामाबाद स्थित संधारणीय विकास नीति संस्थान ने अपने एक शोध लेख में भी गैर मुस्लिमों के खिलाफ पाकिस्तान में बढ़ती प्रताड़नाओं के बारे में जिक्र किया है।

प्रतीकात्मक फोटो।

बांग्लादेश में भी गैर मुस्लिमों पर हमले की खबरें आती हैं। वर्ष 2018 में नवंबर तक धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले की संख्या 1,792 तक आ पहुंची थी। 'द संडे गार्डियन' में नवंबर 2019 में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, विभाजन के दौरान बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) में हिंदुओं की संख्या 31 प्रतिशत थी, जो घटकर नौ प्रतिशत रह गई है। 2017 में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार नामक एक रिपोर्ट के अनुसार, 782 हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, 23 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। 25 महिलाओं और बच्चों का दुष्कर्म किया गया, 235 मंदिरों पर हमला कर नुकसान पहुंचाया गया। कुल मिलाकर अत्याचार की 6,474 घटनाएं हुईं। वहीं 2016 में इन घटनाओं की संख्या 11,335 थी। ढाका यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अबुल बरकत कहते हैं कि अगर इसी तरह हिंदुओं की जनसंख्या घटती रही, तो अगले तीन दशकों में बांग्लादेश से हिंदुओं का नामोनिशान खत्म हो जाएगा।

हालांकि अफगानिस्तान में हिंदुओं की आबादी बहुत ही कम है और यह दिनों-दिन कम भी हो रही है। इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए भी दायरा सीमित रखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ समय के दौरान अफगानिस्तान में भी हिंदुओं को रीति-रिवाज निभाते वक्त सरकारी अधिकारियों की ओर से बाधाओं का सामना करना पड़ा है। काबुल क्षेत्र में सिमटे सिख लोगों के लिए तो दो जून की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। काबुल में कभी आठ गुरुद्वारे होते थे जिनमें से अब केवल एक ही बचा है।

इन हालातों को देखते हुए यह तो साफ हो जाता है कि इन तीनों देशों में तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बात जब उनके धर्म और रिवाजों की हो, तो उनके लिए जिंदगी काटना और भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यह कानून उनके लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

कूटनीति

बोल्सोनारो की भारत यात्रा

विजय कपूर
वरिष्ठ पत्रकार

बोल्सोनारो की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी के लिए एक कार्ययोजना शुरू हो रही है, जो इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच लेन-देन के बिंदु तय करेगी

भारत की 71वीं गणतंत्र दिवस परेड में इस बार विशेष अतिथि होंगे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस खास समारोह में शामिल होने का आमंत्रण नवंबर में ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दिया था। वैसे कोई ब्राजीलियन राष्ट्रपति भारत की गणतंत्र दिवस परेड का तीसरी बार मुख्य अतिथि होगा, पर राष्ट्रपति बोल्सोनारो के लिए यह इसलिए खास है, क्योंकि राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद वह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा कर रहे हैं।

बोलसोनारो की इस भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में गर्माहट आने की उम्मीद तो है ही, दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते भी बेहतर होंगे। भारत और ब्राजील के बीच आपसी व्यापार की व्यापक संभावनाएं हैं। ब्राजील के राजदूत आंद्रे अरान्हा कोरया डो लागो ने कहा है कि दोनों देशों के पास एक दूसरे से बहुत कुछ लेने और देने की संभावनाएं हैं, दोनों ही बहुत तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाएं हैं, बस दोनों के बीच अंतर सिर्फ इतना है कि ब्राजील के पास भारत जितने उपभोक्ता नहीं हैं, पर ब्राजील के पास अपार संसाधन हैं। दोनों देश ऊर्जा, कृषि और रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को बहुत कुछ दे सकते हैं।

ब्राजील के राजदूत ने कहा है कि दोनों देश सामरिक भागीदारी को और अधिक गतिशील बनाना चाहते हैं। भारत और ब्राजील के संबंध पहले से बेहतर हुए हैं। दोनों देशों के बीच 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार 8.2 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले सात प्रतिशत ज्यादा था। इस व्यापार में 3.8 अरब डॉलर का भारतीय निर्यात रहा और 4.4 अरब डॉलर का भारत ने आयात किया। भारत ने जहां ब्राजील को एग्रो-केमिकल, सिंथेटिक यार्न, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स का व्यापक निर्यात किया है, वहीं ब्राजील से कच्चा तेल, खाद्य तेल, चीनी और खनिजों का बड़े पैमाने पर आयात किया है। भारतीय कंपनियों ने इस दौरान करीब छह बिलियन डॉलर का निवेश ब्राजील में किया है। हालांकि ब्राजील द्वारा भारत में किया गया निवेश इसकी तुलना में काफी कम है। लेकिन यह निकट भविष्य बढ़ेगा ऐसी उम्मीद है।

ब्राजील दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश है। यहां की जनसंख्या लगभग 21 करोड़ है। ब्राजील किसी समय पुर्तगाल का गुलाम था जिससे उसे सात सितंबर 1822 को मुक्ति मिली। ब्राजील का संविधान वर्ष 1825 में बना। यह देश दुनिया की कुल आवश्यकता का 20 प्रतिशत ऑक्सीजन अपने अमेजन के जंगलों में पैदा करता है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील पहला देश है जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। ब्राजील ने अब तक खेले गए 20 विश्व कप फुटबॉल में से सबसे ज्यादा पांच बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। बोल्सोनारो की यात्रा के दौरान भारत-ब्राजील संबंधों में निखार आने की खूब संभावनाएं हैं।

बोल्सोनारो से पहले 1996 में राष्ट्रपति फरनांडो हेनरिक कारडोसोर और 2004 में राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डि सिल्वा भी गणतंत्र दिवस में बतौर मुख्य अतिथि समारोह की शोभा बढ़ा चुके हैं, लेकिन यह 2016 के बाद पहला मौका है जब ब्राजील का कोई राष्ट्रपति भारत दौरे पर आ रहा है। इससे पहले वर्ष 2016 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति मिशेल तेमर भारत के दौरे पर आए थे। जहां तक भारत और ब्राजील के बीच कूटनीतिक संबंधों की बात करें तो 1948 में ये स्थापित हुए थे। इसी दौरान भारत ने ब्राजील की राजधानी रियो द जेनेरियो में अपना दूतावास खोला था। अगस्त 1971 में इस दूतावास को ब्रासिलिया में ट्रांसफर कर दिया गया था। भारत और ब्राजील के बीच रिश्तों की शुरुआत पांच शताब्दी पहले 1500 में हुई थी। इसकी शुरुआत सेबरल ने की थी, उन्होंने ही ब्राजील की खोज की थी। वास्तव में जब भारत की खोज के बाद वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल गया और भारत के बारे में बताया तो वहां के राजा ने सेबरल को भारत भेजा था। वैसे यह भी सही है कि अतीत में दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा अच्छे ही नहीं रहे। शीतयुद्ध के दौरान हमारे आपसी रिश्ते बहुत ठंडे भी रहे हैं। गोवा की आजादी और इसके भारत में शामिल किए जाने को लेकर ये रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि ब्राजील गोवा में पुर्तगाल की मौजूदगी को सही बताता था। इसके पीछे उसके पुर्तगाल से ऐतिहासिक रिश्ते थे। ब्राजील मानता था कि भारत ने वहां पर सैन्य कार्रवाई कर अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन वक्त के साथ दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर गए। हालांकि बीच में एक बार यह तब फिर बिगड़ा जब ब्राजील 2009 में पाकिस्तान को 100 एमएआर-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल बेच रहा था। भारत ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन ब्राजील ने इस सौदे को अंतिम रूप दे डाला था। यह मिसाइल लड़ाकू विमानों की मौजूदगी का पता लगाकर उन पर तुरंत हमला करने में सक्षम है। दरअसल भारत का कहना था कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग देकर दूसरी जगहों पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। लिहाजा इस तरह की मिसाइल पाकिस्तान को बेचना ठीक नहीं है।

बहरहाल आज हमारे पास दुनिया का बेस्ट मिसाइल सिस्टम है, इसलिए अब यह कोई बहस का विषय ही नहीं है। आज की तारीख में दोनों देशों के बीच रिश्ते लोकतांत्रिक मूल्यों और कॉमन ग्लोबल विजन पर आधारित हैं, जिनके भविष्य में लगातार बेहतर होने की उम्मीद है।

ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। फाइल फोटो।

50 रुपये शुल्क देकर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कराया जा सकता है। इसके लिए किसी दस्तावेज को देने की आवश्यकता नहीं है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 25 जनवरी 2020

बंगाल

सीएए का भय

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर पूरे देश में पिछले कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। बंगाल में विपक्षी दलों में इसका विरोध करने की होड़ मची है। सभी एक-दूसरे से आगे निकलने में संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे उनकी वोट बैंक की राजनीति छुपी है। वे मुस्लिमों में भय पैदा कर अपने पाले में लाना चाहते हैं। केंद्र सरकार भी मुस्लिमों के मन में बैठे इस डर को निकालने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हर मंच से यह बता रहे हैं कि सीएए से देश के मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं है।

हालांकि केंद्र सरकार को इसमें अपेक्षित सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रदेश में हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई ग्रामीण इलाकों में लोगों के बारे में किसी तरह की पूछताछ करता है तो वहां के लोग आक्रोशित होकर हमला करने लगे हैं। वीरभूम में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाली दो महिलाओं के घरों पर हमला हो चुका है और आगजनी की कोशिश भी। इस तरह का भय और आतंक का माहौल ग्रामीण इलाकों में बन चुका है कि आने वाले समय में जनगणना के लिए भी सरकारी कर्मी शायद ही लोगों के बीच जाएं। वैसे तो बंगाल में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के साथ जनगणना का भी कार्य बंद है, लेकिन जिस तरह से सियासी दलों ने लोगों के मन में भय और आतंक पैदा कर दिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में स्थिति विकट हो जाएगी, क्योंकि सरकारी योजनाओं को लेकर जब सर्वेक्षण या आंकड़ा संग्रह करने का कार्य शुरू होगा, तब क्या होगा?

बंगाल के वीरभूम में अब तक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाली दो महिलाओं के घरों पर हमला हो चुका है और आगजनी की कोशिश भी।

उधर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शुक्रवार को कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पिछले करीब एक माह में स्वदेश लौटने वाले अवैध बांग्लादेशियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ऐसा लगता है कि सीएए के लागू होने के बाद अवैध प्रवासियों के बीच डर के कारण यह संख्या बढ़ी है। बीएसएफ के महानिरीक्षक (साउथ बंगाल फ्रंटियर) वाई बी खुरानिया का कहना है कि पिछले एक महीने में बांग्लादेश जाने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। बीएसएफ ने जनवरी में 268 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा, जिनमें से अधिकतर लोग पड़ोसी देश जाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों के मन में यह डर राजनीतिक दलों की ओर से बैठा दिया गया है कि सीएए या फिर एनपीआर से उनका भारी नुकसान हो जाएगा, जबकि केंद्र सरकार और यहां तक कि इसी बंगाल की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी तक ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएए किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, बल्कि देने वाला है।

दरअसल देश में एक धड़ा इस कानून के समर्थन में है तो दूसरा इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताकर विरोध-प्रदर्शन भी कर रहा है और अब तो छिटपुट हमले की खबरें भी आने लगी हैं। इस मामले पर राज्य सरकार को भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति बिगड़ सकती है और ऐसे में असामाजिक एवं देश विरोधी ताकतें बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकती हैं।

हिमाचल प्रदेश

बेटों से कम नहीं हैं बेटियां

पारंपरिक तौर पर हमारे देश-समाज में बेटियों को बेटों से कमतर आंका जाता रहा है। इतना ही नहीं, बेटियों के साथ व्यवहार में भी भेदभाव किया जाता रहा है। हालांकि इसके लिए हमारी सामाजिक सोच भी जिम्मेदार रही है जिसके तहत यह माना जाता रहा है कि बेटे का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में वंश को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं। लेकिन पिछले दो-तीन दशकों के दौरान अनेक क्षेत्रों में बेटियों द्वारा दमदार प्रदर्शन करने के बाद से इस सोच में बदलाव आया है। फिर भी देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अभी भी बेटे को जन्म को प्राथमिकता देते हैं। वैसे इस दिशा में सरकार द्वारा व्यापक प्रयास जारी है और जब ईमानदारी से प्रयास हों तो सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे उदाहरण समय-समय पर हमारे सामने आते भी रहे हैं।

समाज में लंबे अरसे से बेटियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा है। बेटियों को पराया धन भी कहा जाता रहा है। इसी बीच कन्या भ्रूणहत्या का भी चलन बढ़ गया। नतीजा यह रहा कि हिमाचल प्रदेश का पंजाब से सटा जिला ऊना देश के उन संवेदनशील जिलों में शामिल हो गया, जहां लिंगानुपात में भारी अंतर था। हिमाचल प्रदेश में अल्ट्रासाउंड केंद्रों में भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध था, लेकिन सीमावर्ती जिला होने के कारण बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी राज्यों में इसकी जांच कराते रहे हैं। इस बीच सरकार और कुछ

प्रतीकात्मक फोटो

ऊना जिला में वर्ष 2011 में एक हजार लड़कों के मुकाबले 875 लड़कियां थीं जो अब बढ़कर 948 पहुंच गई हैं।

समाजसेवी संस्थाओं ने इसे गंभीरता से लिया। सरकार ने बेटियों के हित में कई तरह की योजनाएं शुरू कीं। वहीं समाज में भी जागरूकता अभियान चलाए गए।

इसका नतीजा है कि ऊना जिला में लिंगानुपात में काफी सुधार आया है। ऊना जिला में वर्ष 2011 में एक हजार लड़कों के मुकाबले 875 लड़कियां थीं जो अब बढ़कर 948 पहुंच गई हैं। जिला प्रशासन ने भी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत जिला भर में विशेष प्रयास किए। समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आया और लोगों ने बेटियों की महत्ता को समझा। जिला में ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने एक या दो बेटियों के जन्म के बाद परिवार नियोजन को अपनाकर इस धारणा को खारिज कर दिया है कि बेटी पराया धन है या बेटे कुल का दीपक होते हैं। वे बेटियों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं। बेटियों ने भी स्वजनों की आशाओं पर खरा उतर कर बेहतर परिणाम दिए हैं। शिक्षा के अलावा खेल के मैदान में भी बेटियां बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। बख्शो देवी ने नंगे पांव खेल के मैदान पर दौड़ कर राज्य भर में धाक जमाई थी। ऊना जिला के लिए ही यह गौरव की बात है कि यहां की बेटी पुलिस विभाग में जिला प्रमुख के पद पर सेवाएं दे चुकी हैं। ऊना जिला प्रदेश ही नहीं, देश के लिए अब एक मिसाल भी हो सकता है, जिसने साबित कर दिया है कि बेहतरीन प्रयास और जागरूकता से किसी भी कुरीति को दूर किया जा सकता है।

अब समय बदल चुका है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें बेटियों ने अपनी काबिलियत साबित नहीं की है। बस आवश्यकता आज इस बात की है कि बेटियों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाए। बेटियों को भी हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करना होगा और उस मानसिकता पर कड़ा प्रहार करना है, जो बेटियों का कमतर आंकती हैं।

जम्मू-कश्मीर

आयुष का प्रचार-प्रसार

जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक जिले में 50 बिस्तर वाला आयुष अस्पताल स्थापित करने के फैसला स्वागत योग्य है। निःसंदेह इससे राज्य में वर्षों से उपेक्षित आयुर्वेद, युनानी, होम्योपैथी, योग जैसी पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। यह किसी से नहीं छुपा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही जड़ी बूटियों से समृद्ध हैं। यहां उगने वाले औषधीय पौधों से कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां बनती हैं। इसके बावजूद हम आयुर्वेद पर मरीजों का विश्वास हासिल करने में विफल रहे हैं। कुछ महीने पूर्व ही नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया था कि जम्मू-कश्मीर में मात्र दो प्रतिशत के आसपास ही लोग आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराते हैं। अफसोस इस बात पर है कि सरकार के इन आंकड़ों पर कोई भी मंथन नहीं करता। अगर किया जात तो यहां आयुष की तस्वीर ही कुछ और होती। अभी तक स्थिति यह है कि आयुर्वेद का एकमात्र 25 बिस्तर की क्षमता का अस्पताल है। कॉलेज भी दो वर्ष पहले ही खुल पाया। होना तो यह चाहिए था कि

अस्सी के दशक में जब जम्मू में आयुर्वेद कॉलेज को बंद किया गया था, उसी समय इसके कारणों की तह तक सरकार जाती, मगर किसी ने भी ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई। यह अच्छी बात है कि अब सरकार जम्मू-कश्मीर को मेडिकल टूरिज्म के रूप में विकसित करने जा रही है। विगत दो सप्ताह में ही केंद्रीय आयुष मंत्री यहां दो बार आ चुके हैं और हर बार कई घोषणाएं कर चुके हैं। परंतु जब तक सभी घोषणाओं को कागजों से बाहर निकाल कर जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाता, तब तक आयुष का प्रचार-प्रसार संभव नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह नए अस्पताल खोलने के साथ-साथ पहले से खुले अस्पतालों में भी सुविधाओं को अपग्रेड करे। रिक्त पदों को भरे और नए पद सृजित करें, जिससे युवाओं को भी रोजगार मिल सके। अगर सरकार ऐसा करने में सफल रहती है तो जम्मू-कश्मीर में आयुष को एक नई पहचान मिलेगी और लोग भी इन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आएंगे।

इससे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी। डॉक्टर और मरीज का अनुपात सुधरने से प्रदेश में हेल्थ सेक्टर की स्थिति में भी सुधार होगा। जब लोगों को अपने आवास के नजदीक ही उचित इलाज मिलेगा तो उनकी सेहत भी ठीक होगी और आर्थिक बोझ भी कम होगा। इससे कहीं न कहीं प्रदेश को ही फायदा होगा। लोगों की उत्पादकता बढ़ेगी तो जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश

नदियों का महत्व

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस धारणा से शायद ही कोई असहमत हो कि गंगा सिर्फ आस्था नहीं, अर्थव्यवस्था भी है। वास्तव में यह बात गंगा की तरह सभी नदियों पर लागू होती है। यद्यपि विडंबना है कि प्रकृति द्वारा नदियों की शक्ल में प्रदत्त इन जीवनधाराओं का महत्व हम याद नहीं रख पाए और इन्हें स्वार्थ, बेपरवाही और अदूरदर्शिता का शिकार बनाया। इसे उम्मीद की किरण समझा जाना चाहिए कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकारें गठित होने के बाद गंगा और अन्य नदियों के उद्धार के लिए पारदर्शी प्रयास शुरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा पृथक मंत्रालय स्थापित किया और गंगा के उद्धार को अभियान बना दिया। उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंगा समेत अन्य नदियों को पुनर्जीवन देने के लिए कमर कसे हुए हैं। उनकी पहल पर दो दिन बाद बलिया और बिजनौर से गंगा यात्राएं शुरू होने जा रही हैं जिनमें योगी के अलावा राज्यपाल भी शामिल होंगी। पांच दिन बाद दोनों यात्राओं का संगम एवं समापन कानपुर में होगा जहां गंगा की स्थिति सर्वाधिक संवेदनशील है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयास उम्मीद जगाने वाले हैं यद्यपि सिर्फ सरकार के प्रयास से नदियों को प्रदूषणमुक्त करके अविरल-निर्मल बनाना संभव नहीं है। इसके लिए हर आम-ओ-खास व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नदियों को सर्वाधिक नुकसान औद्योगिक इकाइयों की संकीर्ण सोच और नगर निकायों की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली ने पहुंचाया है। गैरभाजपा सरकारों के शासनकाल में गंगा और यमुना को प्रदूषणमुक्त करने के नाम पर खरबों रुपये पानी में बह गए जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं। कागजी कवायद की आड़ में घोटालों के चलते वक्त के साथ नदियों की हालत बदतर ही हुई है।

नदियों से जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक स्वच्छ जल प्राप्त होता है। ऐसे में नदियों का अस्तित्व बचाने के लिए जो भी आवश्यक हो, किया जाना चाहिए।

नदियों के महत्व से हर कोई वाकिफ है। इनसे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक स्वच्छ जल प्राप्त होता है यही कारण है कि अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं, जनजातियां नदियों के समीप ही विकसित हुईं। भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास विकसित हुई। संपूर्ण विश्व के बहुत बड़े भाग में, पीने का पानी और घरेलू उपयोग के लिए पानी, नदियों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी नदियां बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि उद्योगों के लिए आवश्यक जल नदियों से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। सिंचाई के लिए आवश्यक पानी नदियों द्वारा प्रदान किया जाता है। नदियां घरेलू एवं औद्योगिक गंदे एवं अवशिष्ट पानी को अपने साथ बहकर ले भी जाती हैं। नदियों में मत्स्य पालन से मछली के रूप मे खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। नदियों पर बांध बनाकर उनसे पन बिजलीघर बनने से बिजली प्राप्त होती है। इसके अलावा नदियों से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है।

ऐसे में नदियों का अस्तित्व बचाने के लिए जो भी आवश्यक हो, किया जाना चाहिए। जीवन एवं मोक्षदायी नदियों का जल अब जहर बन चुका है। इसे जल्द ही फिर अमृत न बनाया गया तो यह जहर किसी को भी नहीं बख्शेगा। निराशाजनक है कि लोग अभी भी नदियों में शव, सीवर, नालों का पानी और पूजन सामग्री प्रवाहित करने की धृष्टता से बाज नहीं आ रहे। सरकार को विचार करना चाहिए कि क्या इसे रोकने के लिए किसी सख्त कानून की जरूरत है?

नर्मदा की तलहटी में मिलीं दो दुर्लभ प्रजाति की मछलियां

आशीष दीक्षित, होशंगाबाद

नर्मदा नदी की तलहटी में दो दुर्लभ प्रजाति की मछलियां मिली हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्देश पर वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक चले शोध में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के शासकीय नर्मदा महाविद्यालय की प्राणी शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. आशा ठाकुर ने यह खोज की है। खोज में कुल 35 प्रजातियों की मछलियां मिली हैं, इनमें से दो को दुर्लभ माना गया है। इन दो प्रजातियों के दुर्लभ होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश में मछलियों पर लिखी गईं दस प्रमुख किताबों में भी इनका जिक्र नहीं है। इन मछलियों को कॉलेज की लैब में सुरक्षित रखकर आयोग को रिपोर्ट भेज दी गई है।

डॉ. ठाकुर के मुताबिक, यूजीसी ने नर्मदा में मछलियों और जैव विविधता पर शोध कराया था। इसका विषय 'फिश कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नर्मदा एंड बायोडायवर्सिटी' था। शोध के लिए यूजीसी ने करीब 50 हजार रुपये दिए थे। नर्मदा के सेठानीघाट, विवेकानंद घाट, हर्बल पार्क घाट, बांद्राभान घाट, खर्राघाट, मंगलवारा घाट, घोडासफील घाट व आंवरीघाट पर मछुआरों की मदद से मछलियों की खोज कर अध्ययन किया गया।

इन किताबों में नहीं मिली दुर्लभ मछलियों की प्रोफाइल

- एडवान्समेंट ऑफ फिश फिशरीज एंड टेक्नालॉजी-लेखक केपी बिसवास
- एक्वाकल्चर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी-लेखक केपी फिल्क्स
- डिसकस ऑफ फिशेज-लेखक के वी डुयुईजन
- डायवरसिफिकेशन ऑफ एक्वाकल्चर-लेखक अर्चना सिन्हा
- फिश एंड फिशरीज ऑफ नार्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया-लेखक एम. सिन्हा
- फ्रेश वॉटर फिशेज ए प्रेक्टीकल एप्रोच-लेखक वायके खिल्लर
- फंडामेंटल ऑफ फिश टेक्सोनॉमी-लेखक केसी जयाराम
- हैंडबुक ऑफ फिशरीज मैनेजमेंट-लेखक केसी बडापंडा
- सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कनजरवेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी-लेखक एएम पांडे
- टेक्स्ट बुक ऑफ ब्रीडिंग एंड हेचरी मैनेजमेंट ऑफ क्रेप-लेखक गुप्ता एंड मनहोत्रा

होशंगाबाद की प्राणी विज्ञानी द्वारा नर्मदा नदी में खोजी गई दुलर्भ प्रजाति की मछली। इसे नर्मदांसीस नाम दिया है। नई दुनिया

जैव विविधता के लिहाज से नर्मदांचल को काफी विस्तृत माना जाता रहा है। यूजीसी के शोध के दौरान दुर्लभ प्रजाति की मछली को ढूंढ़ने में सफलता मिली है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।
- अनिल अग्रवाल, जिला प्रबंधन समिति सदस्य, मध्य प्रदेश जैव विविधिता बोर्ड

मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित शासकीय नर्मदा महाविद्यालय की लैब में सुरक्षित मछलियों की 35 प्रजातियों को प्रोफेसर आशा ठाकुर ने दिखाया। नई दुनिया

कुल 35 प्रजातियों की मछलियां मिलीं

डॉ. ठाकुर ने बताया कि नर्मदा क्षेत्र में कुल 35 प्रजातियों की मछलियां मिलीं। इनमें से एक दुर्लभ मछली बांद्राभान घाट के पास गहराई में मिली। शोध में मदद कर रहे तीन विशेषज्ञ मछुआरे भी इसके बारे में कुछ नहीं बता सके। मछली के एक सैंपल को कॉलेज की लैब में फार्मेलीन का लेप लगाकर सुरक्षित रखा है। नर्मदा में मिलने के कारण फिलहाल इसे 'नर्मदांसीस' नाम दिया है। यह समुद्र में पाई जाने वाली जेब्रा मछली से मिलती-जुलती है। दूसरी दुर्लभ मछली खर्राघाट पर नेनड्स प्रजाति की है। नैनड्स पहाड़ी जगहों पर मिलने वाली मछली है। बरसात के दौरान इस मछली का संग्रह किया था। खर्राघाट पर पत्थरों की अधिकता है, इसलिए इस मछली की मौजूदगी वहां रही है।

38 साल बाद मध्य प्रदेश के घाटीगांव में सोनचिरैया को फिर से बसाने की तैयारी

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के घाटीगांव अभयारण्य में 38 साल बाद सोनचिरैया को फिर से बसाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। वन विभाग ने 10 साल की कार्ययोजना तैयार की है। इस पर करोड़ों रुपये खर्च होंगे। विभाग इस क्षेत्र को मुरैना के घड़ियाल प्रजनन केंद्र की तर्ज पर विकसित करेगा और राजस्थान के जैसलमेर से सोनचिरैया के अंडे लाकर यहां उनकी हेचिंग कराई जाएगी। मांसाहारी वन्यजीवों से अंडों को बचाने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। घाटीगांव अभयारण्य अधीक्षक ने क्षेत्र में सोनचिरैया को बसाने की योजना वाइल्ड लाइफ मुख्यालय को भेज दी है।

योजना के तहत, इस बार पक्षियों को अपने हाल पर नहीं छोड़ा जाएगा। अंडों से निकलने वाले चूजों को अभयारण्य में सुरक्षित वातावरण दिलाने की कोशिश की जाएगी। वैसे तो वन विभाग घाटीगांव में एक भी सोनचिरैया नहीं होने की जानकारी विधानसभा को दे चुका है, लेकिन विभाग के अफसरों का मानना है कि क्षेत्र में अभी भी ये पक्षी हैं। वाइल्ड लाइफ मुख्यालय के अफसर बताते हैं कि यहां का वातावरण सोनचिरैया के अनुकूल होने की संभावना के चलते ही फिर से प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, योजना के लिए राशि मिलने पर ही काम आगे बढ़ेगा। मालूम हो, 38 साल पहले घाटीगांव अभयारण्य को सोनचिरैया की बसाहट के लिए तैयार किया गया था।

12 साल से नहीं दिखी : घाटीगांव अभयारण्य क्षेत्र में पिछले 12 साल से सोनचिरैया नहीं दिखाई दी है। वर्ष 2008 में एक घायल पक्षी मिला था, जिसकी इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई थी। हालांकि, वर्ष 2011 में देवखो के जंगल में सोनचिरैया का अंडा जरूर मिला था।

111 वर्ग किमी क्षेत्र घट जाएगा : विभाग सोनचिरैया को फिर से बसाने की कोशिशों में लगा है, लेकिन घाटीगांव अभयारण्य को 111 वर्ग किमी क्षेत्र कम हो रहा है, जिसका इस योजना पर असर पड़ सकता है। विभाग स्थानीय लोगों की समस्या के चलते करैरा अभयारण्य को डि-नोटिफाई कर चुका है और घाटीगांव अभयारण्य का 111 वर्ग किमी क्षेत्र भी डि-नोटिफाई करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। संभवतः यह भी जल्द ही मंजूर हो जाएगा।

सोनचिरैया फाइल

- वन विभाग ने बनाई 10 साल की कार्ययोजना
- राजस्थान के जैसलमेर से लाए जाएंगे सोनचिरैया के अंडे

अभयारण्य प्रबंधन सोनचिरैया से संबंधित प्रबंध योजना लेकर आया था। 10 साल की योजना प्रस्तुत की गई है। प्रेजेंटेशन भी दिया गया है।
- जेएस चौहान, अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वाइल्ड लाइफ

देसी गाय में बढ़ रहे सोमेटिक सेल काउंट दुग्ध उत्पादों की विदेश में भी बढ़ेगी मांग

पवन शर्मा, करनाल

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआइ) करनाल के ताजातरीन शोध में पता चला है कि देसी गाय की ज्यादातर नस्लों में सोमेटिक सेल काउंट की तादाद अब एक लाख से बढ़कर डेढ़ लाख प्रति मिलीलीटर यूनिट तक पहुंच गई है। संस्थान द्वारा विकसित करण स्विस सरीखी नस्लों में ये सेल दो लाख तक हो सकते हैं। विदेश में दो लाख सोमेटिक सेल काउंट ही उच्च गुणवत्ता का मानक है। स्पष्ट है कि मानक पर खरा उतरने के बाद देसी गायों व उनके दुग्ध उत्पादों की मांग विदेश में भी बढ़ेगी।

एनडीआरआइ में देसी गाय की कई नस्लों पर अनुसंधान होता है। इनमें साहीवाल, थारपारकर, गिर और राही आदि शामिल हैं। देसी नस्ल की इन गायों के दूध में ए-2 पाया जाता है, जो मानव शरीर के लिए अति लाभदायक है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अभी तक सोमेटिक सेल काउंट एक लाख होने के कारण विदेश में इन गायों और इनके दुग्ध उत्पादों को महत्व नहीं मिलता था। संस्थान के पशु शरीर क्रिया विभाग के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र सिंह बताते हैं कि आम तौर पर देसी गायों के एक एमएल दूध में एक लाख सोमेटिक सेल पाए जाते रहे हैं। अब इनकी मात्रा डेढ़ लाख तक मिल रही है।

क्या है सोमेटिक सेल काउंट : सोमेटिक सेल काउंट दूध में शामिल दैहिक कोशिकाओं की एक कोशिका गणना होती है। इससे दूध की गुणवत्ता का पता चलता है। खासकर, हानिकारक बैक्टीरिया व उच्चस्तरीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे परखा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अधिकांश दैहिक कोशिकाओं का गठन करती हैं।

मौसम की चुनौती झेलने में भी देसी गाय सक्षम : देसी गाय मौसम व तापमान की चुनौतियां सहने में भी खरी उतर रही है। संस्थान में हुए शोध में पता चला है कि संकर या विदेशी नस्ल की तुलना में देसी गाय जलवायु परिवर्तन से कम प्रभावित होती हैं। गर्मी में 40 से ज्यादा व सर्दियों में 20 डिग्री से कम तापमान होने पर दूध उत्पादन में 30 फीसद तक गिरावट आती है, लेकिन देसी नस्ल की गायों पर इसका खास असर नहीं होता। इसके लिए एमसीआर-वन और सरीखे कुछ खास किस्म के जीन जिम्मेदार हैं, जो देसी नस्लों में ही मिलते हैं।

- अब डेढ़ लाख तक पहुंच रही एससीसी की संख्या, मानक काउंट दो लाख तक पहुंचने की संभावना

प्रतीकात्मक

20 फीसद दुग्ध उत्पादन देसी गायों से

देश में गायों की 39 और भैंस की 13 प्रजातियां हैं। कुल दूध उत्पादन का 51 फीसद भैंसों से मिलता है। 20 फीसद देसी व शेष अन्य नस्लों की गायों से प्राप्त होता है। तापमान बढ़ने या घटने पर अन्य नस्लों में दूध उत्पादन गिरने के साथ प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है, लेकिन देसी की गाय मौसम की तमाम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होती हैं।

अब पता चलेगा कि गंगा-यमुना में कितना पानी

केदार दत्त, देहरादून

गंगा और यमुना जैसी सदानीरा नदियों के उद्गम स्थल उत्तराखंड में नदियों में वास्तव में कितना प्रवाह है, अब सही मायने में इसका पता चल सकेगा। इसके लिए नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट (एनएचपी) के तहत राज्य में गंगा, यमुना, शारदा व रामगंगा के साथ ही इनकी सहायक नदियों में ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर (एडब्ल्यूएलआर) लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग एडब्ल्यूएलआर के अलावा यहां रेनगेज, स्नोगेज और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। नदियों के जलीय सिस्टम से संबंधित रीयल टाइम डाटा लेने के मकसद से यह मुहिम एक साल के भीतर आकार ले लेगी।

देशभर में नदियों के जलीय सिस्टम से संबंधित रीयल टाइम डाटा के मद्देनजर केंद्रीय जल आयोग ने बड़ी पहल की है। इसके तहत मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों में ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर लगाने के साथ ही अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में एनएचपी के तहत उत्तराखंड की नदियों को भी शामिल किया गया है।

राज्य में सिंचाई विभाग को इस प्रोजेक्ट का जिम्मा सौंपा गया है। विभाग के अधीक्षण अभियंता शंकर कुमार साहा बताते हैं कि प्रोजेक्ट के तहत गंगा, यमुना, शारदा व रामगंगा नदियों के साथ ही इनकी सहायक नदियों में 59 ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर, 44 ऑटोमेटिक रेनगेज, पांच स्नोगेज, 11 मैनुअल रेनगेज और एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी मिली है। उपकरणों की स्थापना को अब तक 115 स्थल चिह्नित किए गए हैं। फरवरी में टेंडर होंगे और फिर अप्रैल में स्थापना का कार्य शुरू होगा। सालभर में यह सिस्टम स्थापित कर दिया जाएगा।

- केंद्रीय जल आयोग के नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत नदियों में लगेंगे एडब्ल्यूएलआर
- उत्तराखंड में गंगा, यमुना, शारदा व रामगंगा समेत इनकी सहायक नदियों का मिलेगा आंकड़ा
- सिंचाई विभाग को सौंपा गया है इस काम का जिम्मा, 115 स्थल किए गए अब तक चिह्नित

नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर लगाए जा रहे। फाइल

गंगा बेसिन को पहली प्राथमिकता

सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता पीसी गौड़ के अनुसार एनएचपी प्रोजेक्ट में गंगा बेसिन को पहली प्राथमिकता दी गई है। फिर यमुना, शारदा, रामगंगा बेसिन में उपकरण स्थापित किए जाएंगे।

विकसित होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम

नदियों में इन उपकरणों के स्थापित होने पर इनसे डाटा सीधे दिल्ली में मॉनीटर किया जाएगा। असल में सेटेलाइट के जरिये ये उपकरण सीधे दिल्ली में जल आयोग से जुड़े होंगे। फिर आयोग यह डाटा राज्य को भेजेगा। डाटा मिलने पर ये पता चल सकेगा कि कहां और किस नदी में कितना प्रवाह है। बारिश, बर्फबारी के आंकड़े मिलने पर निचले क्षेत्रों में यह भी बताया जा सकेगा कि वहां कितना प्रवाह रह सकता है। यह एक प्रकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा। आंकड़े उपलब्ध रहने पर भविष्य में नदियों में जलस्तर बढ़ाने के मद्देनजर जलसमेट क्षेत्रों में कदम भी उठाए जा सकेंगे।

तंत्र के गण

उत्सव गणतंत्र का...

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 यह प्राविधान करता है कि कोई भी समाज का कोई भी वर्ग, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा है, उसे इसके संरक्षण का पूरा अधिकार है और यह राज्य का भी दायित्व है कि वह इसकी पूर्ति करे। भारतीय संविधान वर्तमान में देश के अलग-अलग हिस्सों, समुदायों द्वारा बोली जाने वाली कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देता है।

भाषा का अधिकार

सांकेतिक भाषा को 23वीं भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता देने की मांग।

देश में 22 भाषाएं स्वीकार्य हैं तो एक 23 वीं भाषा हमारी भी हो...

हमें भी है अभिव्यक्ति का अधिकार

साइन लैंग्वेज को राइट टू लैंग्वेज बनाए जाने की मांग कर रहे मूक-बधिर

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मूक-बधिरों की संख्या करीब 50 लाख है। लेकिन बधिरों के हित संवर्द्धन से जुड़े अखिल भारतीय संगठन- नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ का कहना है कि यह संख्या एक करोड़ 80 लाख है। यही हाल मूक समाज का है। बहरहाल, न्यायालय में याचिका लगा मांग की गई है कि सांकेतिक भाषा को भाषा के अधिकार के तहत मान्यता दी जाए। इनकी मांग और बातों को सामने रखती नई दिल्ली से मनु त्यागी की रिपोर्ट।

मूक-बधिरों के साथ रूमा रोका (मध्य), मूकबधिरों के लिए कुछ करने के जज्बे ने उन्हें इनके साथ ला खड़ा किया। ● सौ. रूमा रोका

मूक-बधिरों के साथ अनुज जैन (मध्य)। ● सौ. अनुज जैन

हम मौन हैं, बोल-सुन नहीं सकते, लेकिन बोलने-सुनने का हक उतना ही है, जितना आपको...। अभिव्यक्ति का हक उतना ही है जितना आपको...। भले जुबां साथ न दे, समाज के स्वर कानों तक पहुंचते न हों, पर एहसास है, आभास है, क्योंकि हम भी इंसान हैं...। इशारों की ही सही, लेकिन यही हमारी भाषा है, यही अभिव्यक्ति। इसे संवैधानिक मान्यता मिलने से हमारी यह भाषा संरक्षित और समृद्ध होते हुए हमारे समाज के लिए मददगार सिद्ध होगी...। यह कहना है नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ के निदेशक अनुज जैन का। संगठन की ओर से न केवल इसे लेकर कैंपेने चलाया जा रहा है वरन गत वर्ष कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है।

अनुज कहते हैं, हमारा कैंपेन देश की मूक-बधिर आबादी का प्रतिनिधित्व है, उनकी आवाज है। दरअसल, इनके पास अभिव्यक्ति का जो सहज साधन है, वह है सांकेतिक भाषा, जिसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। इसके जरिये ये अपनी बात पूरे अधिकार से रखते हैं। ये लोग सांकेतिक भाषा का संरक्षण और संवर्द्धन भी चाहते हैं ताकि इनका यह एकमात्र माध्यम इनकी आवाज बना रहे। मांग सिर्फ इतनी सी है कि ये जिस भाषा में खुद को अभिव्यक्त करते हैं, उसे समाज और संविधान स्वीकार्यता दे, उसका सम्मान करे। देश के संविधान में फिलहाल 22 भाषाएं अधिकृत भाषा के रूप में सूचीबद्ध हैं। हमारी मांग है कि 23वीं भाषा हमारी भी हो। इसे भाषा के अधिकार में शामिल किया जाए...।

अनुज ने सांकेतिक भाषा में एक सहयोगी के माध्यम से हमसे कहा, मैं जब छोटा था मुझे भी अपने अधिकारों का पता नहीं था। मेरी तीन बहनें भी मेरी तरह मूक-बधिर थीं। हम ऐसे ही अपने अधिकारों को जाने-समझे बगैर बड़े हो गए, लेकिन अब चाहता हूं कि आगे दिक्कतें न आएं। इसीलिए पुलिस के माध्यम से और कंपनियों में जाकर मूक-बधिरों के अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं। वर्कशॉप की जाती हैं। होता यह है कि कंपनियों में जब कोई मूक-बधिर नौकरी करता है तो लोग उससे किनारा करते हैं। समाज में हर कोई उनकी सांकेतिक भाषा तो नहीं समझ सकता, लेकिन हम साधारण तरीकों से भी उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हालांकि अब धीरे-धीरे बदलाव भी आ रहे हैं। मैं 15 साल से मूक-बधिरों के अधिकारों को उन तक पहुंचा।

सिग्नेचर कैंपेन से जागे लोग: अनुज ने बताया कि याचिका पर निर्णय आना शेष है। इसके अलावा सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया है, जिस पर अब तक सालभर में तकरीबन 50 हजार लोग साइन कर सांकेतिक भाषा के अधिकार की जरूरत जता चुके हैं। उन्होंने कहा, सरकार को इस व्यथा पर सोचना चाहिए।

स्कूलों में नहीं हैं साइन लैंग्वेज के शिक्षक

अनुज जैन कहते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि मूक-बधिरों के लिए जितने भी स्कूल हैं, उनमें सांकेतिक भाषा के कुशल शिक्षकों का नितांत टोटा रहता है। वहां बच्चों को सांकेतिक भाषा में बात करना सिखाने के बजाए उन्हें दूसरों की बात को सुनने और समझने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वर्ष 2016 में दिव्यांगता अधिकार विधेयक-2016 को पारित किया गया। उसके बाद मैंने डेफ एसोसिएशन के माध्यम से मूक-बधिर स्कूलों में शिक्षकों के स्तर पर भी बदलाव के लिए मांग रखी है। लोगों को यह समझाया है कि यदि एक मूक-बधिर बच्चे को स्कूली स्तर पर ही सांकेतिक भाषाओं का ज्ञान दिया जाए, उसकी पहली भाषा, जिसमें वह सबकुछ सीखे सांकेतिक हो। हर मूक-बधिर को सांकेतिक भाषा नहीं आती। इसीलिए हमारा सबसे पहला लक्ष्य यही है कि स्कूल भी इस भाषा से सुशिक्षित हों। 2011 में हमने बधिरों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने को लेकर याचिका लगाई थी, जिसके बाद अब बधिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

रूमा बना रहीं काबिल

एक दिन अचानक चैनल बदलते वक्त मूक-बधिर समाचारों पर नजर पड़ी। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तय किया कि मूक-बधिरों के लिए कुछ करूंगी, उन्हें सुशिक्षित करूंगी। इसके लिए पहले मैंने खुद जाना समझा कि आखिर ये बच्चे सीखते कैसे हैं और फिर व्यवस्थित शुरुआत की इनका सहयोग करने की...। यह कहना है रूमा रोका का, जो मूक-बधिरों के कल्याण के लिए संघर्षरत हैं। रूमा ने 2004 में सांकेतिक भाषा का कोर्स किया और ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोला। रूमा कहती हैं कि यह सब आज कहने में आसान लगता है, लेकिन खुद को उसी स्तर पर ले जाकर उन्हीं की तरह एहसास करने के बाद ही यह संभव हो सका। दरअसल, ऐसे बच्चों को कम उम्र से ही प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है, ताकि समय रहते वे सब कुछ सीखकर मुख्यधारा में शामिल हो सकें। जिंदगी की खूबसूरती को जी सकें और अपनी जिंदगी में भी कुछ रंग भर सकें। कहती हैं, मैंने वर्ष 2005 में नोएडा डेफ सोसायटी का गठन किया था। हमारे देश में एक करोड़ बीस लाख बधिर हैं, जिनमें से 80 फीसद ऐसे हैं, जिन्हें आधारभूत शिक्षा भी नहीं मिलती। अपने छोटे से घर के एक कमरे में पांच बच्चों के साथ इसकी शुरुआत की थी और अकेली शिक्षक थी, लेकिन आज 1200 छात्र हैं। कई साल से तो अब ये छात्र खुद ही मेरे यहां और बच्चों को लेकर आते हैं।

किसी से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अब तो हर साल कहीं न कहीं मुख्य धारा में जुड़कर काम कर रहे हैं। अब 2400 बच्चों समाज में समान रूप से नौकरी मिल चुकी है। मॉल, बैंक, मैन्यूफैक्चर में सभी जगह नौकरी कर रहे हैं। बकौल रूमा, जो लोग सुन नहीं पाते हैं, हमें उन्हें इतना काबिल बनाना था और बनाना है कि सुनने के अलावा वे कुछ भी कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे कोई सामान्य इंसान कर सकता है। खुशी है कि मैंअपने स्तर पर इसमें सफल हो रही हूं, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

सिखाने को सीखी साइन लैंग्वेज

तान्या को पढ़ातीं शिक्षिका प्रज्ञा श्रीवास्तव। ● जागरण

दिलीप शर्मा ● मैनपुरी

बेटी को पढ़ाने की ये तमन्ना ही थी कि एक मजदूर बोलने-सुनने में अक्षम अपनी बिटिया को गांव के परिषदीय स्कूल में दाखिला कराने पहुंच गया। शिक्षक के लिए ये फर्ज की परीक्षा थी कि वह दाखिला देने के साथ ही बेटी को उसी की भाषा में शिक्षा भी दे। पढ़ने को लेकर बालिका में ललक दिखी तो उत्साहित शिक्षिका ने भी होमवर्क किया। यूट्यूब से साइन लैंग्वेज सीखी, कक्षा में अभ्यास किया। अंततः सफलता पाई और सिखाना शुरू किया। वह बच्ची अब कक्षा चार की छात्रा है।

सिस्टम को आईना दिखाती ये सराहनीय पहल मैनपुरी, उप्र की प्राथमिक पाठशाला बदनपुर की है। वर्ष 2016 में गांव का मजदूर दलवीर सिंह बेटी तान्या का दाखिला कराने आया। बोलने-सुनने में दिव्यांग तान्या को लेकर हेडमास्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव एकबारगी हिचकीं, मगर इसे पढ़ाने को एक चुनौती के रूप में लेते हुए कक्षा एक में दाखिला दे दिया। प्रज्ञा बताती हैं कि कई दिनों तक यही सोचती रहीं कि इस बच्ची को कैसे पढ़ाएं। एक दिन यूट्यूब का सहारा लिया। साइन लैंग्वेज के अमेरिकन और ब्रिटिश फॉर्मेट के ट्यूटोरियल खंगालने के बाद ब्रिटिश फॉरमेट में टू हैंडेड लैंग्वेज का अभ्यास शुरू कर दिया। सांकेतिक भाषा का एक चार्ट लाकर कक्षा में लगा दिया। तान्या से संकेतों की भाषा में संवाद होने लगा। बताती हैं कि दो महीने तक पढ़ाने में बहुत मुश्किल आई, परंतु धीरे-धीरे तान्या भी इस भाषा को समझने लगी। इस सत्र में तान्या कक्षा चार में पढ़ रही है। प्रज्ञा बताती हैं कि तान्या सामान्य बच्चों की तरह एबीसीडी, गिनती, हिंदी के लेखन-अध्ययन के साथ गणित के सवाल भी हल कर लेती है। बतौर शिक्षिका प्रज्ञा श्रीवास्तव को नवाचार के लिए विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है।

भोजन का अधिकार

350 गरीबों को इस अन्नपूर्णा में मिलता है भरपेट भोजन

आशीष सिंह ● धनबाद

घर से लेकर होटल तक भोजन की बर्बादी अक्सर दिखती है। दूसरी ओर देश के अनेक गरीब भूखे पेट सो जाते हैं। गरीबों के इस दर्द को समझते हुए धनबाद, झारखंड के कुछ युवाओं ने अपने स्तर पर पहल की। धनबाद राइजिंग चैरिटेबल सोसायटी बनाकर ये युवक गरीबों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही भोजन की बर्बादी भी रोक रहे हैं।

सेवा की यह लौ जली तो बढ़ती चली गई। आज इस संस्था में 270 सदस्य जुड़े हैं। खास बात यह भी है कि इस सोसायटी में न कोई अध्यक्ष है और न सचिव। सदस्यता शुल्क से प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को 350 गरीबों को भोजन कराया जाता है। जाति-धर्म का बंधन नहीं है। सभी एक साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं।

गरीबों को भोजन कराते सोसायटी के सदस्य। ● जागरण

भोजन कराने आए सोसायटी के 20 से 25 सदस्य भी इनके साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। पंक्ति में बैठकर पहले भोजन कर चुके गरीब अपने भोजन की पारी खत्म होने के बाद अन्य सदस्यों को भोजन कराने के श्रमदान में जुट जाते हैं।

87 सदस्यों ने की थी शुरुआत: सोसायटी के राजन सिन्हा कहते हैं कि कुछ दोस्तों के साथ 2013 में सोसायटी की नींव रखी। इससे पहले 1986 में राइजिंग क्रिकेट क्लब की शुरुआत की थी। 2003 तक क्रिकेट खेले। इस बीच क्लब के सभी खिलाड़ियों की नौकरी लग गई। खेल से किनारा हो गया। तब सोचा कि गरीबों को निश्शुल्क भोजन कराकर समाजसेवा कर सकते हैं। मई 2013 में 122 जरूरतमंदों को भोजन करा मुहिम शुरू कर दी। इसके बाद यह सिलसिला आज तक जारी है। शुरुआत में टीम 87 सदस्य थे, जो अब बढ़कर 270 हो गए हैं। गरीबों के बीच कंबल वितरण व वस्त्र वितरण भी सोसायटी की ओर से किया जाता है। इसके लिए वर्ष में दो बार सोसायटी के सभी सदस्य पुराने कपड़े एकत्रित करते हैं। बाद में गरीबों के बीच इनका वितरण किया जाता है।

हर सदस्य देता है एक हजार रुपये वार्षिक शुल्क: राजन सिन्हा ने बताया कि सेवा के इस काम के लिए किसी से चंदा नहीं लेते। सोसायटी के सदस्य आपसी सहयोग से ही फंड की कमी दूर करते हैं। हर सदस्य वार्षिक शुल्क के तौर पर हजार रुपये देता है। धन की कमी हुई तो सदस्य आपस में फिर सहयोग राशि एकत्र कर लेते हैं। धनबाद के गोल्फ मैदान में खड़ेश्वरी मंदिर के समीप राजेंद्र पार्क में भोजन कराते हैं।

गरीबों को भोजन कराना हमारे लिए पूजा: सिन्हा कहते हैं कि रिक्शा वाला हो या भिक्षा मांगने वाला, सोसायटी के सदस्य अपनेपन के साथ उसे भोजन कराते हैं। मकसद यही कि कोई भी समाज में भूखा न रहे और जो भोजन करने आया है वह श्रद्धा, आनंद, संतुष्टि और सम्मान के साथ अपनी भूख शांत करे। कुष्ठ रोगियों को भी पूरी तन्मयता से भोजन कराते हैं। हमारा मूल मंत्र है गरीबों में भगवान बसते हैं, इसलिए उनको भोजन कराना हमारे लिए किसी पूजा प्रार्थना से कम नहीं है।

500 असहाय बुजुर्गों को खिलाते हैं खाना

बुजुर्ग को राशन देते तुलसी राम मंत्री (बाएं)। ● जागरण

प्रकाश पांडेय ● कोलकाता

बुजुर्गों के लिए उनके बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं लेकिन कई लोगों के बुढ़ापे की लाठी खुद एक बुजुर्ग हैं। ये शख्स हैं 68 साल के तुलसी राम मंत्री। बंगाल के हावड़ा जिले के रहने वाले तुलसी राम 500 असहाय बुजुर्गों को नियमित रूप से राशन मुहैया कराते हैं। उन्होंने अपनों की उपेक्षा के शिकार इन लोगों को आजीवन राशन मुहैया कराने का संकल्प लिया है। तुलसी राम अपने साथियों के साथ हर महीने नियमित रूप से उनके घरों में राशन पहुंचाते हैं। बीमार पड़ने पर उन्हें चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

तुलसी राम ने बताया, इस अभियान की शुरुआत 2001 में छगनलाल भकड़ नामक एक बुजुर्ग ने की थी। उन्हीं की मुहिम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। शुरू में 15 बुजुर्गों को महीनेभर का राशन मुहैया कराया जाता था। धीरे-धीरे संख्या बढ़ती गई। आज करीब 500 बुजुर्गों को आजीवन राशन मुहैया कराने के संकल्प के साथ हम अग्रसर हैं। उन्होंने आगे कहा, बुजुर्गों को आजीवन राशन प्रदान करने को हमने लॉयंस क्लब ऑफ हावड़ा ग्रेटर बी टू की ओर से फूड फॉर लाइफ योजना की शुरुआत की। इस योजना के लिए दान करने वाले भी आगे आ रहे हैं। हम इस योजना का भविष्य में और विस्तार करेंगे ताकि निराश हो चुके असहाय बुजुर्गों को फिर समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर सके। तुलसी राम का इस नेक पहल में अजय सिंह समेत अन्य सहयोग करते हैं।

तुलसी राम ने कहा, पहले हम अन्य लोगों की तरह विशेष अवसरों पर कंबल आदि वितरित कर सेवा धर्म का पालन करते थे, लेकिन सही मायने में छगनलाल भकड़ हमारे लिए प्रेरणास्रोत बने। उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलकर हमने इस योजना की शुरुआत की। आज हमें उस वक्त बेहद खुशी होती है, जब राशन देते वक्त बुजुर्ग हमें आशीष देते हैं।

योजना से लाभान्वित हो रहीं 69 साल की दुर्गावाँ देवी ने कहती हैं, जिस बेटे के लिए अपनी हर इच्छा को त्यागकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, आज उसी ने मुंह मोड़ लिया। चौतरफा अंधेरे के समय तुलसी उम्मीद की किरण बनकर आए।

न अन्न की बर्बादी, न भूखी सोती आबादी

राजेश भट्ट ● लुधियाना

खुशी के मौके पर जब किसी को यह चिंता नहीं होती कि कितना खाना बच गया, जिसे फेंक दिया जाएगा, तब कुछ लोग हैं जो फिक्रमंद रहते हैं कि निवाला कूड़े में नहीं किसी के पेट में जाए। वंचितों को भोजन नसीब हो, इसके लिए दिन रात एक करते हैं यह लोग। नतीजा, शहर में तीन साल पहले शादी या खुशी के मौकों पर आयोजित समारोहों में बचा सैकड़ो लोगों के खाने लायक खाना कूड़ेदानों में चला जाता था, वह अब भूखों के पेट में जाता है। तीन साल बाद अब तस्वीर बदल चुकी है। घरों, होटलों और समारोहों में बचे खाने से अब रोजाना दो हजार लोगों का पेट भर रहा है। यह नेक कार्य कर रहे हैं फीडिंग इंडिया संस्था से जुड़े लोग। शुरुआत चार्टर्ड एकाउंटेंट अनिरुद्ध साही ने की। संस्था की शुरुआत चार-पांच दोस्तों ने की थी। अब संस्था के 160 सदस्य हैं। उनमें से 70 सदस्य सक्रिय रूप से मुहिम में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस मुहिम से जोमैटो, स्वीगी व उबर ईट्स भी जुड़ चुके हैं। ये बचने वाला खाना संस्था को दान कर देते हैं।

खाने की बर्बादी देख शुरू की मुहिम: अनिरुद्ध बताते हैं कि वे वर्ष 2016 में एक दिन दोस्त की बहन की शादी में गए थे। शादी में हलवाई के साथ उनकी ड्यूटी लगी थी। शादी समारोह के अंत में खाना बच गया तो उन्होंने हलवाई से पूछा कि इस खाने का क्या करोगे। हलवाई बोला- फेंक देंगे। यह बात उन्हें खल गई। उन्होंने सितंबर 2016 में फीडिंग इंडिया की लुधियाना शाखा की स्थापना की। अनिरुद्ध तब सीए की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने अपने दोस्तों को मुहिम से जोड़ा। पहले चरण में शहर के मैरिज पैलेसों, होटलों व रेस्टोरेंटों से संपर्क किया। सभी से अच्छा रिस्पांस मिला। धीरे-धीरे उन्होंने कैटरिंग का काम करने वालों के साथ भी संपर्क साधा। इससे घरों में होने वाले समारोहों का बचा खाना भी उन्हें मिलने लगा। संस्था के सदस्य यह खाना शहर के अलग-अलग इलाकों में जाकर जरूरतमंदों को बांटते हैं। संस्था को सबसे ज्यादा खाना अब धार्मिक स्थलों व घरों में होने वाले समारोहों से मिलता है। शहर की कुछ प्रमुख बेकरी शॉप्स से भी नियमित रूप से खाना मिलता है।

लुधियाना के वृंदावन रोड पर रखा फीडिंग इंडिया संस्था का फ्रिज। ● जागरण

फीडिंग इंडिया की लुधियाना शाखा के सदस्य जरूरतमंदों को खाना वितरित करते हुए। ● जागरण

मैजिक फ्रिज से भी मिलता है गरीबों को खाना: संस्था ने वृंदावन रोड पर एक मैजिक फ्रिज लगाया है। इस फ्रिज में आसपास के लोग अपने घरों से बचा साफ खाना डाल देते हैं। इसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति फ्रिज से खाना ले लेता है। अनिरुद्ध बताते हैं कि जिनके पास खाना बचता है, वे फोन कर सूचना देते हैं और वालंटियर उनके पास पहुंच जाते हैं। खाने की गुणवत्ता को देखने के बाद उसे लिया जाता है। खाना एकत्र करने के बाद उसे बांटने के लिए पहुंचाया जाता है।

पैसे हों तो ठीक, नहीं तो मुफ्त में खाओ

विनीत मिश्र ● मथुरा

ये कान्हा की नगरी है। यहां भक्ति की गंगा तो बहती ही है, पैसे नहीं होने पर खाना भी मुफ्त मिल जाता है। खाना किसी भंडारे में नहीं, ठेल वाले की दरियादिली से मिलता है। मथुरा बस स्टैंड पर छोले-भटूरे और कचौड़ी की दुकान (रेहड़ी) लगाने वाले अमृतलाल 28 साल से जरूरतमंदों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं। उनकी दुकान पर भी बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है- पैसा न होने पर चाय-नाश्ता मुफ्त मिलेगा...।

गोवर्धन क्षेत्र के डीग से वर्ष 1985 में मथुरा आकर बसे अमृतलाल बस स्टैंड के सामने नाश्ते की ठेल लगाने लगे। मुफ्त नाश्ता कराने के सफर के बारे में वह बताते हैं कि वर्ष 1992 में एक दिन उनके पास दंपती अपने चार बच्चों के साथ पहुंचे। तब एक कचौड़ी 50 पैसे की थी। दंपती ने दो रुपये में चार कचौड़ी लीं। अमृतलाल ने पूछा- छह लोग हो और कचौड़ी चार? उस व्यक्ति ने जवाब दिया- इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। और वह मायूस होकर लौटने लगा। उसकी इस विवशता ने अमृतलाल को झकझोर दिया। उन्होंने उसे वापस बुलाया और दो रुपये में दस कचौड़ियां दीं। यहीं से तय कर लिया कि कोई भी भूखा उनकी दुकान से बिना खाए नहीं लौटेगा। वह बताते हैं कि हर रोज 15-20 ऐसे लोग आ जाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते और भूखे होते हैं। उनके चेहरे से ही मुझे पता लग जाता है कि वे भूखे हैं। मैं उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप खाना मुहैया कराता हूं। वह कहते हैं, यह बड़ा पुण्य का काम है। भूखे लोगों का पेट भरकर मन को बेहद सुकून मिलता है।

चंदा से करते किराए में भी मदद: अमृतलाल केवल मुफ्त भोजन ही नहीं कराते। किसी भी यात्री की जेब कट जाती है या फिर यात्रा के लिए पैसे नहीं होते, वह खुद लोगों से चंदा कर उसकी मदद करते हैं। एक वाकये को याद करते हुए वह बताते हैं कि एक बार जयपुर के एक यात्री की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उसके पास पैसे नहीं थे, ऐसे में वह निस्सहाय था। तब न केवल पैसे का इंतजाम कराया बल्कि परिवार को छोड़ने जयपुर तक गए।

मथुरा में ठेला लगाते अमृतलाल। ● जागरण

पैरों से दिव्यांग पर, मदद को दौड़ते

जिंदगी में अपना मकान न बनवा सके अमृतलाल के तीन बेटे और एक बेटी है। एक बेटे और बेटी की शादी कर दी। दो बेटे हाईस्कूल में पढ़ रहे हैं। अमृतलाल की जीवटता ही है कि चार बार एक्सीडेंट में वह पैरों से दिव्यांग हो गए। लेकिन लोगों की मदद करने का उनका सफर लगातार चल रहा है।

विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च स्तर पर

मुंबई : देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जनवरी को खत्म सप्ताह में 94.3 करोड़ डॉलर (करीब 6,600 करोड़ रुपये) बढ़कर 46,216 करोड़ डॉलर (लगभग 32.35 लाख करोड़ रुपये) पर जा पहुंचा। आरबीआइ के इस आंकड़े के मुताबिक यह विदेशी मुद्रा भंडार का सर्वकालिक उच्च स्तर है। आरबीआइ के मुताबिक विदेशी मुद्रा संपत्तियों में बढ़ोतरी के दम पर सकल भंडार में इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा संपत्तियों में डॉलर से इतर अन्य विदेशी मुद्राओं के भाव में उतार-चढ़ाव से हासिल कमाई भी शामिल की जाती है। (प्रेट्र)

मौद्रिक नीतियों की अपनी सीमा है। ऐसे में मांग और विकास की गति को बनाए रखने के लिए संरचनात्मक सुधारों और राजकोषीय उपायों पर ज्यादा जोर की जरूरत है।

— शक्तिकांत दास
गवर्नर, आरबीआइ

संसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
41,613.19	12,248.25	₹ 40,780	₹ 47,277	₹ 71.33	$ 62.13
▲ 226.79	▲ 67.90	▲ ₹ 96	▲ ₹ 238	▲ ₹ 0.07	

भारत 50 से ज्यादा वस्तुओं पर बढ़ाएगा आयात शुल्क

- घरेलू उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार उठा सकती है कदम

नई दिल्ली, रायटर : इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, केमिकल्स और हैंडीक्राफ्ट समेत विभिन्न सेग्मेंट की 50 से ज्यादा वस्तुओं पर सरकार आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। कुछ अधिकारियों और उद्योग जगत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, चीन और कुछ अन्य देशों से करीब 56 अरब (करीब 3.9 लाख करोड़ रुपये) के आयात पर नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली फरवरी को बजट में इस तरह के कदम का एलान कर सकती हैं।

अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने कई वस्तुओं की पहचान कर ली है। व्यापार एवं वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के पैनल की सिफारिश पर इन वस्तुओं पर आयात शुल्क पांच से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार का उद्देश्य कुछ गैर जरूरी चीजों के आयात को नियंत्रित करना है। चीन, आसियान और भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते वाले कुछ देशों से सस्ते आयात से घरेलू मैन्यूफैक्चरर्स को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शुल्क में वृद्धि से घरेलू कंपनियों को बराबरी का मौका मिल सकेगा।

गुणवत्ता मानक भी होंगे तय : सरकार आयातित वस्तुओं को लेकर गुणवत्ता मानक तय करने पर भी विचार कर रही है। भारत में आयात होने वाली बमुश्किल 10 फीसद वस्तुएं ही हैं जिनका नियमन सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के मानकों पर होता है। बजट से पूर्व वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए वित्त मंत्रालय से आयातित वस्तुओं पर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाने की वकालत की है।

महिलाओं के सपनों को पंख लगने की आस

बजट से उम्मीदें

- महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त करने को उठाए जा सकते हैं कदम
- महिलाओं द्वारा संचालित होने वाले उद्यमों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाने का भरोसा

नई दिल्ली, आइएएनएस : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करने में अब बमुश्किल हफ्ताभर बचा है। पहली फरवरी को वित्त मंत्री के बजट पिटारे से हर वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसी ही एक उम्मीद है महिलाओं के सपनों को पंख लगाने की। तमाम महिला उद्यमी आगामी बजट में महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त करने और लैंगिक विषमता दूर करने की दिशा में बड़े कदमों की उम्मीद कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सशक्त करने के लिए बजट में योजनाओं का एलान किया जा सकता है।

लीडरशिप डेवलपमेंट कंसल्टेंट निरुपमा सुब्रमणियन ने कहा, '2019-20 का बजट महिलाओं के अनुकूल था। इसमें महिलाओं से जुड़ी परियोजनाओं और स्कीमों में 4.91 फीसद का आवंटन किया गया था। निर्भया फंड, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और स्वयंसहायता समूहों को वित्तीय मदद आदि सही दिशा में उठाए गए कदम थे। अभी इस दिशा में और कदम उठाए जाने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि मातृत्व अवकाश के बाद महिलाओं को काम पर वापस लाने की दिशा में इन्सेंटिव के प्रावधान होने चाहिए। सरकार को महिलाओं द्वारा संचालित होने वाले कारोबार को अतिरिक्त टैक्स छूट तथा महिला संचालित उद्यमों से करार करने वाली कंपनियों को इन्सेंटिव देने पर भी विचार करना चाहिए। इससे महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

महिला उद्यमियों ने आगामी बजट में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों मोर्चे पर कदम उठाने की बात कही है। पुलिस एवं अन्य सरकारी सेवाओं में लगे लोगों के बीच लैंगिक आधार पर संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों के आयोजन का फंड भी बनाया जा सकता है। समाज के हर वर्ग की महिला के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें वित्तीय रूप से सक्षम बनाया जाए।

एमएसएमई पर ध्यान की जरूरत : बड़ी संख्या में निम्न आय वर्ग से जुड़ी महिलाएं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में कार्यरत हैं। अर्थव्यवस्था के इस सेग्मेंट को मजबूत करने के लिए ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। इससे इस सेक्टर से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। दिल्ली स्थित फर्म इंडी कोलाज की सीईओ अनुराधा सिंह ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए फंड्स ऑफ फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने आर्थिक सुस्ती से निपटने की दिशा में जरूरी कदमों की उम्मीद भी जताई। इस सुस्ती से छोटे उद्यमों को गंभीर नुकसान हुआ है।

टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाया जाए : महिला उद्यमियों ने टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने की जरूरत पर भी बल दिया। इससे महिलाएं ज्यादा बेहतर तरीके से कारोबार कर सकेंगी। आर्थिक सुस्ती और टैक्स के कारण टेक्सटाइल व क्राफ्ट सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बजट में इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उद्यमियों का कहना है कि इस दिशा में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी अच्छी प्रतिभाएं श्रमिक बनकर रह जाएंगी।

पेंट इंडस्ट्री ने कहा, मांग बढ़ाने पर जोर दे सरकार

कोलकाता, प्रेट्र : पेंट निर्माता कंपनियों ने मांग को गति देने के लिए बजट में प्रावधान की अपील की है। बर्जर पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ अभिजीत रॉय ने कहा, 'अर्थव्यवस्था में पिछले सालभर से सुस्ती है। सरकार को टैक्स इन्सेंटिव और इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ाकर मांग सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।' देश की सबसे बड़ी पेंट निर्माता एशियन पेंट्स के सीओओ अमित सिंगले ने कहा, 'टैक्स में कटौती अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल पेंट उद्योग टैक्स में कटौती की उम्मीद नहीं कर रहा है। सरकार को आयकर में राहत व अन्य तरीकों को ग्राहकों की खरीद क्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।' पेंट को पहले 28 फीसद के जीएसटी स्लैब में रखा गया था। जुलाई, 2018 में इसे 18 फीसद की स्लैब में कर दिया गया था।

न्यूज गैलरी

महेश गुप्ता को मिला विशेष सम्मान

नई दिल्ली : केंट आरओ सिस्टम्स लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. महेश गुप्ता को उत्तर प्रदेश के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा विशेष मान्यता प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया है। लखनऊ में आयोजित यूपी दिवस उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्यपाल द्वारा गुप्ता को यह विशेष सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर गुप्ता ने कहा कि मैं इस विशेष सम्मान से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से सम्मान प्राप्त करना और भी खास है। हम उत्तर प्रदेश के विकास में और अधिक योगदान देने तथा उच्च मानकों को जारी रखने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। (वि.)

नौ प्रतिशत विकास दर फिलहाल मुश्किल : देबरॉय

कोलकाता : प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति (पीएमईएसी) के चेयरमैन बिबेक देबरॉय ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर पांच प्रतिशत रह सकती है। मौजूदा स्थिति में नौ प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर हासिल करना मुश्किल है। महत्वाकांक्षी वृद्धि दर साढ़े छह से सात प्रतिशत के बीच हो सकती है। देबरॉय ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी जिस माहौल में वृद्धि कर रही है, उसमें कहीं न कहीं संरक्षणवाद का प्रभाव है और इससे निर्यात में गिरावट आ रही है। जब देश नौ फीसद जैसी तीव्र आर्थिक वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रहा था तब जीडीपी में निर्यात का योगदान लगभग 20 प्रतिशत था। लेकिन अब परिदृश्य बदला हुआ है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के धराशायी हो जाने के बाद विकसित राष्ट्र संरक्षणवादी हो गए हैं, जिससे जीडीपी में निर्यात का बड़ा योगदान संभव नहीं हो पा रहा है। (राब्यू)

अल्ट्राटेक सीमेंट का लाभ 80 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई : देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक के कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफे में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2019) के दौरान 80 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ 712 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो उससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 396 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि समीक्षाधीन अवधि में कंपनी का राजस्व गिरकर 10,176 करोड़ रुपये रह गया, जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 10,294 करोड़ रुपये रहा था। (प्रेट्र)

सड़क निर्माण में देरी करने वाले अफसरों का होगा परफॉर्मेंस ऑडिट

सख्ती ▶ परिवहन मंत्री ने 16 राज्यों में 500 सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल की परियोजनाएं शामिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से कहा है कि वे लंबित सड़क परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे जल्द सुलझाएं। इसी के साथ उन्होंने परियोजनाओं में विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का परफॉरमेंस आडिट के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा के मानेसर में दो दिनों तक चली मैराथन बैठक में गडकरी ने सड़क मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) तथा राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें 16 राज्यों में कुल तीन लाख करोड़ रुपये लागत की 28,304 किलोमीटर लंबी करीब 500 निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें दक्षिण भारतीय राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर की परियोजनाएं शामिल हैं। समीक्षा के दौरान ज्यादातर परियोजनाओं में विलंब के लिए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, खनन रॉयल्टी तथा जीएसटी के भुगतान की समस्याएं आम पाई गईं। इनके चलते परियोजनाओं की समय-सीमा बढ़ानी पड़ रही है।

मानेसर में एनएचएआइ, पीडब्ल्यूडी एवं राज्यों के शीर्ष अधिकारियों से चर्चा करते केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। जागरण

गडकरी ने बैठक में शामिल अधिकारियों के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए राज्यों के आला अफसरों से कहा कि वे उलझे हुए मसलों, खासकर भूमि अधिग्रहण की समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुलझाने तथा जरूरत के हिसाब से परियोजना का प्रारूप बदलें। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण में आने वाले खर्च का दावा राज्य यथाशीघ्र मंत्रालय को भेजें। उसका तुरंत भुगतान किया जाएगा। बाद में सेंट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में से उतनी राशि काट ली जाएगी। उन्होंने परियोजनाओं में जान-बूझकर देरी करने वाले अधिकारियों का परफारमेंस आडिट कराने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए। गडकरी ने एनएचएआइ से दैनिक आधार पर परियोजनाओं की निगरानी करने तथा ठेकेदारों की समस्याएं भी दूर करने भी कहा।

बैठक के बाद गडकरी ने तीन लाख करोड़ रुपये लागत से कुल 7,500 किलोमीटर लंबे 22 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित किए जाने की जानकारी भी दी। इनमें से सवा लाख करोड़ रुपये के 2,500 किमी लंबे तीन कारिडोर पर काम प्रारंभ हो चुका है। इनमें अंबाला-कोटपूतली, अमृतसर-जामनगर के अलावा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे शामिल हैं। बाकी सभी ग्रीनफील्ड कारिडोर के ठेके वित्त वर्ष 2021-22 में दे दिए जाएंगे। गडकरी ने अगले वित्त वर्ष में रोजाना 40 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने अधिकारियों के समक्ष महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में सड़कों के माध्यम से जल संरक्षण के मॉडल की चर्चा भी की।

प्रत्यक्ष कर संग्रह दो दशक में पहली बार गिरावट की ओर

- पिछले वित्त वर्ष का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आंकड़ा चालू वित्त वर्ष में छू पाने पर संदेह
- पिछले वित्त वर्ष 23 जनवरी तक के आंकड़ों के मुकाबले इस वित्त वर्ष में कलेक्शन 5.5 प्रतिशत कम

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, रायटर : देश का कॉरपोरेट व आयकर संग्रह दो दशकों में पहली बार गिरावट की ओर है। कई वरिष्ठ टैक्स अधिकारियों का मानना है कि पिछले वर्ष कॉरपोरेट टैक्स में हुई कटौती और आर्थिक सुस्ती के चलते चालू वित्त वर्ष के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले कमी आ सकती है।

देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी से आई गिरावट और कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती के बीच कई वरिष्ठ टैक्स

इस वर्ष मार्च के आखिर में खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने डायरेक्ट टैक्स के मद में 13.5 लाख करोड़ रुपये कलेक्शन का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष के कलेक्शन से 17 प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि मांग में कमी के चलते कंपनियों ने निवेश से हाथ खींच लिए हैं और नई नियुक्तियों पर भी लगभग रोक लगा रखी है। इस वजह से टैक्स डिपार्टमेंट 23 जनवरी तक इस मद में महज 7.3 लाख करोड़ रुपये ही संग्रह कर पाया है। पिछले वित्त वर्ष की 23 जनवरी तक के आंकड़ों के मुकाबले यह रकम 5.5 प्रतिशत कम है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार को डायरेक्ट टैक्स के मद में 11.5 लाख करोड़ रुपये मिले थे। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि कंपनियों से शुरुआती तीन तिमाहियों के एडवांस टैक्स जमा ले लेने के बाद चौथी तिमाही में वित्त वर्ष के कुल डायरेक्ट टैक्स का अमूमन 30-35 प्रतिशत कलेक्शन होता रहा है।

बजाज बनाएगी दो लाख रुपये से सस्ती ट्रायंफ मोटरसाइकिल

कंपनियों की योजना

- ब्रिटिश ब्रांड ट्रायंफ की सबसे किफायती बाइक की कीमत अभी आठ लाख रुपये है
- साझेदारी के तहत 250-750 सीसी क्षमता तक की बाइक बाजार में उतारी जाएंगी

नई दिल्ली, एजेंसियां : बजाज ऑटो और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांड ट्रायंफ ने शुक्रवार को गैर-इक्विटी वैश्विक साझेदारी की घोषणा की। इसके तहत भारत में नई रेंज की मध्यम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों का उत्पादन किया जाएगा। इनकी कीमत दो लाख रुपये से कम होगी। इनकी इंजन क्षमता 200-750 सीसी होगी। ये मोटरसाइकिलें वर्ष 2022 से बाजार में उपलब्ध होंगी। दोनों कंपनियों ने लंबी अवधि की साझेदारी की है, जिसकी बुनियाद अगस्त 2017 में रखी गई थी। ट्रायंफ भारी इंजन वाली मोटरसाइकिलें बनाने के लिए जानी जाती है। वहीं, बजाज ऑटो छोटी बाइक बनाने वाली मशहूर कंपनी है। भारत में ट्रायंफ की सबसे किफायती बाइक की कीमत आठ लाख रुपये है।

गठजोड़ के बारे में बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज का कहना था कि ट्रायंफ दुनिया के प्रतिष्ठित ब्रांड में शुमार है। हमें पूरा भरोसा है कि भारत और अन्य उभरते बाजारों में ऐसे नए प्रोडक्ट (मध्यम क्षमता वाली मोटरसाइकिल) की जोरदार मांग पैदा होगी। वहीं, ट्रायंफ मोटरसाइकिल्स के सीईओ निक ब्लोर ने कहा कि साझेदारी के तहत नई रेंज की बाइक युवाओं को आकर्षित करेगी। लेकिन, हमारी विस्तार योजना में परिपक्व ग्राहक शामिल रहेंगे। तेजी से बढ़ते बाजारों के साथ कंपनी का फोकस यूरोप पर भी बरकरार रहेगा। साझेदारी के तहत एक नया इंजन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल ट्रायंफ की मध्यम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों के लिए किया जाएगा।

दोनों कंपनियां डिजाइन और इंजीनियरिंग के मामले में सहयोग करेंगी। बजाज ये मोटरसाइकिलें भारत और वैश्विक बाजार के लिए एक्सलूसिव तौर पर बनाएगी। वैसे बजाज ट्रायंफ की सभी कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिलों का वितरण भारत और दूसरे कुछ बाजारों में करेगी। ट्रायंफ भी वैश्विक बाजार में बजाज के साथ पार्टनरशिप के तहत तैयार बाइक बेचेगी।

पेट्रोलियम उत्पादों पर इनपुट क्रेडिट देने की तैयारी

- सेनवैट में संशोधन को लेकर उद्योग जगत की ओर से मिले प्रस्ताव पर विचार कर रही है सरकार
- क्रेडिट क्लेम नहीं होने से पेट्रोलियम कंपनियों पर पड़ता है 25,000 करोड़ रुपये का बोझ

नई दिल्ली, प्रेट्र : ऑयल सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उत्पादकों को इनपुट क्रेडिट क्लेम करने का विकल्प देने की तैयारी में है। इसके तहत उत्पादकों को सभी इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स पर चुकाए गए जीएसटी के लिए क्रेडिट क्लेम करने का मौका मिलेगा। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जैसे पेट्रोलियम ईंधनों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाए बिना ही सरकार पेट्रोलियम उत्पादकों को यह सुविधा देने पर विचार कर रही है।

सूत्रों का कहना है कि उद्योग जगत की तरफ से सरकार को इस संबंध में सुझाव मिले हैं। इसमें सरकार से सेनवैट नियमों में संशोधन की अपील की गई है। इसके तहत पेट्रोलियम उत्पादकों को जीएसटी की व्यवस्था के तहत सभी इनपुट पर चुकाया गया टैक्स क्लेम करने की अनुमति मिल सकेगी। एक अधिकारी ने कहा, 'ऑयल सेक्टर के लिए यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर मौजूदा समय में पड़ने वाला करीब 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स बोझ कम होगा। इस मामले में असली समस्या यही है कि सेक्टर का इनपुट जीएसटी की व्यवस्था में है, जहां टैक्स सेट-ऑफ का विकल्प रहता है, लेकिन आउटपुट यानी अंतिम उत्पाद जीएसटी से बाहर है, जहां इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। टैक्स क्रेडिट दो अलग-अलग व्यवस्था के बीच ट्रांसफर नहीं हो सकता।'

प्रतीकात्मक फोटो

आसान नहीं है इनपुट क्रेडिट की राह : जीएसटी के दायरे में नहीं आने वाले उत्पाद के टैक्स क्रेडिट से अकाउंटिंग जटिल हो जाएगी। अगर पेट्रोलियम के अंतिम उत्पाद भी जीएसटी में लाने की तैयारी हो, तो संभवतः अभी अस्थायी तौर पर इस टैक्स क्रेडिट के लिए कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है। फिलहाल आगामी बजट में इस बदलाव के एलान की उम्मीद की जा रही है।

जीएसटी में आ सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद : माना यह भी जा रहा है कि सरकार क्रमिक रूप से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। इसके लिए पहले गैस और एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। तब तक पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी के लिए टैक्स सेट-ऑफ की व्यवस्था दी जा सकती है। ऐसा करना इस सेक्टर के लिए अच्छा कदम होगा। माना जा रहा है कि सरकार सबसे पहले गैस को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। यह मुख्यतः औद्योगिक उत्पाद है और इसे आसानी से जीएसटी में लाया जा सकता है।

पेट्रोलियम मंत्रालय भी कर रहा अपील

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय लंबे समय से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की अपील कर रहा है। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था में आने के बाद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार होने वाले उतार-चढ़ाव से बचा जा सकेगा। उद्योग संगठन फिक्की ने भी सभी पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने से पहले एक्साइज ड्यूटी पर क्रेडिट की अस्थायी व्यवस्था बनाने की जरूरत पर बल दिया है।

तेजी की राह

प्रमुख बैंकों के शेयरों में दो प्रतिशत तक के उछाल से बाजार हुए मजबूत, तिमाही नतीजों और बेहतर बजट की उम्मीदों का दिख रहा असर

शेयर बाजारों को मिला बैंकिंग स्टॉक्स का दम

मुंबई, प्रेट्र : बैंकिंग और सीमेंट शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी के दम पर शुक्रवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्रों में घरेलू शेयर बाजारों में उछाल दर्ज किया गया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 226.79 अंक यानी 0.55 प्रतिशत मजबूती के साथ 41,613.19 के स्तर पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50-शेयरों वाला निफ्टी शुक्रवार को 67.90 अंक यानी 0.56 प्रतिशत उछाल के साथ 12,248.25 अंक पर बंद हुआ। पूरे सप्ताह के दौरान सेंसेक्स में 332.18 अंकों और निफ्टी में 104.10 अंकों का सुधार दर्ज किया गया।

बैंकिंग शेयरों में एक्सिस बैंक (2.01 प्रतिशत), कोटक महिंद्रा बैंक (1.98 प्रतिशत), आइसीआइसीआइ बैंक (1.18 प्रतिशत) और एसबीआइ (0.25 प्रतिशत) में निवेशकों की दिलचस्पी ने बाजार का सकल रुख सकारात्मक रखा। हालांकि सेंसेक्स पैक में शुक्रवार को सबसे ज्यादा 2.47 प्रतिशत का उछाल अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में दर्ज किया गया। कंपनी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2019) में उसके शुद्ध लाभ में 80 प्रतिशत का उछाल देखा गया है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टूब्रो, टाइटन, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयरों में भी 2.43 प्रतिशत का उछाल देखा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को चीन को छोड़कर बाकी दुनिया के लिए खतरा नहीं बताने के फैसले के बाद दुनियाभर के शेयर बाजारों में सकारात्मक स्थिरता दिखी। इसका भी फायदा घरेलू शेयर बाजारों को मिला।

दिन के कारोबार के बारे में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बेहतर बजट और तीसरी तिमाही के दमदार नतीजों की आस में शेयर बाजारों में बजट-पूर्व उछाल दिख रहा है। इस उछाल का बरकरार रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि बजट का स्वरूप क्या रहता है और कंपनियों के आगामी तिमाही नतीजे किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। नायर का कहना था कि पूरे सप्ताह के दौरान सेंसेक्स के दिग्गजों में कंसोलिडेशन दिखा है और उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। इसमें उनके तिमाही नतीजों की ही भूमिका प्रमुख रही है।

प्रतीकात्मक फोटो

सोना-चांदी में सुधार

नई दिल्ली, प्रेट्र : डॉलर के मुकाबले रुपये के भाव में गिरावट के चलते शुक्रवार को 96 रुपये मजबूत होकर 40,780 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया। चांदी में 238 रुपये का उछाल आया और यह 47,277 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकी। जानकारों का कहना था कि पिछले कई सत्रों से डॉलर के मुकाबले रुपये के टूटने का फायदा सोने के भाव पर दिख रहा है। इसके साथ ही चांदी को संस्थागत खरीदारों और सिक्का निर्माताओं का साथ मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना 1,558 डॉलर और चांदी 17.80 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के भाव पर बिक रहे थे।

नवंबर में सृजित हुईं 14 लाख से ज्यादा नई नौकरियां

- राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने जारी किए रोजगार के आंकड़े
- नवंबर, 2019 में ईएसआइसी में 14.33 लाख नए एनरॉलमेंट

नई दिल्ली, प्रेट्र : नवंबर, 2019 में देश में करीब 14.33 लाख नई नौकरियों का सृजन हुआ। अक्टूबर में यह आंकड़ा 12.60 लाख था। एंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ईएसआइसी) के पेरोल डाटा से यह बात सामने आई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) की रिपोर्ट में रोजगार को लेकर कई अहम आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018-19 में ईएसआइसी से कुल 1.49 करोड़ नए सब्सक्राइबर जुड़े थे। वहीं सितंबर, 2017 से नवंबर, 2019 के बीच कुल 3.37 करोड़ लोग ईएसआइसी स्कीम से जुड़े थे। एनएसओ की रिपोर्ट ईएसआइसी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से नए जुड़े सब्सक्राइबर की संख्या के आधार पर तैयार की गई है। एनएसओ ने अप्रैल, 2018 से इन तीनों संगठनों के सब्सक्राइबर का डाटा जारी करना प्रारंभ किया था। इसमें शुरुआती डाटा सितंबर, 2017 का रखा गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर, 2017 से मार्च, 2018 के बीच ईएसआइसी में कुल 83.35 लाख नए एनरॉलमेंट हुए। नवंबर, 2019 में ईपीएफओ में कुल 11.62 लाख नए एनरॉलमेंट हुए। अक्टूबर में यह आंकड़ा 6.47 लाख रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, 2018-19 में ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा स्कीम से कुल 61.12 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े। इसी तरह सितंबर, 2017 से मार्च, 2018 के बीच 15.52 लाख नए एनरॉलमेंट हुए।

27,225 डॉलर (करीब 19 लाख रुपये) के डाक टिकट एकत्र किए हुए हैं संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में रहने वाले 65 वर्षीय भारतीय पीसी रामचंद्रन ने। रामचंद्रन को डाक टिकट के अलावा अनेक देशों की मुद्राएं और अन्य पुरानी चीजें संग्रह करने का शौक है।

चीन ने चार करोड़ से ज्यादा आबादी पर लगाईं बंदिशें

कोरोना का प्रकोप ▶ नए साल के जश्न में खलल, 13 शहर, विश्वप्रसिद्ध दीवार और मंदिर भी बंद

26 हुई जान गंवाने वालों की संख्या, 800 से ज्यादा संक्रमित

बीजिंग, एजेंसियां : चीन में शनिवार से शुरू हो रहे नए साल (लूनर ईयर) के उत्सव में खलल पड़ गया है। रहस्यमय कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने के कारण वुहान समेत 13 शहरों में सार्वजनिक परिवहन रोक दिया गया है। इससे चार करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इन शहरों में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। यही नहीं, चीन की दीवार के कुछ हिस्से समेत मंदिरों तक को बंद कर दिया गया है। नए साल पर मंदिरों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। चीन में इस वायरस की चपेट में आकर अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है और 830 से ज्यादा लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं।

नए साल की छुट्टियों के दौरान लाखों नागरिकों की देश-विदेश में आवाजाही से वायरस का प्रसार बढ़ने की आशंका जताई गई है। इसी के मद्देनजर प्रभावित शहरों में आवाजाही रोकी जा रही है। पिछले माह मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से वायरस का संक्रमण शुरू हुआ था। इसी शहर से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वुहान में गुरुवार से ही सभी परिवहन नेटवर्क और बाहर जाने वाली उड़ानें बंद हैं। चीनी अधिकारियों ने वायरस के प्रकोप पर अंकुश लगाने के प्रयास में प्रांत के चार अन्य शहरों हुआंगगांग, इझोऊ, झिजियांग और कियानजियांग में भी आवाजाही रोक दी। प्रांत में शुक्रवार को ऐसे शहरों की संख्या बढ़कर 13 हो गई, जहां बस और ट्रेन समेत सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बीजिंग के लामा समेत कई प्रसिद्ध मंदिरों को बंद कर दिया गया है। लोग नए साल पर पूजा के लिए इन मंदिरों में पहुंचते हैं। कई मंदिरों में नए साल पर आयोजित होने वाले समारोह भी रद कर दिए गए हैं।

ये हैं वायरस के लक्षण : वुहान में सबसे पहले सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) रोगाणु जैसे रहस्यमय कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। इस वायरस का अभी कोई ज्ञात उपचार नहीं है। सांस संबंधी दूसरी बीमारियों की तरह ही बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत इस संक्रमण के लक्षण हैं। यह न्यूमोनिया का कारण भी बन सकता है।

इन देशों में पहुंचा वायरस : अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में रहस्यमय वायरस पहुंच चुका है। थाइलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और अमेरिका में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में भी कुछ संदिग्ध मामले दिखे हैं। इस रहस्यमय वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।

हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में उपचाराधीन कोरोना वायरस से पीड़ित युवक। रायटर

चीन के लिए हेल्थ इमरजेंसी घोषित

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चीन के लिए हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। इस वैश्विक संस्था ने हालांकि अभी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं की। इस तरह की घोषणा होने पर कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास तेज कर दिए जाते हैं।

दस दिन में बनाया जा रहा एक हजार बेड वाला अस्पताल

वुहान में संक्रमित लोगों के उपचार के लिए दस दिन में एक हजार बेड वाला अस्पताल बनाया जा रहा है। शहर के एक अधिकारी ने बताया कि अस्पताल सोमवार तक तैयार कर दिया जाएगा। इसके लिए बहुत तेज गति से काम चल रहा है।

चीन में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से दुनिया के अनेक देशों में भय का माहौल है। हांगकांग में बच्चे को मास्क लगाकर ले जाती महिला। रायटर

शंघाई डिजनीलैंड भी बंद

कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते शंघाई डिजनीलैंड को भी शनिवार से बंद कर दिया गया है। इस थीम पार्क की रोजाना एक लाख लोगों की क्षमता है। लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों में यहां के सभी टिकट पहले ही बिक जाते हैं।

चीन के संपर्क में भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने दो टेलीफोन नंबर +8618612083629 और +8618612083617 जारी किए

चीन में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को लेकर सरकार की चिंता भी बढ़ती जा रही है। भारत सरकार लगातार चीन से संपर्क में है, ताकि जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ भारतीयों को वहां से निकाला जा सके, बल्कि जब तक वे वहां हैं तब तक उन्हें राशन-पानी की कोई दिक्कत न हो। वुहान, शियानिंग, झिझियांग समेत 10 शहरों में यह वायरस फैल चुका है, जहां सैकड़ों भारतीय छात्र शिक्षा हासिल कर रहे हैं और उद्यमी भी कारोबार के सिलसिले में वहां जाते-आते रहते हैं।

बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से बताया गया है कि हुबेई प्रांत में रहने वाले भारतीयों के रिश्तेदारों की तरफ से लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है और सूचनाएं मांगी जा रही हैं। दूतावास संबंधित विभागों के साथ ही वुहान स्थित प्रशासन से भी संपर्क में है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की तरफ से इस बारे में जारी होने वाली सूचनाओं के मद्देनजर भी कदम उठाए जा रहे हैं। चीन सरकार ने भारत को आश्वस्त किया है कि वुहान में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। भारतीय छात्रों से सतर्क रहने को भी कहा गया है। बुखार होने पर तुरंत विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने दो हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए हैं, जिस पर फोन कर अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के छह संदिग्ध मामले मिले

मिड-डे, मुंबई : महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के छह संदिग्ध मामले सामने आए है। इनमें से तीन मुंबई और तीन पुणे में है। ये सभी लोग हाल ही में चीन और हांगकांग से लौटे हैं। मुंबई में तीनों लोगों को निगम के कस्तूरबा अस्पताल में स्पेशल वार्ड में निगरानी में रखा गया है। इनके ब्लड सैंपल जांच के लिए पुणे स्थित मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर चीन से आने वाले लोगों की जांच में ये सामने पकड़ में आए। इनमें दो पुरुष और एक महिला है। जो 22 और 23 जनवरी को चीन और हांगकांग से लौटे थे।

न्यूज गैलरी

जर्मनी में हुए हमले में छह लोगों की गई जान

फ्रैंकफर्ट : दक्षिण पश्चिम जर्मनी में हुई गोलीबारी की घटना में छह लोग मारे गए और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। माना जा रहा है कि गोलीबारी करने वाले ने निजी कारणों से रोट एम सी कस्बे में हमला किया। पुलिस ने बताया कि हमलावर का पीड़ितों के साथ निजी संबंध था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में किसी और हमलावर के शामिल होने का संकेत नहीं मिला है। पुलिस ने स्थानीय टीवी को बताया कि हमलावर जर्मन है। बिल्ड अखबार ने बताया है कि मारे गए लोग हमलावर के परिवार के सदस्य हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (एएफपी)

अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में भीषण विस्फोट, दो मरे

ह्यूस्टन : अमेरिका के ह्यूस्टन शहर के नजदीक शुक्रवार को तड़के हुए भीषण विस्फोट में मशीन की दुकान धराशायी हो गई। हादसे में दो लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। विस्फोट की आवाज 22 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। एरियल वीडियो से पता चला है कि जिस इमारत में दुकान थी, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। वाट्सन ग्राइंडिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग नाम की इस दुकान से आग की लपटें निकल रही हैं लेकिन वे ज्यादा ऊंची नहीं हैं। हादसा तड़के 4.25 बजे हुआ। इलाके की सुरक्षा के लिए लगे कैमरों की फोटो से पता चलता है कि मृतकों के शरीर के टुकड़े भी दुकान के आसपास बिखर गए है। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। पुलिस जांच कर रही है। (रायटर)

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने जीतीं नेशनल असेंबली की 16 सीटें

ललितपुर : सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) ने संसद के उच्च सदन नेशनल असेंबली की 18 सीटों पर हुए चुनाव में 16 पर जीत दर्ज की है। बाकी की दो सीटें भी एनसीपी की सहयोगी राष्ट्रीय जनता पार्टी-नेपाल (आरजेपी-एन) के खाते में गईं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी दल ने इस चुनाव में विभिन्न प्रांतों में अपने मजबूत गढ़ों के अलावा मधेशी दलों के क्षेत्र में भी जीत दर्ज की। 59 सदस्यीय नेशनल असेंबली के 19 सदस्यों का कार्यकाल तीन मार्च को पूरा हो रहा है। इन्हीं में से 18 सीटों के लिए ये चुनाव हुए थे। (एएनआइ)

ईयू के शीर्ष अधिकारियों ने किए ब्रेक्जिट समझौते पर हस्ताक्षर

ब्रसेल्स, एएफपी : यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सला वान डेर लीयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने शुक्रवार को ब्रेक्जिट समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। उर्सला ने इसके बाद एक ट्वीट में कहा, 'मिशेल और मैंने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे यूरोपीय संसद द्वारा समझौते के अनुमोदन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।' वहीं, मिशेल ने ट्वीट किया, 'परिस्थितियों में अवश्यंभावी परिवर्तन होंगे, लेकिन हमारी मित्रता बनी रहेगी। हम भागीदारी व सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं।'

इस समझौते को अब अनुमोदन के लिए 29 जनवरी को यूरोपीय संसद के समक्ष रखा जाएगा। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राजनयिक इसके अगले दिन समझौते को लिखित मंजूरी देंगे। इससे 31 जनवरी की मध्य रात्रि से ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना सुनिश्चित होगा। संभावना है कि जल्द ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी समझौते पर दस्तखत कर देंगे। उन्होंने हाल में कहा था, देश अब एक यूनाइटेड किंगडम के तौर पर आगे बढ़ेगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि ब्रेक्जिट समझौते को हम कभी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकेंगे, लेकिन हमने इसे पूरा कर लिया है।

'डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए'

▶ महाभियोग पर चर्चा में विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों का आह्वान

▶ राष्ट्रपति ने कहा, पूरी प्रक्रिया झूठ से भरी हुई

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की जरूरत जोरदार तरीके से बताई। प्रतिनिधि सभा से महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए डेमोक्रेट सांसद एडम स्किफ ने कहा, राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वह देश के हित से ज्यादा अपने हित को महत्व देते हैं। सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। प्रक्रिया के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट की झड़ी लगाते हुए कहा, यह पूरी प्रक्रिया झूठ और तथ्यों के गलत प्रस्तुतिकरण से भरी हुई है।

स्किफ ने कहा, अमेरिकी लोग ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं जो अपने हित से ज्यादा उनके और देश के हित में कार्य करे। उन्होंने यह बात यूक्रेन के राष्ट्रपति को ट्रंप के जुलाई में की गई उस फोन कॉल की बाबत कही जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बिडेन के खिलाफ जांच के लिए दबाव बनाया गया। बिडेन 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। स्किफ ने कहा, ट्रंप ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए अमेरिका की प्रतिष्ठा और उसके हितों को दांव पर लगाया। तल्ख अंदाज में सांसदों की ओर मुखातिब होकर कहा, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप भरोसे के काबिल नहीं हैं। वह देश का भला नहीं कर सकते। वह वही कर रहे हैं जो उन्होंने पहले किया। राष्ट्रपति के रूप में आने वाले कुछ महीनों भी वह वही करेंगे, जो उन्होंने अभी तक किया है। ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने का मौका आ गया है। हमें सच्चाई का साथ देना है, अन्यथा हम ट्रंप को हटाने का मौका गंवा देंगे। इसके बाद स्किफ ने ट्रंप के खिलाफ दस्तावेज, बयानों के वीडियो और अन्य साक्ष्य सीनेट के सभी 100 सांसदों के समक्ष रखे। उल्लेखनीय है कि स्किफ की अगुआई में ही प्रतिनिधि सभा के सांसदों की टीम ने ट्रंप के खिलाफ जांच की थी और राष्ट्रपति को हटाने के लिए आरोप तैयार किए थे। इस दौरान सांसद जेरी नैडलर ने भी ट्रंप पर तीखा प्रहार किया। कहा, चुनावी फायदा उठाने के लिए ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का गलत इस्तेमाल किया। पद का ऐसा दुरुपयोग 1789 में पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर अभी तक अन्य किसी ने नहीं किया।

फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रायटर

किसी भी तरह ट्रंप को हटाना चाहता है विपक्ष

रिपब्लिकन सीनेटर जॉन बारासाओ ने कहा, प्रतिनिधि सभा के सांसदों की टीम ट्रंप के खिलाफ एक जैसी बात ही कह रही है। वह तीन दिनों से एक जैसी बात कह रही है। वह किसी भी तरह से ट्रंप को हटाना चाहती है। ट्रंप के वकील जे सेकुलोव ने कहा, हम बार-बार एक ही बात सुन रहे हैं। बातों में नया और सनसनीखेज कुछ नहीं है। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सुनवाई की कई टेलीविजन चैनल लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

महाभियोग में लोगों की रुचि घटी

सीनेट में चल रही राष्ट्रपति ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा के प्रति अमेरिकी लोगों की रुचि घट रही है। संसद की कार्यवाही का टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट देख रहे लोगों की संख्या में 19 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है। मंगलवार को जहां एक करोड़ दस लाख लोगों ने इस कार्यवाही को देखा था, वहीं बुधवार को यह संख्या करीब 80 लाख रह गई।

इराकी प्रदर्शनकारी बोले, अमेरिकी सेना को बाहर करो

बगदाद, रायटर : इराक में अमेरिकी सेना की मौजूदगी के खिलाफ शुक्रवार को राजधानी बगदाद में दो बड़ी रैलियों का आयोजन किया गया। शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के आह्वान पर हुई इन रैलियों में लोग नो-नो अमेरिका, नो-नो इजरायल के नारे लगा रहे थे। इन रैलियों में मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों ने बाद में तहरीर चौक पर आयोजित सरकार विरोधी रैली में भी शिरकत की। अल सद्र इराक में सभी तरह के विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। हाल में उनकी ईरान के साथ निकटता बढ़ी है।

यह रैलियां मध्य बगदाद के अल हुरिया चौक और शहर के मुख्य विश्वविद्यालय के निकट आयोजित की गई थीं। रैली में शामिल धर्मगुरु ने कहा, हम अमेरिका, इजरायल और सरकार के भ्रष्ट राजनेताओं को हटाना चाहते हैं। ये सभी हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच, इराक के शीर्ष शिया मुस्लिम धर्मगुरु आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी ने अपने साप्ताहिक संदेश में राजनीतिक स्थिरता के लिए राजनीतिक समूहों से नई सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इराकियों के जीवन में बेहतरी के लिए व्यापक सुधारों को लागू करने की भी अपील की।

नेपाल ने सागरमाथा संवाद के लिए मोदी को दिया आमंत्रण

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल ने अपने पहले सागरमाथा संवाद के लिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। अप्रैल में होने वाले इस संवाद में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

नेपाल दौरे पर गए भारतीय पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए ग्यावली ने कहा, 'सागरमाथा संवाद का आयोजन 2-4 अप्रैल के बीच होगा। इसका विषय जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य है।' उन्होंने कहा, 'हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और उनकी सहमति का इंतजार है।' ग्यावली ने बताया कि इस आयोजन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समेत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के सदस्य देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका दक्षेस के सदस्य देश हैं। उन्होंने कहा कि इस संवाद का नाम विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) के नाम पर किया गया है जो मित्रता का भी प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु संकट के मुद्दे पर सभी नेताओं के बीच सहमति बनाना और इसके समाधान के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति को बढ़ाना है।

उल्लेखनीय है कि काठमांडू में पिछली बार वर्ष 2014 में दक्षेस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वर्ष 2016 में इसका आयोजन पाकिस्तान में होना था, लेकिन उड़ी सैन्य शिविर पर आतंकी हमले के बाद भारत ने उसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया था। बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान द्वारा शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार किए जाने के बाद शिखर सम्मेलन को ही रद करना पड़ा था। मीडिया से बात करते हुए नेपाली विदेश मंत्री ने भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारत जब बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद खत्म कर सकता है तो नेपाल के साथ क्यों नहीं?

अमेरिका ने ठुकराई राजनयिक की पत्नी के प्रत्यर्पण की मांग, ब्रिटेन नाराज

लंदन, एएफपी : अमेरिका द्वारा सड़क हादसे के मामले में राजनयिक की पत्नी के प्रत्यर्पण की मांग ठुकराए जाने पर ब्रिटेन ने कड़ी नाराजगी जताई है। ब्रिटेन ने शुक्रवार को कहा कि यह दुर्घटना में मारे गए ब्रिटिश किशोर के परिवार को न्याय से वंचित करने जैसा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने बताया कि उन्होंने इस मामले में सरकार की नाराजगी से अमेरिकी राजदूत वूडी जॉनसन को अवगत करा दिया है। उम्मीद है कि वह इस पर विचार करेंगे।

पिछले साल ब्रिटेन में सड़क पर गलत साइड में कार चला रहीं अमेरिकी राजनयिक की पत्नी एनी सकूलाज ने एक किशोर को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में किशोर की मौत हो गई थी। सकूलाज पर खतरनाक ड्राइविंग के साथ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जब अमेरिका से सकूलाज को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया तो उनकी यह मांग ठुकरा दी गई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने इसके पीछे राजनयिकों के परिजनों को मिलने वाली विशेष छूट का हवाला दिया था।

व्लादिमीर पुतिन के संवैधानिक सुधारों पर संसद के निचले सदन की मुहर

▶ 450 में से 432 सांसदों ने किया समर्थन

▶ बदलाव के बाद संसद के पास होगी सत्ता की चाबी

▶ प्रस्ताव पर संशोधन का सुझाव देने के लिए सांसदों के पास 15 दिन का समय है

मॉस्को, आइएएनएस : रूस की संसद के निचले सदन ड्यूमा ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों को मंजूरी दे दी है। निचले सदन में गुरुवार को हुए मतदान में 450 में से 432 सांसदों ने इनका समर्थन किया। अब उच्च सदन की मंजूरी से पहले प्रस्ताव पर संशोधन का सुझाव देने के लिए सांसदों के पास 15 दिन का समय है।

व्यापक संवैधानिक सुधारों की पुतिन की पेशकश के बाद प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव और उनकी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था। संविधान में बदलाव के प्रस्तावों पर देश में जनमत संग्रह कराया जाएगा। नए बदलाव के बाद सत्ता की चाबी राष्ट्रपति के बजाय संसद के पास होगी। सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी के सर्गेई नेवरोव ने शुक्रवार को कहा, हमने सभी सांसदों से आह्वान किया था कि वे हमारे राष्ट्रीय नेता पुतिन द्वारा प्रस्तावित संविधान के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का समर्थन करें। सभी सांसदों ने ऐसा किया और वह भी सिर्फ दो घंटे में। विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। ड्यूमा में यूनाइटेड रशिया पार्टी और अति राष्ट्रवादी सोशल डेमोक्रेट्स का ही प्रतिनिधित्व है। एक दशक से अधिक समय से रूस की संसद में किसी उदार या कट्टरपंथी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं है। संविधान संशोधन प्रस्ताव रखे जाते समय सामाजिक नीतियों को बताने पर जोर दिया गया। इनमें न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम पेंशन जैसी योजनाएं शामिल थीं। कई नेताओं और विश्लेषकों का कहना है कि जब तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद के किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव नहीं करते तब तक ड्यूमा क्रेमलिन (राष्ट्रपति भवन) पर निर्भर रहेगी। आलोचकों ने संवैधानिक सुधारों में पारदर्शिता का अभाव बताया है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फाइल फोटो। रायटर

अपील

ग्रेटा ने आर्थिक और राजनीतिक जगत के लोगों से पर्यावरण सुधार के लिए काम करने की अपील की, गुतेरस ने कहा, सुधार न हुए तो मानव जाति के विनाश का खतरा

दावोस में ग्रेटा ने उठाई लकड़ी जलाने पर रोक की मांग

दावोस, एएफपी : स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की बैठक के मौके पर ग्रेटा थनबर्ग ने आर्थिक और राजनीतिक जगत के लोगों से पर्यावरण सुधार के लिए कार्य करने की अपील की है। पर्यावरण सुधार के लिए कार्य करने वाली ग्रेटा थनबर्ग (17) हर प्रमुख मौके पर लोगों से इस तरह की अपील करती हैं। इस प्रयास के चलते वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तल्ख टिप्पणी की भी शिकार हो चुकी हैं।

थनबर्ग ने पर्यावरण के मुद्दे पर युवा पीढ़ी को जागरूक करने का कार्य किया है। इसके लिए पूरी दुनिया के स्कूलों में एक दिन की हड़ताल करवाकर बच्चों को सड़क पर आकर पर्यावरण के लिए चिंता जताने का अभियान भी चलाया है। फोरम के 50 वें संस्करण की बैठक के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भी बिगड़ते पर्यावरण के खतरों की ओर दुनिया की ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोका नहीं गया तो आने वाला समय मानव जाति के विनाश का होगा। गुतेरस और थनबर्ग ईंधन के रूप में लकड़ी के इस्तेमाल पर अविलंब रोक चाहते हैं। लकड़ी और कोयले को जलाने से पैदा होने वाला धुंआ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े कारणों में से एक है।

थनबर्ग ने कहा कि दुनिया के शक्तिशाली और धनी देशों के लोगों से वह चाहती हैं कि बिना देरी के वे पर्यावरण सुधार के लिए बड़े कदमों की घोषणा करें और उन पर आगे बढ़ें। दुनिया सुधार के कदमों की जिस तरह से अनदेखी कर रही है उससे स्थिति दिनों-दिन खराब होती जा रही है। अगर कुछ नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे इसका जवाब मांगेंगी। थनबर्ग ने दावोस में फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम से आयोजित प्रदर्शन का भी नेतृत्व किया। फोरम में हिस्सा ले रहे स्वीडन ने थनबर्ग की बातों का समर्थन किया है और कहा है कि हमारे घर आग पर खड़े हैं। अगर ध्यान न दिया गया तो कुछ दशकों के बाद ये जलकर खाक हो जाएंगे।

चीन में उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न पर इमरान ने साधी चुप्पी

दावोस, एएनआइ : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन में उइगर मुसलमानों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न के सवाल पर फिर चुप्पी साध गए। बीबीसी रेडियो के साथ बुधवार को एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने हालांकि कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने यहां के मुस्लिमों के साथ सही बर्ताव नहीं किए जाने का आरोप लगाया। साक्षात्कार ले रहीं पत्रकार मिशल हुसैन ने जब चीन के शिनजियांग प्रांत के शिविरों में कैद लाखों उइगर मुसलमानों के बारे में पूछा तो इमरान यह कहकर आगे बढ़ गए कि इस बारे में उन्हें कोई खास जानकारी नहीं है।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चीन में अल्पसंख्यक मुसलमानों के सवाल पर पाकिस्तानी पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। ज्ञात हो कि चीन में लाखों मुस्लिमों को प्रशिक्षण के नाम पर यातनाएं दी जा रही हैं। उन्हें अपने धर्म का पालन करने पर भी दंडित किया जाता है। उइगर मुस्लिमों के साथ उत्पीड़न के मुद्दे को दरकिनार करने पर सोशल मीडिया पर इमरान खान की काफी आलोचना हो रही है।

इमरान खान। फाइल

म्यांमार ने रखाइन प्रांत में नरसंहार से किया इन्कार

▶ आइसीजे के सर्वसम्मत फैसले के बाद विदेश मंत्रालय ने दी सफाई

▶ कहा-मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अशांत क्षेत्र की पेश की विकृत तस्वीर

यंगून, आइएएनएस : म्यांमार ने रखाइन प्रांत में नरसंहार से इन्कार करते हुए कहा है कि कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अशांत क्षेत्र की विकृत तस्वीर पेश की। साथ ही वहां के सतत विकास में बाधा भी उत्पन्न की। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार देर रात यह बयान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के उस फैसले के बाद जारी किया, जिसमें कहा गया था कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार रोकने के लिए म्यांमार को सभी उपाय करने चाहिए।

म्यांमार ने कहा कि उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि अदालत मामले के गुण-दोष के आधार पर सही निर्णय पर पहुंचे। विदेश मंत्रालय के बयान में इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इन्क्वायरी (आइसीओई) के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा गया कि रखाइन प्रांत में कोई नरसंहार नहीं हुआ। आइसीओई के मुताबिक युद्ध अपराध जैसे कुछ मामले सामने आए हैं और ऐसे लोगों पर म्यांमार की न्याय प्रणाली के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। यह देश की भलाई के लिए जरूरी भी है।

अगस्त, 2017 में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (एआरएसए) ने रखाइन प्रांत में पुलिस और सैन्य चौकियों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए थे। इसके बाद म्यांमार की सेना ने प्रांत में बड़ी कार्रवाई की थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई में दस हजार से ज्यादा लोग मारे गए और सात लाख से ज्यादा रोहिंग्याओं को भागकर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी।

ये भी जानिए

भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में खेला गया टी-20 मुकाबला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास का एकमात्र ऐसा मैच रहा जिसमें पांच बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए।

कीवियों को हराकर टीम इंडिया ने उतारी अपनी थकान

पहले टी-20 में अय्यर और राहुल के दम पर छह विकेट से जीती भारतीय टीम, 12300 किमी से ज्यादा का सफर तय करने के तीन दिन बाद ही अपने नाम किया मैच

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया को घरेलू वनडे सीरीज में हराने के बाद अगले ही दिन करीब 12300 किलोमीटर और 20 घंटे से ज्यादा का हवाई सफर तय करने के बाद भारतीय टीम जब मंगलवार को न्यूजीलैंड पहुंची तो उसे तीन दिन बाद ही शुक्रवार को इस दौरे पर अपना पहला मैच खेलना था। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद गुरुवार को लगातार मैच खेलने और लगातार सफर करने के चलते थकान हावी होने की बात कही थी, लेकिन जब टीम इंडिया इस दौरे पर ऑकलैंड में अपना पहला टी-20 मैच खेलने उतरी तो उसके प्रदर्शन में कहीं भी थकान नजर नहीं आई और उसने कीवी टीम को आसानी से छह विकेट से हराकर लंबे दौरे की शानदार शुरुआत की।

भारत ने साल 2020 के शुरुआती चार दिन कोई मैच नहीं खेला था, लेकिन अगले 20 दिन में उसने कुल सात मैच खेल लिए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड दौरे के पहले टी-20 को मिलाकर कुल चार टी-20 और तीन वनडे मैच शामिल हैं। इस दौरान भारतीय टीम गुवाहाटी, इंदौर, पुणे, मुंबई, राजकोट और बेंगलुरु में मैच खेलने के बाद शुक्रवार को ऑकलैंड में मैच खेलने उतरी। इस तरह भारत ने देखा जाए तो दो देशों के सात अलग-अलग शहरों में 20 दिन के भीतर सात मैच खेले, यानी औसतन तीन से भी कम दिन में एक मैच खेला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली किसी और टीम ने इस साल ना तो इतने मैच खेले हैं और ना ही इतनी यात्रा की है।

छा गए अय्यर: भारत की पहले टी-20 मैच की जीत में श्रेयस अय्यर की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 29 गेंदों पर नाबाद 58 रन की शानदार पारी खेलने के साथ ही फिनिशर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा में इजाफा किया। रिषभ पंत की जगह विकेटकीपर के तौर पर उतरे केएल राहुल (56 रन, 27 गेंद) की तूफानी शुरुआत और विराट कोहली के 32 गेंदों पर उपयोगी 45 रनों के बाद अय्यर ने जीत की इमारत तैयार की, जिसके चलते भारत ने एक ओवर बाकी रहते हुए ही 19 ओवर में चार विकेट पर 204 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले कोलिन मुनरो और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने तूफानी अर्धशतकीय पारियां खेलीं, लेकिन ईडन पार्क पर न्यूजीलैंड को पांच विकेट पर 203 रन पर रोकने का भारतीय गेंदबाजों को दिया जाना चाहिए।

सस्ते में लौटे रोहित: 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने रोहित शर्मा (07) का विकेट जल्द ही दूसरे ओवर में गंवा दिया। रोहित ने स्पिनर मिशेल सेंटनर (1/50) की गेंद पर छक्का जड़ने के बाद उनकी अगली गेंद को भी सीमारेखा के पार पहुंचाने की कोशिश की, जो उन्हें महंगी साबित हुई। बैकवर्ड प्वाइंट पर रॉस टेलर ने उनका कैच लपककर उन्हें पवेलियन भेजा।

राहुल-कोहली को जीवनदान: यहां से राहुल और कोहली ने पारी को संवारने की जिम्मेदारी संभाली और सिर्फ 51 गेंदों पर 99 रन की साझेदारी कर डाली। दोनों ने अपने स्ट्रोक्स की बेहतरीन व्यूहरचना दिखाई और मिलकर सात चौके व चार छक्के जड़ते हुए न्यूजीलैंड को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों के बीच तूफानी साझेदारी की बदौलत भारत ने नौवें ओवर में अपने 100 रन पूरे किए। हालांकि, इन दोनों को ही जीवनदान मिले। राहुल गफलत का शिकार होने के बावजूद रन आउट होने से बचे, क्योंकि कीवी खिलाड़ी दो बार गेंद को स्टंप पर मारने से चूक गए। उसके बाद गेंदबाज ईश सोढ़ी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का एक आसान सा कैच टपका दिया।

गुप्टिल ने लपका बेहतरीन कैच: अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए राहुल ने 23 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया, जबकि कोहली सिर्फ पांच रन से अर्धशतक पूरा करने से दूर रह गए। दोनों ने मिलकर भारत के मध्यक्रम के लिए मैच खत्म करने का आधार तैयार किया। कीवी टीम ने भारत को दोहरे झटके देकर वापसी की उम्मीद जताई। पहले राहुल 10वें ओवर में सोढ़ी की गेंद पर लपके गए और उसके सात गेंद बाद ब्लेयर टिकनर की गेंद पर मार्टिन गुप्टिल ने कोहली का हवा में उड़ते हुए बेहतरीन कैच लपका। टिकनर ने गेंद धीमी फेंकी, जिसे कोहली ने फ्लिक कर दिया। गेंद हवा में थी डीप मिडविकेट पर तैनात गुप्टिल अपनी जगह से दौड़े, लेकिन गेंद अभी भी उनकी पहुंच से दूर थी। ऐसे में गुप्टिल ने डाइव लगा दी और गेंद को घास छूने से कुछ इंच पहले ही अपने हाथों में कैद कर लिया। उनका यह कैच देखकर कोहली भी दंग रह गए।

अय्यर ने उठाई जिम्मेदारी: भारत ने अपने दोनों जमे-जमाए बल्लेबाज छह रन के भीतर खो दिए। जल्द ही शिवम दुबे (13) भी कीवियों की चाल में फंसकर विकेट गंवा बैठे। दुबे और अय्यर ने 21 रन जोड़कर भारत की रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सोढ़ी ने दुबे को अपना दूसरा शिकार बनाया। इसके बाद अय्यर ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से भारत को जीत दिलाई। उन्होंने मनीष पांडे के साथ 29 गेंदों पर 50 रन की साझेदारी निभाई। पांडे ने 12 गेंदों पर एक छक्के की मदद से नाबाद 14 रन बनाए।

छह ओवर में आठ गेंदबाज: इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम ने ऑलराउंडर दुबे और जडेजा समेत छह गेंदबाजों का संयोजन उतारा। युजवेंद्रा सिंह चहल को कुलदीप यादव पर और शार्दुल ठाकुर को नवदीप सैनी पर तरजीह दी गई। रिषभ पंत को बाहर रखा गया। न्यूजीलैंड की पारी में मुनरो ने 42 गेंद में छह चौकों और दो छक्कों के साथ 59 रन बनाए। वहीं, विलियमसन ने 26 गेंद में चार चौकों और चार छक्कों की मदद से 51 रन की पारी खेली। रॉस टेलर 27 गेंद में 54 रन बनाकर नाबाद रहे। जसप्रीत बुमराह (1/31) को छोड़कर भारत के सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए। भारत ने पहले आठ ओवर में ही छह गेंदबाज आजमा लिए। दुबे (1/24) ने गुप्टिल को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा, जिनका कैच रोहित ने लपका।

टेलर ने एक ओवर में कूटे 22 रन: इसके बाद विलियमसन और मुनरो ने 24 गेंद में 36 रन जोड़े। मुनरो ने 36 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। शार्दुल ठाकुर (1/44) ने मुनरो को पवेलियन भेजा। चार गेंद बाद रवींद्र जडेजा (1/18) ने कोलिन डि ग्रैंडहोम (00) को आउट किया। न्यूजीलैंड का स्कोर 13वें ओवर में तीन विकेट पर 117 रन था, लेकिन विलियमसन और टेलर ने 28 गेंद में 61 रन जोड़ डाले। टेलर ने तीन चौके और तीन छक्के लगाए। उन्होंने मुहम्मद शमी (0/53) के 16वें ओवर में 22 रन कूटे और 25 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। विलियमसन ने भी 25 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी सिर्फ 24 गेंद में पूरी हुई। विलियमसन को युजवेंद्रा सिंह चहल (1/32) ने आउट किया। टेलर ने न्यूजीलैंड को 200 रन के पार पहुंचाया। बुमराह को 20वें ओवर में फॉलोथ्रू के दौरान बायें टखने में चोट लगी और वह दर्द से कराहते दिखे। उन्होंने हालांकि तुरंत संभलकर आखिरी चार गेंद डालीं और ओवर पूरा किया।

मैच को छक्के के साथ खत्म करना अच्छा लगता है। हमें एक अहम साझेदारी की जरूरत थी। मैदान छोटा था और इस मैदान पर चार ओवरों में 50 रन भी बनाए जा सकते थे इसलिए हमने तय किया कि एक ओवर में एक बाउंड्री लगाएंगे और गेंदबाज भी दबाव में आ जाएंगे।
श्रेयस अय्यर, मैन ऑफ द मैच

स्कोर बोर्ड

टॉस : भारत (गेंदबाजी) — मैन ऑफ द मैच : श्रेयस अय्यर

न्यूजीलैंड — **203/5** (20 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
मार्टिन गुप्टिल का. रोहित बो. दुबे	30	19	04	01
कोलिन मुनरो का. चहल बो. ठाकुर	59	42	06	02
विलियमसन का. कोहली बो. चहल	51	26	04	04
डि ग्रैंडहोम का. दुबे बो. जडेजा	00	02	00	00
रॉस टेलर नाबाद	54	27	03	03
टिम सेफर्ट का. अय्यर बो. बुमराह	01	02	00	00
मिशेल सेंटनर नाबाद	02	02	00	00

अतिरिक्त : (लेबा-1, वा-5) 06
कुल : 20 ओवर में पांच विकेट पर 203 रन

विकेट पतन : 1-80 (गुप्टिल, 7.5), 2-116 (मुनरो, 11.5), 3-117 (डि ग्रैंडहोम, 12.2), 4-178 (विलियमसन, 16.6), 5-181 (सेफर्ट, 17.5)
गेंदबाजी :
जसप्रीत बुमराह 4-0-31-1
शार्दुल ठाकुर 3-0-44-1
मुहम्मद शमी 4-0-53-0
युजवेंद्रा सिंह चहल 4-0-32-1
शिवम दुबे 3-0-24-1
रवींद्र जडेजा 2-0-18-1

भारत — **204/4** (19 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोहित शर्मा का. टेलर बो. सेंटनर	07	06	00	01
केएल राहुल का. साउथी बो. सोढ़ी	56	27	04	03
विराट कोहली का. गुप्टिल बो. टिकनर	45	32	03	01
श्रेयस अय्यर नाबाद	58	29	05	03
शिवम दुबे का. साउथी बो. सोढ़ी	13	09	01	01
मनीष पांडे नाबाद	14	12	00	01

अतिरिक्त : (नोबॉ-1, वा-10) 11
कुल : 19 ओवर में चार विकेट पर 204 रन

विकेट पतन : 1-16 (रोहित, 1.4), 2-115 (राहुल, 9.6), 3-121 (कोहली, 11.1), 4-142 (दुबे, 13.2)
गेंदबाजी :
टिम साउथी 4-0-48-0
मिशेल सेंटनर 4-0-50-1
हैमिश बेनेट 4-0-36-0
ब्लेयर टिकनर 3-0-34-1
ईश सोढ़ी 4-0-36-2

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने अच्छी सीरीज खेली और यहां आत्मविश्वास दिखाया। आप इस तरह की पिच पर किसी के प्रति कड़ा रवैया नहीं अपना सकते। हमने बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें 210 से कम स्कोर पर रोकना अच्छा प्रयास था। क्षेत्ररक्षण ऐसा विभाग है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं।
विराट कोहली, कप्तान, भारत

मैं अपनी इस भूमिका (विकेटकीपिंग) से खुश हूं। मेरे लिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नया है। पिछले तीन-चार साल से मैं आइपीएल में खेल रहा हूं और अपनी प्रथम श्रेणी टीम के लिए ओपनिंग करता हूं। इन सबके बावजूद मैं हमेशा विकेटकीपिंग पर ध्यान देता हूं। विकेट के पीछे की जिम्मेदारी का मैं काफी लुत्फ उठा रहा हूं। इससे मुझे यह पता लगता है कि पिच कैसा बर्ताव कर रही है। **केएल राहुल**, विकेटकीपर-बल्लेबाज

हम जानते थे ईडन पार्क पर स्कोर का बचाव करना मुश्किल होता है और थोड़ा ओस भी थी। भारत ने निश्चित तौर पर अपनी काबिलियत दिखाई। हम जानते थे कि पहले बल्लेबाजी करते हुए हमें बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। गेंदबाजी करते हुए अगर हम जल्दी तीन या चार विकेट ले लेते तो मैच पर हमारा पलड़ा भारी होता।
केन विलियमसन, कप्तान, न्यूजीलैंड

68 रन बनाए न्यूजीलैंड के लिए मुनरो और गुप्टिल ने पावरप्ले में। भारत के खिलाफ टी-20 में पावरप्ले में न्यूजीलैंड का यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर है

54 नाबाद रन बनाए रॉस टेलर ने, जो छह साल में टी-20 क्रिकेट में उनका पहला अर्धशतक है

शुक्ला ने व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम पर किया कोहली का समर्थन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम पर सवाल उठाए थे। आइपीएल के पूर्व चेयरमैन राजीव शुक्ला ने टीम के व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम को लेकर भारतीय कप्तान विराट कोहली की चिंता का समर्थन किया। तो वहीं प्रशासकों की समिति (सीओए) ने उल्टा कोच रवि शास्त्री और कप्तान कोहली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के पांच दिन के भीतर ही न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंचकर मैच खेल रही भारतीय टीम के कप्तान कोहली ने गुरुवार को कहा था कि क्रिकेटर ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जब सीधे स्टेडियम पर लैंड करके खेलना शुरू करना होगा।

शुक्ला ने ट्वीट किया कि मैं कोहली का समर्थन करता हूं कि कैलेंडर बहुत व्यस्त है। लगातार मैच और सीरीज नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ियों को आराम और अनुकूलन का पूरा समय मिलना चाहिए। उन्होंने इसके लिए पूर्व में विनोद राय की अध्यक्षता में बीसीसीआइ का काम देखने वाली प्रशासकों की समिति (सीओए) को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम तय करने से पहले सीओए को इस पर ध्यान देना चाहिए था। कोहली ने कहा था कि कार्यक्रम इतना व्यस्त हो गया है लेकिन इतनी यात्रा करके अलग टाइम जोन वाले देश में आकर तुरंत ढल जाना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा था कि मुझे यकीन है कि भविष्य में इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

सीओए ने कहा कि सबसे सलाह के बाद तय हुआ था कार्यक्रम

बीसीसीआइ के में नई एपेक्स काउंसिल आने के बाद भंग हो चुकी सीओए ने इस आलोचना का जवाब दिया है। सीओए से संबंध रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) के बारे में कप्तान और कोच रवि शास्त्री से बात की गई थी और साथ ही महेंद्र सिंह धौनी से भी इस संबंध में बात की गई थी। यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी में हुई थी और अब अचानक से इस बात को उछालने की कोई तुक नहीं है। सूत्र ने कहा कि यह हमारे लिए हैरानी वाली बात है क्योंकि एफटीपी को लेकर दिल्ली में कोहली, शास्त्री और धौनी से बात हुई थी। सीओए ने एफटीपी तय नहीं किया था। तीनों ने अपनी बात रखी थी और कहा था कि क्योंकि 2020 में टी-20 विश्व कप होना है इसलिए ज्यादा ध्यान टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों पर दिया जाए। उस बैठक में न्यूजीलैंड दौरे को लेकर किसी तरह के सवाल खड़े नहीं किए गए थे। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि वह इस बात को जानते थे कि उन्हें पहला मैच 24 जनवरी को खेलना है तो इसके लिए उन्हें कुछ दिन पहले पहुंचना होगा। वह इस बात को भी जानते थे कि ऑस्ट्रेलियाई सीरीज कब खत्म हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि अब यह बात कहां से उठ गई।

कोहली ने कहा, हमने कभी जेटलैग की बात नहीं की : न्यूजीलैंड को पहले टी-20 में हराने के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि टीम में कभी जेटलैग (विमान की थकान) की बात नहीं हुई और उनकी टीम का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि टीम को जीत के लिए क्या चाहिए। कोहली ने पहले मैच के बाद कहा कि दो दिन पहले यहां आना और इस तरह का मैच खेलना शानदार रहा। हमने इसका लुत्फ उठाया है।

शीर्ष पर कोहली, रहाणे आठवें स्थान पर

दुबई, प्रेट्र: आइसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली का जलवा बरकरार है। कोहली आइसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि उप कप्तान अजिंक्य रहाणे एक पायदान ऊपर आठवें स्थान पर पहुंच गए। कोहली के 928 अंक हैं जबकि दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ है जो उनसे 17 अंक पीछे हैं।

चेतेश्वर पुजारा 791 अंक लेकर छठे स्थान पर हैं। रहाणे के 759 अंक हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह 794 अंक लेकर छठे स्थान पर हैं जबकि आर अश्विन आठवें और मुहम्मद शमी 10वें स्थान पर हैं। रवींद्र जडेजा 438 अंक लेकर ऑलराउंडर की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। जिंबाब्वे के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में 10 विकेट से जीतने वाली श्रीलंकाई टीम के एंजेलो मैथ्यूज शीर्ष 20 बल्लेबाजों में लौटे हैं। जिंबाब्वे के खिलाफ मैथ्यूज ने नाबाद 200 रन की पारी खेली थी। वह आठ पायदान चढ़कर 16वें स्थान पर हैं। इंग्लैंड के ओली पोप 52 पायदान की छलांग लगाकर 52वें स्थान पर हैं।

आइसीसी टेस्ट रैंकिंग

- **चेतेश्वर पुजारा 791 अंक लेकर छठे स्थान पर मौजूद**
- **शीर्ष पांच गेंदबाजों में एक भी भारतीय गेंदबाज शामिल नहीं**

टेस्ट रैंकिंग में पांच शीर्ष बल्लेबाज

रैंक	बल्लेबाज	देश	अंक
1	विराट कोहली	भारत	928
2	स्टीव स्मिथ	ऑस्ट्रेलिया	911
3	लाबुशाने	ऑस्ट्रेलिया	827
4	विलियमसन	न्यूजीलैंड	814
5	डेविड वार्नर	ऑस्ट्रेलिया	793

टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पांच गेंदबाज

रैंक	गेंदबाज	देश	अंक
1	पैट कमिंस	ऑस्ट्रेलिया	904
2	नील वैग्नर	न्यूजीलैंड	852
3	जेसन होल्डर	वेस्टइंडीज	830
4	रबादा	द. अफ्रीका	810
5	मिशेल स्टार्क	ऑस्ट्रेलिया	796

रोजर ने पांच सेट तक चले मैराथन मुकाबले में मिलमैन को हराया, महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स के रिकॉर्ड 24 ग्रैंडस्लैम खिताब की राह में रोड़ा बनीं कियांग

उलटफेर से बाल-बाल बचे रोजर फेडरर

मेलबर्न, रायटर: ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स में शुक्रवार को जहां महिला सिंगल्स में कई उलटफेर देखने को मिले तो वहीं पुरुष सिंगल्स में भी कुछ यादगार मुकाबले देखने को मिले। एक तरफ जहां गत चैंपियन नोवाक जोकोविक ने आसान जीत के साथ चौथे दौर में जगह बनाई तो वहीं स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंचकर अंतिम-16 का टिकट कटाने में सफल रहे।

मेलबर्न पार्क में फेडरर की 100वीं जीत: छह बार के चैंपियन फेडरर ने पांच सेट तक चले तीसरे दौर के मैराथन मुकाबले में स्थानीय स्टार जॉन मिलमैन को 4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6 से हराकर अंतिम-16 में प्रवेश किया। मेलबर्न पार्क में फेडरर पर टाइब्रेकर में उलटफेर का साया मंडरा रहा था लेकिन 20 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन ने दुनिया के 47वें नंबर के खिलाड़ी मिलमैन को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी 100वीं जीत दर्ज की। रॉड लेवर एरीना में खेले गए इस मुकाबले में मिलमैन ने घरेलू दर्शकों के समर्थन के बीच पहला सेट अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद फेडरर ने दूसरा सेट टाइब्रेकर में अपने नाम किया और फिर मिलमैन की सर्विस तोड़ते हुए तीसरे सेट में भी जीत दर्ज की। इसके बाद फिर से मिलमैन ने दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी को चौथे सेट में हराकर मुकाबले को पांचवें सेट में पहुंचा दिया। पांचवां सेट बेहद रोचक रहा। निर्णायक सेट के टाइब्रेकर में 38 वर्षीय फेडरर एक समय 4-8 से पिछड़ रहे थे लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार छह अंक अर्जित करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। खास बात यह रही कि मिलमैन ने आखिरी छह अंक में बेजा गलतियां कीं।

जॉन मिलमैन *vs* रोजर फेडरर		
11	ऐस	16
04	डबल फॉल्ट	06
64%	फर्स्ट सर्व विन	65%
40	विनर्स	62
48	असहज गलतियां	82
178	कुल अंक	181

रिकॉर्ड आठवें खिताब की ओर नोवाक: यहां रिकॉर्ड आठवें खिताब की कोशिश में जुटे सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने शानदार फार्म जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स के चौथे दौर में जगह बना ली। गत चैंपियन जोकोविक ने जापान के योशिहितो निशिओका को 6-3, 6-2 , 6-2 से मात दी। वह 50वीं बार किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के अंतिम-16 में पहुंचे हैं। अब उनका सामना 14वीं वरीय डिएगो श्रावट्मैन से होगा जिन्होंने सर्बिया के डुसान लाजोविक को 6-2, 6-4, 7-6 से हराया। जोकोविक अगर आस्ट्रेलियन ओपन जीतते हैं तो एक ही खिताब आठ या अधिक बार जीतने वाले वह राफेल नडाल (12 बार फ्रेंच ओपन) और रोजर फेडरर (आठ बार विंबलडन) के बाद तीसरे खिलाड़ी होंगे। निशिओका के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त सर्विस की और 17 ऐस लगाए। इस दौरान उन्होंने 93 फीसद अंक फर्स्ट सर्व पर हासिल किए। पूरे मैच के दौरान केवल एक बार उनकी सर्विस टूटी।

सितसिपास हुए उलटफेर का शिकार: उधर क्रोएशिया के मारिन सिलिक ने नौवीं वरीय रॉबर्टो बुटिस्टा अगुत को पांच सेट तक चले मुकाबले में 6-7, 6-4, 6-0, 5-7, 6-3 हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की। वहीं बिग सर्विंग कनाडा के मिलोस राओनिक ने छठी वरीय यूनान के स्टीफानोस सितसिपास को तीसरे दौर में 7-5, 6-4, 7-6 से हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया। राओनिक ने 19 ऐस और 55 विनर लगाते हुए एटीपी फाइनल्स के चैंपियन सितसिपास को पूरे मैच में कोई भी ब्रेक प्वाइंट हासिल करने का मौका नहीं दिया। वहीं अमेरिका के टेनिस सेंडग्रेन ने हमवतन सैम क्वेरी को 6-4, 6-4, 6-4 और फैबियो फोगनिनी ने ग्यूडो पेला को 7-6, 6-2, 6-3 से सीधे सेटों में हराया।

यह मुश्किल मुकाबला था। भगवान का शुक्र है कि यह सुपर टाइब्रेकर (10 अंक) था। अन्यथा मैं यह मुकाबला हार गया होता। मैं अंतिम लम्हों में लय में आया। मिलमैन बहुत अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने दिखाया कि बड़े मुकाबलों में किस तरह का प्रदर्शन किया जाता है। मैं एक समय हार की कगार पर पहुंच गया था लेकिन मैंने मैच पर नजर बनाए रखी जिसका मुझे फायदा मिला।
रोजर फेडरर, स्विस टेनिस खिलाड़ी

जीत के बाद रोजर फेडरर • रायटर

जीत का जश्न मनाती कोरी गॉफ • एएफपी

18 वीं बार रोजर फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में पहुंचने में कामयाब रहे

2018 में जॉन मिलमैन ने रोजर फेडरर को यूएस ओपन के चौथे दौर में पराजित किया था

50 वीं बार ग्रैंडस्लैम टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दौर में पहुंचे सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक

15 साल की कोरी ने ओसाका को हराया

मेलबर्न, एएफपी: अमेरिका की अनुभवी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स शुक्रवार का चीन की वांग कियांग के हाथों हार के साथ ही साल के पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन से सफर समाप्त हो गया जबकि 15 वर्षीय कोरी गॉफ ने गत चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।

सेरेना का इंतजार बढ़ा: महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में विलियम्स को 27वीं वरीय कियांग ने 6-4, 6-7, 7-5 से मात दी जिससे उनके रिकॉर्ड 24वें ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने का इंतजार बढ़ गया। सेरेना सात बार यहां खिताब जीत चुकी हैं लेकिन 2006 में तीसरे दौर में बाहर होने के बाद पहली बार इतनी जल्दी उनकी रवानगी हुई है। इस हार के बाद सेरेना भावुक नजर आईं।

वांग ने किया कोच को याद: चीन की दिग्गज टेनिस स्टार वांग के पूर्व कोच पीटर मैकनमारा की पिछले साल कैंसर से मृत्यु हो गई थी लेकिन वांग को लगता कि सेरेना पर मिली जीत का जश्न मनाने के लिए शुक्रवार को मेलबर्न पार्क पर उनके पूर्व कोच मौजूद थे। मैकनमारा ने वांग को सात साल तक कोचिंग दी थी। सेरेना को हराने के बाद भावुक वांग ने कहा, मैं अभी भी उनके सपने को पूरे करने की कोशिश करती हूं। मुझे लगता है कि वह ऊपर बैठे मुझे देख रहे थे। काश वह इस जीत को देखने के लिए कोर्ट के बगल में मौजूद होते।

कोरी का जलवा जारी: पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेल रहीं गैरवरीय अमेरिका की गॉफ ने तीसरी वरीय ओसाका को 67 मिनट तक चले तीसरे दौर के मुकाबले में सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ ही गॉफ ने यूएस ओपन में इस खिलाड़ी से मिली पिछली हार का बदला भी ले लिया। इस दौरान गॉफ ने पहले सेट में एक बार और दूसरे सेट में दो बार ओसाका की सर्विस तोड़ी।

सेरेना भूत, गॉफ भविष्य: टूर्नामेंट में भाग ले रही सबसे कम उम्र की खिलाड़ी गॉफ ने इससे पहले सात बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स और अनुभवी सोराना क्रिस्टी को हराया था। सेरेना जहां 38 साल की हो गई हैं तो वही उनकी हमवतन गॉफ उनसे 23 साल छोटी हैं। दोनों के खेल में टेनिस के भूतकाल और भविष्य की झलक दिखी।

भीगी पलकों से विदा हुईं वोज्नियाकी: सेरेना की दोस्त और दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी कैरोलिन वोज्नियाकी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में मिली हार के साथ भीगी पलकों के साथ टेनिस को अलविदा कह दिया। वोज्नियाकी ने दिसंबर में ही कह दिया था कि यह उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। उन्हें ट्यूनीशिया की ओंस जाबुर ने 7-5, 3-6, 7-5 से हराया इसके साथ ही उनके सुनहरे करियर का अंत हो गया जिसमें उन्होंने 30 डब्ल्यूटीए खिताब जीते। उन्होंने एकमात्र ग्रैंडस्लैम खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में 2018 में जीता था। विश्व रैंकिंग में 78वें स्थान पर काबिज जाबुर से मिली हार के बाद वह अपने आंसू नहीं रोक सकीं। मैच के बाद प्रेस वार्ता में उनकी आंखे लाल और सूजी हुई थीं। उन्होंने मजाक में कहा, 'मैंने फोरहैंड पर गलती के साथ अपना करियर खत्म किया। मैं अपने पूरे कैरियर में इन चीजों पर मेहनत करती रही हूं।' उधर ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने एलीना रेबाकिना को 6-3, 6-2 से हराकर चौथे दौर में प्रवेश किया।

मुझे अभी भी यकीन है कि मैं मार्गरेट कोर्ट के सर्वाधिक 24 ग्रैंडस्लैम खिताब की बराबरी हासिल कर सकती हूं अन्यथा मैं टूर में हिस्सा नहीं ले रही होती। इस मुकाबले में मैंने कई गलतियां की। मैं केवल मजे लेने के लिए नहीं खेलती। **सेरेना विलियम्स**

दो साल पहले मैं यहां जूनियर स्तर पर खेलते हुए पहले ही दौर में हार गई थी और अब मैं इस मुकाम पर हूं। यह शानदार है। मुझे लगता है कि इन गर्मियों में यह मेरा सबसे अच्छा मैच था।
कोरी, अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी

शरण का सफर समाप्त

मेलबर्न: भारत के दिविज शरण और न्यूजीलैंड के अर्टेम सिटाक पुरुष डबल्स में ब्रूनो सोरेस और मैट पेविच से सीधे सेटों में हारकर बाहर हो गए। शरण और सिटाक ने ब्राजील के सोरेस और क्रोएशिया के पेविच के खिलाफ मुकाबला 6-7, 3-6 से गंवाया। रोहन बोपन्ना बुधवार को ही हारकर बाहर हो गए थे। दो साल बाद कोर्ट पर लौटी सानिया मिर्जा पैर में चोट के कारण महिला डबल्स से बाहर हो गईं थी।

दैनिक जागरण
सबरंग
शहर को जानने के...
नई दिल्ली, शनिवार, 25 जनवरी, 2020
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

दिल्ली की देहरी

पहले गणतंत्र दिवस की परेड में फ्लाई पास्ट का था, विशेष आकर्षण

नलिन चौहान
दिल्ली के अनजाने इतिहास के खोजी

देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद (1884-1963) ने 26 जनवरी 1950 के दिन सुबह राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उल्लेखनीय है कि उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1962 तक रहा और वे दो बार राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के उपरांत 26 जनवरी 1950 के दिन वे प्रिंस एडवर्ड प्लेस (अब राष्ट्रपति भवन) से इर्विन स्टेडियम (अब नेशनल स्टेडियम) के लिए दोपहर 230 बजे से राजकीय बग्घी में बैठकर निकले थे। उनका राजकीय काफिला राष्ट्रपति भवन से निकलकर बारास्ता संसद भवन से होकर पार्लियामेंट स्ट्रीट, आउटर कनॉट सर्किस, बाराखंभा रोड, भगवान दास रोड, हार्डिंग एवेन्यू से होते हुए करीब 345 बजे इर्विन स्टेडियम पहुंचा था।

तब राष्ट्रपति के स्टेडियम में पहुंचने पर रक्षामंत्री बलदेव सिंह ने उनकी अगवानी की और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से परिचय करवाया। फिर राष्ट्रपति ने स्टेडियम में तिरंगा फहराया, जिसके बाद वहां मौजूद सशस्त्र सेना के बैंड समूहों ने नौसेना के ड्रम मेजर बर सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रगान की धुन बजाई थी। इन सभी बैंड समूहों के लिए संगीत का संयोजन नौसेना के संगीत निदेशक लेफ्टिनेंट एसई हिल ने किया था। उसके बाद, राष्ट्रपति को तोप के 31 गोले दागकर सलामी दी गई। राष्ट्रपति ने जीप पर चढ़कर परेड का निरीक्षण किया और फिर सलामी स्थल की ओर लौट गए। इस परेड में तीनों सेनाओं और पुलिस के करीब तीन हजार अफसरों और जवानों ने भाग लिया था। इस समारोह की मुख्य परेड के कमांडर ब्रिगेडियर जेएस ढिल्लन थे। जबकि सुनहले बैज के साथ नीली वर्दी पहने नौसेना के 120 सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह ने किया था। थल सेना के जवानों ने हरे जैतून रंग की वर्दी और सिर पर टोपी पहनी थी। जबकि विभिन्न इकाइयों के सैनिकों ने अपनी-अपनी रेजिमेंटों के अनुरूप रंगों वाली पोशाकें पहनी थीं। जबकि वायुसेना के दो दस्तों में 240 वायुसैनिक थे, जिनकी कमान स्काड्रन लीडर वीएम राधाकृष्णन और स्काड्रन लीडर जेएफ शुक्ला के हाथ में थी। इसके अलावा, दूसरी पंजाब बॉयज बटालियन की भी एक कंपनी थी। दिल्ली पुलिस के पुलिस अधीक्षक अजब सिंह की कमान वाली खाकी वर्दी पहने 120 जवानों की भी एक टुकड़ी थी। इरविन स्टेडियम में परेड समारोह की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति किंग्सवे (राजपथ) से होते हुए वापिस गवर्नमेंट हाउस लौट गए। राष्ट्रपति के काफिले के पूरे रास्ते पर सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिक तैनात किए थे। इतना ही नहीं, राजधानी के पूरे तयशुदा रास्ते में जगह-जगह पर स्वागत के लिए तोरण द्वार बनाए गए थे। दिल्ली में समाज के सभी वर्गों की तिरंगे को फहराने और परेड समारोह में भागीदारी को निश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। इर्विन स्टेडियम में होने वाले समारोह के लिए आस-पड़ोस के गांवों के निवासियों के आने के लिए प्रबंध किए गए थे। इस कार्यक्रम के लिए खास आमंत्रण भी भेजे गए थे। यहां आने वाले गणमान्य व्यक्तियों से लेकर जनसाधारण के वाहनों जैसे बस, कार, तांगा और साइकिलों की पार्किंग के लिए भी प्रबंध किया गया था। स्टेडियम के भीतर होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित व्यक्तियों को विशेष कार पार्क दिए गए थे। इस परेड का मुख्य आकर्षण इर्विन स्टेडियम के ऊपर आकाश में विमानों का 'फ्लाई पास्ट' था। जिसमें रॉयल इंडियन एयरफोर्स के चार इंजन वाले लिबरेटर विमानों सहित एक बम वर्षक विमान की संयुक्त उड़ान प्रमुख थी। 'लिबरेटर' नामक विमानों के बेड़े का नेतृत्व विंग कमांडर एचएस आर गुहेल ने किया था। इस फ्लाई पास्ट में भाग लेने वाले विमानों से समारोह स्थल पर होने वाले कार्यक्रम के समय के अनुरूप तालमेल बनाए रखने के लिए स्टेडियम में एक नियंत्रण कक्ष वाली कार तैनात की गई थी। जिससे राष्ट्रपति के झंडारोहण के ठीक बाद होने वाले फ्लाई पास्ट में विमान स्टेडियम के ठीक ऊपर से सही समय पर उड़ान भर सकें। उल्लेखनीय है कि भारत में कस्बों और शहरों के ऊपर आकाष में विमानों के समूह (फार्मेशन) में उड़ान पर प्रतिबंध था। पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एलमर्हिस्ट ने ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस परेड के महत्व को देखते हुए इसकी अनुमति दी थी। एक तरह से, आजाद हिंदुस्तान के मुक्त आकाश में, इन विमानों की उड़ान इतिहास के एक नए अध्याय के आरंभ का प्रतीक थी।

चुनावी धरोहर

दिल्ली का चुनावी सफर

आज नेता जी फोन करके वोट मांगते हैं, भले पांच साल शक्ल न दिखाएं। सोशल मीडिया पर आपके सबसे करीबी...सेवक वही बनते नजर आते हैं। वादों की घोषणाओं के तीर प्रतिद्वंद्वियों के बीच जमकर चलते हैं। अब कैसे-कैसे हथकंडे और प्रचार के लिए जतन करने पड़ते हैं नेताओं को। वहीं एक दौर था जब बैलगाड़ी और भोंपू सबसे प्रिय प्रचार के साथी होते थे। मतदान के दिन हर उम्र वर्ग में गजब का उत्साह होता था...सबरंग के इस अंक में दिल्ली की चुनावी यात्रा से रूबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

दिल्ली अभिलेखागार विभाग में उपलब्ध दस्तावेजों में दिल्ली चुनाव के ऐसे ही विभिन्न दृश्य नजर आते हैं। सभी फोटो : जागरण

जैसे चटक धूप को बर्फीली हवा चिढ़ा रही है...और लोग चाहकर भी उस गुनगुनी धूप का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। वैसे ही कुछ हालात दिल्ली के चुनावी महासमर में भी बने हुए हैं। अलग-अलग पार्टी के प्रत्याशी इसी धूप और हवा की तरह हो गए हैं। इसीलिए प्रचार के लिए तरह-तरह के जतन कर जन जन को रिझा रहे हैं। लेकिन दिल्ली ने वो भी दौर देखा है जब हाइटेक चुनावी मोड से दूर प्रचार बैलगाड़ी पर होता था। प्रत्याशियों गलियों में घूमते थे। रिक्शा के पीछे लाउडस्पीकर पर चुनावी नारे गूंजते थे। अब भले हार-जीत के बाद ईवीएम का गला पकड़ा जाता है लेकिन बैलेट बॉक्स ही सब तय कर देते थे। यह दिल्ली वालों की परिपक्वता ही थी कि पहली बार नोटा का प्रयोग भी यहीं किया गया।

मुश्किलें कम नहीं: दिल्ली अभिलेखागार विभाग में उपलब्ध दस्तावेजों की मानें तो दिल्ली के पहले चुनाव की तैयारियां बहुत कठिन थीं। कारण, यहां विस्थापितों की संख्या ज्यादा थी। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो अस्थाई झोपड़ियों और टेंट, तंबू आदि में रह रहे थे। कई परिवार तो ऐसे भी थे जिन्होंने झोपड़ियों आदि में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन फिर रोजी रोटी की तलाश में कहीं और चले गए। ऐसे में उनके नए पते पर उनका इंरोलमेंट उस समय बहुत मुश्किल इसलिए भी था क्यों कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। बहरहाल इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी आराम से चुनाव संपन्न हुआ। अब तो लोग नजदीकी मतदान केंद्र तक जाने में कष्ट महसूस करते हैं लेकिन तब डीटीसी को जिम्मेदारी दी गई थी अतिरिक्त बस चलाई गईं थीं ताकि ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह गए हैं वो अपने पते पर आकर अपने मतदान का निर्वाह कर सकें। लोगों ने बगैर न नुकुर के ऐसा किया भी।

पहली बार बैलेट बॉक्स : अब तो हम लगातार हाइटेक चुनावी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन दिल्ली ने जब पहली बार बैलेट बॉक्स से मतदान किया था तो वह भी अजूबा था। वरिष्ठ नेता सुभाष आर्या कहते हैं कि लोगों के बीच इसे लेकर कई तरह की बातें होती थीं। उधेड़बुन थी कि आखिर एक छोटे से बक्से में इतने सारे लोग कैसे मतदान करेंगे। चुनाव अधिकरियों ने मतदाताओं को काफी प्रशिक्षण दिया था। मॉक चुनाव भी आयोजित किया गया था। पहले चुनाव में अजूबा बने बैलेट बॉक्स के बारे में और अधिक जानकारी मुख्य चुनाव कार्यालय अधिकारी के कश्मीरी गेट स्थित कार्यालय में बने संग्रहालय में दिखती है। जिसमें बकायदा बैलेट बॉक्स का इतिहास दर्शाया गया है। एक पदाधिकारी ने बताया कि सन् 1951-52 के चुनाव में प्रयुक्त बैलेट बॉक्स भी यहां रखे गए हैं। पहले पहल ये बॉक्स अपेक्षाकृत छोटे होते थे। लेकिन चुनाव दर चुनाव इनका आकार बढ़ता गया। 1977 के चुनाव में प्रयोग किया गया बड़ा बैलेट बॉक्स भी यहां प्रदर्शित है।

तीन भाषाओं में प्रत्याशी का नाम : दिल्ली में आपको सभी जगह साइन बोर्ड में तीन भाषाएं दिखाई देती हैं न उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी... इसी तरह उन दिनों चुनावों में बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में इन्हीं तीन भाषाओं में लिखा जाता था। किनारे पर संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह छपा होता था। इसी पर ठप्पा लगाया जाता था। मतदाता को जिसे मत देना होता था, उसके सामने ही मोहर लगाता था। संग्रहालय में मादीपुर और हस्तसाल का बैलेट पेपर प्रदर्शित भी किया गया है।

घर-घर होता था प्रचार : सुभाष आर्या कहते हैं कि उस समय इतनी आबादी नहीं थी। इतना तामझाम भी नहीं होता था। चुनाव सादगी में संपन्न होता था। प्रत्याशी सुबह घर पर हवन, पूजा पाठ आदि करके निकलते थे। प्रत्याशी नामांकन के समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को प्रस्तावक बनाता था। इससे एकता प्रदर्शित होती थी। प्रत्याशी जब प्रचार के लिए निकलते थे तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ढोल बजता था। एक व्यक्ति ढोलक बजाते हुए आगे निकलता था और उसके दस कदम पीछे से प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ गुजरता था। ढोलक की आवाज सुनकर गांव-देहात के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आ जाते। जो किसान खेतों में काम कर रहे होते थे वो आते एवं फिर एक छोटी सभा हो जाती। एक समय ऐसा भी था जब प्रत्याशी घर घर जाते थे। वोटर से बात करते थे। लेकिन अब तो प्रत्याशी सिर्फ कॉलोनी की मुख्य गली से ही गुजर जाते हैं। अब तो टेलीफोन, डिजिटली संपर्क ज्यादा हो पाता है। एक दिलचस्प वाकया सुभाष आर्या बताते हैं कि 1958 के चुनाव में हमें लोहे का भोंपू मिला हुआ था। यह दरअसल एक मुड़ा हुआ लोहा होता था। जिसे पीछे से काट दिया जाता था। इस वजह से जब बोलते तो आवाज गुंजती थी। इसी से बोलकर लोगों को इक्ट्ठा किया जाता था।

ब्रह्म प्रकाश भी बैलगाड़ी पर : वहीं इतिहासकार आरवी स्मिथ बताते हैं कि पुराने दिनों में चुनाव का महीना मेले की मानिंद गुजरता था। इतना शोर शराबा नहीं था, आबादी दूर-दूर थी। पुरानी दिल्ली को छोड़ दें तो डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, करोल बाग सरीखे इलाकों में भीड़ होती थी। ब्रह्मप्रकाश सरीखे नेता भी बैलगाड़ी से प्रचार करते थे। उन दिनों बैलगाड़ी पर नेता अपने समर्थकों के साथ बैठ जाते थे। सुबह सफर शुरू होता था, दिन भर प्रचार होता था। साथ में चना वगैरह लेकर चलते थे एवं पानी पीते-चना खाते प्रचार होता रहता था। चुनाव के समय मानों मेला सा माहौल हो जाता था। एक के बाद एक नेता आते। पहले हालचाल पूछते और फिर अपना चुनाव प्रचार करते। जबकि पुरानी दिल्ली में सभाओं पर ज्यादा जोर रहता था। सभाएं भी अक्सर शाम से शुरू होकर रात तक चलती थी। इसे जलसा भी कहा जाता था। अद्भुत नजारा होता था। चंद फासले पर विभिन्न दलों के नेता जलसा करते थे एवं लोग ध्यान से सुनकर यह तय करते थे कि वोट किसे देना है।

सन 1952 में दिल्ली चुनाव में मतदान के लिए बैठे ग्रामीण

दिल्ली के चुनाव में इन चुनाव चिन्हों का होता था इस्तेमाल

हर प्रत्याशी पर होता था एक बैलेट

संग्रहालय में लगी तस्वीरों से आपको एक हैरान कर देने वाली कहानी भी पता चलती है कि किस तरह पहले एक प्रत्याशी के लिए एक बैलेट बॉक्स पोलिंग स्टेशन में रखा जाता था। यानी यदि 20 प्रत्याशी हुए तो हर पोलिंग स्टेशन पर 20 बॉक्स रखे जाएंगे और उनके सामने चुनाव चिह्न का चित्र लगाया जाएगा। यहां दिल्ली में बैलेट बॉक्स से ईवीएम तक का दिलचस्प सफर भी देखने को मिलेगा। बता दें कि साल 2004 में हुए आम चुनाव में करीब 10 .75 लाख ईवीएम के इस्तेमाल के साथ भारत ई-लोकतंत्र में प्रवेश कर गया था। हालांकि भारत में ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग 1982 में केरल में 50 मतदान केंद्रों पर हुआ था, लेकिन 1983 में ईवीएम मशीनों को इस्तेमाल में नहीं लाया गया। 1988 में ईवीएम मशीनों के प्रयोग का अधिकार मिला।

नारे वही जो जन के मन भाएं

प्रचार के रंग

नारे वही जो जन के भन भाएं...और जीत दिलाएं। कमरतोड़..जीतोड़ मेहनत करते हैं...क्रिएटिविटी के साथ एड़ी चोटी तक का जोर लगाते हैं बाकायदा प्रचार के लिए बैनर, नारे तैयार करने को विशेषज्ञ रखे जाते हैं। अब तो समय के साथ अब नारों की प्रकृति भी बदलती चली जा रही है। कभी ये नारे, समाज की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित लिखे जाते थे लेकिन अब तो व्यक्ति केंद्रित होते जा रहे हैं। यही नहीं अब एग्रेसिव नारे भी खूब दिए जाते हैं।

नारों ने बनाया दिलचस्प : यह नारे ही हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की जुबां पर है तो वहीं लगे रहो केजरीवाल नारा भी खूब लोकप्रिय हो रहा है। आम आदमी पार्टी के पलटवार में कांग्रेस और भाजपा ने भी नारों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस का नारा, कांग्रेस वाली दिल्ली भी कार्यकर्ताओं में खासा पसंद किया जा रहा है। भाजपा ने इस चुनाव में देश बदला है, अब दिल्ली बदलेंगे और 5 साल दिल्ली बेहाल, अब नहीं चाहिए केजरीवाल नारा दिया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता राहुल कहते हैं कि नारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग प्रचार माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। अभी तक पार्टियों के स्तर पर प्रचार हो रहा है तो नारे भी पार्टी स्तर के लगाए जा रहे हैं। उम्मीदवारों के नामांकन के बाद चुनाव प्रचार में तेजी आने के साथ अभी और नए नारे व जुमले गढ़े जा रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली में विकास की डोर टूटने, अपने 15 साल शासन चलाने के अनुभव की दलील देकर मतदाताओं को वापस जोड़ने में लगी है। यही नहीं नारों को पंक्तियों में गढ़कर भी ट्विटर, फेसबुक पर पोस्ट कर रही है।

दिल्ली को हमने बनाया, दुनिया में इसको नाम दिलाया। अब बुरा हुआ है इसका हाल, कांग्रेस संग बनाएं इसे खुशहाल।

भाजपा का प्रचार अभियान संभाल रहे वरिष्ठ नेता सुभाष आर्या कहते हैं कि पहले चुनावी नारे अधिकतर जनता द्वारा या, किसी कार्यकर्ता द्वारा दिया जाता था। ये नारे आज के गोली मारों सालों की तरह एग्रेसिव नहीं होते थे, बल्कि बड़े साधारण और दिल को छूने वाले होते थे। जनता की बात करते थे कई बार ऐसा होता है कि नेता किसी जनसभा में जा रहे हैं, वहां किसी ने राह चलते कुछ गढ़ दिया और वो हिट हो गया। बकौल आर्या, दरअसल नारे दो प्रवृति के होते हैं। जिसे पार्टी लांच करती है वो नारा हम एक साल की मेहनत के बाद गढ़ पाते हैं। इस पर बड़े नेता कड़ी मशक्कत करते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान कई तात्कालिक नारे भी गढ़े जाते हैं। यह नारे, चुनाव के दौरान की परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। हालांकि अब तो कंपनियां भी हायर की जा रही है। राजनीतिक दल इन कंपनियों को वस्तु स्थिति दे दी जाती है। कंपनियां एक वस्तु स्थिति पर बतौर नमूना 20 से 50 नारे गढ़ती हैं। जिसमें पार्टी अपनी पसंद अनुसार एक दो या फिर कई बार ज्यादे नारे चुनती है।

दिल्ली में चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के पोस्टर्स से ऐसे भरी होती थी दीवारें। जागरण अर्काइव

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी छोर का आखिरी गांव है मंडोली

शहर के गांव

इतिहास वह है जो घटनाओं व ऐतिहासिक साक्ष्यों के तथ्य के आधार पर बताते हैं कि यह निश्चय था। दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिला क्षेत्र में स्थित मंडोली गांव में मिले सदियों पुराने साक्ष्य भी इतिहास के कुछ ऐसे ही प्रमाण देते हैं। जहां मोहनजोदड़ो व हड़प्पाकाल से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मंडोली उत्तर-पूर्वी दिल्ली का सबसे आखिरी गांव है जिसकी सीमा उत्तर-प्रदेश से लगी हुई है। यह कब और कैसे बसा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा कालीचरण कहते हैं कि पहले यह गांव मेरठ का हिस्सा हुआ करता था। हमारे पूर्वज बताते थे कि यहां सबसे पहले मेव मुसलमान रहने आए थे। उस समय इस गांव का नाम मांडू गढ़ हुआ करता था। एक बहुत ही भयानक आपदा में पूरा गांव खत्म हो गया और महज एक टीला रह गया था। उस टीले के एक ओर मंडोली गांव बसा तो दूसरी ओर सबोली। पहले गांव में कुछ ही लोगों का परिवार था लेकिन वर्ष 1970 के बाद से यहां आबादी बढ़नी शुरू हुई।

10 वर्षों पहले मिले हड़प्पा से पुरानी सभ्यता के अवशेष :गांव के निवासी विजेंद्र सिंह त्यागी कहते हैं कि मंडोली व सबोली गांव के बीच एक बड़ा टीला है। करीब 10 वर्षों पहले पुरातत्व विभाग द्वारा उस जगह खोदाई से जो चीजें निकलीं वह आश्चर्यचकित करने वाली थीं। वहां मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष निकले। जिसमें मिट्टी के बर्तन, टूटी दीवार, गहने, सिक्के आदि शामिल हैं। उसी स्थान पर एक कब्रिस्तान व खेड़ा टीला देवी मंदिर भी है, जो सदियों पुराने इस गांव के अस्तित्व की पहचान है।

गांव की विशेषता है दूसरी सबसे बड़ी रामलीला :मंडोली गांव में पिछले 60 वर्षों से लव-कुश रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। रणधीर चौहान कहते हैं कि 20 वर्षों तक यह रामलीला शिव मंदिर में होती रही लेकिन बाद में टीले वाले स्थान पर बड़े स्तर पर आयोजित किया जाने लगा। यह यमुनापार की दूसरी सबसे बड़ी रामलीला है जिसमें बड़े-बड़े अधिकारी शिरकत करते हैं। पूरा गांव इसे एक उत्सव की तरह मनाता है, जिसमें मथुरा व वृंदावन के कलाकार मंचन करने आते हैं। अभी पिछले वर्ष ही गांव में रेलवे हाल्ट का शुभारंभ हुआ है जिसकी वजह से अब यहां तीन से चार ट्रेनें रुकती हैं। गांव के लोगों को इससे काफी सुविधा हुई है क्योंकि कई वर्षों से गांव वालों को इसका इंतजार था।

रितु राणा

गांव का कुआं दिखाते निवासी, देखकर ही अंदाजा लगता है कि लोगों ने इसका अच्छे से सरंक्षण किया है • सभी फोटो : जागरण

मंडोली गांव स्थित टीला जहां पुरातत्व विभाग को खोदाई में मिले थे हड़प्पा काल से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष।

कभी समृद्ध हुआ करता था गांव :

चंद्रशेखर शर्मा कहते हैं कि वर्ष 1975 तक गांव की जमीन जीटीबी अस्पताल तक फैली हुई थी। इतना ही नहीं नंदनगरी, दिलशाद गार्डन आदि आसपास के क्षेत्र कभी इस गांव का हिस्सा हुआ करते थे। खास बात तो यह है कि उस समय गांव वालों ने सरकार को अपनी जमीनें मात्र दो रुपये गज में बेची थी। गांववासियों का कहना है कि वर्ष 1975 तक गांव के लोग खेती पर ही निर्भर थे। लेकिन जमीन बेचने के बाद उनका रोजगार खत्म हो गया। वहीं ज्यादा पढ़े-लिखे न होने के कारण अपने घर को किराए पर चढ़ाकर ही गुजारा किया और आज भी ऐसे ही जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं।

चुनावी चर्चा में चाशनी घोल देते हैं एमपी भुजियावाले

चुनावी जायका

किसी मुद्दे पर जोरदार बहस चल रही हो तो दस लोग अपनी बात रखने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। आतुर होते हैं कि हमारी बात पहले सुनी जाए। हम जो कह रहे हैं वही तथ्य सत्य है। और जब बात हो रही हो चुनावी सरगर्मी में तो भला कौन अपना मत और तर्क नहीं रखना चाहेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव व प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से ही राजधानी के विभिन्न जगहों पर कुछ ऐसा ही माहौल है। दिल्ली के न्यू पटपड़गंज रोड शकरपुर स्थित एमपी भुजियावालों के यहां भी ऐसी चुनावी महफिल नजर आती है। यहां गर्मागर्म गाजर का हलवा गुलाब जामुन व मूंग दाल का हलवा खाते हुए दिल्ली के सियासी मिजाज पर चर्चा करते लोग नजर आते हैं। कोई मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी के पांच सालों का कामकाज तो कोई केंद्र में भाजपा सरकार के कामकाज को चुनाव परिणामों से जोड़ता हुए मत रखता है। कुछ लोग तो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के 15 सालों के कार्यकाल में हुए दिल्ली के विकास को भी याद करते दिखे। चुनाव जैसे गर्म मुद्दे की बहस में यहां के मीठे पकवानों की चाशनी बड़े आराम से घुल जाती है और लोग आनंद लेते हुए चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। भले एक-दूसरे से कोई जान पहचान नहीं हो लेकिन जब मजमा लगता है तो सब जायका भूल इस बहस में अपना मत रखने जुट जाते हैं।

वर्ष 1989 में हुई थी शुरुआत : पिछले 31 वर्षों से दिल्ली वालों को स्वादिष्ट मिष्ठान परोसने वाले एमपी भुजियावाले दुकान के मालिक लकी सिंह तोमर कहते हैं कि वर्ष 1989 में इस दुकान की शुरुआत मेरे पिता पीएस तोमर ने की थी। करीब 22 वर्षों से मैं भी यहां का काम संभाल रहा हूं। कहते हैं, आज ही नहीं बल्कि हमेशा से जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो ग्राहकों का समूह मिठास का भरपूर स्वाद लेते हुए चुनाव पर चर्चा करते हैं। कभी दोस्त तो कभी अंजान लोग भी खाते-खाते चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में आजकल तो रोजाना ही नियमित आने वाले ग्राहकों में कोई गाजर का हलवा तो कोई रबड़ी फालूदा लिए चुनावी बहस करते नजर आता है। ग्राहकों का यह तक कहना है कि यहां के व्यंजनों में घुली खुशबू इतनी अलग है कि लोगों को खींच लाती है। फिर ग्राहकों की भीड़ में से आवाज आती है कि क्या लगता है आपको दिल्ली में कौन-सी पार्टी सरकार बनाएगी। जवाब मिलता है कि पांच साल में आम आदमी पार्टी ने काफी काम किया है तो सरकार उनकी ही बनेगी। किसी ने कहा कि भाजपा भी इस बार पूरी तैयारी में है कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी आसपास और भी लोग जमा हो जाते हैं और चुनावी बहस जोर पकड़ती है।

ऐसे पहुंचें : लक्ष्मी नगर मेट्रो से पैदल चलकर 5 से 10 मिनट की दूरी पर एमपी भुजियावाले की दुकान है।

रितु राणा

ये हैं एमपी भुजियावाले...यहां आजकल स्वाद में घुली है चुनावी मिठास • जागरण

चुनावी चर्चा के साथ इन मिष्ठानों की बड़ी मांग :

चार लोगों के साथ सर्द मौसम में चुनावी चर्चा करते हुए गर्मागर्म स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मजा ही कुछ और है। ऐसे में एमपी भुजियावाले के यहां कई तरह के व्यंजन मिलते हैं जो चर्चा में जोश भरने का काम करते हैं। इनमें देसी घी से बना गाजर का हलवा, मूंगदाल का हलवा, रस मलाई, रबड़ी फालूदा शामिल है। यहां आपको 20 रुपये पीस गुलाब जामुन, 500 रुपये किलो गाजर का हलवा, 500 रुपये किलो मूंग दाल हलवा मिल जाएंगे।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 25 जनवरी 2020
आजकल
16
www.jagran.com

विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न से किया गया सम्मानित

आज ही के दिन 1983 में स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। उन्होंने भूदान आंदोलन के जरिए भूमिहीनों मजदूरों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की।

थॉमस एडीसन और ग्राहम बेल ने बनाई टेलीफोन कंपनी

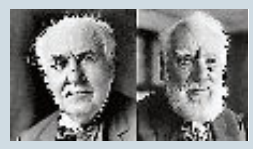

आज ही के दिन 1881 में थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अमेरिका में ओरिएंटल बेल टेलीफोन कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, भारत, जापान, चीन जैसे देशों में टेलीफोन बेचने का लाइसेंस देती थी।

दिल को छूने वाली कविता कृष्णमूर्ति की खनकती आवाज

आज ही के दिन 1958 में गायिका कविता कृष्णमूर्ति का जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने आठ साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। 14 साल की उम्र में मुंबई आ गईं। 1971 में पहली बार फिल्म श्रीमन पृथ्वीराज में लता मंगेशकर के साथ गाने का मौका मिला। 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं से उन्हें सफलता मिली। कविता हिंदी सहित करीब दर्जन भर भाषाओं में 25 हजार गाने गा चुकी हैं। 2005 में पद्मश्री, चार बार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। पेशेवर सक्रियता अभी जारी है।

इधर-उधर की

बीमार कुत्ते को बनाया अधिकारी

वाशिंगटन, एजेंसी : कुत्ते वफादारी का प्रतीक समझे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बीमार होने पर इन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि कुछ लोग इनके आखिरी दिनों में मददगार बन जाते हैं। गंभीर रूप से बीमार कुत्ते को यहां एक दिन के लिए के-9 अधिकारी बनाया गया। कुत्ते का नाम एडी है। एडी को उसके मालिक ने त्याग दिया था। वह नवंबर में अकेला और शहर की सड़कों पर घूमता मिला था। एडी को ट्यूमर है और उसकी एक आंख की रोशनी जा चुकी है। उसके पास अब सिर्फ 6 से 12 महीने बचे हैं। एडी को क्रिस्टी ने लिया और उसके जीवन को खुशियों से भर देने का निर्णय लिया। क्रिस्टी के सपने को पास्को पुलिस ने पूरा किया। एडी को पुलिस की असली वर्दी दी गई और के-9 अधिकारी के रूप में शपथ भी दिलाई गई। एडी ने पूरा दिन गश्त में बिताया। पास्को पुलिस ने अधिकारी बने एडी की तस्वीरें फेसबुक पर साझा कीं और लिखा हम इन अनुभवों और भविष्य के प्रयासों के लिए एडी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज तुम्हारे साथ काम करना एक सम्मान था।

प्राचीन तारे में ऑक्सीजन का भंडार

लगाया पता ▶ खगोलविदों को 'जे0815 प्लस 4729' के वातावरण में मिली ऑक्सीजन

रहस्यमय ब्रह्मांड के अन्य पिंडों में भी जीवन की संभावनाओं को मिला बल

लंदन, प्रेट्र : खगोलविदों ने एक सबसे पुराने और मौलिक रूप से कमजोर तारे के वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का पता लगाया है। यह एक ऐसी खोज है, जो ब्रह्मांड में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण यौगिकों के गठन पर प्रकाश डालती है। साथ ही इससे अंतरिक्ष के अन्य खगोलीय पिंडों पर जीवन की संभावनाओं को और बल मिला है।

एस्ट्रोफिजिकल लेटर्स नामक जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने जे0815 प्लस 4729 नामक एक प्राचीन तारे की रासायनिक बनावट का विश्लेषण किया और यह पता लगाया कि ब्रह्मांड में फर्स्ट जनरेशन के तारों यानी शुरुआती दौर के तारों में ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों का निर्माण कैसे होता है।

शोधकर्ताओं में शामिल ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों ने कहा, 'जे0815 प्लस 4729 नामक तारा अपने नक्षत्र मंडल 'लिंक्स' से लगभग 5000 प्रकाशवर्ष दूर स्थिति है यानी इस तारकीय स्रोत से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में पांच हजार साल लग जाएंगे।' अमेरिका की डब्ल्यू. एम. कीक वेधशाला के वैज्ञानिक और इस अध्ययन के सह-लेखक जॉन ओ मारिया ने कहा, 'यह परिणाम बहुत ही रोमांचक है। यह हमारे ब्रह्मांडीय बैक यार्ड में मौजूद तारों का उपयोग करके ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती समय के बारे में बताता है।' उन्होंने कहा कि 'जे0815 प्लस 4729' में ऑक्सीजन मिलने का मतलब है कि अन्य तारों में भी जीवन संभव हो सकता है।

यह अध्ययन एस्ट्रोफिजिकल लेटर्स नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

कैल्शियम और आयरन है दुर्लभ : वैज्ञानिकों के मुताबिक, जे0815 प्लस 4729 नामक इस तारे में कार्बन, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन की मात्रा क्रमशः 10, आठ और तीन प्रतिशत है। ऐसी ही कुछ स्थिति सूर्य की भी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इसमें कैल्शियम और आयरन जैसे अन्य तत्व बेहद दुर्लभ थे।

आकाशगंगा में नहीं है ऐसा तारा : अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज के पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता और इस अध्ययन के सह-लेखक डेविड एगुओडो ने कहा, 'हमारी आकाशगंगा के प्रभामंडल में केवल कई तारे पाए जाते हैं, लेकिन किसी तारे के पास कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इतनी भारी मात्रा नहीं है।' उन्होंने कहा कि इस अध्ययन से ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को बल मिलेगा।

न्यूक्लियर रिएक्शन से बनीं गैसें

शोधकर्ताओं के अनुसार, हाइड्रोजन और हीलियम के बाद ब्रह्मांड में ऑक्सीजन तीसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, और पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों के लिए आवश्यक है। हालांकि, उन्होंने कहा, यह तत्व प्रारंभिक ब्रह्मांड में मौजूद नहीं था। इनका निर्माण बड़े पैमाने पर तारों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होने पर अल्ट्राहाई एनर्जी के उत्सर्जन के माध्यम से हुआ, जिनका द्रव्यमान सूर्य की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है।

शोधकर्ताओं ने तारे से 16 रसायनों का डाटा किया एकत्र

एक ही रात में तारे का पांच घंटे से अधिक समय तक अवलोकन करने के बाद खगोलविदों ने इसके वातावरण में ऑक्सीजन सहित अन्य 16 रसायनों का डाटा एकत्र किया। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक, जोयन गोंजालेज हर्नांडेज ने कहा, 'इस तारे की संरचना यह इंगित करती है कि बिग बैंग के बाद सैकड़ों करोड़ों वर्षों के दौरान इसका गठन हुआ था। संभवतः यह मिल्की वे के पहले सुपरनोवा से निकली हुई सामग्री से बना होगा। इस अध्ययन के निष्कर्ष यह भी बताते हैं कि इस तारे एक बहुत ही असामान्य रासायनिक संरचना थी।

फोटो न्यूज

पेंशन सुधार योजना के खिलाफ फ्रांस में प्रदर्शन

फ्रांस सरकार की पेंशन सुधार योजना के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल के दौरान शुक्रवार को पेरिस के रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करतीं महिला रेलकर्मी। इस हड़ताल में देश के विभिन्न संगठनों से जुड़े लाखों लोग शामिल हैं। येलो वेस्ट आंदोलन के बाद देशव्यापी इस हड़ताल से रेलवे यातायात और हवाई सेवाएं काफी प्रभावित हुई हैं। एएफपी

बुजुर्गों की भी देखभाल करेगा यह रोबोट

गुरुदीप त्रिपाठी, प्रयागराज

- ट्रिपल आइटी के सेंटर ऑफ इंटेलीजेंट रोबोटिक्स ने किया ईजाद
- शोधकर्ताओं की इसे जल्द बाजार में उतारने की है तैयारी

भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो जहां अपने पहले मानवरहित गगनयान में 'लेडी रोबोट' व्योममित्र को अगले साल दिसंबर में भेजने की तैयारी में है, वहीं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल आइटी) ने बैठने, चलने और बात करने वाला रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट नृत्य करने के साथ-साथ बुजुर्गों की देखभाल भी कर सकता है। जल्दी ही इसे बाजार में उतारने की तैयारी है।

वास्तविक जीवन में रोबोट अभी उतने विकसित नहीं हैं, हालांकि टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म 'रोबोट' या विज्ञान के क्षेत्र में तमाम रोबोट वे सभी काम करने लगते हैं, जो इंसान करते हैं। 'रोबोट' फिल्म का रोबोट तो नायिका से प्रेम भी करता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआइटी) में तैयार किए गए रोबोट की बात भी अनूठी है। यह आपका अकेलापन दूर करने के साथ हर निर्देश का बखूबी पालन करेगा। इसे ट्रिपल आइटी के सेंटर ऑफ इंटेलीजेंट रोबोटिक्स के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीसी नंदी के निर्देशन में सात छात्र-छात्राओं ने मिलकर तैयार किया है। प्रो. नंदी ने बताया कि अब वह इस रोबोट को आम इंसान की तरह बनाने में जुटे हैं। इस रोबोट को विभाग के सात विद्यार्थी गौरव यादव, प्रिया शुक्ला, श्रुति जायसवाल, पद्माकर पांडेय, आदित्य सिंह, वंदना कुशवाहा और वेंकट वेरी ने मिलकर तैयार किया है। विभाग के शिक्षक डॉ. राहुल काला छात्रों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। प्रो. नंदी बताते हैं कि अब न तो कामकाज करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं और न ही घरों में काम करने के लिए लोग। ऐसे में घर के बुजुर्गों की देखभाल के लिए यह रोबोट तैयार किया गया है। इसे संस्थान की प्रयोगशाला में अभी कई अन्य तकनीक से लैश किया जा रहा है। वह बताते हैं कि अभी रोबोट की पकड़ मजबूत नहीं है। ऐसे में किस सामान को किस तरह पकड़ना है, यह सिखाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित ट्रिपल आइटी के सेंटर ऑफ इंटेलीजेंट रोबोटिक्स की ओर से तैयार किया गया रोबोट। जागरण

प्रोफेसर नंदी ने दावा किया कि वह भविष्य में इस तरह के रोबोट को बाजार में भी उतारेंगे। सफल परीक्षण के बाद कम लागत में रोबोट तैयार किया जाएगा। उसे बाजार में ऐसे दाम में उतारा जाएगा कि मध्यमवर्गीय परिवार भी खरीद सकें।

बोल उठी मिस्र की तीन हजार साल पुरानी ममी

- थ्री-डी प्रिंटिंग के जरिये शोधकर्ताओं ने विकसित की स्वर प्रणाली

लंदन, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने थ्री-डी प्रिंटिंग के जरिये स्वर प्रणाली विकसित कर तीन हजार साल पुरानी मिस्र की एक ममी को आवाज दी है। माना जा रहा है कि अपने तरीके के इस पहले शोध के माध्यम से प्राचीन मनुष्यों की आवाज सुनने में मदद मिल सकती है।

शोधकर्ताओं में शामिल लंदन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि मिस्र की नेसयामुन ममी 1099 से 1069 ईसा पूर्व के बीच फेराओ रामसेस द्वितीय के राजनीतिक रूप से अस्थिर शासन के दौरान की है।

साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक नेसयामुन मिस्र के विश्व धरोहर स्थल थेब्स के मंदिरों में पुरोहित और मुंशी के तौर पर काम करते थे। इन मंदिरों के खंडहर मिस्र के आधुनिक शहर लक्सर में देखे जा सकते हैं। नेसयामुन द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठानों में उनकी आवाज का खास महत्व था। वैज्ञानिकों ने नेसयामुन के मुंह और गले का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन नामक एक्सरे डिवाइस इस्तेमाल की। इसके बाद थ्री-डी प्रिंटिंग का उपयोग करते हुए ममी के वाइस बॉक्स या स्वरयंत्र को फिर से बनाया गया। अध्ययन में कहा गया है कि जब शोधकर्ताओं ने थ्री-डी प्रिंटेड सेटअप का इस्तेमाल आर्टिफिशियल स्वर यंत्र के साथ किया (इसका प्रयोग आमतौर पर स्पीच सिंथेसिस में किया जाता है) तो वे एक ही ध्वनि को दोहरा सकते थे।

प्रतीकात्मक

दो दवाओं के मिश्रण से कैंसर का मुकाबला

शोध अनुसंधान

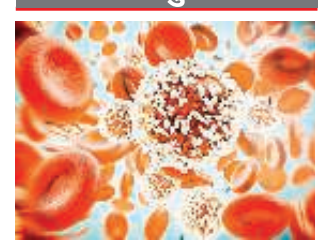

वैज्ञानिकों को कैंसर से मुकाबले की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने दो दवाओं का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया है, जो कैंसर सेल्स (कोशिकाओं) के प्रसार पर अंकुश लगा सकता है। कैंसर सेल जर्नल में छपे अध्ययन के अनुसार, कैंसर सेल्स खास तरह के जीन म्यूटेशन को प्रेरित करती हैं। हर2 नामक म्यूटेशन से वास्तव में एक नई दवा को लेकर प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। कैंसर में प्रभावी मानी जा रही यह दवा अभी परीक्षण के दौर में है। अमेरिका के साउथवेस्टर्न साइमंस कैंसर सेंटर के शोधकर्ताओं ने बाजार में पहले से मौजूद एक दूसरी दवा भी प्रभावी पाई है। यह दवा प्रतिरोधी क्षमता से मुकाबला करने के साथ ही कैंसर के फैलाव को रोक सकती है। इन्हीं दोनों दवाओं के मिश्रण से कैंसर के साथ ही हर2 जीन म्यूटेशन से मुकाबले के लिए नई दवा बनाने का आधार मिला है। -एएनआइ

किशोरों में गट बैक्टीरिया का मोटापे के खतरे से संबंध

अनियमित दिनचर्या के कारण वर्तमान में मोटापा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। यह हर आयुवर्ग के लोगों को प्रभावित कर रहा है। इससे संबंधित एक नए अध्ययन में स्वास्थ्य के लिहाज से नुकसानदेह गट (आंत) बैक्टीरिया का संबंध किशोरों में मोटापे और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) के उच्च खतरे से पाया गया है। इससे इन समस्याओं की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान हो सकती है। पीसीओएस एक हार्मोन विकार है। इसके चलते लड़कियों के रक्त में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्तर उच्च हो जाता है। नतीजन मुंहासे और ज्यादा बाल बढ़ने के साथ ही माहवारी भी अनियमित हो जाती है। अमेरिका के चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोलोराडो की शोधकर्ता मेलानी क्री ग्रीन ने कहा, 'सामान्य बच्चों की तुलना में पीसीओएस और मोटापे से प्रभावित किशोरों में अनहेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा पाए गए। टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर का संबंध इस बैक्टीरिया से पाया गया है।' शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन से इन समस्याओं का प्रारंभ में पता लगाने में मदद मिलेगी, जिससे समय रहते उपचार की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकेगा। -प्रेट्र

फिल्म रिव्यू

★★★★

पंगा

प्रमुख कलाकार : कंगना रनोट, जस्सी गिल, रिचा चड्ढा, नीना गुप्ता, यज्ञ भसीन
निर्देशक : अश्विनी अय्यर तिवारी
अवधि : 2 घंटे 9 मिनट

सपनों को दूसरा मौका देने की कहानी

नौकरीपेशा महिलाएं शादी करने और मां बनने के बाद अपने करियर को तिलांजलि दे देती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक दबाव के चलते वे समझौता कर लेती हैं। सपनों को भूलकर खुद को घर-गृहस्थी तक सीमित कर लेती हैं। यदि पति अपनी पत्नी के सपनों, इरादों और इच्छाओं का सम्मान करें तो सपनों को जीने का दूसरा मौका दिया जा सकता है। 'पंगा' मनोरंजक अंदाज में यही कहती है।

कहानी कबड्डी खिलाड़ी जया निगम (कंगना रनोट) की है। भोपाल में रेलवे में कार्यरत जया वर्ष 2010 में कबड्डी टीम की कैप्टन हुआ करती थी। रेलवे में कार्यरत अपने पति प्रशांत (जस्सी गिल) और सात साल के बेटे आदि (यज्ञ भसीन) के साथ वह खुशहाल जीवन बिता रही है। कबड्डी छोड़ देने के बावजूद उसके पांव में खेलने की थिरकन कायम है। बेटे और पति के प्रोत्साहन पर 32 साल की उम्र में जया मैदान पर वापसी करती है। उसकी यह डगर आसान नहीं होती। बढ़ा वजन, उम्र, घर-परिवार की जिम्मेदारी जैसी चिंताएं उसके सामने होती हैं, लेकिन 'जो सपने देखते हैं वे पंगा लेते हैं'। जया के सफर में उसकी बेस्ट फ्रेंड मीनू (रिचा चड्ढा) भी देश के लिए खेलने के सपने में उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी होती है। यह फिल्म रिश्तों के खट्टे-मीठे अनुभवों को बड़े प्यार से आचरण में ले आती है। अश्विनी अय्यर तिवारी महिलाओं की आकांक्षाओं और सपनों को पंख देने की कहानी दर्शाने में माहिर हैं। 'निल बट्टे सन्नाटा' में उन्होंने एक नौकरानी के अपनी बेटी को अफसर बनाने की जद्दोजहद को दर्शाया था। 'बरेली की बर्फी' आजाद ख्याल लड़की की कहानी थी। निखिल मल्होत्रा और अश्विनी द्वारा लिखित 'पंगा' की कहानी में शादीशुदा खिलाड़ी के मैदान में वापसी के सफर में घर-परिवार की दिक्कतों, सामाजिक सोच और खेल में वापसी के संघर्ष जैसे पहलुओं को उन्होंने खूबसूरती के साथ गूंथा है।

'दंगल' फिल्म के निर्देशक नीतेश तिवारी को एडीशनल स्क्रीनप्ले का क्रेडिट दिया गया है। वह अश्विनी के पति भी हैं। उनके जुड़वां बच्चे हैं। अश्विनी का कहना है कि पति के सहयोग की वजह से ही वह फिल्में बना पा रही हैं। जब वह व्यस्त होती हैं, तब नीतेश बच्चों का ख्याल रखते हैं। बहरहाल, कंगना ने जया के किरदार को शिद्दत और जरूरी भाव के साथ पर्दे पर निभाया है। पंजाबी गायक और अभिनेता जस्सी गिल की यह पहली हिंदी फिल्म है। वह प्रभावित करते हैं। नीना गुप्ता की मौजूदगी भर से दृश्यों में निखार आ जाता है। बाल कलाकार यज्ञ भसीन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी मासूमियत और संवाद किरदार को स्मरणीय बनाते हैं। कई दृश्यों में लगता है कि कलाकार तत्क्षण अपनी प्रतिक्रिया और बातों से कुछ नया टांक देते हैं, जिससे उस दृश्य की खूबसूरती बढ़ जाती है। कई प्रसंग ऐसे हैं, जो सिनेमाघर से बाहर आने पर भी याद रह जाते हैं। दमदार और चुटीले संवादों का धागा तो सभी कलाकारों को मिला ही हुआ है। शंकर-एहसान-लॉय का संगीत और जावेद अख्तर के बोल कहानी के साथ सुसंगत हैं। फैमिली ड्रामा के रूप में यह रोचक फिल्म है, जो मनोरंजन करने के साथ-साथ अपने अधूरे सपनों को न छोड़ने और उन्हें दूसरा मौका देने की बात करती है। -स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

स्क्रीन शॉट

'मिर्जापुर 2' में खलनायक के रूप में दिखेंगे लिलिपुट

डिजिटल प्लेटफॉर्म कुछ कलाकारों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर जहां लगातार नए चेहरों को खुद को साबित करने का मौका मिल रहा है, वहीं पुराने कलाकारों को भी उनकी पसंद का काम मिल रहा है। 'चमत्कार', 'आंटी नं 1' और 'बंटी और बबली' जैसी फिल्मों ने नजर आ चुके अभिनेता एम फारुखी उर्फ लिलिपुट काफी समय से स्क्रीन से गायब थे। अब वह वेब सीरीज 'मिर्जापुर' की सीक्वल 'मिर्जापुर 2' में खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे। बताया जाता है कि उनके किरदार के दो हमशक्ल बेटे होंगे। दोनों का स्वभाव एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक की सोच नकारात्मक है, जबकि दूसरे की सकारात्मक। दोनों पुत्रों के बीच संतुलन बनाने वाला उनका किरदार काफी रोमांचक होगा। उसके अलावा, लिलिपुट एक अन्य फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। वास्तविक कहानियों से प्रेरित उनकी फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के माफिया कल्चर को दिखाती वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मेस्सी, अली फजल, कुलभूषण खरंबदा और रसिका दुग्गल मुख्य भूमिका में थे। यह साल 2018 की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज में से एक रही। 'मिर्जापुर 2' की रिलीज डेट के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस साल की अंतिम तिमाही में उसके रिलीज होने की संभावना है।

कहानियों की कठपुतलियां हैं कलाकार : आयुष्मान खुराना

अभिनेता आयुष्मान खुराना का मानना है कि कलाकार कहानियों के अनुसार ही काम करते हैं। उनका कहना है कि स्क्रिप्ट लेखन को फिल्म इंडस्ट्री में कमतर आंका जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट ही कलाकार की परफॉर्मेंस में अंतर लाती है। आयुष्मान कहते हैं, 'स्क्रिप्ट लिखना आसान नहीं है। कलाकार केवल स्क्रिप्ट की कठपुतलियां हैं। वे वही करते हैं, जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है।' लगातार सात हिट फिल्में देने वाले आयुष्मान का कहना है कि कलाकार के लिए जरूरी है कि वह आम लोगों से जुड़ा रहे, ताकि उसकी पकड़ किरदार की बारीकियों पर बने। उन्होंने बताया कि वह जब भी वह शूटिंग करते हैं, आम आदमी की तरह रहने की कोशिश करते हैं। वह अपने किरदार की तैयारी सेट पर मौजूद ड्राइवर, चायवाले से बात करके भी करते हैं। वह कहते हैं कि आम लोगों को जानना है तो उनके बीच का बनना होगा। आयुष्मान की आगामी फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' समलैंगिक संबंधों पर आधारित है।

एक्शन सीन के लिए बॉडी डबल लेने से इन्कार किया अनन्या-ईशान ने

दर्शक इन दिनों वास्तविक सिनेमा देखना पसंद कर रहे हैं। कलाकार भी उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात की जाए ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की तो दोनों अपनी आगामी फिल्म 'खाली पीली' में वास्तविकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म का दूसरा शेड्यूल महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई में पूरा हुआ, जिसमें कई एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए। स्टंट खतरनाक था, जिसमें चोट लगने की आशंकाएं थीं, लेकिन ईशान और अनन्या दोनों ने ही अपने स्टंट के लिए बॉडी डबल लेने से इन्कार कर दिया। दरअसल, एक्शन डायरेक्टर परवेज शेख ने जो एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किया था, उसमें ईशान को एक बड़े से वाहन से कूदना था और तीस मीटर तक फिसलते हुए नीचे जाना था। इसमें चोट लगने का खतरा देखते हुए निर्देशक मकबूल खान ने दोनों से इसके लिए बॉडी डबल लेने के लिए कहा। दोनों ने ही इससे इन्कार करते हुए सीन की खूब प्रैक्टिस की। दस दिनों तक शूट हुए इस सीक्वेंस में ईशान ने वाई की तंग गलियों में कई पीछा करने वाले सीन भी किए। फिल्म 12 जून को रिलीज होगी।

दिशा ने किरदार की वजह से साइन की 'राधे'

'एमएस धौनी : द अनटोल्ड स्टोरी' से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली दिशा पटानी लगातार बड़ी बजट की फिल्मों का हिस्सा बन रही हैं। पिछले साल 'भारत' में वह सलमान खान के अपोजिट नजर आई थीं। हालांकि उसमें उनकी मेहमान भूमिका थी। अब प्रभु देवा निर्देशित 'राधे : योर मोस्ट वांटेट भाई' में एक बार फिर यह जोड़ी नजर आएगी। दिशा का कहना है कि सलमान ने उन्हें यह फिल्म ऑफर की थी। उन्होंने यह फिल्म इसलिए करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें प्रभुदेवा के साथ पहली बार काम करने का अवसर मिल रहा था, साथ ही किरदार उनका अच्छा था। दिशा के मुताबिक, सलमान ने उनसे पूछा था क्या वह फिल्म करना चाहेंगी? उन्होंने स्वीकृति दे दी। फिल्म में सलमान, प्रभु देवा के अलावा फिल्म की कहानी और अपने किरदार की वजह से भी उन्होंने 'राधे' करने का फैसला किया। 'राधे' में उनके अलावा रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ प्रमुख भूमिका में होंगे। यह फिल्म इस साल ईद पर रिलीज होगी, जिसमें सलमान पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। सात फरवरी को रिलीज होने वाली मोहित सूरी निर्देशित 'मलंग' में वह आदित्य रॉय कपूर के अपोजिट नजर आएंगी।

लंबी छलांग के लिए लंबी नींद जरूरी है...

राजकुमार राव अभिनीत फिल्म 'छलांग' का पहला पोस्टर शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जारी किया गया। इस फिल्म में राजकुमार मोंटू नाम के ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, जो स्कूल का पीटी मास्टर है। पोस्टर में वह स्कूली बच्चों के बीच एक कुर्सी पर सोते हुए दिख रहे हैं। पास खड़ी नुसरत भरूचा बच्चों के साथ उन्हें देख रही हैं। राजकुमार ने लिखा, 'लंबी छलांग के लिए लंबी नींद जरूरी है। 'छलांग' 13 मार्च को रिलीज हो रही है।' फिल्म की कहानी मोंटू की है, जो अपने काम को मजबूरी समझता है। प्रेमिका सहित सब कुछ दांव पर लग जाने बाद उसे अपना फर्ज याद आता है और वह मेहनत और लगन के साथ काम करके सफलता पाता है।

एक मंच पर उतरे दिग्गज सितारे...

शुक्रवार को अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन, कन्नड़ सुपरस्टार शिवराज कुमार और तमिल सुपरस्टार प्रभु के साथ तस्वीर साझा की। तस्वीर में अमिताभ के साथ पत्नी जया बच्चन भी हैं। अमिताभ ने लिखा, 'मेरे और जया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। भारतीय सिनेमा के तीन दिग्गजों के तीन सुपरस्टार पुत्रों के साथ काम करना सम्मान की बात है। तेलुगु सुपरस्टार अक्किनेनी नागेश्वर राव के पुत्र नागार्जुन हैं। शिवराज कुमार कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार डॉ. राज कुमार के पुत्र हैं, जबकि प्रभु तमिल फिल्मों के सुपरस्टार शिवाजी गणेशन के बेटे हैं।

शूटिंग पूरी होते ही बॉबी ने दाढ़ी से पाया छुटकारा

किरदार के मुताबिक कलाकारों को अपना लुक बदलते रहना पड़ता है। जब तक फिल्म या सीरीज की शूटिंग चलती है, कलाकार उसी लुक में रहने को मजबूर होते हैं। लेकिन काम खत्म होते ही वे उस लुक से बाहर आ जाते हैं। बॉबी देयोल ने भी कुछ ऐसा ही किया है। बॉबी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर चुके हैं। प्रकाश झा निर्देशित वेबसीरीज में बॉबी अहम भूमिका में होंगे। सीरीज में उन्होंने जो लुक रखा है, उसमें वह दाढ़ी में नजर आएंगे। खबरें हैं कि अब इस सीरीज की शूटिंग पूरी हो चुकी है। शूटिंग खत्म होते ही बॉबी ने दाढ़ी से छुटकारा पाया। उन्होंने दाढ़ी शेव कर ली है। कुछ दिनों पहले बॉबी ने अपना दाढ़ी वाला लुक साझा करके बताया भी था कि जल्द ही वह क्लीन शेव्ड होने वाले हैं। बॉबी लगातार अपने लिए अलग तरह का काम अब तलाश रहे हैं। उनकी पिछली फिल्म 'हाउसफुल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था।